

LOK SABHA

DEBATES

(Fourth Session)



(Vol. XII contains Nos. 21-30)

**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

CONTENTS

No. 24, Monday, March 27, 1978/Chaitra 6, 1900 (Saka)

	COLUMNS
Welcome to the Parliamentary Delegation from the Republic of Korea	1
Obituary Reference	2
Oral Answers to Questions:	
*Starred Questions Nos. 449 to 451, 455, 460, 461 and 463	2—37
Papers Laid on the Table	37—39
Written Answers to Questions:	
Starred Questions Nos. 452 to 454, 456 to 458, 462, 464 to 466 and 468	39—49
Unstarred Questions Nos. 4238, to 4269, 4271 to 4404 and 4406 to 4437	49—294
<i>Re. Motion for Adjournment—</i>	
Firing on BHEL workers at Hardwar	294—96
Papers Laid on the Table	297—98
Messages from Rajya Sabha	299—300
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Obstructions in the functioning of Grover Commission	300—16
Shri Hari Vishnu Kamath	300-301, 302—310
Shri Charan Singh	301—02
Shri S. Nanjeshu Gowda	311—15
Matters Under Rule 377—	
(i) Reported Strike by employees of Indian Oil Corporation on 22-3-1976—	
Dr. Laxminarayan Pandeya	316—17
(ii) Medical Officers of National Health Service—	
Dr. Ramji Singh	317—18

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

(iii) Reported Discontentment amongst Central Government Employees for non-payment of Additional D.A. in cash—

Shrimati Ahilya P. Rangnekar 318—19

(iv) Reported clash between senior officers of Lakshdweep Administration and students of the J.N. College on 3-3-1978 at Kavarathi Headquarters—

Shri P. M. Sayeed 319—22

Demands for Grants, 1978-79—

Ministry of Defence 323—452

Dr. Karan Singh 326—41

Shri Yadavendra Dutt 341—48

Shri P. V. G. Raju 348—51

Shri Yagya Datt Sharma 351—59

Shri Krishna Chandra Halder 359—63

Shri Rudolph Rodrigues 363—69

Shri B. P. Kadam 369—71

Shri Narendra Singh 371—73

Shri Mukhtiar Singh Malik 373—77

Shri D. D. Desai 377—81

Shri Nathu Singh 381—91

Shri Keshavrao Dhondge 391—400

Prof. Sher Singh 400—10

Shri Rinching Khandu Khrame 410—14

Shri S. D. Somasundaram 414—17

Dr. R. Rothuama 417—19

Shri V. Kishore Chandra S. Deo 419—26

Shri Baldev Singh Jasrothia 426—32

Shri Nirmal Chandra Jain 432—36

Shri R. L. Kureel 436—39

Shri Jagjivan Ram 439—52

LOK SABHA DEBATES

1

LOK SABHA

Monday, March 27, 1978/Chaitra 6,
1900 (Saka)

*The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock.*

[MR. SPEAKER in the Chair.]

WELCOME TO THE PARLIAMEN- TARY DELEGATION FROM THE REPUBLIC OF KOREA

MR. SPEAKER: Hon. Members, at the outset, I have to make an announcement.

On my own behalf and on behalf of the Hon'ble Members of the House, I have great pleasure in welcoming H.E. Mr. Il Kwon Chung, Speaker of the National Assembly of the Republic of Korea and the Hon'ble Members of the Parliamentary Delegation from Republic of Korea who are on a visit to India as our honoured guests. The other Hon'ble Members of the delegation are:

- (1) Mr. Sam Chul Park, Member of Parliament;
- (2) Mr. Sang Cho Shin, Member of Parliament;
- (3) Mr. Sang Sin Lee, Member of Parliament;
- (4) Mr. Young Pyo Lee, Member of Parliament.

The delegation arrived here yesterday afternoon. They are now seated in the Special Box. Through them we convey our greetings and best wishes to His Excellency the President, His Excellency the Prime Minister, esteemed National Assembly, Government and the people of the Republic of Korea.

2

OBITUARY REFERENCE

MR. SPEAKER: I have to inform the House of the sad demise of Shri Shantilal Girdharilal Parikh, who passed away at Ahmedabad on the 16th March 1978 at the age of 73.

Shri Shantilal Girdharilal Parikh was a Member of First Lok Sabha during the years 1952-57 representing Mehsana East constituency of the erstwhile Bombay State. Earlier he had been a Member of Baroda State Legislative Council during the years 1946-49 and of Bombay Legislative Council during 1949-52. An industrialist and social worker, he was a very amiable person.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure, the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the deceased.

The Members then stood in silence for a short while.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पटना को बचाने के लिए गंगा और सोन नदियों पर तटबंध

* 449. श्री रामदेव सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना नगर को बाढ़ से बचाने के विचार से सरकार ने गंगा तथा सोन नदियों के बायें किनारे पर मजबूत तटबंध बनाए हैं ;

(ख) क्या गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर तटबंध न होने के कारण सारन तथा वैशाली जिलों (बिहार) के सारे क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त होने की भांशंका बन गई है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ने इन जिलों को बाढ़ से बचाने के लिए गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर तटबंध बनाने की कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो वहां कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाना है ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

After the deluge of Patna city in August 1975, works to protect Patna were carried out comprising *inter alia* strengthening of the then existing south bank Ganga embankment, construction of new embankments on the right bank of Sone from Digha to Saidabad and on the left bank of Sone from Puzpur.

The area on the north bank of Ganga in Saran and Waishali districts of Bihar have been liable to flooding even earlier whenever the Ganga flood discharge exceeded its bankfull capacity. The Bihar Government have prepared three schemes for construction of embankments on the north bank of Ganga from Dumari to Chapra, from Chapra to Sonapur and from Hajipur to Bazipur at a total estimated cost of Rs. 20 crores. These schemes were technically examined by the Centre and the State was required to modify the reports and estimates. These are awaited.

श्री रामदेव सिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि गंगा के उत्तर की तरफ पटना के सामने जहाँ सोनपुर का मेला लगता है और जहाँ सारन और वैशाली जिले के महत्वपूर्ण गांव हैं उन को बचाने के लिए आप ने कोई योजना बनायी है ? यदि बनायी है तो कब बनायी ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Three schemes by the Government of Bihar were received in the Ganga Flood Control Commission during November-December, 1975. They were:

1. Dumari-Chaupra Embankment Scheme.
2. Chapra-Sonepur Embankment Scheme.
3. Hajipur-Wazirpur Embankment Scheme.

ये तीन स्कीम है जो 1975 के नवम्बर दिसम्बर में बनी :

श्री रामदेव सिंह : यह सन् 76 की स्कीम है तो इस स्कीम में अभी तक निर्माण का काम शुरू हुआ या नहीं ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: These Schemes were scrutinised by the Ganga Flood Control Commission and the comments were sent to the State Government in July-November, 1976, for modifying the schemes. These were subsequently further discussed in the Sixth Meeting held on 27th January 1977, and thereafter, in the Eight Meeting on 30th December, 1977, by the Ganga Flood Control Commission. The modified schemes from the State Government are now awaited.

श्रीधरी बलबीर सिंह : मैं मंत्री महोदय से आप के जरिए यह जानना चाहूंगा कि क्या जिन इलाकों में फ्लडिंग आते हैं उन इलाकों के मेम्बरान पालियामेंट और उन

के साथ आफिशियल्स को मिला कर एक हाई पावर कमेटी बनाएँ जिस से कि उन इलाकों में फ्लड्स को रोकने के लिए कोई मुस्तकिल इंतजाम किया जा सके ? अरबी रुपये का मुकसान हर साल हिन्दुस्तान में इन फ्लड्स से होता है। जिन इलाकों में ये फ्लड्स आते हैं उन के आदमी और उन के नुमाइन्दे ज्यादा बेहतर तरीके से इस काम में सरकार की मदद कर सकते हैं। तो क्या सरकार ऐसी कमेटीयां बनाएगी जिस से कि उन इलाकों के लोगों के नुमाइन्दे और सरकारी आफिशियल्स मिल कर इस को रोकने के लिए अपने मुसाव दे सकें ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कमेटी बनाने का तो अभी कोई विचार नहीं है लेकिन जो फ्लड कंट्रोल कमीशन बैठाया गया है उन्होंने कुछ क्वेश्चनारर तैयार किए हैं जो स्टेट्स को भेजे गए हैं। पिछली दफा यह सवाल सदन में आया तो यह कहा गया कि क्वेश्चनारर ही क्यों नहीं भेजे गए। तो वह क्वेश्चनारर अब मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट को भी भेज दिए गए हैं जिस में सब अपने अपने मुसाव दे सकते हैं कि कैसे यह काम होना चाहिए। अभी तक उन की तरफ से कोई मुसाव प्राप्त नहीं है।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : पटना शहर ही नहीं, अनेक ऐसे शहर हैं जहां पर कि कई नदियों की बाढ़ से उन को बड़ा परेशान होना पड़ता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, देश में ऐसे बहुत से पुराने तालाब हैं जिन में सिल्ट जमा हो गई है, क्या वह

सिल्ट बुलडोजर से निकालने का इंतजाम करेंगे ताकि तालाब गहरे हो जायें और उन में ज्यादा पानी रह सके ? मैंने मंत्री जी से इस की चर्चा की थी और उन्होंने यह माना था कि यह मुसाव ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ क्या इस मुसाव को कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह सवाल इस से निकलता नहीं है, लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि तालाबों को कुछ गहरा किया जाये, उन को गहरा करने की बात सोची जा सकती है।

श्री राम बिलास पासवान : यह फ्लड का जो मामला है यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि जिन लोगों को फ्लड का तजुर्बा है, मैं समझता हूँ, वे ही इसको समझ पाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि फ्लड कंट्रोल का जो मामला है, 1976 में आपने रिपोर्ट मांगी लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट पर रिव्यू ही चल रहा है, आपने स्टेट्स को क्वेश्चनारर भेजे हैं और उधर से उनकी मांग रहती है लेकिन फ्लड फिर आने वाले हैं तो क्या मंत्री महोदय सदन को निश्चित आश्वासन देंगे कि कब तक बिहार और उत्तरी बिहार ही नहीं दूसरे प्रान्त के लोग भी सरकार से आश्वस्त हो जायें कि अब हम बाढ़ की चपेट में नहीं पड़ेंगे ? इसके अलावा जब तक आप बाढ़ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको केन्द्रीय सहायता के रूप में आप क्या देने जा रहे हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहाँ तक बाड़ का ताल्युक है, मेरा खयाल है इस सदन से ग्रानरेबिल मेम्बर बाकिफ हैं कि किसी न किसी इलाके में बाड़ जरूर आती है लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कौन सी तारीख तक बाड़ का काम मुकम्मल हो जायेगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। यही नहीं है कि स्कीम्स देखी जा रही हैं, एग्जामिन की जा रही हैं बल्कि साथ साथ कोशिश है कि काम चलता रहे, काम चलता रहता है और नेशनल पालिसी फार फ्लड कन्ट्रोल को भी बनाने की कोशिश की जा रही है।

महानगरों में केन्द्रीय सरकार के क्वार्टर

* 450. श्री लालजी भाई : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्बास मन्त्री निम्नलिखित की जानकारी दयाने क्षाला विवरण समा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली तथा देश के अन्य महानगरों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए टाइपवार, कितने सरकारी क्वार्टर निर्माणाधीन हैं; और

(ख) अब तक कितने क्वार्टर पूरी तरह बन चुके हैं और उन्हें कब तक आबंटित किये जाने की प्राशा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्बास मन्त्री (श्री सिकन्दर बल्ल) (क) और (ख) : सामान्य पूल के क्वार्टरों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना का एक विवरण सलग्न है। 1977-78 के दौरान बनाए गये 921 क्वार्टरों में से 888 क्वार्टरों का आबटन कर दिया है। शेष क्वार्टरों का भी आबटन कर दिया जायेगा।

विषय

शहर का नाम जनवरी 1978 के अन्त तक निर्माणधीन बनावे गये क्वार्टरों की संख्या
 जून 1978 के अन्त तक निर्माणधीन क्वार्टरों की संख्या

शहर का नाम	जनवरी 1978 के अन्त तक निर्माणधीन क्वार्टरों की संख्या					जून 1978 के अन्त तक निर्माणधीन क्वार्टरों की संख्या						
	I	II	III	IV	कुल	I	II	III	IV	कुल		
नई दिल्ली	1236	2746	1797	134	184	6097	288	215	70	68	641	625
दम्बई	300	640	250	80	60	1330	29	40	40	—	100	100
कलकत्ता	56	1192	856	—	84	2188	30	—	—	—	30	30
भद्रास	120	98	—	—	—	219	—	—	—	32	—	32
बंगलौर	80	120	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—
चण्डीगढ़	100	60	40	—	—	200	16	—	16	8	40	40
दिल्ली	36	40	32	—	—	108	—	—	—	—	—	—
गाजियाबाद	—	200	100	—	—	300	64	—	—	—	64	64
इन्दौर	66	—	—	—	—	66	—	6	—	8	—	14
कुल	1994	5097	3075	214	328	10708	418	261	126	116	—	921

श्री लालजी भाई : अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि 1975 से 77 तक इन क्वार्टर्स के निर्माण पर वर्षवार कितनी कितनी राशि खर्च की जा चुकी है तथा भागे के लिए कितनी राशि रखी गई है ?

श्री सिकन्दर बख्त : 1974-75 में 6 करोड़ 30 लाख रुपए रखे गए थे जिसमें से खर्चा 5 करोड़ 24 लाख रुपया हुआ। 1975-76 में 7 करोड़ रुपए रखे गए थे जिसमें से 6 करोड़ 55 लाख खर्चा हुआ। 1976-77 में 9 करोड़ रुपए रखे गए थे जिसमें 10 करोड़ 10 लाख खर्चा हुआ। 1977-78 में 18 करोड़ रुपया रखा गया था जिसमें से 16 करोड़ 75 लाख खर्चा हुआ। 1978-79 में 26 करोड़ 10 लाख रुपए रखे गए हैं।

श्री लालजी भाई : क्या यह सच है कि रेडियो और टेलीविजन प्राथमिक सेवायें हैं परन्तु इनके कर्मचारियों के लिए किसी भी स्थान पर सरकारी क्वार्टर नहीं बनाये गए हैं जबकि रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आदि के कर्मचारियों के लिये अलग से सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं ? इसके साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि रक्षा मंत्रालय के एक बहाली कर्मचारी को 1973 में 52 हजार रुपए में एक क्वार्टर दिया गया था परन्तु कुछ निजी स्वार्थवश अधिकारियों ने उसको वह प्लॉट भी नहीं दिया और न ही ब्याज सहित राशि ही वापिस की है। इस मामले में मैंने कई चिट्ठियाँ भी लिखी हैं मन्त्री जी को लेकिन आज तक वह केम पडा हुआ है तो इसके बारे में भी मन्त्रीजी कुछ बतायें।

श्री सिकन्दर बख्त : यह कुल्लत है कि रेडियो और टी वी के कर्मचारियों के लिए पलाहिदा से क्वार्टर्स की व्यवस्था नहीं है।

माननीय सदस्य का जो दूसरा सवाल है जो कि व्यक्तिगत है उसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री लालजी भाई : माननीय मन्त्री जी नोटिस माग कर इस बात को टालना चाहते हैं। 55 हजार रुपए में बहाली कर्मचारी को लिखकर प्लॉट दिया गया था। या तो उसे प्लॉट मिलना चाहिए या ब्याज सहित रुपया वापिस होना चाहिए। उस प्लॉट पर दूसरे ने बिन्डिंग बना ली है, उससे रुपया ले लिया गया है तो इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं।

श्री सिकन्दर बख्त इस सवाल से यह पैदा नहीं होता है।

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : मैं वजीर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिन शहरों में सरकार का जमीन मिलती है वहाँ पर सरकार मकान बना सकती है लेकिन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कोई बाहर का प्रादमी जमीन नहीं खरीद सकता है। वहाँ पर सरकार जमीन खरीद नहीं सकती है लेकिन क्या लम्बी लीज पर जमीन लेकर मुलाजमीन के लिए मकान बनाने का कोई प्रोग्राम सरकार के पास है ?

श्री محمد شفی کوریشی :
وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ
جن شہروں میں سرکار کو زمین ملتی
ہے وہاں پر سرکار مکان بنا سکتی ہے -
لیکن جہوں کاشمیر اور لداخ میں کوئی
باہر کا آدمی زمین نہیں خرید سکتا
ہے وہاں پر سرکار زمین خرید نہیں
سکتی ہے - لیکن کیا لمبی لیز پر زمینیں
لیکر ملازمین کے لیے مکان بنانے کا کوئی
پروگرام سرکار کے پاس ہے

SHRI SIKANDAR BAKHT: This does not arise from the question. I will require notice for this.

में धर्ज कर्क कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट इम्प्लोईज जम्बू थ काश्मीर मे नही है ।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI:
He says there are no Central Government employees there.

श्री सिम्कवर बख्त: मेरे कहने का मतलब यह था कि हमारे यहाँ उस किस्म की कोई योजना नहीं है ।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा: मंत्री महोदय ने बताया है कि इस साल 951 मकान पूरे हुए हैं और बाट दिये गये हैं । मेरा कहना यह है कि यह मकान सरकारी कर्मचारियों की टोटल संख्या का देखते हुए बहुत कम है । इस तरह से तो बहुत सारे वर्ष लग जायेंगे और तब कही जा कर सारे कर्मचारियों को क्वार्टर मिल सकेंगे । जो गवर्नमेंट इम्प्लोईज किंगडम पर मकान लेते हैं, उन को एक बहुत बड़ा भाग 80-90 परसेन्ट अपनी तनख्वाह का किराये पर खर्च करना पड़ता है । ता मैं मंत्री जी से यह जानना चाहना हू कि जितन सेन्ट्रल गवर्नमेंट इम्प्लोईज दिल्ली मे है उन सब को मकान देने के लिये आप के पाम कोई योजना है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जा गवर्नमेंट एम्प्लोईज रिटायर हा जाते है, उनसे रिटायरमेंट मे चार पाच साल पहले से धनराशि ले कर उन का डो० डो० ए० के माध्यम से मकान देने की योजना आप बनान जा रहे है या नही ताकि रिटायरमेंट के बाद उनका मकान मिल सके ?

श्री सिम्कवर बख्त 951 नहीं, 921 मकानात तैयार है और हम ने एक कृष प्रोग्राम हाल में लिया है जिसमे 10708 मकानात कम्प्लीशन के मुकदालिफ स्टेज पर है । दो साल मे यानी मार्च, 1980 तक जा 30 हजार मकानो का कमिटेमेंट : 972 का था, वह हमारा पूरा करने का इरादा है । रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स, जितनी भी स्कीमे फ्लोट की जाती हैं, उन मे हिस्सा ले सकते

है । उन के लिये ब्रान से कोई योजना नहीं है ।

डा० रामजी सिंह जो सभा पटल पर बक्तव्य रखा गया है, वह मुझे बहुत अन्यायपूर्ण लगता है क्योंकि उस मे क्लास 1 प्रफिसर्स के लिए 1994 क्वार्टर हैं, क्लास 2 के लिए 5097 है, क्लास 3 के लिए 3075 और क्लास 4, जिन को सब से कम पैसा मिलता है, उन के लिए सब से कम मकानो का इन्तजाम है । इस से बढ कर और कोई अन्यायपूर्ण काम नही हो सकता है । उन के लिए केवल 214 है और जो पहले बन गए हैं वे 116 है । इस का मतलब यह है कि हम समझते हैं कि पहले से यह व्यवस्था न्यायपूर्ण चल रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि जिन को कम पैसा मिलता है क्या उन के लिए आप ज्यादा मकानो का प्रबन्ध करेगे और जिन को ज्यादा पैसा मिलता है उन के लिये कम मकानो की व्यवस्था करेगे ? कुछ इस तरह की योजना आप बनायेगे ।

श्री सिम्कवर बख्त आनरेबल मँबर ने इस का गलत पढ़ा है । यह क्लास 4 इम्प्लोईज के नही है बल्कि यह मकानो का टाइप है । टाइप 1 हम क्लास 4 एम्प्लोईज का देते है और उस से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले को टाइप 2 देते है और इस तरह से बढते जाते है । सब से कम तनख्वाह वाले को टाइप 1 दिया जाता है । इसलिये यह जो माननीय सदस्य ने समझा है, वह गलत समझा है । मैं आप की इत्तिला के यह भी अर्ज कर दू कि 30 हजार मकान बनाने का जो हमारा प्रोग्राम है, वह सिर्फ टाइप 1, 2 और 3 वाला है । ऊपर की श्रेणी के लोगो को उस मे नही रखा गया है ।

श्री राम सेवक हजारी मैं यह कहना चाहता हू जो मकानात कर्मचारियों को दिये जाते है वे उन को मिलते हैं जिन की

घरकी होती है और जिन की पहुंच होती है। ग्राम कर्मचारियों के साथ जो न्याय होना चाहिए वह नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे ऐसा पैल बनाने की बात सोचेंगे कि जिस पैल के आधार पर जिस वर्ग में मकानात हों, वे उस के आधार पर दिये जायें ताकि कर्मचारियों को मकान लेने के लिए पैरवी न करबानी पड़े और न ही इसमें करपशन हो। क्या इस तरह को व्यवस्था ग्राम करने जा रह है ?

श्री सिकन्दर बख्त : माननीय सदस्य को इतना दुस्त नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। एलाटमेंट का एक कामदा मुकर्रर है और उसी के मुताबिक मकान एलाट किए जाते हैं।

डा० बलदेव प्रकाश : मैं यह कहना चाहता हूँ कि पीछे लोक सभा सेक्रेटेरियेट की तरफ से एक पत्र लोक सभा के सभी मੈम्बर्स को भेजा गया था कि संसद् सदस्यों के लिए भी कुछ कोटा रिजर्व किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इन के पास कुछ एप्लीकेशन्स आई हैं और अगर आई हैं, तो उन पर क्या एक्शन हुआ है। कितना कोटा रखा गया है और कितना एलाटमेंट हुआ है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

SHRI SIKANDAR BAKHT: The main question relates to allotment to the Central Government employees.

Crop Insurance

DR. VASANT KUMAR PANDIT:

*451. **SHRI K. MAYATHEVAR:**

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether any steps have been taken by Government to introduce and implement crop insurance policy throughout India;

(b) if so, the results of implementation in various States; and

(c) the reasons for the very slow progress in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) to (c). The new scheme of crop insurance on an area basis is under the active consideration of the Government of India. This will be finalised and introduced in consultation with the State Governments and the General Insurance Corporation of India. In the past, at the instance of the Government of India, the General Insurance Corporation of India implemented certain experimental crop insurance schemes during 1973 to 1976. The scheme were implemented in Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and West Bengal; the crops covered were cotton, groundnut, wheat and potato. The General Insurance Corporation had to pay indemnity of Rs. 36.06 lakhs against the premium income of only Rs. 3.38 lakhs. As the results were not encouraging, the schemes had to be discontinued. The General Insurance Corporation has now formulated a new scheme taking into account its past experience. The new scheme will be for homogeneous agro-climatic blocks with common premia rates and indemnity. This scheme involves collection of substantial data on crop cutting experiments and in-depth study for deriving indemnity limits as well as premia payable. In view of the past experience in implementing the crop insurance scheme, the new scheme has to be framed very carefully.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: May I know from the Minister whether the results of the past experiment during 1973 to 1976 were based on the mere economic point of view that you had paid so much claims and that you had received so much premium? Have the Government made any in-depth study of the failure of the scheme? I want the Government to re-examine insurance of food crops for the small

farmers and marginal farmers and not the large scale sugar-cane growers or sugar mills or cotton growers, because they can pay the premium. Will the Government get the study made through the Gokhale Institute of Economics and Politics, Poona or through Prof. Dandekar School of Research in Economics, of the crop pattern and then frame its scheme in collaboration with the State Governments? Will the Government re-examine the causes of the failure and frame such a scheme which will be beneficial both for the food crops as well as money crops?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: All these suggestions are under consideration. As I have stated, the details for the success of such a scheme are not easily available. For example, it is only in an irrigated area that crop insurance can be taken with some hope of success. In the past also, it is not only the cash crops which were insured but wheat was also insured. In the new scheme, we are adopting an area approach which means, whosoever falls in that area whether small farmer or big farmer, will be covered if he wants to get his crop insured.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Government also consider the scheme of having insurance for live-stock?

MR. SPEAKER: I think, you will have to ask a separate question for that.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: He has included GIC in that Statement. Since the scheme is being re-considered, I want to know whether the Government is contemplating to include animals, crops and stocks, everything else which the small farmer owns, under stores.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: It is a good suggestion. But in implementing such a scheme, we have only to move very cautiously.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: May I know whether all the crops in the area which is going to be taken

for the introduction of crop insurance, are to be insured; if so, whether the crop insurance is going to be voluntary or compulsory?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: The scheme is not yet finalised. The concurrence of the State Governments is necessary before the scheme is implemented. Their concurrence has not yet been received. So, I cannot at present give any specific reply to such a question. But the scheme will be crop-wise and not covering all the crops in an area. It will be for individual crops from year to year.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Whether it will be compulsory or voluntary?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: That aspect is very much under our consideration.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: After hearing the reply of the hon. Minister, we are convinced that the Government is not sincere about the scheme. If they were sincere, the Government would have taken the decision to implement the scheme and asked the Department to enforce it. The reply is the other way round. May I ask him: Is he going to take a decision to implement the scheme immediately?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: We will implement only such a scheme which is viable and acceptable to the State Governments and also acceptable to the cultivators of that area.

SHRI B. K. NAIR: The Government is considering the introduction of this new scheme on the basis of the past experience. I would like to ask one or two things in regard to the implementation of this new scheme. Firstly, will they consider the inclusion of Kerala in this scheme and, secondly, will they also be including paddy? In our State of Kerala, the yield is very low. Most of the cultivators are under heavy debts. They do not find any means to get out of the debts.

Every time, whenever there is a flood or a drought, they suffer all the more. So, there should be some sort of crop insurance to cover paddy. I also want to know whether the scheme will be extended to Kerala.

SHRI BHANU PRATAP SINGH The Kerala State Government is associated with this scheme. Actually, their representatives were with us and they have discussed their special problems also with us.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा किन-किन राज्यों में आप ने इस का सर्वेक्षण किया है—क्या वहाँ की राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में आश-यक्त वार्ता आप ने की है यदि हा तो उसका क्या परिणाम निकला है ? यदि निकला है तो उस को देखते हुए उस के अनुसार कब तक आप इस में ठोस कदम उठा सकेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आप थे और हमारे साथ वार्ता हुई थी। परन्तु उन्होने कहा कि अंतिम निर्णय वे वापिस जा कर कभी लेंगे ? अभी उनका अंतिम निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राजस्थान और केरल राज्यों में बातचीत चल रही है और उन राज्यों के विषय में प्रीमियम इंडेमनिटी टेबलज बनाने की तैयारी की जा रही है। यदि इन राज्यों सरकारों ने स्वीकार कर लिया तो अगली खरीफ में सम्भवतः यह स्कीम लागू की जा सकेगी।

उपजाऊ भूमि में पानी का जमा होना

* 455. **श्री विनायक प्रसाद यादव :**

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विभिन्न सिंचाई योजनाओं को अर्थज्ञानिक तथा अभ्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित किये जाने के कारण देश में विशेषकर बिहार में कई लाख हेक्टेयर उपजाऊ भूमि

में पानी जमा हो गया है जिस से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और छोटे किसान और गरीब हो रहे हैं,

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पम्पो द्वारा पानी निकालने की कोई योजना बनाई है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिए बिहार को कितनी राशि दी गई तथा पानी का इस तरह जमाव कब समाप्त होगा ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House

Statement

(a) waterlogging is caused by rise of sub-soil water level within and above the root zone which affects adversely the productivity of the soil. Introduction of irrigation can cause waterlogging under certain conditions. Waterlogging conditions had earlier developed in certain areas within the commands such as Sirhind Canal and Upper Bari Doab Canal System in Punjab, Western Yamuna Canal in Haryana and Chambal in Madhya Pradesh and Rajasthan but the problem in these projects is under control as a result of introduction of drainage and conjunctive use of surface and ground water. Waterlogging conditions however do prevail in certain pockets of irrigation commands.

So far as Kosi and Gandak projects concerned there is drainage congestion due to natural depressions and unfavourable outfall conditions during monsoon.

(b) and (c) Irrigation projects now provide for appropriate drainage measures and the problem areas are now being tackled by the State Governments by means of measures such

and sub-surface drains, conjunctive use of surface and ground water etc. to control the water table.

The Government of Bihar have made a provision of Rs. 20 crores and Rs. 27 crores for drainage in the revised project estimates for Kosi and Gandak projects respectively for improving the drainage conditions and the works have been taken in hand. These projects are expected to be completed in the next 5-6 years.

श्री बिनायक प्रसाद यादव : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह लिखा है — जहां तक कोसी और गंडक परियोजनाओं का सम्बन्ध है, प्राकृतिक गड्ढे और जल निकासी की व्यवस्था के प्रतिकूल होने के कारण भीनसूत के मौसम में जल निकास में रुकावट पैदा हो जाती है ।

जहां तक इस जवाब का सम्बन्ध है हम समझते हैं कि यह बिल्कुल गलत जवाब है इस पानी में कि वहां जो नहर बनी है कोसी की और गंडक की उस के पहले जो उपजाऊ जमीन थी जिस में कमी पानी नहीं लगता था नहर बनने के बाद वहां पर फाजिल पानी का निकास कर दिया जाता है और उस की वजह से जो उपजाऊ जमीन है उसमें वह पानी आ कर के जमा हो जाता है और उस के वहां से निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है । क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि गंडक और कोसी कमांड एरिया में कितनी जमीन अभी तक बाटर लाग्ड हुई है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कोसी कमांड एरिया में 1. 12 लाख हैक्टियर जमीन बाटर लाग्ड हुई है और गंडक कमांड एरिया में 2. 95 लाख हैक्टियर जमीन बाटर लाग्ड है ।

श्री बिनायक प्रसाद यादव : जैसा मंत्री महोदय ने कहा मैं अध्यक्ष जी, आप के

जरिये इन से कहना चाहता हू कि कोसी में जो अभी सिंचाई हो रही है उस में मुश्किल से 2 लाख हैक्टियर जमीन में सिंचाई हुई है, जब कि उसी कोसी नहर के चलते जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया 1 लाख हैक्टियर से ज्यादा जमीन में पानी जमा हो गया है और उस के निकालने के लिये मंत्री जी ने कहा है कि बिहार सरकार ने कोसी योजना में 20 करोड़ ६० दिया है बाटर निकासने के लिये और गंडक योजना में 27 करोड़ ६० दिया है । तो मैं पूछना चाहता हू कि यह रुपया कब दिया गया, कितने दिन से स्कीम चल रही है, कितनी जमीन में से पानी को निकाला गया है कोसी और गंडक योजना में और कितना ६० हर साल ड्रेनेज विभाग ने वापस सरकार का लौटा दिया काम न कर के और वह रुपया लैप्स हो गया है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जवाब में बनाया गया है कि बिहार सरकार ने 20 करोड़ ६० कोसी के लिये और 27 करोड़ रुपया रिवाइज्ड प्राजेक्ट ऐस्टीमेट गंडक के लिये बनाया है । पहले जो धोरीजनल स्कीम थी उस में ड्रेनेज के लिये बहुत थोड़ा प्राविजन किया गया था । कोसी प्राजेक्ट में महज 1 करोड़ 32 लाख का एप्रुवल था और गंडक में 42 लाख का प्रावीजन था जिस को बढ़ा कर 27 करोड़ कर दिया गया है और इस में काम शुरू किया जा रहा है और धारा है कि 5, 6 साल में यह सारा काम पूरा हो जाएगा ।

श्री बिनायक प्रसाद यादव : ड्रेनेज डिपार्ट-मेंट 5, 7 वर्ष से कोसी और गंडक में काम कर रहा है, मैं पूछना चाहता हू कि कितना काम हुआ है ? लाखों ऐकड़ जमीन कोसी और गंडक योजना के चलते बाटर लाग्ड हो गई है इस का जवाब दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं आप सवाल पूछ चुके हैं ।

श्री डी० एम० सिबारी : यह सुन कर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि गंडक कमान्ड एरिया में करीब 3 लाख एकड़ जमीन वाटर लागू है। मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी जमीन की सिंचाई उससे होती है और 3 लाख एकड़ के करीब जो जमीन वाटर लागू है उसमें कुछ होता नहीं है तो उससे कितना नुकसान हर साल होता होगा।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : नुकसान का तो भ्रंदाजा नहीं लगाया गया है कि कितना नुकसान होता है।

श्री डी० एम० सिबारी : कितने एरिया में सिंचाई होती है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : टोटल सिंचाई कितनी होती है इससे संबंधित यह सवाल नहीं था इसलिए उस के फ़ैक्ट्स नहीं बता सकूंगा। भ्रम से सवाल करें तो जवाब दूंगा।

श्री बी० पी० मण्डल : कोसी में जितनी जमीन की सिंचाई होती है उससे ज्यादा जमीन, अच्छी जमीन, डिफ़िक़्टिव ऐलाइनमेंट के कारण वाटर लागू हो जाती है और वही हालत गंडक की भी है। क्योंकि भारत सरकार देश की उपज को बढ़ाना चाहती है, तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस किस्म का जो वाटर लागिंग है, और बिहार सरकार का मैं यह भी कह दूँ कि रुपया लैप्स कर जाता है, काम नहीं होता है, तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस में कहां तक इंटरवेंट लेना चाहती है देश की उपज बढ़ाने के लिये ? वाटर लागिंग की प्रोब्लम को दूर करने के लिये प्रापका पर्सनली कितना इंटरेस्ट है ?

MR. SPEAKER: It is a suggestion.

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इरीगेशन और पम्प कंट्रोल स्टेट सबजेक्ट है इसलिए

मैनवी स्टेट्स ही स्कीम बनाती हैं और ऐग्जीक्यूट करती हैं और फ़ाइनेंस करती हैं। इसीलिये स्टेट गवर्नमेंट ने यह 42 लाख से बढ़ाकर 27 करोड़ २० किया है। उन्होंने समझा है कि इस प्रोब्लम को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिये और वह इस काम पर लगी हुई है। जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं बहुत देर से यह मसला है, इसमें बहुत काम अभी तक नहीं हो सकता है। लेकिन अब धीरे काम अच्छे तरह से होगा। हम भी इसमें दिलचस्पी लेंगे और स्टेट गवर्नमेंट भी दिलचस्पी ले रही है।

Payment to re-employed teachers of Aided Schools in Delhi

*460. SHRI BALAK RAM: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the services of some teachers working in Government aided schools of Delhi had been terminated after declaring them as unqualified;

(b) whether it is also a fact that some of the teachers whose services had been terminated were found qualified only after intervention of his Ministry and thus given re-employment;

(c) whether it is also a fact that such teachers have not been paid their emoluments for the above said intervening period which varies from months to years; and

(d) what remedial steps are being taken by the Central Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI-MATI RENUKA DEVI BARAKATA-KI). (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

According to information received from Delhi Administration, some aided private schools were found to have recruited certain persons who did not possess the educational qualifications and/or were over-aged, in accordance with the provisions of the Delhi School Education Rules, 1973. Accordingly, the services of such employees had to be terminated. However, representations received from the concerned employees were considered by the Administrator, Delhi, and it was decided, on compassionate grounds, to relax the age limit in favour of those who had been appointed upto the end of December, 1975 and who had completed one year's service. No relaxation was, however, granted in favour of those who did not possess the minimum educational qualifications. There was no occasion for intervention by the Government of India.

The persons in whose favour the age limit was relaxed were reinstated and the period between the termination of service and reinstatement was treated as leave of the kind due. The concerned institutions have also been authorised to disburse the admissible leave salary.

श्री बालक राम : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जबाब जो मंत्री महोदय ने दिया है वह मेरे सवाल के जबाब में तमस्सी गड़ग नहीं है, क्योंकि टीचरों को गलत प्रारंभ देकर 30-11-65 में लेकर 2-2-67 तक नोकरी से भ्रमण रखा गया अन-क्वालीफाइड का बहाना लगाकर, फिर उसी पोस्ट के प्रग्रेन्ट उन्हें उसी स्कूल में वापिस लेना पड़ा और टीचरों को बिना गलती पाये तनक्वाह से महकूम रखा गया, जबकि सारी गलती दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की थी। उन्होंने अपनी गलती छिपाने के लिये टीचरों को 14 महीने की तनक्वाह नहीं दी। इसमें एज कोई भी सवाल नहीं था। इस बारे में मैंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को भी कई

बार लिखा लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला।

मैं मंत्री महोदय से एम्प्लॉयर्स बहाल हूँ कि इस तरह से गलती से निकाले गये टीचरों को क्या उसी तरह की तनक्वाह और एलाउन्सेज की भ्रमायगी की जायेगी और जिन अफसरों ने ऐसी गलती की है, क्या उन्हें जिम्मेदार ठहराया जायेगा ?

SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI: In the Statement which I have laid on the Table of the House, I have clearly stated that some of the aided private schools had appointed some under-qualified teachers, and when the claim for grants came to Delhi Administration, on scrutiny it was found that many of these teachers—not many, but ten—were found under-qualified in respect of educational qualifications and were also over-aged. Their services had been terminated. But afterwards when they appealed to the Administrator, at the level of Lt. Governor, a decision was taken to reinstate those teachers to whom relaxation had been given in respect of age; but no relaxation was given to their educational qualifications. Accordingly, the teachers were reinstated. This intervening period between termination of service and reinstatement was taken as leave of the kind due and the concerned institutions were requested to make the payment to the teachers.

श्री बालक राम : दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे भी टीचर हैं, जिनको अफसरों ने गलत आज्ञा देकर वक्त से पहले रिटायर कर दिया और उन्हें फिर घर बैठे ही तनक्वाह दी। इस तरह से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों की मनमानी के कारण जो डबल पालिसी चल रही है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस विषय में भारत सरकार की क्या नीति है ?

SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI: If the hon. Member can bring the specific cases to our notice, then we will examine them.

श्री भारतीरथ शंकर : मैं यह जानना चाहता हूँ कि निकाले गये अध्यापकों की संख्या कितनी है और कितने लम्बे समय से ऐसा चला आ रहा था कि अयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी ? क्या ऐसी गड़बड़ियों की जांच के लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था है ? जो लोग शासन की ओर से एड लेकर पैसे का दुरुपयोग करते हैं और नाजायज फायदा उठाते हैं, इस सम्बन्ध में जांच के लिये क्या कोई व्यवस्था भी शासन की ओर से है ? यदि है, तो इसकी अभी तक जांच क्यों नहीं की गई ?

SHRIMATI RENUKA DEVI BARA-KATAKI: As we have been informed by the Delhi Administration, the number of teachers whose services were terminated was ten and out of them, eight were reinstated and it was not for years together. The Delhi Administration School Department came into existence in 1974, the Delhi Administration School Education Rules were passed in 1973. In 1976, we decided to reinstate some of these teachers. It was, therefore, not for years, but for a few months only. And for one year, we have given relaxation to them.

श्री राम कंचार बेरवा : मंत्री महोदय ने बताया है कि जो शिक्षक अयोग्य पाये गये, उन्हें निकाला गया है। यह बहुत पुराना मामला है। पिछली सरकार ने काफी टीचरों को राजनीति में भाग लेने का आरोप लगा कर निकाल दिया था। मंत्री महोदय पिछली लकीर पर चल कर इस प्रकार के जवाब दे

रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय ने पर्सनली रिकॉर्ड ले कर इस मामले की अच्छी तरह जांच की है। क्या यह सत्य नहीं है कि अयोग्य होने का बहाना बना कर योग्य व्यक्तियों को भी निकाला गया है ? क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि ऐसे शिक्षकों को वापस लिया जायेगा ?

SHRIMATI RENUKA DEVI BARA-KATAKI. This question related to the aided schools under the Delhi Administration and not all the schools.

Implementation of Land Ceiling Laws

*461. SHRI HITENDRA DESAI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to lay a statement showing:

(a) how much land has been obtained under the Land Ceiling laws in each of the States and Union Territories; and

(b) when will the implementation of Ceiling laws be completed?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) A statement is placed on the Table of the Sabha.

(b) Implementation of Ceiling laws is the responsibility of State Governments. They have been urged to expedite implementation and to find out methods of overcoming legal and procedural difficulties. It is not possible to indicate any date by which implementation of ceiling laws will be completed.

Statement

Extent of land obtained under the land ceiling laws

(Figures in acres)

Sl. No.	Name of the States/Union Territories	Under pre-revised laws (upto Sept. 1977).	Under revised laws upto December, '77).	Total
1.	Andhra Pradesh	25,792	2,75,428	3,01,220
2.	Assam	1,71,871	5,44,137*1	7,16,008
3.	Bihar	N.A.	1,25,602	1,25,602
4.	Gujarat	44,207	4,122	48,329
5.	Haryana	83,013*	56,262	1,39,275
6.	Himachal Pradesh	292*	81,760	82,052
7.	Jammu & Kashmir	4 50,000	..	4,50,000
8.	Karnataka	N.A	..
9.	Kerala	Nil	64,784	64,784
10.	Madhya Pradesh	5,828	1,32,086*2	1,90,914
11.	Maharashtra	2,45,787	2,66,314*3	5,12,101
12.	Manipur	Nil	Nil
13.	Orissa	Nil	1,07,700	1,07,700
14.	Punjab	97,475	5,577	1,03,052
15.	Rajasthan	2,85,046	2,22,734*4	5,07,780
16.	Tamil Nadu	32,724	38,176	90,900
17.	Tripura	838	838
18.	Uttar Pradesh	2,04,119	2,23,873	4,27,992
19.	West Bengal	8,26,733	66,346*5	8,93,129
20.	Dadra & Nagar Haveli	4,623	4,628
21.	Delhi	286*	192	478
22.	Pondicherry	730	730
TOTAL		25,46,223*	22,21,289	47,67,512*

*Includes 1,81,066 Standard Acres

*1 Till January, 1977.

*2 Till September, 1977.

*3 Till July, 1977.

*4 Till September, 1977.

*5 Till June, 1977.

SHRI HITENDRA DESAI: The national objectives about land reforms were fixed long time back, but there has not been much progress in this respect. For instance, the Government of Gujarat has appointed a Land Commission recently to go into the whole question of land reforms. Will the Government assure that no State will be allowed to legislate anything against the national objectives already fixed?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: So far, no State has passed a legislation against the national objectives. We have not received any information that any land legislation contrary to this has been passed by any State.

SHRI HITENDRA DESAI: Will you give an assurance that nothing will be done against the national objectives?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: It has not come to our notice that anything contrary to this is being done.

MR. SPEAKER: Unless a concrete case is there, how can he say anything?

SHRI HITENDRA DESAI: Even in Gujarat under the revised laws upto December, 1977, only 4,122 acres of land have been obtained? Will the Government let us know the reasons for the delay?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Probably, the hon. Member himself must be knowing the reasons for the delay because he....

SHRI HITENDRA DESAI: I was not in Government.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: It is a fact that so far only 4,122 acres of land have been declared surplus under the revised laws upto December, 1977.

SHRI HITENDRA DESAI: What are the reasons?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: This is for the State Government to say and for giving that information, I require a separate notice.

SHRI CHITTA BASU: According to the statement laid on the Table of the House, 47,67,512 acres of land have so far been made available under the Land Ceiling Laws in the various States. May I know from the hon. Minister, what is the total estimate of the available surplus land. In this connection, may I know from the hon. Minister whether he knows that Dr. Mahalanobis at a certain stage before the 1st Five-Year Plan suggested that six crores acres of land would be made available as surplus provided the 16 standard acres was the highest ceiling on land? Later, Shri Dandekar had estimated that four crores acres of land would be available as surplus. What are the particular reasons by which the available surplus land has been drastically reduced to this extent? How has it been reduced right from the 1st Five Year Plan to date?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: The total estimated area of surplus land in the country is 54,94,763 acres. Regarding the second part of the question, a separate notice is necessary.

SHRI CHITTA BASU: Six crores acres were found surplus by Prof. Mahalanobis whereas the Minister says that only 56 lakhs would be made available.

MR. SPEAKER: What statistics mean you know.

SHRI SHAMBUN NATH CHATURVEDI: May I know whether there is any uniformity in the area of the ceiling in all the States, and if not, what is the range of variation? Secondly, I want to know whether the revision of the ceiling was done under the revised law of December 1977 in all the States at the instance of the Central Government or on their own?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA
The national guidelines were formulated in 1972. According to those guidelines these amendments were made by the States. Some States legislated after that and according to the guidelines all the States have passed their own laws. So uniformity could not be maintained. We have only provided guidelines and according to the guidelines, the ceiling area has been from 17½ to about 10 acres varying from State to State, of 'A' class land.

श्री कंवर लाल गुप्ता : क्या यह सही बात है कि पहले जा सरकार लैंड थी उस का एस्टीमेट, जिन समय ला बना, बहुत ज्यादा थाया गया था और आज भी डिफ्लैटड लैंड बहुत है जिन के केमेज कोर्ट में कई-कई सालों में चल रहे हैं और अभी भी एक-एक लैंड साईड के पास कई-कई हजार एकड़ जमीन है ? मैं जानना चाहता हूँ कि इस सब में आप का साग एस्टीमेट, क्या था और स्टेट गवर्नमेंट्स का आप क्या हिदायत दे रहे हैं जिन में जा जमीन लिटिगेशन में है उम के फैल का एकमीडाइट किया जाये ? इस के अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो आप के पास सगल लैंड है 47 लाख एकड़ इस का आप ने क्या उपयोग किया है ? क्या यह सही है कि इस में मैं जा जमीन कुछ गरीब लोगों का दी गई थी वह वापस छीन ली गई है ? यदि हाँ, तो उम भबध में आप ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय सदस्य न कई सवाल डक्टो कर दिए हैं। मैंने जा पहले एस्टीमेट डटल एरिया बताया था वह शायद आप ने सुना नहीं। 54 लाख 94 हजार 763 एकड़ जो टोटल एस्टीमेट एरिया था। इस में से जैसा मैंने पहले अर्ज किया स्टेटमेंट में 47 लाख 67 हजार 512 एकड़ जमीन लैंड सीलिंग के नीचे ले ली गई है। मैं समझता हूँ कि 54 में 230LS—2

से 47 लाख ले लिया जाय तो यह कफ़ी प्रॉब्लम हुई है और ऐसी कोई बात हमारे नॉटिस में नहीं आई कि किसी गरीब को दे कर फिर उसमें अमीन छीन ली गई हो।

श्री अगत राम : मैं जानना चाहता हूँ कि नैट सोलिंग लाज के अन्तर्गत जो जमीन प्राप्त की गई है उस में से स्टेट-बाइज कितनी बाटी गई है और कितने परिवारों में बाटी गई है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह तो बहन लम्बा स्टेटमेंट हा जायगा। मैंने पास फॉर्म है अगर वह चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ।

MR SPEAKER You have had the statement. You need not read again what is contained in that statement.

SHRI C M STEPHEN. We are also interested to know that. Let him read it.

MR SPEAKER The statement is on record.

Shri Mahi Lal

श्री मही लाल : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का वाद करेगें कि भूमि वितरण में जो प्रगति चल रहा थी उस में अब शिथिलता आ गई है ? क्या वर्तमान शासन ने पूर्वगामी शासन के निर्णय में कोई परिवर्तन करने का निश्चय किया है ? यदि नहीं तो जो प्रगति चल रही थी उम में शिथिलता किस कारण आई है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : प्रगति में कोई शिथिलता नहीं आई है बल्कि काम और तेजी से चल रहा है। हम ने स्टेट गवर्नमेंट्स का लिखा है कि तेजी में काम किया जाय और अगर कोई कास्टेंस हैं दिक्कतें हैं तो उन को दूर करने की कोशिश की जाये। मैं बताता चाहूंगा कि 31-3-77 से 30-11-77 तक के 8 महीनों में 1 लाख 45 हजार हेक्टेयर एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है।

SHRI R. K. MHALGI: May I know if the Central Government has recently issued instructions to the State Governments in respect of complete implementation of the ceiling laws?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: I have been writing letters. Recently also I have written letters.

It has been mentioned in my arguments earlier.

MR. SPEAKER: Primarily it is a State subject.

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, सीलिंग कानून जो बना था उसका उद्देश्य यह था कि अधिक से अधिक जमीन ले करके गरीबों में बांट दी जाये। जब सीलिंग कानून बना तो उसके बाद जिन बड़े-बड़े लोगों के पास अधिक जमीन थी उन्होंने अपनी जमीन को बचाने के लिए कुछ ऐसे रास्ते निकाले जिससे कि उनको जमीन न देनी पड़े। ऐसी हालत में पहले जो अनुमान था कि इतनी जमीन मिलेगी जोकि गरीबों में बांटी जायेगी उतनी जमीन नहीं मिल सकी— यह बात भाकड़ों से सिद्ध होती है। इसमें गड़बड़ी यह हुई है कि जितने बड़े-बड़े जमींदार थे उन्होंने अपनी जमीन अपने छोटे-छोटे बच्चों के नाम करवा दी। पाच साल, दस साल के बच्चों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम उन्होंने अपनी जमीन करवा दी। तो उस समय लोगों ने अपनी जमीन बचाने के लिए कानून में जो लूपहोल निकाल लिया था अपनी जमीन को बचाने के लिए, क्या सरकार उस कानून को बदल कर परिवार के अनुसार जमीन की सीलिंग करने का कानून बनाने पर विचार कर रही है जिस से कि गरीबों को जमीन मिल सके ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय सदस्य को शायद पता नहीं है, पहले भी परिवार की डेफनीशन करके जमीन देने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने जो यह कहा कि बेटों के नाम जमीन करके जमीन

बचा ली गई तो यह हर कानून में लिखा है कि फलां डेट के बाद जो भी जमीन के ट्रांसफर होंगे वह इनवैलीड माने जायेंगे और उनको बिल्कुल कंसीडर नहीं किया गया। हर कानून में यह प्रावधान रखा गया था। श्री नहीं जान : वह कौन सी तारीखें थी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : भलग-भलग डेट्स रखी गई है।

SHRI K. A. RAJAN: I would like to know from the hon. Minister, is there a thinking in the Northern States to change the ceiling over and above the direction given by the Centre Government?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: There is no such thinking. Northern States in some respects have done better than some of the States.

बालाघाट, मध्य प्रदेश में रोजर्स प्रतिष्ठान केन्द्र

* 463. श्री लक्ष्मी नारायण नायक :
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री मध्य प्रदेश में बेतूल में फारेस्ट रोजर्स प्रशिक्षण कालेज के बारे में 19 दिसम्बर, 1977 के तारकित प्रश्न संख्या 470 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य के बालाघाट जिले में एक फारेस्ट रोजर्स प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाये, और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त केन्द्र कब तक खोल दिया जायेगा ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is still under consideration.

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव कब से चल रहा है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कुछ समय से अलग अलग जगहों से जो प्रपोजल माये थे उनको कंसीडर करने के बाद फैसला कर दिया गया कि बालाघाट में स्टेशन खोला जायेगा ।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या हम आशा करें कि जल्दी से प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया जायेगा ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हमारी कोशिश है कि 1978 से वहां पर शिक्षा शुरू हो जाय ।

MR. SPEAKER: Question No. 453, Shri Sarat Kar. Not here. I think Question List is over. This is really a day to be celebrated. Now, Papers to be laid on the Table. Dr. Chunder.

11.56 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annual Report and Review and certified Accounts of Indian Institute of Technology, Madras for 1976-77 and certified Accounts of Visva-Bharati University—Santi Niketan for 1975-76

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): Sir, with your permission,

I beg to lay on the Table—

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Madras, for the year 1976-77.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Indian Institute of Technology, Madras, for the year 1976-77.

(iii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the documents mentioned at (1) and (ii) above. [Placed in Library. See No. LT-1897/78].

(2) A copy of the Certified Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Madras for the year 1976-77 along with the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 28 of the Institutes of Technology Act, 1961.

(3) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the document mentioned at (2) above. [Placed in Library. See No. LT-1898/78].

(4) (i) A copy of the Certified Accounts (Hindi and English versions) of the Visva-Bharati University, Shantiniketan, for the year 1975-76 together with the Audit Report thereon.

(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above papers. [Placed in Library. See No. LT-1899/78].

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: You will have to repeat.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You have to repeat the list again of those who are absent if they have come again.

MR. SPEAKER: Only the authorised one....

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Somebody might have also come.

MR. SPEAKER: Only if somebody is authorised. Please take out the rule. I thought I should call it if it were only authorised.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: You will have to repeat it again.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: You must re-cycle the whole list.

MR. SPEAKER: All right. Q. No. 352—Shri Phool Chand Verma. Not here. Q. No. 453—Shri Sarat Kar. Not here. Q. No. 454—Shri C. K. Chandrappan. Not here. Q. No. 456—Shri Saya Ram Shakya. Not here. Q. No. 457—Prof. P. G. Mavalankar. Not here. Q. No. 458—Shri Jagdish Prasad Mathur. Not here. Q. No. 462—Shri Shyamlal Dhurve. Not here. Q. No. 464—Shri G. S. Reddi. Not here. Q. No. 465—Shri Kishore Lal. Not here. Q. No. 466—Shri K. Ramaurthy. Not here. Q. No. 468—Shri Dharasinhbhai Patel. Not here.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक सेवा कामिकों के गृहों का पंजीकरण * 452. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताना ही कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विधान प्राधिकरण उन सामुदायिक सेवा कामिकों के गृहों के आवंटियों के नाम रजिस्ट्री करने की अनुमति नहीं दे रहा है जो उनके द्वारा बेचे गये हैं और जिनके लिए पूरी धनराशि की अदायगी पहले ही की जा चुकी है यद्यपि आवंटियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को गृहों की रजिस्ट्री के लिए लिखा है; और

(ख) यदि हा, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बजत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Assistance to small fishing units

*453. SHRI SARAT KAR: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the small firms engaged in fishing operations are facing stiff competition from big industrial units which have entered the fishing line with huge resources and modern equipment; and

(b) if so, the details regarding Government's plan to extend its help to the small firms?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA). (a) No, Sir.

(b) Does not arise

Change in present Education System

*454. SHRI C. K. CHANDRAPPAN Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in January a meeting took place at Rajkot where eminent educationists and 90 Vice-Chancellors participated to bring a change in the present educational policy;

(b) whether it is a fact that a 28-page "policy frame" document was circulated which reflected the present Government's line of thinking on education;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether Government intend to place this document on the Table of House?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) to (d). The University Grants Commission has adopted a policy frame for the development of higher education in the next ten years. The document was also placed before the annual session of the Association of

Indian Universities held at Rajkot in January, 1978. The salient features of the policy are indicated in the statement laid on the Table of the House. The document is under consideration of the Government.

Statement

The policy frame adopted by the University Grants Commission for development of higher education in India over the next ten to fifteen years visualises the following:—

(i) Adoption of measures which will reduce pressures on the university system through effective vocationalisation at the secondary stage, delinking jobs from degrees, changing recruitment policies which make a degree a minimum qualification for any good job;

(ii) Restraint in the establishment of new institutions, which should not be set up (except in backward areas) unless the need is established on academic considerations and availability of resources;

(iii) Planning the location of new institutions very carefully and rationalising that of the existing ones;

(iv) Selective admission to full-time institutions of higher education at the first degree and postgraduate levels on the basis of merit with reservation of at least half the seats for weaker sections;

(v) Provision of facilities to meet the full cost of education of talented but economically weaker students;

(vi) Expansion of higher education through non-formal channels; and

(vii) Opening Secondary/Intermediate Board and University examinations to private candidates.

The policy frame also visualises a major programme of restructuring under-graduate courses, confinement of post-graduate education and research to university departments, decentralisation of university administration,

extension services to schools and to the community at large, improvement of standards both in terms of academic achievement as well as social commitment and contribution to national development, introduction of the regional languages as the medium of instruction etc.

पत्रकारों/समाचार एजेन्सियों और समाचार-पत्रों के कर्मचारियों के लिए सरकारी मकान

* 456. श्री दया राम शाक्य : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार एजेन्सियों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए मकान बनाने तथा उन्हें सस्ती दरों पर आबंटित करने के बारे में एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो समाचार पत्रों में काम कर रहे कितने कर्मचारियों और पत्रकारों को उक्त योजना के अन्तर्गत मकान अलॉट किये गये हैं और भविष्य में उन्हें और अधिक सुविधा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

-निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा बनाई गई सामाजिक आवास योजनाएं बिना व्यवसाय, जाति, धर्म अथवा समुदाय के भेदभाव के समाज के सभी सदस्यों के लिए लागू होती हैं। किन्तु समाचार एजेन्सियों में काम कर रहे कर्मचारी निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत सुविधाओं का स्वयं लाभ उठा सकते हैं:—

(i) निम्न आय वर्ग आवास योजना; और

(ii) मध्यम आय वर्ग आवास योजना ।

समाचार एजेन्सियों के कर्मचारी सहकारी आवास समितियां भी बना सकते हैं और एक्स कोम्पारेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटीज और आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास सिर्फ समाचार एजेन्सियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए कोई योजना नहीं है । किन्तु इसने दिल्ली प्रशासन से अधिकृत पत्रकारों और दिल्ली क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार से अधिकृत पत्रकारों एवं न्यूज कैम्पर्मनों तथा दैनिक समाचार पत्रों के उप-सम्पादकों एवं रिपोर्टरों जो कि दिल्ली में रह रहे हैं के लिए ग्राम लॉगो हेतु निमित्त फ्लैटों का 2 प्र०श० आरक्षण किया है । ये फ्लैट दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिन (एडवान्स) पञ्जीकरण योजनाओं के अन्तर्गत पञ्जीकृत व्यक्तियों को आबंटित किए जाते हैं ।

Irrigation Potential in States

*457. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some States of the Union have immense irrigation potential but it is not being adequately exploited and used;

(b) if so, whether Central Government propose to help augment the irrigation facilities in such States,

(c) if so, how and when; and

(d) if not, why not?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The total irrigation potential in the country is at present assessed as 107 m.ha. This, however, is likely to increase with the

advancement of technology economical use of water and possibilities of diversion of water from areas having surplus to deficit areas. The irrigation potential likely to be created by the end of 1977-78 is 54 m. ha. which is 50 per cent of the ultimate. The level of exploitation and its utilisation, however, varies from State to State.

(b) to (d). Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, formulated and implemented by the State Governments. The Central assistance is in the form of block loans/grants which is not related to any sector of development or scheme.

It is envisaged that most of the balance irrigation potential would be created during the next 15 years. The next Five Year Plan (1978-83) envisages creation of additional irrigation potential of 17 m. ha. This will be mainly in the States where there is large scope for further development of irrigation potential.

काल-पात्र

*458. श्री जगदीश प्रसाद मानुर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काल-पात्र में रखे लेख (स्कूल) के ब्यारे का अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन कौन सी बातें ठीक नहीं हैं प्रथमा बढ़ा चढ़ा कर कही गई है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप कन्न कन्न): (क) से (ग). काल पात्र सम्बन्धी संसदीय समिति द्वारा

प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की जांच की जा रही है और इसे काल पात्र से पुनः प्राप्त किए गए 1947 से 1972 तक की बटनाओं के तिथि पत्र और भारतीय इतिहास के 10,000% शब्दों के बृत्तान्त की प्रति के साथ यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा। उसके बाद यह निर्णय माननीय सदस्यों को करना होगा कि क्या इसमें गलत अथवा बड़ा चढ़ा कर कही गई कोई बात शामिल है।

प्रादिवासी क्षेत्रों में निरक्षरता समाप्त करना

462. श्री ह्याब लाल शुभे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री निम्न-लिखित की जानकारी दशानि धाला विचरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रादिवासी क्षेत्रों से निरक्षरता समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशेष योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण विचरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग). प्रादिवासी क्षेत्रों सहित, देश से निरक्षरता के उन्मूलन के लिए सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण तथा प्रौढ़ शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। अगले पांच वर्षों के दौरान औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत 320 लाख अतिरिक्त बच्चों को तथा प्रस्ताव के अनुसार 2 अक्टूबर, 1978 से प्रारम्भ किए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम द्वारा 15-35 आयु वर्ग के लगभग 10 करोड़ बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय के स्वीकृत प्रादिवासी विकास

कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक स्वीकृत 116 परियोजनाओं में विशेष सैद्धिक प्रगति के कार्यक्रम भी शामिल हैं।

Wheat Farming in Andhra Pradesh

*464. SHRI G. S. REDDI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether wheat farming is being popularised in Andhra Pradesh;

(b) if so, with what result; and

(c) whether any rice or millet growing area has been diverted to wheat growing?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir, Though wheat is not an important crop in Andhra Pradesh, it is getting popular year by year.

(b) The area under wheat in the State has increased from 13,800 hectares in 1967-68 to 26,300 hectares in 1975-76. Similarly, the production of wheat has increased from 2,700 tonnes to 21,500 tonnes during the same period. However, both area and production of wheat in the State declined to 23,800 hectares and 14,600 tonnes respectively, during 1976-77, owing to unfavourable weather conditions.

(c) The increase in wheat area in Andhra Pradesh is mostly due to increase in gross cropped area.

Loni Road Residential Scheme, Delhi

*465. SHRI KISHORE LAL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during the period of Emergency land under Loni Road Residential Scheme of Delhi Development Authority was neither acquired by Delhi Administration nor handed over to DDA;

(b) whether it is a fact that Delhi Development Authority prepared a layout plan of this land, published it for sale of the plots and executed sale deeds in favour of the purchasers in the name of and on behalf of the President of India; and

(c) whether it is a fact that Delhi Development Authority continue to execute sale deeds even now?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The land was acquired through awards announced in September, 1967 and January, 1968 and part of the land was transferred to D.D.A. in February, 1972.

(b) Yes, Sir.

(c) No lease deed has been executed after 5th January, 1978.

Programme of "Teacher preparation for the new school system"

*466. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) reasons for selecting eight States for the training programme of "Teacher Preparation for the New School System" when the training programme was conducted on a sharing basis at a cost of Rs. 15,23,875; and

(b) when all the other States will be covered by this project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI-MATI RENUKA DEVI BARAKA-TAKI): (a) During 1975-76 and 1976-77 some of the State Governments which had implemented or decided to implement the 10 plus 2 pattern of school education requested the NCERT to help them in the organisation of training for their teachers to teach according to the new

syllabi mainly in classes IX and X. NCERT agreed to undertake the training programme and meet part of the expenses provided the State Governments met the TA/DA expenses of the participating teachers. Nine States and one Union Territory which approached the NCERT and agreed to share the expenses were provide with financial assistance for organising the training programme. The total financial assistance provided by the NCERT amounted to Rs. 18,06,175.

(b) At present there is no such proposal.

बीज अधिनियम, 1966 के अधीन संकर कपास और बाजरा के बारे में अधिसूचना

*468. श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करने कि :

(क) क्या बीज अधिनियम, 1966 के अधीन संकर—4 कपास (हाइब्रिड-4 काटन) और संकर (हाइब्रिड) बाजरा—जे 1399, बी०जे०—104 और सी० जे० 104 किस्मों को गुजरात के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को हानि होती है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने अगस्त 1977 में बीज अधिनियम, 1966 के अधीन उपरोक्त किस्मों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यह कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). गुजरात सरकार से कपास की संकर-4 किस्म तथा संकर बाजरा की जे-1399, बी०जे०

104 प्रीर सी०जे० 104 कस्मों को प्रधिसूचित करने के प्रस्ताव प्रगस्त, 1977 में प्राप्त हुए थे। राब्य के लिए कपास की संकर 4 किस्म हेतु, प्रधिसूचना जारी की जा रही है। बाजरे की किस्मों के प्रस्तावों के बारे में बीज प्रधिनियम के अंतर्गत गठित फसल मानकीकरण तथा प्रधिसूचना विषयक केन्द्रीय उप-समिति 1 अप्रैल, 1978 को होने वाली अपनी अगली बैठक में विचार करेगी। इस प्रश्न की कोई शिकायत नहीं मिली है कि इन किस्मों के प्रधिसूचित न होने से गुजरात के किसानों को नुकसान हुआ है।

Supply of inferior pesticides and insecticides

4238. SHRI PARMANAND GOV-INDJIWALA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have received the report that the pesticides and insecticides supplied to the cultivators are inferior;

(b) whether it is a fact that pesticides supplied by even the Government agency is found inferior and

(c) if so, what steps are being taken by the Government to ensure a pure supply of pesticides?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Some reports about the inferior quality of insecticides and pesticides have been received.

(b) No specific report to this effect has been brought to the notice of Government

(c) The Insecticides Act '68 (No 46 of 1968) which, among other things, regulates manufacture and sale of insecticides is being administered by the State Governments. To monitor the quality of pesticides, the Insecti-

cides Inspectors appointed by the State Governments draw samples and launch prosecutions wherever insecticides are found to be mis-branded. Reports about seizure, prosecutions and convictions of the manufacturers/dealers of mis-branded insecticides have been received from time to time. To further strengthen the quality control machinery, 17 State Insecticides Laboratories are being set up in a phased manner, besides, appointment of 220 Joint Input Inspectors. In addition to this, the Government of India is setting up a Central Insecticides Laboratory at national level. The progress made by State Governments in enforcing quality control measures is now being discussed in half yearly Zonal Conferences also.

Cases filed under Delhi Rent Control (Amendment) Act, 1976

4239. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) how many cases were filed under Section 14-A of the Delhi Rent Control (Amendment) Act of 1976 by Government servants who owned residential properties in the Union Territory of Delhi but were residing in Government accommodation; and

(b) how many cases under Section 14-A of the same Act were entertained by the Delhi High Court and Supreme Court and how many were sent back to the lower courts for further proceedings and what were the reasons thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) 611.

(b) Supreme Court entertained and decided 3 cases. Delhi High Court entertained 80 cases of which 22 case of the following types were remanded to trial courts for fresh trial.

- (i) Where tenants were refused permission to defend and contest the cases and ex-parte eviction orders were passed by the trial courts
- (ii) Where rents of the private accommodation owned were less than Rs. 1,000 or Rs. 1,000 to Rs. 2,000 and the Government servant were allowed to retain Government accommodation under the revised house-owning rules at normal rates and at half the market rates, respectively.
- (iii) Where it was in dispute whether the building owned by Government servant was residential or commercial.
- (iv) Where the trial court depended merely on affidavits or other types of evidence but not on both.

Grant to Members and Member-Secretary of I.C.S.S.R.

4240. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the amount of grant given to each of the Members and Member-Secretary of the Governing Body of the Indian Council of Social Science Research during the last five years, year-wise;

(b) the criterion followed in giving grant to them; and

(c) whether any enquiry is being instituted in the matter; if so, with what results?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUN-

DER): (a) and (b). Like any other social scientist it is open to a member of the I.C.S.S.R. to submit a proposal for research to the Council which is considered on merit according to rules. No salary or honorarium is admissible to a member out of the grant for the project. A list showing the projects assigned to members together with the amounts therefor, during the last 5 years is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1919/78].

(c) No Sir.

U.G.C. grants to universities and colleges in Orissa

4241. SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the total amount granted to the U.G.C. during the financial years 1976-77 and 1977-78; and

(b) the U.G.C.'s grants to the Orissa State and to the different Orissa Universities and Orissa's individual colleges both Governmental and non-Government?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Total grants released to the University Grants Commission in 1976-77 and 1977-78 were Rs. 7209.29 lakhs and Rs. 7747.50 lakhs respectively

(b) Grants released by the University Grants Commission to the universities and their affiliated colleges in Orissa in 1976-77 and 1977-78 are indicated below:

Sl. No.	Name of the University	1976-77		1977-78	
		University	Colleges	University	Colleges
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	Berhampur . . .	29,19,789.38	6,05,931.65	41,77,820.00	4,59,776.67
2	Oriasa Agricultural . . .	21,264.96	—	—	—
3	Sambalpur . . .	25,75,931.49	4,75,042.76	10,08,717.00	8,87,161.02
4	Utkal . . .	38,36,773.55	11,45,787.45	31,20,645.00	17,61,115.74

Information about the grants paid to the individual colleges in Orissa is being compiled by the U.G.C. and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

विश्वविद्यालय में एकरूपता

42 42. श्री हुकम चन्द्र कच्छवाय : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न विश्व-विद्यालयों में एकरूपता लाने के लिये कोई नीति बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी कोई शैक्षिक नीति बनाने का है जिससे शिक्षित युवकों के लिये अपनी शिक्षा समाप्त करने के तुरन्त बाद अधिक से अधिक रोजगार करने के अवसर प्रदान किये जा सकें, और यदि हां, तो कब तक; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में बढ़ते हुए अवन्तोष का मूल कारण बेरोजगारी है यदि हां, तो सरकार उनकी समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सभी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में, उनकी शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उनमें से प्रत्येक को पूर्ण प्राधिकार दिया गया है। इस मामले में पूर्ण एकरूपता लाने के लिए सरकार का नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यद्यपि शैक्षिक नीति ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं कर सकती, तथापि 2 स्तर पर व्यावसायीकरण के कार्यक्रम का अभिप्राय छात्रों को ऐसे अवसरों की तलाश करने के लिए तैयार करने हेतु जो पहले ही उपलब्ध हैं, उन्हें आवश्यक निपुणता और सामर्थ्य से युक्त करना तथा उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है।

(ग) यह सच है कि बेरोजगारी उन प्रमुख कारणों में से एक है जो बहुत से छात्रों के मन में उत्तेजना पैदा करते हैं। तथापि, बेरोजगारी की समस्या का हल केवल देश के आर्थिक विकास द्वारा ही किया जा सकता है। छठी योजना, जिसे आजकल तैयार किया जा रहा है, का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है।

Preservation of Wild Life

4243 SHRIMATI PARVATI DEVI
SHRI SUKHENDRA SINGH

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the effective measures being taken for the preservation of wild life specially valuable species like the snow leopard markhot ibex brown bear and hangul (stag) once fairly common in the valley of Kashmir and also in Ladakh and Jammu?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha

Tribal Area Development Agency in Orissa

4244 SHRI GIRIDIHAR GOMANGO
Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) the money released for Tribal Area Development Agencies of Orissa by the Ministry in the year 1977-78 Project wise

(b) achievement made by these agencies particularly in irrigation and communication and money spent on these schemes

(c) proposed allocation for the year 1978-79 for Tribal Area Development Agency of Orissa and

(d) money spent by the State Government in these Project areas in normal development schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) (a) Release of funds to the four Tribal Development Agencies (TDAs) of Orissa State during 1977-78

(upto 20th March 1978) is as under

TDA Project		Amount (Rs in lakhs)
Ganjam		34 00
Koraput		40 82
Keonjhar		25 08
Phulbani		22 08
	TOTAL	121 98

(b) A statement showing the physical achievements of these TAD Projects located in Orissa since their inception upto September 1977 is laid on the Table of the House [Placed in Library See No LT-1920/78] The following table gives the total expenditure incurred by them since inception upto December 1977

TDA Project	Total Expenditure	Expenditure on irrigation and communication
Ganjam	209 57	129 50
Koraput	214 78	119 43
Keonjhar	95 31	39 71
Phulbani	63 49	14 59

(c) TDA Project	Proposed allocation of funds for 1978-79
	(Rs. in lakhs)
Ganjam	35.00
Koraput	35.00
Keonjhar	27.50
Phulbani	27.50
TOTAL	125.00

(d) Name of the IDA Project	Expenditure incurred by State Government from 1-4-77 to 31-1-78
	(Rs. in lakhs)
IDA Ganjam	3.47
IDA Koraput	5.04
IDA Keonjhar	3.20
IDA Phulbani	3.75
TOTAL	15.46

गांधीवादी विचारधारा पर आधारित बुनियादी शिक्षा का अध्ययन

4245. श्री छीतूभाई गामित : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि नए ढंग के पोस्ट बेसिक स्कूलों में गांधीजी की विचारधारा पर आधारित बुनियादी शिक्षा का अध्ययन बड़े सतोपजनक ढंग में चल रहा है और यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान शिक्षा के परिणामों को ध्यान में रखकर देश भर में इस नये ढंग की बुनियादी शिक्षा को माध्यमिक कक्षाओं में भी लागू करने का है, और यदि हाँ तो उसे कब लागू किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और

(ग) क्या जा स्कूल यह नये ढंग की शिक्षा देगे उनका सरकार कोई विशेष अनुदान देगी और यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और यह अनुदान कब से दिया जायेगा

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दा) : (क) देश के बुनियादी और उत्तर-बुनियादी स्कूलों का हाल ही में कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) गांधीजी की बुनियादी शिक्षा को विचारधारा के आधार पर दस-वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या मन्त्रालय पुनरीक्षण समिति (ईश्वर भाई पटेल समिति) ने सामाजिक रूप में उपयोगी उत्पादक कार्य और समाज सेवाओं का स्कूलों को पढाई के एक अनिवार्य अंक के रूप में शामिल करने की सिफारिश की है। राज्य सरकारों को ईश्वर भाई पटेल समिति द्वारा सिफारिश की गई इस पाठ्यचर्या को लागू करने की सलाह दी गई है।

(ग) सामाजिक रूप में उपयोगी उत्पादक कार्य का एक विषय के रूप में लागू करने के परिणामस्वरूप स्कूलों को सहायता-अनुदान की वर्तमान पद्धति में, जैसी कि राज्यों में प्रचलित है, किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की सलाह नहीं है।

Krishi Vigyan Kendra

4246. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the basis of recommendations of the Education Commission (1964-66) for setting up Krishi Vigyan Kendra, the I.C.A.R. constituted a Committee to work out the details of the Scheme;

(b) if so, whether it is also a fact that the Committee submitted its report to Government in 1974 and the Government have accepted its recommendations; if so, the details thereof;

(c) the names of the places where these Krishi Vigyan Kendras were opened till date against the proposed target; and

(d) names of the places where these Kendras are to be opened in the near future?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The Education Commission has recommended the establishment of Agricultural Polytechnics. I.C.A.R. decided to establish institutions (Krishi Vigyan Kendras) where the latest technical skills in agriculture, animal husbandry and fisheries could be imparted through the technique of learning by doing. The I.C.A.R. constituted a Committee headed by Dr. Mohan Sinha Mehta to recommend the kind of Institution that will be relevant to our agricultural needs.

(b) The Committee submitted its report in 1974 and the ICAR has accepted the recommendation to establish Krishi Vigyan Kendras in the country. The important recommendations of the Committee are:—

1. The 50 Krishi Vigyan Kendras proposed to be set up during the Fifth Plan may be estab-

lished in a phased manner on the basis of need and suitability for different regions.

2. At the State level the scheme should be supported by a small advisory Committee headed by the Agricultural Production Commissioner.
3. At the National level, an active operative cell should be established in the ICAR, under a senior officer with necessary staff interested in establishing the Krishi Vigyan Kendras and guiding them.
4. In the staffing pattern, economy should be exercised on administration. Among academic staff, the usual University hierarchy should be avoided, and experienced practical people should be recruited on the staff for specific training needs.
5. The qualifications prescribed for the staff should not be rigid. To restrict it to graduates only would not be wise. Even diploma-holders or master craftsmen may be recruited for their special skills if they are found competent to teach their skills.
6. Voluntary institutions with a record of good service and competent leadership, keen to participate in the programme of establishing Krishi Vigyan Kendras should be welcomed.
7. These proposed innovative institutions, which are expected to catch the imagination of the people, should not be allowed to languish due to paucity of funds

The Centre (ICAR) may provide 100 per cent assistance for non-recurring items other than purchase of land

and municipal facilities (which are to be provided by the State/Institution) and recurring items like cost of academic staff.

ICAR formulated a proposal for establishing 50 Krishi Vigyan Kendras and 7 Trainers Training Centres during the Fifth Plan Period. As advance action, it also sanctioned a K.V.K. at Pondicherry in March, 1974. The Fifth Plan scheme was approved by the Ministry of Finance in April, 1976, following which additional Kendras were established.

(c) To date 19 Krishi Vigyan Kendras have been established at the locations mentioned in the attached statement. In addition, 7 Trainers Training Centres were established.

(d) The locations for new Krishi Vigyan Kendras have not yet been finalised. However, many proposals have been received from different parts of the country which will be processed after the approval of the Government of India for establishing new Krishi Vigyan Kendras during the 6th Plan period.

Statement

List of Krishi Vigyan Kendras established during 1976-77 and 1977-78

Sl. No.	State	Institution to which KVK is attached	Location
1	2	3	4
1	Andhra Pradesh	All India Co-ordinated Research Project in Dryland Agriculture, Amberpet, Hyderabad.	Hayatnagar
2	Bihar	Ramkrishna Mission, Morabadi, Ranchi.	Morabadi (Ranchi)
3	Gujarat	(a) Gujarat Agricultural University, Ahmedabad.	Deesa
		(b) Gujarat Vidyaapeeth, Ahmedabad.	Randheja
4	Haryana	National Dairy Research Institute, Karnal.	Karnal
5	Karnataka	(a) University of Agricultural Sciences, Hebbal, Bangalore.	Hanumanmatu
		(b) Indian Institute of Horticultural Research, Bangalore.	Chettali (Coop.)
6	Kerala	Central Marine Fisheries Research Institute, Narakkal, Ernakulam.	Narakkal
7	Maharashtra	Agricultural Institute, Kosbad-Hill, Distt Thana.	Kosbad Hill
8	Madhya Pradesh	(a) Kasturba Gandhi National Memorial Trust, Indore.	Indore
		(b) Central Institute of Agricultural Engineering, Nabibagh, Bersia Road, Bhopal	Bhopal

1	2	3	4
9	Nagaland	ICAR Research Complex, Shillong (Meghalva)	Jharnapani (Nagaland)
10	Orissa	Central Inland Fisheries Research Institute, Barrackpore (West Bengal)	Dhauri (Bhubaneswar)
11	Rajasthan	University of Udaipur, Udaipur, Rajasthan.	Fatehpur-Sekhawati (Sikar)
12	Tamil Nadu	Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.	Navalur-Kuttapatti, Tiruchirappalli.
13	Uttar Pradesh	Kamla Nehru Institute of Science and Technology, Sultanpur (U.P.)	Sultanpur
14	West Bengal	Sewa Bharti, Kaggari, Midnapur.	Kaggari, Midnapur.
15	Pondicherry Union Territory	Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore (Tamil Nadu).	Pondicherry
16	Mizoram	Directorate of Agriculture, Government of Mizoram, Aizawl.	Kolasil.

Demolition of jhuggies in Delhi

Statement

4247. SHRI M. RAM GOPAL REDDI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state the number of jhuggies demolished in Delhi from March, 1977 to February, 1978 locality-wise and the reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): Delhi Development Authority have reported that 4195 jhuggies were demolished by them with effect from 1st March, 1977 to 28th February, 1978 as per statement enclosed. These were demolished as these were fresh encroachments on public lands.

Sl. No.	Name of the site	No. of Jhuggies
1	2	3
1.	R. K. Puram Sector I & II	37
2.	I.N.A. Panchsheel Marg	5
3.	Rouse Avenue	13
4.	Gujrati Basti	150
5.	Majnu-ka-tilla	10
6.	Jafrabad	2500
7.	Shakarpur	:
8.	Geeta Colony	1500
9.	Motia Khan	75
10.	Majnu-ka-tilla	96
11.	Pusa Road	16

1	2	3
12. Bela Estate		290
13. G. T. Road (Ganda Nala)		45
14. East of Kailash		10
15. Azadpur Bus Terminal		50
16. Lawrence Road		10
17. Wazirpur J. Block	(Mud- huts)	60
18. Madangir		4
19. Mori Gate		61
20. R. K. Puram		30
21. Pusa Dist. Centre		25
22. Dus Ghara, Todapur & Pando Nagar		60
23. Jhandewalan		65
24. R. K. Puram		12
25. Ashok Vihar Phase I & III		84
26. Madangir		50
27. Janakpuri 'B' Block		34
28. Janakpuri 'I' Block		60
29. Trilokpuri		91
30. Arjun Nagar		2
31. Kalu Sara		6
32. Mahindra Enclave		23
33. Bela Estate		160
GRAND TOTAL		4195

ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों के लिए नियत धनराशि

4248. श्री जीतीश्याई द्वार० चौधरी :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री ग्रामीण आधार-भूत ढांचा विकास के बारे में 27 फरवरी,

1978 के अतारंकित प्रश्न संख्या 853 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़क बनाने के लिये 17.58 करोड़ रुपये राज्यों के लिये नियत किये गये थे और यह धनराशि किस आधार पर वितरित की गई थी;

(ख) इस प्रयोजना के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) क्या उन राज्यों को अग्रिक धन-राशि दी जायेगी जो सड़कों के मामलों में पिछड़े हुए हैं जिससे ऐसे पिछड़े राज्यों को अन्य राज्यों के बराबर लाया जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों का ग्रामीण आधारभूत ढांचा—ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय अनुदान के रूप में 1977-78 के बजट प्राक्कलन में 20 करोड़ रुपये की राशि मुलभ की गई है तथा उसमें से राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों को 19 975 करोड़ रुपये वंटित किए जा चुके हैं :

इस राशि को वंटित किए जाने का आधार निम्न प्रकार है:—

(1) राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र में प्रति 100 वर्ग किलो मीटर सरफेस रोड्स ।

(2) राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र में प्रति लाख जनसंख्या पर सरफेस रोड्स ।

(3) सड़कों, उनकी भौतिक विशेषताओं, भूभागों आदि के संदर्भ में राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों का पिछड़ापन ।

(ख) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र को दिए गए केन्द्रीय अनुदान की राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) 1978-79 से योजना को राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाएगा तथा उसके लिए अधिक प्रावधान किया जा रहा है।

विवरण

1977-78 के लिए ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को बँटित की गई राशियाँ।

क्र०	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित आबटन (लाख रुपये में)
------	-----------------------------------	---------------------------------

1.	आन्ध्र प्रदेश	120
2.	असम	65
3.	बिहार	180
4.	गुजरात	75
5.	हरियाणा	33
6.	हिमाचल प्रदेश	38
7.	जम्मू तथा कश्मीर	54
8.	कर्नाटक	82
9.	केरल	49
10.	मध्य प्रदेश	180
11.	महाराष्ट्र	130
12.	मणिपुर	22
13.	मेघालय	28
14.	नागालैण्ड	38
15.	उड़ीसा	87
16.	पंजाब	49

1	2	3
17.	राजस्थान	147
18.	सिक्किम	23
19.	तमिलनाडु	71
20.	त्रिपुरा	15
21.	उत्तर प्रदेश	288
22.	पश्चिम बंगाल	98
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	10
24.	अरुणाचल प्रदेश	44
25.	चण्डीगढ़	2.5
26.	दादरा तथा नगर हवेली	..(a)
27.	दिल्ली	10
28.	गोवा, दमन तथा दीव	10
29.	लक्षद्वीप	..(a)
30.	मिजोरम	44
31.	पांडिचेरी	5
		1997 5

@1977-78 के दौरान योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

Setting up of Polytechnic in Andaman and Nicobar Islands

4249. SHRI DINEN BHATTACHARYA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to set up a polytechnic in the Andaman and Nicobar Islands;

(b) if so, when; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) So far no proposal has been received from the local administration.

Study on Students Behaviour

4250 **SHRI C. K. JAFFER SHARIEF**: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state

(a) whether any study has been made regarding the students behaviour^u recently;

(b) whether any leadership laboratory was conducted at Mount Abu for this purpose; and

(c) if so, the details of the findings made at the laboratory and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) (a) Government have not conducted any such study recently

(b) and (c) No information is available about the leadership laboratory conducted at Mount Abu. The position is being ascertained and will be laid on the Table of the House

Torsa River Master Plan

4251. **SHRI SHYAMAPRASANNA BHATTACHARYYA**: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have received the "Torsa River Master Plan" from the Government of West Bengal for approval and financial assistance; and

(b) if so, what action has been taken by the Government thereon?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). A copy of Master Plan of river Torsa in North Bengal estimated to cost Rs. 48.41 crores was received at the Centre in September, 1977 and is under examination. This is however yet to be considered by the Board of Technical Consultants of North Bengal Flood Control Commission and by the North Bengal Flood Control Board.

Grants and Loans to AMUL

4252 **SHRI OM PRAKASH TYAGI**: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to refer to answer to Unstarred Question No. 4493 on 19th December, 1977 regarding gifts, grants, loans from World Organisations and Centre to Amul and state

(a) the rate of interest and terms for repayment of various loans given to Amul and its associated bodies;

(b) whether the Government have satisfied themselves about productive use of equipments and facilities received and whether the working results reflect their effective and profitable use;

(c) the manner in which gains made possible by use of above equipments and facilities are distributed to cooperatives, suppliers and consumers; and

(d) the quantities of milkpowder and butter oil received by Amul Complex, unit-wise, commoditywise and yearwise, during the last three years with rupee value, showing the basis of billing price, as compared to commercial and market value?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Supply of Furniture in Government Schools under Delhi Administration

4253 SHRI PIUS TIRKEY Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state

(a) whether Government are aware that new furniture has not been supplied to Government Schools under the Delhi Administration during the last five years and every year the amount sanctioned on this score lapse due to the technical formalities,

(b) if so, the reasons therefor and what steps Government propose to take in the matter so that funds do not lapse and furniture is supplied in schools, and

(c) how many Government schools are there which are short of furniture in class rooms and what steps the Delhi Administration have taken during the last five years to provide adequate furniture for the students in the class rooms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI MATI RENUKA DEVI BARAKA-TAKI) (a) to (c) The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be placed on the table of the Sabha as soon as possible

Funds for Development of Animal Husbandry Dairying etc in Orissa

4254 SHRI PADMACHARAN SAMANTASINHERA Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether Government of Orissa require funds for small and marginal farmers in Development of Animal Husbandry, Dairying (Operation flood item Part I-II),

(b) if so, when proposal in this regard was received and amounts required for such schemes; and

(c) whether the required amount has been sanctioned?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) to (c) Orissa was not covered under Operation Flood I programme. In view of this Orissa has been included as one of the 7 States for implementation of a programme for milk production and marketing as a Central Sector Scheme. Accordingly the Government of Orissa have sent proposal in February, 1978 at an estimated cost of Rs 274.62 lakhs for dairy development involving small and marginal farmers. The proposal is under examination.

केन्द्रीय जल प्रायोग में स्थानान्तरण

4255 श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय जल प्रायोग के अधीन दिल्ली और दिल्ली में बाहर कितने अधीनस्थ कार्यालय हैं तथा वहाँ पर श्रेणी 1, 2 और 3 के कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनका गत पांच वर्षों में स्थानान्तरित नहीं किया गया है

(ख) वर्ष 1976-77 में प्रायोग के द्वारा कुल कितना स्थानान्तरण आदेश बिय गए हैं और उनमें से वास्तव में कितना क्रियान्वित हुए हैं,

(ग) क्या प्रायोग में ऐसे 50 प्रतिशत आदेश भी क्रियान्वित नहीं होते और उन्हें बहाने बनाकर रद्द करवा लिया जाता है, और

(घ) ऐसी व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और किसानों से (बी सुरक्षित सिद्ध करना) : (क) से (ब) : सूचना एकत्र की जा रही है और सचा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Regularisation of Shastri Nagar, Delhi

4256. SHRI GANGADHAR APPA BURANDE: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the reasons for non-regularisation of Shastri Nagar near Sarai Rohila, a residential colony in Delhi;

(b) whether he is aware that the colony had been set up in 1962 but it has not been provided with drinking water facilities and sewerage and no proper roads have been laid;

(c) whether he is also aware that insanitary conditions have developed in the colony as a consequence posing a hazard to the health of lakhs of people residing there; and

(d) the steps Government propose to take to improve the living conditions of the people of Shastri Nagar and the time by which this would be done, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) to (d). The colony is situated on land which is reserved for district park/play ground according to the Master Plan. As the land use is not residential, the colony could not be regularised. The colony is to be considered for regularisation in accordance with the terms and conditions contained in the Ministry of Works and Housing letter dated 18th February, 1977, a copy is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1921/78]. Certain civic amenities are already being provided in unauthorised colonies. Other amenities will have to await the formulation of regularisation plans. Drinking water and Sewerage are not

available in Shastri Nagar now. The Municipal Corporation has however deployed 140 persons as road sweepers, drain sweepers, lorry sweepers, etc., to look after the sanitation of the colony. By the end of 1977-78 the Municipal Corporation would be spending approximately Rs. 1.50 lakhs for providing drains, brick payment, etc.

Short Supply of Rice to Tripura

4257. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as against the monthly requirement of 8000 metric tonnes of Rice in Tripura the Food Corporation of India had supplied to that State only 620 metric tonnes in December 1977, 730 metric tonnes in January, 1978 and about 400 metric tonnes in February, 1978;

(b) if so, the reasons for the short supplies of such an order;

(c) whether it seriously affected the price trends of foodgrains and other cereals in Tripura and if so, to what extent; and

(d) the steps taken to ensure adequate supplies of rice during coming months?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) The position regarding demand, allotment and off-take of rice in respect of Tripura Government for the months of December, 1977 and January and February, 1978, is as under:—

(In tonnes)

Month	Demand	Allotment	Offtake
December '77	3,000	3,000	1,000
January '78	1,500	1,500	1,200
February '78	1,500	1,500	920

(b) The stock of 13,000 tonnes of rice available in the FCI depots in Tripura is quite adequate for the State's needs. The off-take by the State Government was, however, unsatisfactory as the stocks offered by the FCI were not initially found acceptable to the State Government. With the cleaning and reconditioning of the stocks to conform to Government of India's specifications and the introduction of joint inspection by the officers of the FCI and the State Food Department the off-take is now expected to increase.

(c) No, Sir. There was no marked effect on the retail prices in the open market.

(d) As already stated, about 13,000 tonnes of rice is held by the FCI in their depots in Tripura as on 1-3-78. In addition, the FCI have also been instructed to move adequate fresh stocks of rice to Tripura from outside for issue to the State Government against the Central allocations.

भारत में शिक्षा पाने वाले विदेशी

4258. श्री सुरेश झा सुमन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने विदेशी इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) उनमें से इंजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की प्रलग-प्रलग संख्या क्या है और कला एवं विज्ञान के छात्र कितने हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और लोकसभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Assault on President of Delhi I.I.T. Employees Union

4259. DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the Delhi IIT Employees Union President has been assaulted causing serious injury to him, and hospitalizing him;

(b) whether the prime suspect of the police is another IIT Employee;

(c) whether this employee applied for anticipatory bail in the case registered and it was turned down by the courts;

(d) whether the IIT Administration then sanctioned to the suspect 10 days leave to enable him to abscond; and

(e) whether in Government's view this action of the Administration constitutes complicity of the IIT authorities in the assault or is otherwise improper?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) On the night between 26/27-2-78 Shri Prakash Singh Takkar, generally mentioned as President of IIT employees' Union, was found lying on the ground in an open place of the quarters of Block No. 16, IIT Hauz Khas in an injured condition and was removed to Safdarjung Hospital.

(b) Shri Prakash Singh Takkar suspected Shri Gurdev Singh a driver in the IIT and two unknown persons.

(c) According to the information received from the local police authorities, Shri Gurdev Singh applied for anticipatory bail but it was turned down by the court.

(d) According to the Institute, Shri Gurdev Singh had applied, on 28-2-78, for ten days' casual leave from

1-3-76. He was sanctioned eight days' leave with effect from 1-3-78 in accordance with rules. The Institute has denied the suggestion that Shri Gurdev Singh was granted leave to enable him to abscond.

(e) Though Shri P. S. Takkar in his statement to the police made on 28-2-78 stated that the IIT administration had some hand in the incident, the statement stands uncorroborated according to police authorities. On the other hand the Institute has denied its complicity in the incident. The whole case is under investigation by the police.

"Protected" Temples in Maharashtra

4260. SHRI R. K MHALGI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the names of the temples in Maharashtra which are "protected" as monuments of national importance;

(b) what steps have been taken or are being taken to 'protect' these temples in Maharashtra; and

(c) what is the expenditure incurred on preservation and maintenance of these temples during last three years and the allocation made for the year 1978-79?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) A list is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See LT-1922/78].

(b) The temples are being preserved by carrying out structural repairs periodically and attending to their general maintenance.

(c) The break-up of the expenditure yearwise is as follows:

	Rs.
1975-76	98,899.84
1976-77	34,584.23
1977-78 (Upto Feb.)	78,144.91

Allocation made for the year 1978-79 is Rs. 2,50,000.

Employees working under Public Undertakings

4261. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA:
SHRI RAM PRASAD DESHMUKH:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the class-wise (I, II, III & IV) total number of persons in each of the undertakings functioning under his Ministry *viz.* Central Fisheries Corporation Ltd., Indian Dairy Corporation, National Seeds Corporation Ltd., State Farms Corporation Ltd., Central Warehousing Corporation, Food Corporation of India, Modern Bakeries (India) Ltd., Banana & Fruit Development Corporation Ltd. and Water & Power Development Consultancy Services Ltd.;

(b) the number of Scheduled Castes & Scheduled Tribes in each class and each undertaking separately;

(c) whether the Government of India's order relating to reservation of vacancies are followed in the matter of recruitment and promotion in these undertakings; and

(d) if not, the reasons thereof?

statement is enclosed.

**THE MINISTER OF AGRICULTURE
AND IRRIGATION (SHRI SURJIT
SINGH BARNALA):** (a) and (b). A

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

Statement

Sl No.	Name of Undertaking	Total No. of employees as on 1-1-1978 in various categories				No. of Sch. Castes and Scheduled Tribes in various categories			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Central Fisheries Corporation Ltd. Hewrah	2	20	175	275	..	1	13	43
2.	Indian Dairy Corporation, Baroda	32	..	101	17	5	..	10	6
3.	National Seeds Corporation, Ltd., New Delhi	90	319	520	217	6	21	51	66
4.	State Farms Corporation Ltd., New Delhi	64	84	1015	220	8	3	179	42
5.	Central Warehousing Corporation, New Delhi	82	223	2178	1988	7	21	266	503
6.	Food Corporation of India, New Delhi	876	3125	35162	27139	59	275	6013	8152
7.	Modern Bakeries (India) Ltd., New Delhi	112	88	730	1019	7	2	68	238
8.	Banana & Fruit Development Corporation Ltd., Madras	1	4	11	4	1	3
9.	Water & Power Development Consultancy Services Ltd., New Delhi	19	7	60	10	4	5

Establishment of Kendriya Vidyalaya at Hoshangabad

4262. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of Security Paper Mill,

Hoshangabad, have made a representation for the establishment of a Kendriya Vidyalaya (Central Govt. School) there;

(b) whether it is a fact that the management of the Mill and the Minister of Education, Madhya Pradesh have also strongly supported the demand of the employees;

(c) whether Government have accorded their sanction to the demand;

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRIMATI RENUKA DEVI BARA-KATAKI): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) and (d). As large number of proposals have been received from various quarters for opening of Kendriya Vidyalayas, the proposal received from the Security Paper Mill, Hoshangabad, will be considered in due course along with other proposals for opening of Kendriya Vidyalayas in 1978-79, since only four Kendriya Vidyalayas can be opened at civil stations in an academic year. The proposals for opening of new Kendriya Vidyalayas at civil stations have to be sponsored by departments of the Central Government or State Governments and the sponsoring authority has to provide 15 acres of land for the Vidyalaya and suitable temporary accommodation free of rent or on nominal rent until a permanent building is constructed. The proposals which fulfil all the pre-conditions are considered together for determining priorities in respect of stations on the basis of relative concentration of Central Government employees and the provision of educational at the concerned stations.

शिक्षा की 10+2 पद्धति के पाठ्यक्रमों में कमी किया जाना

4263. श्री राजकेशर सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा की 10+2 पद्धति के पाठ्यक्रमों की जांच करने हेतु नियुक्त उच्चस्तरीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में क्या कमी और सुधार किये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दा) (क) और

(ख) विचरण सभा पटल पर रखा है। [संचालक ने रखा गया। देखिये सभा एलटी-1923/78]

Cases of Unauthorised construction in Delhi

4264. SHRI KACHARULAL HEM-RAJ JAIN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is fact that the cases of unauthorised construction in Delhi are increasing day by day;

(b) whether one of the main reasons for spurt in unauthorised construction is the availability of cement on ration cards;

(c) whether the Ministry would request the Ministry of Civil Supplies to order for stopping sale of cement in Delhi on ration cards and instead allow the sale of cement on sanctioned plans and house tax receipts only; and

(d) if so, when, and if not, whether it is the policy of the Government to encourage unauthorised construction by allowing sale of cement on ration cards?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Unauthorised constructions have been noticed.

(b) In April, 1977, in view of the prevailing scarcity conditions and to ensure easy availability of cement to bona fide consumers for repairs purposes it was decided to sell part of the cement against ration cards. Prior to this cement was available in the open market. In order to ensure that the cement is not misused, a new clause has been added in Delhi Cement (Licensing and Control) Order, 1972 by promulgating an amendment on 10th March, 1978. No permit holder can now transfer his permit or cement to any other person. Contravention thereof is punishable under the Essential Commodities Act, 1955.

(c) and (d). No, Sir, as it would cause hardship to bona fide users. Instructions have been given to local authorities to exercise constant vigil against unauthorised constructions. A weekly programme for removal of unauthorised constructions is chalked out at meetings held by the District Authorities where representatives of local bodies are present.

Construction at Chittaranjan Park, New Delhi

4265. SHRI A K. SAHA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of quarters under construction in Chittaranjan Park to accommodate the community service personnel;

(b) number of community service personnel that are needed for work in Chittaranjan Park; and

(c) the way balance of the quarters which are not needed to accommodate community service personnel in Chittaranjan Park will be disposed of, and whether these can be allotted to the displaced persons from erstwhile East Pakistan for whom the colony is intended and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) As reported by the Delhi Development Authority, 48 houses have already been constructed in Chittaranjan Park. Another 144 houses are under construction there.

(b) Delhi Development Authority has reported that as per the norms laid down in the Master Plan, 5 per cent of the housing units are to be provided for service personnel family housing i.e. dhobis, janitors, jamadars, malis, domestic servants, etc.

(c) All the flats would be allotted by the D.D.A. to the service personnel as per their existing policy. A large number of service personnel are already registered with them since 1969 onwards under its Advance Registration Scheme. However, DDA had been requested to consider for allotment of quarters on applications from displaced persons also who fall under the prescribed categories of service personnel.

मेडिकल आधार पर सरकारी आवास बदलने सम्बन्धी नियम

4266. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल आधार पर क्वार्टरों के आवंटन सम्बन्धी व्यवस्था क्या है;

(ख) मेडिकल आधार पर मकान बदलने की अनुमति देने सम्बन्धी नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मेडिकल आधार पर उसी श्रेणी के मकान बदलने की अनुमति देने के क्या नियम हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में मेडिकल आधार पर टाईप-दो में कितने व्यक्तियों को मकान बदलने की अनुमति दी गई ?

निर्माण और आवास तथा पुति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बजत): (क) पाठ सरकारी कर्मचारियों तथा/अथवा उनके आश्रितों को चिकित्सा के आधार पर निम्नलिखित मामलों में आबंटन किए जाते हैं:—

(ख) तपेदिक रोग :

(i) फेफड़ों का तपेदिक रोग (सक्रिय हो तथा उससे दूसरों को खतरा हो) ।

(ii) एफ्यूजन वाली फ्लूरसी मास्तिष्क तपेदिक ।
कैंसर

(ब) विद्यालू न्यूक्लाइडम

इसके अतिरिक्त, जो अग्रग कर्मचारी निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं वे भी सामान्य पूल से रिहायशी आवास के तदर्थ आबंटन के पात्र हैं ।

(ख) और (ग) . एक ही टाइप में एक कालोनी से दूसरी कालोनी अथवा एक मंजिल से 3 मंजिल में चिकित्सा आधार पर मकान बदलने के अनुरोध पर गृणावगुण के आधार पर तथा वैद्य चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विचार किया जाता है ।

(घ) 185 ।

Rural Infra-structure development for construction of link road in Sikar, Rajasthan

4267. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the progress made so far in the rural infra-structure development scheme for the construction of link road between Reengus Junction and Tehsil Dataram in Sikar District, Rajasthan;

(b) when this project is likely to be completed;

(c) whether the work on link road between Khatu and Baigaon has not yet started, and if so, the reasons therefor and when the work on this portion of the road is likely to be started and completed; and

(d) the amount provided by Central Government for this purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) to (c). Information has been called for from the Government of Rajasthan and will be placed on the Table of the House later.

(d) Under the scheme, Rural Infrastructure Development—Construction of Rural Link Roads, a sum of Rs 147 00 lakhs has been provided to the State Government of Rajasthan for implementing the scheme in the current year.

Distribution of Fertilizers at subsidised Price

4268 SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have drawn up schemes for distribution of fertilizers to the agriculturist at subsidised prices according to the new economic policy of the present Government;

(b) if so, details about the facts thereabout; and

(c) the State-wise break up of distribution of fertilizers for the year 1977-78?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). In the small farmers Development Agencies, Drought Prone Areas Programme, Tribal Development Agencies, Hill Area Development Projects and the Dry Land Development Projects, subsidy is given, subject to certain limits for the purchase of fertilisers. Apart from this, the Government is also giving a subsidy of Rs. 1,250 on every tonne of indigenously produced P, O₅. In addition, the Government is also subsidizing the cost of transport of fertilisers to certain remote areas by bearing the cost of transport upto specified road points, declared as rail heads for the purpose of distribution of imported fertilisers. By reducing price of Urea by Rs. 100 per tonne while giving each manufacturer a retention price which would give him a reasonable return, the Government is indirectly subsidizing the sale of indigenous and imported fertilisers.

(c) The fertilisers are distributed in accordance with a supply plan drawn up by the Government well before each cropping season and the requirements of States are met from imports and domestic production. A statement indicating the allocations made for 1977-78 under the Essential Commodities Act is placed on the Table of the Sabha of the House.

Statement

Statement indicating the allocation of Fertilizers (Nutrients) for 1977-78

State/Union Territories	In tonnes
1	2
1. Andhra Pradesh	451980
2. Assam	4878
3. Bihar	180177

1	2
4. Gujarat	298735
5. Haryana	195008
6. Himachal Pradesh	7912
7. Jammu & Kashmir	11017
8. Karnataka	320628
9. Kerala	91812
10. Madhya Pradesh	140032
11. Maharashtra	325276
12. Manipur	3659
13. Meghalaya	1988
14. Nagaland	259
15. Orissa	64732
16. Punjab	318785
17. Rajasthan	138005
18. Tamil Nadu	456500
19. Tripura	1245
20. Uttar Pradesh	855164
21. West Bengal	184868
22. Andaman & Nicobar Islands	22
23. Arunachal Pradesh	1100
24. Dadra & Nagar Haveli	445
25. Delhi	3753
26. Goa, Daman & Diu	5215
27. Mizoram	17
28. Pondicherry	8673
29. Commodity Board	90982
30. Chandigarh	785
31. North Tea	51979
32. Sikkim	908

उत्तरकों में मिलावट

4269. श्री ब्रजभूषण सिन्धारी: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्तरकों में मिलावट के मामले में वृद्धि हुई है,

(ख) मार्च, 1977 से देश में उत्तरकों के निर्माताओं तथा मप्लायरों के परिसरों से परीक्षण हेतु कितने नमूने लिये गये,

(ग) कितने मामलों में मिलावट पाई गई थी और दोगी व्यापारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) उत्तरकों में मिलावट को रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) से (ग) किसी राज्य के भीतर उत्तरकों का वितरण करना संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। उत्तरकों (निबन्धन) आदेश के अंतर्गत अन्य उत्तरकों की क्वालिटी का सुनिश्चित करने तथा मिलावट की जांच करने का पूरा अधिकार है। अंतः राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपेक्षित सूचना भेज दें। अभी तक 15 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने संबंधित सूचना भेजी है, जो सलन्न विवरण में दी गई है। राज्य सरकारों के उत्तरों से यह स्पष्ट है कि उत्तरकों में मिलावट के मामलों में वृद्धि नहीं हो रही है। शेष राज्यों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उत्तरकों में मिलावट की रोकथाम करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उत्तरकों को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है। उत्तरकों (निबन्धन) आदेश के अंतर्गत राज्य सरकारों के निर्धारित अधिकारी उत्तरकों के नमूने लेकर उनका विश्लेषण कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार अपराधियों पर मुकद्दमा चला सकते हैं। इस आदेश को "विशेष आदेश" के रूप में घोषित किया गया है ताकि अपराधियों पर सक्षिप्त मुकदमे चलाकर उन्हें सजा दी जा सके।

(ख) उत्तरकों के नमूनों का सुविधापूर्वक विश्लेषण करने के उद्देश्य में भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत पाचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 36 उत्तरक गुणा नियंत्रण प्रयोगशालायें स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) 76 गुणा नियंत्रण निरीक्षकों की नियुक्ति की भी मजूरी दे दी गई है। ऐसे 50 और निरीक्षकों की मजूरी देने का प्रस्ताव है।

(घ) राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे उत्तरकों की क्वालिटी पर कड़ी निगाह रखें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो वे उसे बतायें।

विबरण

लोक सभा में 27-3-78 को पूछे जाने वाले प्रतारकित प्रश्न सख्या 4269 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

क्रम सं०	राज्य/सब राज्य क्षेत्र का नाम	क्या देश में मिलावट के मामले बढ़ रहे हैं	मार्च, 1977 से लिए गए नमूनों की संख्या	मिलावट के पता लगाए गए मामलों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	उर्वरको का निजी व्यापार नहीं किया जाता है	शून्य	मिलावट की कोई समस्या नहीं है
2	अण्डोड	जी नहीं	शून्य	शून्य
3	अन्वमान तथा निकोबार द्वीप समूह	जी नहीं	उर्वरको का वितरण सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।	शून्य
4	मिज़ोरम	जी नहीं	शून्य	शून्य
5	बिहार	जी नहीं	335	37
6	महाराष्ट्र	जी नहीं	1097	शून्य
7	उड़ीसा	जी नहीं	1281	शून्य
8	नागालैण्ड	जी नहीं	शून्य	शून्य
9	प० बंगाल	जी नहीं	307	1
10	मेघालय	जी नहीं	शून्य	शून्य
11	गोवा, दमन तथा द्वीप	जी नहीं	38	शून्य
12	दिल्ली प्रशासन	जी नहीं	8	शून्य
13	पांडिचेरी	जी नहीं	282	शून्य
14	मणिपुर	जी नहीं	12	शून्य
15	दादर तथा नगर हवेली	जी नहीं	शून्य	शून्य

National Capital Region

4271. CHOUDHURY BRAHM
PERKASH:

SHRI MOHAN LAL PIPIL:
SHRIMATI PARVATHI
KRISHNAN:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there was a proposal under consideration of the Government to set up a National Capital Region;

(b) whether the Master Plan also envisages the setting up of a National Capital Region;

(c) the steps taken in this regard and whether any amount has been spent so far in this respect and if so, how much;

(d) whether the Government have changed their policy in this regard; and

(e) if so, the new thinking of the Government for the development of Delhi the Capital of India?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b) Yes, Sir

(c) The National Capital Regional Plan was approved by the High Powered Board in September, 1973.

A sum of Rs. 518 lakhs has so far been sanctioned as Central loan assistance to the State Governments concerned for the development of the regional towns.

(d) and (e) Not yet, Sir.

Pollution in Delhi

4272 SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether attention of the Government has been drawn to the high degree of atmospheric pollution in Delhi; and

(b) if so, the steps the Government propose to take in this matter?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) A legislation to control air pollution in the country is being processed and the necessary Bill will be introduced in the Parliament soon. Meanwhile to combat the hazards caused by the smoke emitted by chimneys attached to furnaces installed by the industries, the Delhi Administration are taking necessary action as provided under the Bombay Smoke Nuisances Act, 1912, as extended to the Union Territory of Delhi, and Rules framed thereunder. Remedial measures for preventing the fly-ash pollution from the Indraprastha Power Station are also being taken by the Government

Allotment of Nitrogen Fertilisers to Punjab

4273 SHRI G S TOHRA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Punjab has been allotted only 6000 tonnes of nitrogen (fertiliser) against its annual requirement of 20 000 tonnes; and

(b) if so, the reasons for allotting to Punjab small quantity of fertilizer quota?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BANALA): (a) No, Sir. During Kharif 1978 (ie February to July, '78), Punjab State has been allotted 1,21,000 tonnes of nitrogenous fertilisers on the basis of their net agronomic requirements. Requirements for Rabi 1978-79 will be assessed in the month of July, 1978 and allotment made accordingly.

(b) Question does not arise. [

राष्ट्रीय बीज निगम में हरिजनों और आदिवासियों की पदोन्नति

4274. श्री राजवेली राम : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम में हरिजनों और आदिवासियों के लिये प्रारम्भित कोटा पूरा करने और वहाँ काम कर रहे हरिजनों और आदिवासियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये बहुत से आदेशों का पालन नहीं किया गया है, और

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Rehabilitation of Handicapped

4275 SHRI DHARMA VIR VASISHT: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the National Society for equal opportunities for the handicapped (NAS-EOH) at its recent meet at Bombay urged Government to formulate a National policy and plan of action for the Medical Educational, vocational, economic and social rehabilitation of over 40 million handicapped in the country including 8 million blind or near blind; and

(b) if so, the steps taken by Government to meet their demands?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN):

(a) and (b). While the record of proceedings/recommendations of the Conference have not so far been received, it may be stated that various programmes have been formulated, both at the Centre and State levels, for rehabilitation of the physically handicapped, including the blind in the country. Although relief to the disabled is primarily a responsibility of the State Governments, Centre has also taken up certain programmes in this regard. One such important programme is financial assistance to voluntary organisations for the physically handicapped for taking up programmes for education, training and rehabilitation of physically handicapped. Government is also planning to establish National Institutes for each of the four categories of handicapped persons i.e blind, deaf, orthopaedically handicapped and mentally retarded. Scholarships/Stipends are given to physically handicapped students, reading in class IX and above and assistance is given to State Governments for introducing integrated Education for disabled students in normal schools

Improvement of Cow Progeny

4276 SHRI S S SOMANI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) the details of efforts made by Government in regard to the protection and increasing the cow progeny and for improvement in their breed;

(b) the number of centres established in the country by Government during the last three years or by the State Governments with the assistance of the Central Government for improvement of their breed; and

(c) the details of progress made in the said centres during the last three years?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The

following schemes formulated/initiated by the Government of India mostly in consultation with the various State Governments, are currently in vogue and directly concern improvement of cattle breeds and also help in increasing the cow progeny:

- (i) All India Key Village Scheme.
- (ii) Intensive Cattle Development Projects.
- (iii) Central Cattle Breeding Farms.
- (iv) Central Exotic Cattle Breeding Farms.
- (v) Central Herd Registration Scheme.
- (vi) All India Coordinated Projects for Progeny Testing.
- (vii) Foreign Aided Cattle Breeding Programmes.
- (viii) Establishment of Frozen Semen Banks.
- (ix) Crossbreed calf rearing programme under SFDA/MFAL Projects.
- (x) Central Forage Production and Demonstration Farms.

For protection of cow progeny, following measures are in vogue.

- (i) Gosamvardhana Advisory Council (Central) has been reconstituted w.e.f. 1-1-1978. This Council is to advise the Government about various measures concerning protection, increase of the cow progeny and for their breed improvement.
- (ii) In accordance with the directive principles of our Constitution (Article 48), in several States laws have been enacted prohibiting the slaughter of cows and their progeny and for preserving and improving their breeds. Livestock Improvement Acts have also been enacted.

These Acts prohibit maintenance of unapproved bulls by any one. The State Governments are empowered hereunder to lay down breeds or classes of bulls for propagation in various areas.

(iii) Protection against disease is ensured through the Centrally Sponsored Schemes which envisage vaccinations against Rinderpest and Foot and Mouth Diseases as also production of vaccines sera etc., under the Expansion of Biological Production Stations. A scheme for setting up of Quarantine Stations to prevent introduction of exotic diseases from abroad is also under implementation.

(b) Under Central or Centrally Sponsored Schemes for A.I. work and improvement of breeds there are three Intensive Cattle Development Projects in milk shed areas of Delhi Milk Supply Scheme. During the last three years, no new A.I. Centres have been set up under these Cattle Development projects because the requisite number envisaged to be set up under each project had already been established more than three years back.

These projects are run on the basis of 75 per cent grant-in-aid and 25 per cent loan from the Centre.

12 Frozen Semen Bull Centres (Stations) have been set up through DANIDA assistance under a Central Scheme in various States during the last three years. These have been supplying frozen semen to various A.I. sub-centres in respective States for cross-breeding programmes being pursued therein.

(c) Specific information concerning the progress of these Centres namely, number of frozen semen doses being supplied year-wise, animals covered therewith and progeny produced thereafter would be collected from concerned States and placed at the Table of the Sabha when received by this Ministry.

**वेतनमानों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग का अनुदान**

4277. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री
यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने
उम प्रत्येक राज्य को जिसने अपने अपने क्षेत्रों
में स्थित अथवा उनके अधिकांश क्षेत्र में अपने
वाले कालेजों के प्रोफेसरो तथा लेक्चररों
के वेतनमान बढ़ा कर विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग स्तर के वेतनमान कर दिये हैं उनको
अनुदान के रूप में कितनी राशि दी है ; और

(ख) किन-किन राज्यों ने उक्त
सहायता की मांग की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री
(डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्रीय सरकार
ने राज्य सरकारों का विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग के मश्राधित वेतनमान अपनाने के
लिए 1. 1. 73 अथवा लागू करने के दिन
31-3-79 तक, होने वाले अनिश्चित व्यय
के 80% के आधार पर वित्तीय सहायता देने
का प्रस्ताव किया है। विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों
से भिन्न वेतनमान निर्धारित करने का विकल्प
भी राज्य सरकारों को दिया गया है। विभिन्न
राज्य सरकारों को, विश्वविद्यालय और कालेज
दोनों प्रकार के शिक्षकों के लिए, इस योजना
के अंतर्गत अब तक दी गई केन्द्रीय सहायता
इस प्रकार है :

क्रम संख्या राज्य का नाम दी गई केन्द्रीय
सहायता

	(रुपये लाखों में)
1. बिहार	317' 00
2. गुजरात	419' 00
3. हरियाणा	170' 00
4. हिमाचल प्रदेश	45' 00
5. महाराष्ट्र	48' 00
6. मणिपुर	25' 00
7. मेघालय	20' 00
8. उड़ीसा	100 00
9. पंजाब	200 00
10. त्रिपुरा	20' 00
11. उत्तर प्रदेश	305' 00
12. पश्चिम बंगाल	535 45

(ख) आन्ध्र प्रदेश, जम्मू एंव काश्मीर,
मध्य प्रदेश, नागालैण्ड और तमिलनाडु की
सरकारों के प्रस्ताव उनके परामर्श से विचारा-
धीन हैं। अरम सरकार के प्रस्तावों को अब
स्वीकृत दे दी गई है जब कि केरल सरकार के
प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए हैं। कर्नाटक
और राजस्थान की सरकारों से अब तक कोई
निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

Production of Pulses

4278 SHRI S. R DAMANI: Will the
Minister of AGRICULTURE AND
IRRIGATION be pleased to state:

(a) the details of researches carried
during the year for increasing the pro-
duction of pulses;

(b) whether a breakthrough has
been made in production of high
yielding variety of seeds of different
pulses and, if so, the details thereof;
and

(c) by what time sufficient stocks of these seeds will be built up for distribution among the farmers?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA). (a) During the year 1977-78 major emphasis in research on pulses has been on evolving high yielding and short duration suitable varieties for different agro-climatic regions. Emphasis has also been on improving production and protection technology, with a view to increasing and stabilising the production of pulses.

(b) The following improved varieties of pulses have been evolved by research efforts:

Gram: C-235, G-130, G-543, H-208, RS-10, T-3, K-468, Randhey, BG-203, L-550, G-62404, Annigiri.

Tur: (arhar) T-21, Ageti, Sharda, Mukta,

Prabhat, UPAS-120.

Lentil: T-36, L9-12, Pusa-4, Pusa-6, P-209, P-406

Pea: T-163, EC-33866, L-116.

Moong: T-44, Pusa Baisakhi, PS 7, 8, 9, 10 and 16

Urd: T-9, Pusa Selection 1, U-19.

Cowpea: C-152

(c) It is expected to build sufficient stocks of certified seeds of pulses within next few years for supply to the farmers.

सिंचाई के लिये ली जाने वाली पिछड़े क्षेत्रों की भूमि

4279. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के पिछड़े क्षेत्रों की कितनी भूमि सिंचाई के लिये ली जायेगी ; और

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य से कितनी जमीन सिंचाई के लिये लिये जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). सिंचाई राय का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के आयोजन, अन्वेषण, उन्हें तैयार करने तथा कार्यान्वित करने का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। पंचवर्षीय योजना (1978-83) में 17 मिलियन अतिरिक्त सिंचाई शक्यता का सज़न करना परिकल्पित है। इसका राज्यवार न्यौरा, जिसमें पिछड़े क्षेत्रों का न्यौरा भी शामिल हो, अभी तक अंतिम रूप से तैयार नहीं किया गया है।

Agricultural Research Centre in M.P.

4280. SHRI NARENDRA SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government will consider the proposal of the Government of Madhya Pradesh for setting up an Agricultural Research Centre in the State during the next financial year 1978-79;

(b) if so whether Government have received suggestions from the State Government in this regard; and

(c) if so, details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Any proposal, as and when received from the Government of Madhya Pradesh, would receive due consideration of the Government of India, depending on the need for setting up of a new research centre in that State in addition to those already existing.

(b) and (c). No, Sir. It may, however, be mentioned that certain proposals were received from the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur for strengthening/setting up of Regional Research Stations in Madhya Pradesh under the proposed ICAR-IBRD National Agricultural Research Project. The clearance of the State Government for pursuing these proposals is awaited.

Replacement of replaced Scheme of Road Building through payment of Foodgrains

4281. SHRI YADVENDRA DUTT: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have cancelled the scheme of road building through payment of foodgrains and replaced it by the scheme of digging ponds, pokhara and Tal in lieu of foodgrains if so, why;

(b) whether Uttar Pradesh Government have opposed the scheme of digging Tal, Pokhara in payment of foodgrains and has insisted on the scheme of road building in lieu of foodgrains; and

(c) if so, what is the decision of Central Government on the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) No, Sir. Government have not cancelled the scheme of road building through payment of

foodgrains. Road building schemes are also being implemented by the State Governments against payment of foodgrains alongwith other schemes for creation of durable assets, such as digging tanks, ponds, pokharas etc.

(b) Uttar Pradesh Government have not opposed the scheme of digging Tal, Pokhara etc. against payment of foodgrains but are implementing the scheme according to the Government of India's guidelines which include building of roads along with digging of tanks, ponds, etc.

(c) The question does not arise.

Low prices of Agricultural Goods

4282. DR. RAMJI SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the prices of agricultural goods have fallen during the present season;

(b) can the Government assure that the same price line will hold on throughout the year;

(c) whether it is a fact that the farmers are selling their hard earned produce now to the traders to repay Government loans and other revenues due to them; and

(d) whether Government propose to enter into a big purchasing so that the agriculturists do not suffer the loss at the hand of the traders?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (d). Yes, Sir. The prices of some agricultural products have generally shown a fall in recent months. Prices of agricultural commodities are subject to seasonal fluctuations. Prices usually tend to fall during the post harvest months as the farmers dispose of bulk of their produce to meet their cash requirements etc., and rise during the lean supply months. Part of the fall in prices in recent months is seasonal.

It is the policy of the Government to ensure remunerative prices to the producers of agricultural commodities. For this purpose, Government fixes procurement/support prices for major foodgrains and other agricultural commodities and undertakes procurement/purchase operations, to the extent necessary, to ensure that the interests of the producers are safeguarded.

Need for Dwelling Units in the Country

4283. DR. BALDEV PARKASH: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government have fixed any annual target to build dwelling units in rural and urban areas State-wise; and

(b) if so, the annual cost to build the houses and agencies financing the scheme?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Except the Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers which is in the Central Sector, all other social housing schemes are in the State Sector. The Central Government has not, therefore, fixed any State-wise annual target to build dwelling units.

(b) Apart from the annual plan outlay on housing for the State Sector Plan Schemes, the Housing and Urban Development Corporation, a public sector undertaking of the Central Government, provides finances to housing agencies for housing. The Life Insurance Corporation of India also provides finance to State Governments and Apex Cooperative Housing Finance Societies for housing.

Scheme of I.A.R.I. for training of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for Higher Posts

4284. SHRI K. PRADHANÍ: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether any scheme has been drawn by the Indian Agricultural Research Institute in pursuance of Government's policy to provide more opportunities for institutional training to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also for attending seminars, symposium, conference, to improve their chances of selection in higher category of post; and

(b) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Officers which have been provided an opportunity during last two years, State-wise?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) No separate scheme as such has been drawn up by the Indian Agricultural Research Institute. However, in pursuance of the Government's policy, the Indian Agricultural Research Institute is giving preference to the officers belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities in the matter of institutional training as well as deputation to scientific seminars, symposia, conferences etc. to enable them to improve their knowledge.

(b) The information is being collected and will be furnished as soon as it becomes available.

Cooperative Farming

4285. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have framed any scheme to develop co-operative farming for the poorer section of the peasantry; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) and (b). The Government of India do not have any scheme for development of Cooperative Farming.

Encouragement to game of Billiard

4286. SHRI A. SUNNA SAHIB: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the game of billiards is not being given encouragement by the All India Council of Sports;

(b) whether it is a fact that the World Champion of Billiards, at present an Indian, was not even conveyed the message of congratulations from our Prime Minister by the Indian Embassy in New Zealand;

(c) whether it is a fact that this International Champion was not even given financial assistance for competing in the game abroad; and

(d) if so, the reasons for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN): (a) No, Sir.

(b) Prime Minister's message congratulating Shri M. Ferreira on his winning the World Championship in Billiards in Melbourne (Australia) was not sent by Prime Minister's Office to our High Commission in Australia. It was released to the press only.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Construction of Godowns by Private Parties

4287. SHRI PRASANNBHAI MEHTA:

SHRI R. V. SWAMINATHAN:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that encouraged by the response to the first and second phases, the Food Corporation of India had decided to go in for the third phase of construction of godowns by private parties under the guarantee scheme;

(b) if so, to what extent the first two phases have been achieved; and the target fixed for the third phase of storage;

(c) how many private parties are proposed to be asked to set up godowns for storage and in what States; and

(d) what will be the capacity of each godown and by what time these godowns will be set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) A capacity of about 35.95 lakh tonnes is being added under first two phases. 19.39 lakh tonnes capacity has already been completed and taken over by the Corporation upto 31-1-1978 the balance 16.56 lakh tonnes under construction is likely to be taken over soon.

Target for the third phase is 2 million tonnes.

(c) Offers have been invited from private parties for construction of such godowns under Phase III in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Maharashtra and West Bengal.

(d) Minimum capacity of each godown will be 5000 tonnes. The private parties will be required to complete the godowns within 6 months of entering into agreement with the Corporation.

News Item Captioned "CPWD Junior Engineers Launch Stir"

4288. SHRI AGHAN SINGH THAKUR: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether attention of the Government has been drawn to the news item published under caption "CPWD Junior Engineers launch Stir" in Times of India dated the 3rd February, 1978; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto and how the Government propose to solve the problem and injustice done to graduate Junior Engineers?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) There is no question of injustice to graduate Junior Engineers. The post of Junior Engineers is open to persons having a Diploma in Engineering as well as any equivalent or higher qualification. Such graduates and Diploma holders as offered themselves for the post and were found suitable have been recruited as Junior Engineers. After such recruitment they have become members of one cadre and the Government has decided not to make any distinction between them for promotion to the next grade. However, to enable the more meritorious ones amongst them to get accelerated promotion without having to wait for their turn, according to their seniority, the Government has provided that 50 per cent of the promotions will be made through a competitive examination and only the remaining

50 per cent will get their promotion through merit-cum-seniority. The graduates who are better qualified can avail of this opportunity.

Rice from Fair Price Shops in Delhi

4289. SHRI BHAGAT RAM: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that rice of a very inferior quality is being supplied to the ration card holders in Delhi; and

(b) if so, what is the reaction of the Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) and (b). The rice available with the Food Corporation of India in the Delhi depots is mostly of the medium variety and this is being supplied to the consumers in Delhi through the Fair Price Shops. It is, however, ensured that the rice so supplied is of Fair average quality and conforms to the specifications laid down by the Government.

Financial Assistance for Shifting Calcutta University

4290 SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the Government of West Bengal has sent any proposal for financial assistance for shifting the Calcutta University from its present site to a better one, at Salt Lake area; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). No proposal has

been received from the Government of West Bengal for shifting the Calcutta University from its present site. However, the University Grants Commission had, in July, 1976, agreed to provide an additional financial allocation of Rs. 1.00 crore to the Calcutta University to set up a Second Campus in the metropolitan area. In April, 1977, the State Government made a proposal for establishing a new campus in the Salt Lake area. Land has been allotted to the University by the State Government for this purpose and the Commission has paid a sum of Rs. 46,14,490/- therefor. The proposals for buildings etc would be considered by the Commission, as and when received.

Hingangaon and Bhakuchi-Wadi Irrigation Projects

4291. SHRI ANNASAHEB GOTK-HINDE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether the Government have been scrutinizing the medium irrigation projects namely (1) Hingangaon and (2) Bhakuchi-Wadi of Sangli district, Maharashtra State; and

(b) if so, the broad particulars regarding both the projects and the time by which they are likely to be cleared?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The project Reports of Hingangaon and Bhakuchi-wadi irrigation projects have not so far been received in the Central Water Commission from the Government of Maharashtra.

(b) Does not arise.

"Fishermen Face Mechanised Cyclones"

4292. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in 'Blitz' dated the 4th March, 1978 under the caption "80,000 fishermen face mechanised cyclone"; and

(b) if so, the details and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Government are aware of this news item.

(b) The Government of Goa had promulgated the "Goa, Daman & Diu Fisheries Rules" in 1974 under which the mechanised boats should not operate within 5 fathom depth, as a measure of protection to the traditional coastal fishermen. The complaint of the traditional fishermen is that they are being deprived of their fish catches because mechanised boats are violating this rule, and fishing in the prohibited zone. The traditional fishermen are demanding that the Government should establish adequate machinery to implement the rules, amend them suitable so as to increase the fine, and impose other penalties on the violators.

The Government of Goa have proposed setting up of a patrolling squad with two speed boats to prevent mechanised boats from operating in the prohibited area. This has been agreed to. They are also considering taking up other necessary measures to ensure effective implementation of the rules. When these proposals are received, Government of India would consider them on merits and take required decision.

उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों और चीनी मिल मालिकों के बीच समझौता

4293. श्री कल्याण सिंह याचक : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य मंत्री की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों और चीनी मिल-मालिकों के बीच कोई समझौता हुआ था कि गन्ना उत्पादकों को 12 रुपये से लेकर 13.50 रुपये प्रति क्विंटल कीमत अदा की जायेगी ;

(ख) यदि हा, तो क्या इस समझौते का उल्लंघन कर चीनी मिल मालिकों ने गन्ना खरीदना और इसे मिलों में बेचना बन्द कर दिया है ; और

(ग) यदि हा, तो सरकार ने चीनी मिल मालिकों की इस कार्यवाही को गैर-कानूनी घोषित क्यों नहीं किया है और चीनी मिलों का अधिग्रहण न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) : हमारे पास उपलब्ध सूचनानुसार, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को सप्लाई किये गए गन्ने के सरकार द्वारा बताये गये मूल्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 12.50 रु० प्रति क्विंटल, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए 13.50 रु० प्रति क्विंटल है। हमारे पास ऐसी कोई सरकारी सूचना नहीं है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों और चीनी मिल मालिकों के बीच मुख्य मंत्री की उपस्थिति में कोई करार हुआ है।

(ख) राज्य की ज्वाइंट स्टॉक फैंक्ट्रियों की एसोसिएशन ने सरकार को नोटिस दिया था कि वे राज्य द्वारा बताए गए मूल्य देने में

असमर्थ थे और वे 21-2-1978 से केवल न्यूनतम अधिसूचित मूल्यों का ही भुगतान करेंगे। बहुत सारी मिलों ने 21-2-78 से न्यूनतम अधिसूचित मूल्य से कुछ भी अधिक नहीं दिया। तथापि, 1977-78 के लिए घोषित की गई नयी चीनी नीति से, जिसमें 1-3-1978 से लेबी चीनी के मूल्यों में वृद्धि करना भी शामिल है, मिलों ने राज्य द्वारा बताए गए मूल्यों को फिर से भुगतान करना शुरू कर दिया और जिन मामलों में उन्होंने केवल न्यूनतम अधिसूचित मूल्यों का ही भुगतान किया था, वहाँ दोष धनराशि का भुगतान भी करना मान लिया है। 15-3-1978 का राज्य की सभी चीनी मिलें पूरे वेग से कार्य कर रही है।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि से, प्रश्न ही नहीं उठता।

Homeless Families in the Country

4294. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Government have conducted any survey to estimate the homeless families in the country;

(b) if so, the State-wise figures, thereof;

(c) what are the programmes under active considerations to provide homes to homeless families; and

(d) how many families have been provided with the homes by the Government for the period 1976-78?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). The Government have not conducted any survey. However, according to an estimate made by the National Buildings Organisation, the housing shortage on the

eve of the Fifth Five Year Plan, i.e., as on 1st April 1974, was 156 million housing units in the country

(c) The main highlights of the proposed programme in the field of housing are —

(i) Adoption of a housing programme aimed at clearing the backlog and meeting the additional demand due to population growth and replacement of unusable houses, over a period of 20 years

(ii) Restricting utilisation of public funds for low income households so that larger number of dwelling units are constructed with the resources allocated to this sector

(iii) Provision of incentives to the private sector for taking up housing on a large scale

(d) According to reports available with the Ministry construction of 1,33,458 houses had been sanctioned, out of which 1,19,559 had been completed during the period from 1st January, 1976 to 31st December 1977 under the various social housing schemes introduced by the Ministry of Works and Housing. Moreover, 15,00,915 house-sites have been allotted to landless families under the Scheme for Provision of House-sites to Landless Workers in Rural Areas during that period

Apart from the houses constructed under the Social Housing Schemes and the house-sites allotted to landless workers in rural areas houses were also built with the funds made available by Housing and Urban Development Corporation Limited and the Apex Cooperative Housing Finance Societies which receive the bulk of their resources from the Life Insurance Corporation of India

Defective Seeds of Edible Oils

4295. SHRI D D DESAI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether certified seeds of edible oils marketed by the National Seeds Corporation are found to be defective;

(b) if so, what steps have been taken to correct this, and

(c) if not, how is it that groundnut output in the current year has been lower than expected?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) No Sir Certified seeds of edible oils marketed by the National Seeds Corporation has been found to be generally reliable

(b) Does not arise

(c) The overall production of major oilseeds including groundnut in the country during 1977-78 is expected to be considerably higher than in the previous year. Firm estimates of production of oilseeds including groundnut during 1977-78 would become available after the close of agricultural year i.e. some time in July—August, 1978.

राज्य मत्स्य विकास निगमों को दी गई धनराशि

4296 श्री छविराम शर्मा क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की वृत्ता करेंगे कि

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें मत्स्य उद्योग के विकास हेतु राज्य मत्स्य विकास निगमों की स्थापना की गई है और उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें उक्त निगमों की स्थापना नहीं की गई है।

(ख) पाचवी पंचवर्षीय योजनावधि में केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश जैसे एक पिछड़े राज्य को मत्स्य उद्योग के विकास हेतु जो धनराशि दी गई थी उससे किस-किस प्रकार की योजनाएँ आरम्भ की गईं, और

(घ) क्या यह सच है कि वर्ष 1978-79 में मध्य प्रदेश राज्य को और अधिक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पश्चिम बंगाल,

आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में राज्य मत्स्य की विकास निगमों स्थापित की जा चुकी है। महाराष्ट्र भी मात्स्यकी विकास के लिए एक पृथक निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। गुजरात में एमो मेराइन प्रोडक्ट्स लि० तथा उडुपी में उडुपी कृषि तथा लघु उद्योग निगम मात्स्यकी विकास की देखभाल कर रही है। अमम सरकार ने राज्य में भीलों के विकास के लिए एक भील मात्स्यकी विकास निगम की स्थापना की है। अन्य किमी राज्य ने अभी तक मात्स्यकी विकास निगमों की स्थापना नहीं की है।

(ख) गहन मत्स्य-पालन के विकास के लिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के रायपुर तथा सहडोल जिलों में दो मत्स्य-पालक विकास एजेंसियों की स्थापना की है और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 1,24,000 रु० की रकम ऋण के रूप में तथा 10,53,178 रु० की रकम अनुदान के रूप में दी है।

(ग) राज्य सरकार की आवश्यकताओं का पता लगने पर 1978-79 के दौरान मध्य प्रदेश को गहन मत्स्य पालन के लिए अधिक रकम उपलब्ध की जाएगी।

संकटग्रस्त और बन्द चीनी मिलों से बकाया राशि की वसूली

4297. श्री सुर्यजय प्रसाद बर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संकटग्रस्त और बन्द चीनी मिलों से गन्ना उत्पादकों को गन्ने का बाकी मूल्य कर्मचारियों को उनके वेतनों की बकाया राशि तथा बैंकों और अन्य महाजनों के ऋणों तथा सरकारी करों की बकाया राशि दिलवाने और नई, अच्छी प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन ऐसी मिलों की कार्यकारी पूंजी उपलब्ध करा कर उन्हें फिर से चलाने के बारे में सरकार की व्यापक नीति क्या है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार किन परिस्थितियों में स्वयं इस बोझ को अपने ऊपर लेती है, राज्यों, सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देती है या प्राइवेट पार्टियों के हाथों में ऐसी मिलों की बिक्री के लिए मंजूरी देती है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) गन्ना उत्पादकों के बकायों की वसूली सामान्यतया गन्ने की खरीदारी और सप्लाई संबंधी राज्य के कानून के अधीन होती है, जिसमें गन्ने के नक़ायों को भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने की व्यवस्था है। वेतन के बाकियों, बैंक तथा अन्य साहुकारों के बकायों की अदायगी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कानून हैं। सरकारी करों की वसूली करने के लिए मिन को रिसीवरशिप के अधीन कर दिया जाता है और कुप्रबन्ध के मामले में, मिलों के प्रबन्ध को उद्योग (सिकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन ले लिया जाता है। उनके सामान्य व्यापार में वित्तीय सस्थानों द्वारा कार्यकारी पूंजी की व्यवस्था की जाती है।

(ख) केन्द्रीय सरकार इसका भार अपने ऊपर नहीं लेती है। ऐसी रण्य मिलों की सम्पति हस्तान्तरण से संबंधित सामान्य कानूनों के अन्तर्गत निजी पार्टियों को बेचा जाता है।

Development of Small and Marginal Farmers and Landless Labourers in M.P.

4298. SHRI SURYANARAYAN SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) details of the development programmes for marginal farmers, small farmers and landless labourers under the Central Programme that is to be undertaken during the year 1978-1979 in Madhya Pradesh;

(b) whether the programme launched hitherto is running satisfactorily; and

(c) if so, his reaction in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRA-TAP SINGH): (a) Under the Central Sector Scheme of Small Farmers Development Agency, 12 projects are being implemented in Madhya Pradesh. Generally speaking, each project has an outlay of Rs. 150.00 lakhs for the project period ending in 1978-79. The Agencies extend assistance to small/marginal farmers and agricultural labourers for various schemes of crop husbandry and subsidiary occupations in their area of operation. Assistance is given in the shape of subsidy at the rate of 25 per cent to small farmers and 33-1/3 per cent to marginal farmers and agricultural labourers on the capital cost of development against loan from institutional sources. The crop husbandry programme includes introduction of high yielding varieties, multiple cropping, land development, soil conservation, minor irrigation, horticulture, etc., and those of subsidiary occupations include dairy, poultry, piggery, sheep and goat rearing. Each agency is expected to extend benefits to approximately 50,000 small/marginal farmers and agricultural labourers during the five year project period.

For the year 1978-79, the agencies are expected to draw up their programme and submit suitable proposals including their physical targets and the financial outlays for release of grant-in-aid by the Government of India during April, 1978.

(b) and (c). The information available indicates that the implementation of the programme is generally satisfactory in Madhya Pradesh though there are variations from project to project in regard to performance. The progress and problems of the projects are reviewed periodically by the State Government as well as the Government of India and suitable remedial measures are taken to improve the pace of implementation. It is proposed to take up intensive development in selected number of blocks during 1978-79.

Loss in Export of Wheat to Russia

4299. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the wheat was exported from India to Russia on F.O.B. Basis through Russian shippers;

(b) is it also a fact that the Government of India neither contacted the Shipping Corporation of India nor the other shippers to take the cargo to Russia;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) is it also a fact that about 5,000 tonnes of rice was also exported from India to Indonesia and about 2 lakh tonnes of urea was imported from Indonesia to India through foreign shippers; and

(e) if so, why?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRA-TAP SINGH): (a) to (c). As per contract between the Food Corporation of

India and EXPORTKHEB of Moscow a quantity of 14.98 lakh tonnes of wheat is being shipped to the USSR in repayment of the balance quantity of wheat loan taken from that country. According to the terms of the contract, the delivery of wheat is to be made on FOB basis and as such it is the responsibility of EXPORTKHEB to charter suitable vessels for lifting the contracted quantity from the Indian ports. However, the contract also provides for participation of Indian tonnage in the carriage of wheat cargo in accordance with the Indo-Soviet Shipping Agreement of 1976. Out of 4.55 lakh tonnes of wheat shipped upto 18-3-1978, quantity of 1.09 lakh tonnes was shipped in Indian Flag vessels. The Food Corporation of India as well as the Shipping Corporation of India remain in touch with the concerned Soviet authorities to secure maximum utilisation of Indian tonnage.

(d) and (e). Supplies of 50,000 tonnes of rice to Indonesia are being made on FOB basis. A quantity of 1,60,000 tonnes of urea has also been purchased from Indonesia on C & F basis. In both the cases, it is the responsibility of the Indonesian parties to fix vessels of their choice, including Indian vessels, and utilisation of Indian tonnage cannot be insisted upon.

Unauthorised Construction in Delhi

4300 SHRI AMARSINH V. RATHAWA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government has been drawn to some news papers reports and complaints that many unauthorised constructions of houses, shops, industries and such others have come up in Delhi since April, 1977; and

(b) if so, the details of the action taken or proposed to be taken in the matter in each case?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) Instructions have been given to local authorities to exercise constant vigil. A weekly programme for removal of unauthorised constructions is chalked out at meetings held by the District Authorities where representatives of local bodies are present.

राप्ती नदी पर जलकुंडी परियोजना और करनाली परियोजनाओं का निर्माण

4301. श्री किरंती प्रसाद : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभिन्निका को समाप्त करने के लिये राप्ती नदी पर जलकुंडी परियोजना और करनाली परियोजनाओं (बधरा भयवा सरयू नदी) के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या हल करने हेतु राज्य सरकार की कोई निर्देश दिया है ; और

(ग) बाढ़ की विभिन्निका रोकने संबंधी प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ताकि जीवन और सम्पत्ति को बाढ़ों से बचाया जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से राप्ती नदी पर जलकुण्डों परियोजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट 1956 और उसके बाद संशोधित रिपोर्ट 1976 में

प्राप्त हुई थी। इस परियोजना में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लाभ परिकल्पित हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत बड़े क्षेत्र के जलमग्न होने के कारण नेपाल की महामहिम सरकार ने जलकुण्डी स्थल के प्रतिप्रवाह में भालूभग में बैकल्पिक जल-संचयन बाध का प्रस्ताव किया है। इस परियोजना के अकार पर नेपाल की महामहिम सरकार के अधि-कारियों के सच विचार विमर्श किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश द्वारा करनाली नदी उत्तर प्रदेश में घाघरा के नाम से जानी जाती है, पर जल संचयन बाध के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

(ख) और (ग). बाढ़ नियंत्रण राज्य क्षेत्र का भाग होता है इसलिए बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के प्रारम्भन तैयार करने एवं कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के जरिये, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री हैं और बाढ़ में मबधित राज्यों के कार्यभारी मंत्री इसके सदस्य हैं, राष्ट्रीय महत्व के मुख्य जोति-निर्णय लिए जाते हैं। 1970 में हुई अपनी बैठक में राज्य सरकारों में प्रत्येक राज्य में बाढ़ नियंत्रण की मास्टर योजनाएँ शीघ्र तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि बाढ़ नियंत्रण उपायों का समन्वित रूप से प्रायोजित किया जा सके तथा उन्हें पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर क्रियान्वित किया जा सके।

केन्द्रीय सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना को तैयार करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की है जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है। आयोग ने 1043 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर गंगा बेसिन के लिए 1973 में एक योजना की रूपरेखा तैयार की थी। आयोग द्वारा सहायक नदी के उप-बेसिनो के लिए व्यापक योजनाओं को तैयार करने का कार्य हाथ में लिया गया है और इनमें से

घाघरा और गोमती के लिए कार्य पूर्ण हो गया है और आगे कार्यवाही के लिए एच मास्टर योजना में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है मास्टर योजना के तैयार होने तक काफी सच्चा में विशिष्ट स्कीम तैयार की गई है और राज्य सरकार द्वारा इनका क्रियान्वयन किया गया / किया जा रहा है। प्राथमिकता प्राप्त बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा 1972-73 और 1973-74 के दौरान राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता भी दी गई थी।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य में बाढ़-पूर्व सूचना यूनितें भी स्थापित की है जो राष्ट्रीय स्कीम का भाग है और ये बाढ़ों की पूर्व सूचना देती है ताकि राज्य सरकार बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को अग्रिम चेतावनी जारी करने, आदमियों को निकालने का प्रबन्ध करने, पशुओं और चल सम्पत्ति को जब भी आवश्यक हो, सुरक्षित स्थानों पर ले जाने तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों की निगरानी करने और राहत तथा बाढ़ से बचाव के कार्य कर सके।

Complaint, about F.C.I. Godowns, Kerala

4302 SHRI K A RAJAN Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports appeared in Malayalam newspapers regarding rampant corruption and malpractices in Food Corporation of India godowns in Kerala and if so, the details thereof,

(b) whether any inquiry has been conducted into these allegations, and

(c) if so, the details and action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRA-TAP SINGH); (a) The Food Corporation of India have reported that certain allegations of a general nature were published in the "Malayalam Manorama" dated 26th February, 1978. The following is the gist of allegations:—

(i) There has been underweighment in the foodgrains issued for public distribution system from the Food Corporation of India sub-depots.

(ii) The entire gunnies for which money has been remitted is not released from the depots.

(iii) The gunnies used are of inferior quality

(iv) The FCI officials behave in a haughty manner and do not care for the directions of the superior officers.

(b) and (c). The Corporation have reported that the allegations being of a general nature and not against any particular depot or individual it has not been possible to conduct any specific inquiry but supervision has been tightened and instructions have been issued to the District Managers to eliminate scops for such complaints.

नेहरू युवक केन्द्र

4303. श्री सुभाष झाड़ा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवक केन्द्र प्रमुखतया प्रछात्र युवा वर्ग के लिये है ;

(ख) यदि हाँ, तो इनके क्या कारण हैं; और

(ग) जिले के एक केन्द्र में कितने प्रछात्र युवक एवं युवतियाँ हैं और प्रत्येक केन्द्र

में प्रति वर्ष कितने युवक और युवतियों को कार्यक्रमों का लाभ मिलना चाहिए ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्ता सिंह गुलशन) :
(क) से (ग) . नेहरू युवक केन्द्रों की योजना मुख्यतः गैर छात्र युवकों के लिए 1972 में शुरू की गई थी। क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के पहले के युवक कार्यक्रमों से मुख्य रूप से छात्र युवकों को ही लाभ पहुंचता था, अतः इस योजना में गैर छात्र युवकों को महत्व दिया गया था। सम्मिलित होने वाले गैर छात्र युवकों की संख्या के सम्बन्ध में नेहरू युवक केन्द्रों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं और सम्मिलित होने वाले युवकों की संख्या विभिन्न केन्द्रों में भिन्न-भिन्न है।

Slum Wing of D.D.A.

4304. SHRI MAHI LAL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Slum Wing of the Delhi Development Authority is again being entrusted to the Municipal Corporation of Delhi and if so, the reasons therefor;

(b) the grounds on which this Wing was taken away from M.C.D. and placed under D.D.A. and whether those grounds, no more exist; and

(c) the time by which the Slum Wing is likely to be converted into an autonomous board?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) to (c). The Implementation of the Slum Clearance/Improvement Scheme is being transferred to Municipal Corporation Delhi with effect from 1st April, 1978. The

Scheme was transferred from Municipal Corporation Delhi to Delhi Development Authority on 11th February, 1974 as the Public Accounts Committee and Lt Governor of Delhi had pointed out certain defects in the working of the Scheme and recommended that this scheme and J J R Scheme should be entrusted to one agency. The Municipal Corporation Delhi had passed a Resolution in July, 1977 recommending transfer of the work back to them on the consideration that transfer of work to Delhi Development Authority had added to the difficulties of the dwellers worsened their lot greatly retarded the progress achieved in the field dwellers are demanding take over by the Municipal Corporation Delhi and the work is by and large provided for in various provisions of the Delhi Municipal Corporation Act. It was decided by Government to accept the recommendation of the Municipal Corporation Delhi. No proposal to convert the Slum Wing into an autonomous board is under examination of Government.

Financial Operation of Indian School of Mines, Dhanbad

4305 SHRI A K ROY Will the Minister of EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state

(a) whether any difference of opinion between the Director and the Chairman of the Executive Board with regard to the functioning of financial operations of the Indian School of Mines, Dhanbad, has been reported to Government,

(b) the amount of T A /D A drawn by the Director of the Indian School of Mines, Dhanbad during the last two years, and

(c) whether any irregularities were found in the construction and repairing of bungalows during the same period?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR PRATAP CHANDRA CHUNDER) (a) No, Sir

(b) Approximately Rs 25,000/-

(c) According to the School, no irregularities were found in the construction and repairing work. All such work is done through Central public Works Department.

राज्यों के लिये चीनी का कोटा

4306. श्री सुचराज : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1977 से राज्यों के लिये प्रति व्यक्ति लेबी चीनी का कोटा 425 ग्राम फिर से निर्धारित किया है,

(ख) यदि हाँ तो क्या सरकार ने बिहार के लिये चीनी का मासिक कोटा बढ़ाया है, और

(ग) यदि हाँ तो वर्ष 1977-78 के लिये प्रत्येक राज्य के लिये कूल कितनी आवश्यकता है और उन्हें अब तक कितनी चीनी दी गई है?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और

(ख) जी हाँ।

(ग) प्रत्येक राज्य की चीनी से सम्बन्धित आवश्यकता का मास से मास के आधार पर पूरा किया जाता है और चास विशेष के लिए लेबी चीनी के कोटे के प्रति निर्मुक्ति प्रादेश जारी किए जाते हैं जोकि पिछले महीने की 23 तारीख से सम्बन्धित महीने के अन्त तक वैध होते हैं। यदि वैध अवधि के दौरान किसी मात्रा को नहीं उठाया जाता है तब राज्य

सरकारी/भारतीय बाध निग्रम के प्रयुक्त पर निर्भूक्त आदेश की वैध प्रवधि को बढ़ा दिया जाता है ताकि समस्त आवंटित मात्रा को उठाया जा सके। चीनी वर्ष 1977-78 (अक्टूबर, 1977-अप्रैल, 1978) के दौरान अब तक आवंटित किए गए लेवी चीनी के मासिक कोटों का राज्यवार व्यौरा सभा पटल पर रख गये विवरण में दिया गया है [प्रश्नसंख्या में रखा गया। देखिये संख्या LT—1924/78]। अप्रैल, 1978 के कोटे के प्रति की निर्भूक्त आदेश जारी किए गए हैं जिनकी वैधता प्रवधि 23-3-1978 से 30-4-1978 है। जहां तक 1977-78 चीनी वर्ष की शेष प्रवधि का सम्बंध है, वर्तमान राज्यवार कोटे तक तक मासिक आधार पर आवंटित किए जाते रहेंगे जब तक उनकी मात्रा में कोई परिवर्तन करने का निर्णय नहीं ले लिया जाता है।

Three Language Formula

4307. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state

(a) whether there is a great discontentment in whole of the South regarding imposition of Hindi in that area;

(b) if so, whether the three language formula is not being followed strictly in whole of India;

(c) whether it is also a fact that not many teachers are available to teach Hindi in the South; and

(d) what facilities are being considered by the Union Ministry to help the States in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENAKA DEVI BARKALAK): (a) It is not correct to say that there is any imposition of Hindi in the South or that there is discontentment in whole of the South over any imposition;

(b) There are some exceptions but the matter is being pursued with the State Governments.

(c) No, Sir.

(d) Under the Centrally Sponsored Scheme 'pending of Hindi Teachers Training Colleges/Wings in the non-Hindi speaking States', 100 per cent financial assistance is given to the non-Hindi speaking State Governments for opening of Hindi Teachers Training Colleges/Wings. The Kendriya Hindi Sansthan, Agra is also conducting courses for training of Hindi Teachers from non-Hindi speaking States.

Investment in Cotton and Jute Production

4308. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the money invested to raise production of cotton during last two years;

(b) the actual production of cotton during the last two years;

(c) the money invested for production of jute and its actual production; and

(d) the percentage of rise in selling price of cotton and jute during last two years?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). The funds released under the Centrally Sponsored Schemes of Intensive Cotton Districts Programme (ICDP) and Intensive Jute District Programme (IJDP) and the estimates of produc-

tion of cotton and jute for the last two years are indicated below:

Year	Funds released under Centrally Sponsored Schemes of		Production of Cotton and Jute Mesta	
	ICDP (in lakhs)	IJDP	(in thousand bales of 170 kgs. each)	(in thousand bales of 180 kg. each)
1975-76	266.35	8.20	5950	5914
1976-77	244.47	121.16	5781	7085

(d) A statement showing index number of wholesale prices of cotton and jute during 1975-76, 1976-77 and

1977-78 and the percentage rise in the index numbers in the current year over those two years ago in enclosed

STATEMENT

(Monthly Average)

Base year 1970 71-100)

Year	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb,	March	April	May	June	July	August
COTTON												
1975-76	135.6	130.6	129.9	133.4	143.1	141.2	157.6	177.2	183.5	201.4	197.9	
1976-77	200.9	206.1	207.1	202.1	213.7	209.4	209.5	214.6	210.5	206.6	297.8	
1977-78	189.6	171.1	172.2	162.2	168.1							
Percentage rise in 1977-78 over 1975-76	39	9.2	38.5	3.6	1.9	1						
JUTE												
1975-76	111.2	113.3	113.2	112.2	112.2	116.3	126.1	122.4	131.5	131.8	132.7	128.1
1976-77	120.4	115.9	114.7	114.5	114.1	120.1	132.8	130.6	142.0	141.0	143.6	147.6
1977-78	130.2	121.1	121.1	117.2	117.2	121.9	141.6	149.6				
Percentage rise in 1977-78 over 1975-76	38.5	3.4	10.3	3.1	1.2	9.6	12	13.0				

गाजियाबाद में निर्मित केन्द्रीय सरकार के क्वार्टरों का आवंटन

4309 श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार गाजियाबाद में बने सरकारी क्वार्टरों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का आवंटित करने का है, और

(ख) यदि हा तो ये क्वार्टर कब तक आवंटित किये जायेंगे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हा। गाजियाबाद के सामान्य पूल के क्वार्टर मुख्यतया गाजियाबाद में कार्य कर रहे पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवंटन के लिए हैं। उनकी मांग का पूर्ण रूप से पूरा करने के बाद यदि कोई खाली क्वार्टर बच जाते हैं तो वे दिल्ली में कार्य कर रहे उन पात्र सरकारी कर्मचारियों का आवंटित कर दिए जाते हैं जिन्होंने उनमें लिए आवेदन किया होता है।

(ख) पहले पूर्ण किए गए टाईप—1 में टाईप—3 तक व बर्गों के 200 क्वार्टरों में से 178 क्वार्टर गाजियाबाद में कार्य कर

रहे कर्मचारियों को आवंटित किए गए थे और उनकी मांग को पूरा करने के बाद 21 क्वार्टर दिल्ली में कार्य कर रहे कर्मचारियों को आवंटित किए गए थे। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के लिए 6 एकड़ प्रयोग में लाए जा रहे हैं। वर्ष 1978 के दौरान टाईप—1 और 2 के 300 और क्वार्टरों को पूरा किया जाने की सम्भावना है।

Sheep Breeding Farm

4310 SHRI AHMAD M PATEL
Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether there is any programme to develop large sheep breeding farms in the country;

(b) the names of States selected for this programme,

(c) the amount sanctioned and determined for this programme during the last two years 1976-77 and 1977-78 State-wise, and

(d) the result achieved?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) Yes Sir

(b) Andhra Pradesh, Bihar Jammu & Kashmir Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh.

(c) The amount sanctioned and expenditure incurred during the year 1976-77 and amount sanctioned during 1977-78 State-wise is as below

S No	Name of the State	Amount sanctioned for 1976-77 (Rs in lakhs)	Amount spent in 1976-77 (Rs in lakhs)	Amount sanctioned for 1977-78 (Rs in lakhs)
1	Andhra Pradesh	10 00	10 00	10 00
2	Bihar	5 40	5 10	20 00
3	Jammu & Kashmir	33 00	25 11	40 00
4	Karnataka	12 00	7 40	15 00
5	Madhya Pradesh	7 00	1 7	20 00
6	Rajasthan	20 00	19 33	45 00
7	Uttar Pradesh	30 00	21 06	30 00
Total		119 40	104 77	180 00

(d) The number of rams produced in these farms during 1976-77 and 1977-78 is as below —

	1976-77	1977-78
Pure-bred	1230	100
Cross-bred	331	1270
Total	1561	2270

Elections of Delhi School Teachers Cooperative House Building Society, Delhi

4311 SHRI RAMANAND TIWARY Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) the total number of persons who have filed affidavits so far before Shri C K Mahajan, Commissioner in Civil Writ No 659/77 in response to his Public Notice relating to the membership of Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society,

Delhi appearing in the *Hindustan Times*, dated the 24th January 1978, and

(b) how the eligibility of those has been or is to be decided who have not filed affidavits before the aforesaid Commissioner but whose names appear in that List of Members released by the existing Managing Committee which has been challenged?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (1) 296 affidavits were received by him of which 239 were received within the time specified in the Public Notice issued by him

(b) The matter is sub-judice

Construction of Houses for Plantation Workers with Central Assistance in Kerala

4312 SHRI P K KODIYAN Will the Minister of WORKS AND HOUS-

ING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Kerala Government had requested the Centre to allocate Rs. 33 lakhs for construction of houses for plantation workers under the Central Sector Scheme for this purpose for the year 1977-78;

(b) if so, whether any fund has been allotted for it;

(c) if so, the details thereof;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether any demand has been made by the State Government for the year 1977-78 for this purpose; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The Kerala Government requested allotment of Rs 32.78 lakhs for 1977-78.

(b) Yes, Sir.

(c) A sum of Rs. 28 lakhs was released to the Government of Kerala for implementation of the Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers during the year 1977-78.

(d) to (f) Do not arise.

Industrial workers Housing Scheme

4313. SHRI SHIV SAMPATI RAM: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Government have decided to allow the tenements built in the States under the Subsidised Industrial Housing Scheme for Industrial workers and economically weaker sections of community to purchase them at a concessional rate;

(b) whether there is any proposal to allow the Government servants to

purchase those quarters in which they had been living for more than ten years and have already paid the rent to the Government which comes more than the cost of construction; and

(c) if so, the particulars thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) The Government of India have taken a decision to permit the sale of houses built for the industrial workers under the Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of Community to the existing occupants. The price payable will be 80 per cent of the original cost and hire-purchase facilities will be available.

(b) No, Sir

(c) The sale of the quarters in the general pool cannot be even contemplated because numbers involved are so large that it is not possible to construct more dwellings as replacements at the rate which would be needed to reach the existing level of percentage satisfaction.

Medium irrigation schemes

4314. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) what is the total number of medium schemes in progress in various States with their estimated cost, anticipated expenditure and irrigation potential to be created during the current year and provision/outlay proposed for these schemes for 1978-79, State-wise;

(b) whether Government are proposing to revise the criteria/definition for medium irrigation schemes and details thereof;

(c) what is the reaction of the State Governments to the new definition of medium irrigation schemes; and

(d) how far it would effect the financing of medium irrigation schemes by the Central Government?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) 514 medium irrigation schemes estimated to cost Rs. 1343 crores and which would provide annual irrigation benefits of 2.7 million hectares are under execution during the current financial year, and irrigation potential of 8.7 lakh ha. would be created upto the end of 1977-78. The expenditure anticipated upto the end of 1977-78 on these schemes would be Rs 494 crores. The outlay

recommended for these schemes in the year 1978-79 is Rs. 7188 crores. The State-wise break-up of these is given in the attached statement.

(b) and (c). Irrigation projects are now classified on area basis. Schemes having culturable command area of more than 2,000 ha. but less than 10,000 ha. are classified as medium schemes. There has been no reaction of the States so far to the new definition. The State Governments are now submitting the Project Reports accordingly.

(d) Irrigation projects are financed by the State Governments and the Central assistance is in the form of block loans/grants which is not related to any sector of development of specific scheme.

Statement

Statement showing state-wise details of the number of medium irrigation schemes under execution during 1977-78 and their estimated cost, ultimate potential and financial and Physical progress

Rs Crores/ 000' ha.

Sl No.	Name of State	Number of schemes	Estimated cost.	Ultimate potential	Expenditure to (end of 3/78 anticipated)	Potential to end of 1977-78 (anticipated)	Outlay for 1978-79 recommended by Sub-Group
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Andhra Pradesh	30	136	239	43	42	19
2	Assam . . .	19	55	157	15	45	5
3	Bihar . . .	71	90	263	15	100	17
4	Gujarat . . .	51	107	194	42	55	20
5	Haryana . . .	8	20	149	10	96	1
6	Himachal Pradesh . . .	2	7	5	2		2
7	Jammu & Kashmir . . .	11	10	158	11	75	5
8	Karnataka . . .	38	141	161	42	41	12
9	Kerala . . .	4	27	16	2		5
10	Madhya Pradesh . . .	48	120	249	62	61	24
11	Maharashtra . . .	126	245	514	90	156	23

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Manipu	0	8	16	4		2
13	Meghalaya	1	2	3			
14	Orissa	24	118	155	36	9	16
15	Punjab	4	3	0			1
16	Rajasthan	11	61		11		13
17	Sikkim	3	1				0
18	Tamil Nadu	2	39	18	10	0	1
19	Tripura		8				
20	Uttar Pradesh	30	120	343	4	103	15
21	West Bengal	19	14	43	8	1	3
FORMER STATES		51	1339	268	413	300	137
Union Territories			4	0	1		1
ALL INDIA		514	1343	2684	104	363	188

Production of Tur Dal

4315 DR BAPU KALDATE Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether the Government assessed the production of Tur dal during the next quarter (April to June 1978)

(b) if so the details thereof

(c) whether the present increase in the price of Tur dal would be affected and

(d) if so to what extent?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) The estimates of production of 'tur dal' for the year 1977-78 are not yet due from different State Governments

(b) No details can therefore be furnished

(c) and (d) The impact on prices can be known only after the estimates of production of tur dal becomes available. The impact on price cannot therefore be stated at present.

कपास की फसल में केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, रायचूर को घाटा

4316 श्री बीरेन्द्र प्रसाद क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय राज्य फार्म निगम जबलपुर रायचूर (कर्नाटक) को वर्ष 1977-78 में कपास की फसल में कराडा रुपये का घाटा हुआ है

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है और यदि हाँ तो इस बारे में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का व्यौरा क्या है और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम के रायबूर फार्म में उगायी गई 1977-78 की कपास को फसल को अभी काटा नहीं गया है। हालांकि, वनस्पति संरक्षण उपाय अपनाए गए थे लेकिन विशिष्ट वायु सम्बन्धी परिस्थितियों और फिर नवम्बर, 1977 में तूफान के आने के कारण भीषण कोट आक्रमण की वजह से उत्पादन प्राग्भिन्न अनुमानों से कम रहेगा। तथापि, यह कहना ठीक नहीं होगा कि नुकसान करोड़ों रुपयों में होगा। वर्तमान अवस्था में यह कहना सम्भव नहीं होगा कि इस कारण से फार्म को निवल हानि होगी।

(ख) ग्राम (ग) भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा दम बात की विस्तृत व गहराई में छानबीन की जा रही है कि क्या कोटा के अचानक आक्रमण से दम नुकसान का रोकना या समाप्त किया जा सकता था। उसके पश्चात् ही उपयुक्त कार्यवाही की जायगी।

Correspondence Course in LL.B.

4317 SHRI MANORANJAN BHAJTA Will the Minister of EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state

(a) the names of Universities offering LL.B Courses privately or by correspondence at present;

(b) whether the Degrees given by these Universities are considered at par with other regular Degrees, if not, the reasons, and

(c) whether Government propose to direct more Universities to start correspondence courses in Law and other subjects, and if so, details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER):

(a) According to information furnished by the University Grants Commission, the Universities which allow certain categories of person to appear privately in the LL.B. examination are. A. P. Singh University, Rewa, Berhampur University, Indore University, Jabalpur University, Ravi Shankar University, Raipur, Sambalpur University, Utkal University, Bhubaneswar and Vikram University, Ujjain. A proposal of the Jammu University for instituting a two-year LL.B. (Academic) Course through Correspondence has been accepted. The Universities of Madurai and Mysore also offer Correspondence Course for Bachelor of General Laws.

(b) Degree in law obtained either privately or through Correspondence Courses is not recognised for purposes of enrolment as advocates in accordance with the Bar Council of India Rules, 1975 framed under the Advocates Act, 1961

(c) Government have no proposal to direct any University to start correspondence courses in Law. As far as other subjects are concerned, it is expected that the needs for higher education will be met by Universities to the extent possible by offering facilities through non-formal channels.

Industrial Licence to Cadbury to make Apple Juice

4318. SHRI BIHARAT SINGH CHOWHAN Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Ministry are considering to give an Industrial licence to Cadbury to make Apple Juice concentrate;

(b) what new technology will Cadbury be able to bring to India;

(c) how will this affect the State owned unit in Himachal Pradesh; and

(d) whether it is a fact that the Himachal unit is not able to fully utilise its capacity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) to (c). An application received from M/s. Cadbury Fry (India) Private Ltd. for grant of an industrial licence for the manufacture of Apple Juice Concentrate in the State of Jammu and Kashmir with technical know-how and the processing technique of M/s. H. P. Bulmer Ltd. of U. K. is under consideration of the Government. The question whether this will affect any existing units will be considered before a final decision is taken.

(d) Yes, Sir.

Wheat	. 711 bags
Rice	. . . 153 bags
Paddy	. . . 81 bags
Sugar	. . . 5 bags

(b) A quantity of 4947 tonnes has been found unfit for human consumption out of a total quantity of 5.9 lakh tonnes of foodgrains held in the godowns of Food Corporation of India in West Bengal.

(c) The Vigilance and Security division in the Food Corporation of India has been adequately strengthened. Frequent surprise checks are made to ensure security of the stocks both in storage and in transit. Disciplinary action is taken against the concerned persons if any irregularity is detected.

Settlement of East Bengal refugees in Andaman

4320. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

Foodgrains missing to F.C.I. Godowns, West Bengal

4319. SHRI DHIRENDRANATH BASU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large quantities of foodgrains have been found missing in different F.C.I. godowns in West Bengal;

(b) whether it is a fact that large quantities have also been found unfit for human consumption; and

(c) if so, what steps Government have taken in this connection?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) The following shortages, only have been found as a result of physical verification as on 30-6-77:—

Wheat	. 711 bags	. Including 631 bags involved in theft.
Rice	. . . 153 bags	. including 147 bags involved in theft.
Paddy	. . . 81 bags	. involved in theft.
Sugar	. . . 5 bags	..

(a) whether the West Bengal Chief Minister has proposed to the Central Government for further settlement of East Bengal refugees in Andamans;

(b) if so, details of the proposal; and

(c) the reaction of the Central Government thereto?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) to (c). No formal proposal has been received from the Chief Minister, West Bengal in regard to the settlement of displaced persons from former East Pakistan in Andaman and Nicobar Islands though an inquiry

about the scope for such settlement had been made by him during discussions on 6-3-1978 and he had been informed that this was not feasible for ecological and other reasons and that adequate arrangements had already been made for the settlement of all the remaining displaced persons in the Dandakaranaya Projects.

Expansion of Rural Credit facility

4321. SHRI ISHWAR CHAUDHRY: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have taken any concrete measures in 1976-77 for expanding rural credit facilities;

(b) if so, the detail thereof and the results achieved so far; and

(c) what further steps Government are taking to extend rural credit facilities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PARTAP SINGH): (a) to (c). The policy of Government is to increase progressively the coverage of institutional credit for agricultural development. Various steps to build up the institutional credit structure had been continued during 1976-77. These are, mainly, building up of a viable and efficient multi-purpose primary cooperative society at the base level, strengthening the cooperative credit institutions in technical and managerial competence and financial resources, widening the coverage of membership, particularly of weaker sections, expanding the commercial banks branch network in rural areas and establishing regional rural banks and periodical review of the loaning policy and procedures to facilitate smoother flow of credit. The several measures taken have led to increase in the level of advances by credit institutions in the agricultural sector. The short-term loan for agricultural production given by primary agricultural credit societies are estimated to have increased from Rs. 881

crores at the end of 1975-76 to Rs. 1,016 crores at the end of 1976-77. The level of outstanding of agricultural credit by scheduled commercial banks increased from Rs. 1,092 crores in June 1976 to Rs. 1,381 crores by June 1977.

The Government are continuing their efforts to widen the flow of institutional credit in rural areas. In addition to the various measures mentioned above, steps are also being taken to reduce the rate of interest charged by the institutional credit agencies. In May 1977, the scheme of differential rates of interest operated by commercial banks has been extended to cover the entire country. Under this scheme, loans are available for certain priority group including small farmers at 4 per cent rate of interest. The Reserve Bank of India has provided a soft loan window with effect from 1st January 1978 to commercial banks to enable them to lend to small farmers short-term and medium term loans of less than Rs. 2,500 at 11 per cent; similarly, for the cooperative, the Reserve Bank has reduced the lending rate to 3 per cent below the Bank rate for short-term loans and 2½ below the Bank rate for medium term loans recently. The Government of India has also announced the withdrawal of the tax on interest so that the scheduled banks can pass on the benefit to the ultimate borrower by way of reduction in rate of interest. The Government of India and the Reserve Bank of India, apart from State Governments, are periodically reviewing the coverage and credit flow in the rural areas.

Checks on loaded Wagon in transit by F.C.I.

4322. SHRI SOM NATH CHATTERJEE: Will the Minister of AGRICULTURE & IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Food Corporation of India conduct surprise checks on loaded wagon in transit to see that

the correct number of bags were loaded in the wagon at despatch points,

(b) if so, the number of such checks conducted during the last 3 years,

(c) the total number of irregularities detected during the checks, and

(d) action taken against the culprits?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) (a) Yes, Sir

(b) 634 checks were conducted during the last three years

(c) In 63 cases irregularities were detected involving shortage of 1045 bags 48 bags was found to be in excess

(d) (i) The claim for shortages were lodged with the Railways for necessary action

(ii) The matter was taken up with the despatching parties

(iii) The responsibility was fixed and departmental action was taken against the parties concerned Necessary action was also taken against the handling and clearing contractors, in some cases

Dal contract to F.C.I

4323 SHRI D G GAWAI Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether it is a fact that tenders for Moong Dal and Moong Whole were invited by the Government for delivery up to 28th Feb, 1978,

(b) if so, how many tenders were received, the total amount deposited with Government as earnest money and the amount received on the sale of 'Tender forms',

(c) what were the lowest rates offered by the traders and the rates claimed by Food Corporation of India including railway freight for 1977-78;

(d) whether Government rejected all the tenders and gave contract to the Food Corporation of India, and

(e) if so the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) (a) Yes Sir

(b) Thirtytwo tenders were received The total amount of earnest money of Rs 16,000 00 was kept with Government The same has already been returned to the parties The cost of one tender form is Rs 15 00 The amount received on account of sale of 34 tender forms was Rs 510 00

(c) The rates offered by the various firms were as follows—

(i) Whole moong ranging from Rs 304/ to Rs 344 80 per quintal

(ii) Dal moong ranging from Rs 328 00 to Rs 410 00 per quintal The F.C.I is the official procurer for Army Purchase Organisation The prices payable to them would be decided by the Price Fixation Board of the Deptt of Food

(d) The tenders were allowed to lapse as it was felt that it would be possible to procure through normal channels

(e) As explained in (d)

Irrigation Projects under completion in Kerala

4324 SHRI V M SUDHEERAN:
SHRI VAYALAR RAVI-

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state.

(a) which are irrigation projects yet to be completed in Kerala and

how far the works progressed in these projects;

(b) what are the reasons for such a long delay and the action taken for the completion of these projects in Kerala?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT

SINGH BARNALA): (a) The latest estimated cost and the expenditure likely to be incurred by the end of 1977-78 in respect of seven irrigation projects of Kerala which have been under construction for a long time and have not been completed so far are given below:—

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of Scheme	Latest estimated cost	Anticipated expenditure upto 1977-78
1	Kallada	8830.00	1839.16
2	Pamba	2856.00	2035.37
3	Periyar Valley	2633.00	1432.92
4	Chitturpuzha	842.00	611.63
5	Kanhirapuzha	1603.00	956.39
6	Kuttiadi	3275.00	2405.57
7	Pazassi	2550.00	1394.12

Four projects, viz Periyar Valley, Kuttiadi, Pamba and Chitturpuzha, have started yielding benefits.

(b) The delay in the completion of these projects has been mainly due to inadequacy of funds, this has also resulted in increase in project costs. Larger outlays on major and medium irrigation sector have been provided since the beginning of the Fifth Plan. The outlay on this sector during the four years of the Fifth Plan i.e. 1974-75 to 1977-78 was about Rs. 75 crores against Rs. 27 crores in the Fourth Plan. The outlay envisaged for 1978-79 is Rs. 35 crores.

The Government of India is providing advance plan assistance for accelerating the progress on certain major projects of Kerala. The assistance was of the order of Rs. 2.1 crores, Rs. 2.50 crores and Rs. 5 crores during the years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 respectively.

It is expected that all these projects except Kallada would be completed during the next Five Year Plan (1978-83).

Inquiry into the working of DDA

4325. **SHRI CHATURBHUJ.** Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) whether attention of Government has been drawn towards newspaper reports demanding enquiry into the working of the Delhi Development Authority, its financial bunglings, inability to pay salaries to the staff, slow construction programme, top heavy management etc. and whether Government propose to order thorough probe into the functioning of the DDA; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). Yes, Sir. The Lt. Governor of Delhi has been requested to send a report on the allegations.

Milk Token holders and capacity of Delhi Milk Scheme

4326. SHRI MOHAN LAL PIPIL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the total number of token card holders who are supplied milk by DMS and the number of those who are on the waiting list;

(b) what is the additional quantity of milk that is required to be supplied by DMS to meet the demands of the consumers on the waiting list; and

(c) whether any special steps are proposed to be taken to meet this demand during the financial year 1978-79, if so, the nature thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) About 3,20,000 token holders are supplied milk daily by D.M.S. and 1,546 applicants are on the waiting list.

(b) D.M.S. is already handling its maximum installed capacity and there is no further scope of increased supplies of milk to consumers.

(c) A second dairy with a handling capacity of four lakh litres of milk per day has been established which is in a position to supply additional quantities of milk.

Grievances of Students of Delhi University and Jawaharlal Nehru University

4327. DR. SUSHILA NAYAR:
SHRI DILIP CHAKRA-
VARTY:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state what is the stage of enquiry into the grievances of the students of Delhi University and Jawaharlal Nehru University?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): The preliminary enquiry is still in progress.

Funds for Channelization of Swan Nadi in H.P.

4328. SHRI RANJIT SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from Legislators of Himachal Pradesh that the funds for channelization of Swan Nadi be provided by the Central Government;

(b) if so, whether the same is receiving attention of the Ministry of Agriculture; and

(c) the latest stage of consideration?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). A representation from some Members of Legislative Assembly of Himachal Pradesh had been received for providing funds for channelization of Swan Nadi. This has been considered by the Government of India. As Flood Control forms part of the State Sector, the initiation, planning and implementation of flood control schemes and provision of funds therefor is the responsibility of the State Government. An estimate for channelizing the river in a length of 6.73 Km. has been prepared by the State Government and is under examination with them.

Clearance of Scheme on Development of Hill Regions of U.P.

4329. SHRI JAGANNATH SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether a coordinating cell in the Rural Department of the Ministry of Agriculture and Irrigation has been set up for expeditious clearance of proposals relating to the development of U.P. Hill regions; and

(b) if so, the schemes to be undertaken for development of Garhwal Division in view of the Government policy to ensure social and economic justice for the people of that region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) No, Sir.

(b) In view of reply to (a) above, the question does not arise.

Houses for Community services personnel in Chittaranjan Park, New Delhi

4330. SHRI DILIP CHAKRAVARTY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) the number of quarters under construction in Chittaranjan Park to accommodate the community services personnel;

(b) the number of community services personnel that are needed for work in Chittaranjan Park;

(c) the way the balance of the quarters which are not needed to accommodate community services personnel in Chittaranjan Park will be disposed of;

(d) whether DDA will be paying for the land, and if so, at what rate; and

(e) whether the money so realised will be credited to the account of the Colony to reduce the cost of acquisition and development for the allottees?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) As reported by the Delhi Development Authority, 48 houses have already been constructed in Chittaranjan Park. Another 44 houses are under construction there.

(b) Delhi Development Authority has reported that as per the norms laid down in the Master Plan, 5 per cent of the housing units are to be provided for service personnel family housing i.e. dhobis, janitors, jamadars, malis, domestic servants etc.

(c) Flats after construction would be allotted by the Delhi Development Authority to the service personnel as per their existing policy. The Delhi Development Authority has been requested to consider allotment of quarters to such displaced persons also who fall under the prescribed categories of service personnel.

(d) The Delhi Development Authority has intimated that sites earmarked for service personnel should revert to the Delhi Development Authority after development free of cost. However, Government has not taken any final decision in the matter

(e) Under the principle of 'no profit no loss' basis on which the plots have been allotted to the eligible displaced persons in Chittaranjan Park, the total expenditure on acquisition of land and development is chargeable from the allottees of residential plots including sites earmarked for group housing.

पंचायतों का कार्यकाल

4331. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या छवि और सिन्हाई मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि

(क) किन-किन राज्या में पंचायतों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और वहां अभी तक नये चुनाव तैयार कराए गये हैं,

(ख) इन राज्यों में पंचायतों के नये चुनाव कब तक कराये जाने का प्रस्ताव है, और

(ग) राज्या/संघ क्षेत्रों में पिछले चुनाव कब-कब हुए थे ?

छवि और सिन्हाई संभाल्य में राज्य

मंत्री(श्री बालू प्रताप सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान।

(ख) संघ सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) एक विवरण सभापति पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य का नाम	पिछले चुनाव की तिथि
आन्ध्र प्रदेश	जून, 1970
असम	अप्रैल, 1974
बिहार	1969 में एक जिला, 1970 में एक जिला और 1971 में 6 जिले। शेष 23 जिलों में 1969 और 1971 के बीच चुनाव कराए गए थे।
गुजरात	19
हरियाणा	1971
हिमाचल प्रदेश	1972
जम्मू तथा काश्मीर	अगस्त, 196
कर्नाटक	1968
केरल	दिसम्बर, 1963
मध्य प्रदेश	मई, 1970

राज्य का नाम

पिछले चुनाव की तिथि

महाराष्ट्र	सभी ग्राम पंचायतों के चुनाव साथ-साथ नहीं किए जाते हैं। अलग-अलग तिथियों को ग्राम पंचायते स्थापित की जाती हैं और उनके चुनाव उनकी सामान्य अवधि बढ़ाई हुई अवधि, जो भी स्थिति हो, के पूर्ण होने के पश्चात् अलग-अलग तिथियों को होते हैं। आपातकाल के कारण ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। स्थगन अवधि 20-9-77 को समाप्त हो गई।
मणिपुर	1970
मेघालय	पंचायतीराज लागू नहीं किया गया है।
नागालैण्ड	पंचायतीराज व्यवस्था नहीं है : तथापि यहां क्षेत्र, प्रक्षेत्र और जनजातीय परिषदें हैं।
उड़ीसा	अप्रैल, मई 1975
पंजाब	1972
राजस्थान	फरवरी, 1978
मिज़ोरम	15-12-1976 और 16-12-1976
तमिलनाडु	जुलाई, 1970
त्रिपुरा	1968-72 (क्षेत्रवार)
उत्तर प्रदेश	1972। ग्राम पंचायतों की अवधि को 14-6-78 तक बढ़ाया गया है।
पश्चिम बंगाल	1958-64
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1976 और 1977। 32 ग्राम पंचायतों के चुनाव 1976 में किए गए थे और शेष 6 ग्राम पंचायतों के चुनाव 1977 में किए गए थे।
अरुणाचल प्रदेश	1976
चण्डीगढ़	19-8-73
दादरा तथा नगर हवेली	1976
दिल्ली	29 दिसम्बर, 1977
गोवा, दमन और दीव	नवम्बर, 1977
लक्षद्वीप	पंचायते नहीं हैं।
मिज़ोरम	—यथोपरि—
पाण्डिचेरी	दिसम्बर, 1968 माह में एक्स फ्रेन्च म्यूनिसिपल डिप्टी दिनांक 12-3-1880 के अधीन पिछले चुनाव किए गए थे। डिप्टी के अनुसार, नगर पालिका कांसलरो का कार्यकाल 6 वर्ष था। नए अधिनियम के अधीन चुनाव अभी होने हैं।

Amount distributed to Indian Enclave Migrants at Coochbehar, Jalpaiguri, Darjeeling and West Dinajpur

4332. SHRI AMAR ROY PRADHAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the amount sanctioned for the rehabilitation of Indian Enclave migrants who are staying at Coochbehar, Jalpaiguri, Darjeeling, West Dinajpur districts in West Bengal;

(b) how much money has been distributed so far for the rehabilitation out of that sanctioned amount; and

(c) whether a good number of people who are not enclave refugees are also getting rehabilitation benefit and are depriving the real migrants?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) A sum of Rs. 121.23 lakhs has been sanctioned so far for the rehabilitation of migrants from Indian Enclaves staying in Coochbehar, Jalpaiguri and West Dinajpur districts in West Bengal. According to information received from the State Government, there are no Indian Enclave migrants staying in the District of Darjeeling

(b) The West Bengal Government have reported that an amount of Rs. 49,72,295 was disbursed upto the end of 1976-77. During 1977-78 the disbursements expected are of the order of Rs 23 43 lakhs. Thus, the total disbursements to Enclave migrants, upto the end of March, 1978 may work out to Rs. 73.15,295.

(c) The Government of West Bengal, who have been entrusted with the implementation of this scheme, have intimated that they are not aware of any such cases.

Acquisition and Development Cost of Land in Kalkaji

4333. SHRI RAJ KRISHNA DAWN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the refugees from West Pakistan allotted lands in Kalkaji colony, New Delhi were charged total premium of Rs. 7.50 (acquisition plus development cost) per sq. yd. of plotted area;

(b) whether in case of the refugees from former East Pakistan allotted land at Kalkaji (EPDP) were charged Rs. 12/- per sq. yd. on account of acquisition cost only;

(c) if so the details thereof; and

(d) the reasons for abnormal increase in development cost after ten years to Rs. 24 20 per sq. yd. land in EPDP colony Kalkaji from Rs. 18/- which was real at the time of allotment in 1968?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) No Sir. The premium (acquisition plus development cost) charged from refugees from West Pakistan allotted land in Kalkaji (main) colony was Rs. 11 per square yard and not Rs. 7.50 per square yard.

(b) and (c) Yes, Sir. The land for Chittaranjan Park (formerly EPDP) colony was made available out of the surplus land comprising private lands, nazul lands and evacuee lands acquired for rehabilitation colonies for the West Pakistan displaced persons. The rate of Rs 5 per square yard for the gross area of Rs. 12 per square yard for the plotted area, plotted area being 41 per cent of the entire area, was estimated at the time the scheme was sanctioned in 1961 and was reckoned as such in the provisional price. Following the guiding principle adopted for colonies for the West Pakistan displaced persons, the provisional

cost of acquisition of land has been treated as final notwithstanding the market price appreciations as in 1966, when applications for allotment of plot were first invited, and even higher escalations since then.

(d) The development cost went up from Rs. 18 to Rs. 24.20 per square yard mainly due to the fact that a large sum of money has had to be paid to the Municipal Corporation of Delhi after the responsibility for the maintenance of civil services was transferred to them in 1974 so as to bring the civil services on par with the standard followed by them.

Sub-Soil Water in Delhi

4334. SHRIMATI CHANDRAVATI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether sub-soil water in Delhi is only 5 feet deep;

(b) whether it is a fact that property worth lakhs and crores of rupees (M.P.'s houses etc.) is being damaged as a result thereof; and

(c) whether it is also a fact that this is because of the negligence of his Ministry in not pumping out the sub-soil water?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Sub-soil water level in Delhi varies from place to place and from time to time.

(b) No, Sir However, existence of sub-soil water does cause dampness in the old houses which had not been provided with a damp proof course at the time of their construction

(c) Pumping of water through shallow tube wells had been tried for 12 years from 1961-62 but this did not have any effect on the water table. As there was no danger to structures and the pumping was not making any impact, the work was given up.

Changes in Aligarh Muslim University Act

4335. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to refer to the replies given to Unstarred Question Nos. 1130 and 1174 on 21st November, 1977 regarding declaring of Aligarh Muslim University as minority education institution and changes in AMU Act and state:

(a) whether Government have taken any decision in the matter;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to consult old students, teachers and officers of AMU before the introduction of appropriate Bill in the Lok Sabha?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) to (c). The matter is still under consideration of the Government.

Inter-State Bus Terminus, Delhi

4336. SHRI BHARAT BHUSHAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether he is aware that due attention is not paid to sanitation at the Inter-State Bus Terminus and it stinks at several places, food stuffs are sold at a rate higher than their market price and proper arrangements for light and drinking water during night are also lacking, and

(b) if so, the action being taken by Government to improve the condition?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The Delhi Development Authority has reported that arrangements for sanitation and light and drinking water at night are satisfactory at present. No rates had been

fixed previously for foodstuffs sold by licensees of shops at ISBT. They were, however, required to exhibit their selling rates at their shops.

(b) The Delhi Development Authority has reported that shops are being allotted now on the condition that they will sell the foodstuffs etc. at the rates fixed by the Railways and according to the quality and quantity fixed by them.

Sugarcane Price

4337 SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there is a demand for fixing the price of sugarcane at the rate of Rs. 13 per quintal; and

(b) if so, what action has been taken by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966 lays down the following basis for fixing sugarcane price payable by sugar factories:

(i) the cost of production of sugarcane;

(ii) the return to the grower from alternative crops and the general trend of prices of agricultural commodities;

(iii) the availability of sugar to the consumer at a fair price;

(iv) the price at which sugar produced from sugarcane is sold by producers of sugar; and

(v) the recovery of sugar from sugarcane.

In addition to the above, an expert body, the Agricultural prices Commission, the State Governments concerned and various Associations of Sugar Mills

cane growers are consulted before arriving at a final decision regarding the fixation of the minimum cane price under law. For the sugar seasons 1977-78, the Central Government after considering all circumstances having a bearing on the case, had decided to fix the statutory minimum cane price at Rs. 8.50 per qtl. linked to a basic recovery of 8.5 per cent or below, with a premium of 10 paise for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent.

The average recovery in the country is about 10 per cent and hence the average minimum price is Rs. 10 per quintal. In addition to this, sugarcane growers supplying sugarcane to sugar factories are entitled to 50 per cent share of the excess realisations from the sale of levy from sugar. In the past the average share has been of the order of Rs. 2 to 3 per quintal. In actual practice sugarcane growers get what is usually referred to as the State advised price which for the season 1976-77 was around Rs. 13.50 p. per quintal on an all-India average.

Agitation by Graduate Junior Engineers

4338 SHRI AGHAN SINGH THAKUR: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether active members of Graduate Junior Engineers Association and the EMI Junior Engineers Association have been issued memos regarding arbitrary transfer orders to out stations and threatened with disciplinary action because of their agitation for a separate cadre; and

(b) if so, the reasons for such arbitrary action and not solving the problem in a democratic way?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) No, Sir. There has

been no threat of disciplinary action. As for transfers these have been done in order to provide field experience to graduate Junior Engineers working in the design offices; and such transfers are neither arbitrary nor confined only to the active members of the Association.

(b) The question does not arise.

Fund for the Aid of Poor and Physically Handicapped

4339. SHRI RAMJI LAL SUMAN: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to create a national fund for the aid of poor, physically handicapped and people dependent on others; and

(b) if so, by what time and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN): (a) and (b). The idea of a national fund for aid of the poor, the physically handicapped and destitutes, laudable as it may appear, is hardly a practical proposition.

Relief to the disabled and the unemployable is a State subject under the Constitution. The Central Government nevertheless extend substantial assistance for rehabilitation and welfare of the physically handicapped, destitute women and children and other deprived sections of the population.

Under the existing schemes, financial assistance is also provided to the voluntary organisations working in this field. Direct aid to voluntary organisations has been stepped up from Ra. 58 lacs in 1974-75 to more than 100 lacs in 1977-78.

Production and Consumption of Fertilizers

4340. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the production and consumption of fertilizers annually in the country;

(b) the quantity of fertilisers imported from each foreign country during the last three years, year-wise;

(c) what is the foreign exchange involved in the import of fertilisers during the above period;

(d) the steps being taken by Government to achieve self-sufficiency in fertilisers;

(e) by when India will be self-sufficient in fertilisers; and

(f) what instructions are issued by Government for effecting economy in the consumption of fertilisers in the country and with what results?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The production and consumption of fertilisers during the years 1976-77 and 1977-78 are indicated below:—

Year	(In lakh tonnes)					
	Production			Consumption		
	N	P	K	N	P	K
1976-77 . . .	19.0	4.8	Nil	24.57	6.35	3.19
1977-78 (Estimated)	20.0	6.7	Nil	28.88	8.27	4.69

(b) and (c). The quantity of fertilisers imported from each foreign country during the last three years, year-wise alongwith the C & F value thereof is indicated in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1925/78].

(d) The Government have taken the following steps to reduce dependence on imports and achieve self-sufficiency in fertilisers:—

(i) ensure maximum utilisation of the capacity of the fertiliser units;

(ii) implement programmes for improvement in the capacity/capacity utilization of existing units;

(iii) implement a programme for creating new capacity for fertiliser production.

(e) A large scale programme for augmentation of fertiliser production capacity involving the setting up of 12 new projects has been taken in hand. Even with the commissioning of these projects, the production available by 1983-84 is not expected to be sufficient to meet the demand for Nitrogen and Phosphates. There are no known reserves of Potash in the country and India will have to continue to depend on imports for obtaining its requirement.

(f) Economy in consumption of fertilisers means most efficient use so that every kilogram of fertilizer applied to the soil gives the maximum return. Guidelines with regard to efficient use of fertilizers have been issued by the Government are given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in the Library. See No. LT/1925]. Implementation of these instructions is a continuous task for the extension machinery and State Governments, who, by constant training seasons, bring home to farmers before every cropping seasons, bring home to the farmer the message of efficient fertiliser use. The results of this pro-

cess of extension are reflected in the figures of agricultural production.

Extension of Fertiliser Promotion Campaign

4341. SHRI SARAT KAR: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to cover more districts under the Fertiliser Promotion Campaign during the current year;

(b) whether Central Government have received any proposal from the State of Orissa for including more districts in that State under this campaign; and

(c) if so, the reaction of the Central Government to extend the scheme to that State?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) No, Sir. The Fertilizer Promotion Campaign will continue in the 75 districts which were selected for Rabi 1977-78.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise

Prices of Agricultural Products

4342. SHRI C. K CHANDRAPPAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the floor prices of rice, paddy, wheat, jute, cotton, sugarcane, tobacco, groundnuts, coconuts, cashewnut for 1976-77 and 1977-78; and

(b) at what price these above mentioned agricultural products were sold during 1976-77 and 1977-1978 and details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) A statement giving procurement prices for paddy and wheat and minimum support prices in respect of jute, cotton and groundnut and minimum prices for sugarcane payable by sugar factories for 1976-77 and 1977-78. Is Laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1926/78]. These prices act as flood prices. Support prices are not being fixed for tobacco, coconuts and cashewnut. In the case of rice, procurement prices are fixed by the State Governments on the basis of the procurement price of paddy announced by the Central Government.

(b) Statements giving month-end wholesale prices of rice, paddy, wheat, jute, cotton, tobacco, groundnut, coconut and cashewnut and prices of sugarcane as paid by sugar factories during 1976-77 and 1977-78 are laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. LT-1926/78].

बाहनों के टायरों पर रबड़ चढ़ाना

4343. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या निर्माण और आवास तथा पुति और पुनर्वास मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिक्षित बेरोजगार हरिजन, प्रादिवासियों तथा भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बाहनों के पहियों पर रबड़ चढ़ाने के लिए दी गयी निषिद्धाओं का स्वीकार करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन लोगोंके लिए कोई पृथक नोति बनाई गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इन्हें किस प्रकार को राहत प्रदान की गई है; और,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पुति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बजल) : (क) के (ख). पुति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा दिए जाने वाले ठेकों में लघु उद्योग एककों (जिन्हें मूल्य अधिमान दिया जाता है) और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (जिन्हें कम अधिमान दिया जाता है) के प्रतिरिक्त अन्य किसी वर्ग या श्रेणी के पुतिकर्ताओं को किसी प्रकार का विशेष अधिमान नहीं दिया जाता। पुति तथा निपटान महानिदेशालय वाणिज्यिक स्तर पर कार्य करता है और बहुत ही कफायत के आधार पर खरीद करने की कोशिश करता है। इसलिए बेरोजगार व्यक्तियों, हरिजनों प्रादिवासियों और भूतपूर्व सैनिकों प्रादि को प्राथमिकता देना सम्भव नहीं है।

Re-evaluation of Answer Sheets

4344. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) names of Universities in India that allow re-evaluation of students answer sheets in their examinations;

(b) whether Jawaharlal Nehru and Jamia Millia Universities also allow such facility of re-evaluation of answer sheets on request; and

(c) if not whether there is any proposal to allow this facility to students in these universities?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Provision for re-evaluation of answer books is made by the Universities themselves depending upon the system of examinations, etc., followed by them. Information about the names of all Universities which permit re-evaluation is not available.

(b) Jawaharlal Nehru University has no provision for revaluation as the final grade awarded to a student is not based on a single final examination. In the Jamia Millia Islamia, provision is made only to scrutinise cases of rechecking of results whenever proper applications are made.

(c) No, Sir.

Commercial use of Residential Buildings in Delhi

4345. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) what are the details in respect of commercial use of residential buildings by professionals like doctors and Chartered accountants etc. referred to in reply to Unstarred Question No. 766 dated 27th February, 1978, specifically in areas under the jurisdiction of the Land and Development Office at New Delhi;

(b) will the Minister lay on the Table a copy of the administrative orders/guidelines being followed by the Land and Development Office in respect of allowance of residential buildings for commercial purposes by professionals and other categories; and

(c) how many cases in respect of each category of professionals etc. have been allowed to use residential areas for commercial purpose in land under the Land and Development Office?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). The use of a residential building for non-residential purposes is a breach of the terms of lease and such use is temporarily regularised by the Land and Development Office on recovery of misuse charges. In certain cases, use of residential premises by professionals etc.

to the extent prescribed is condoned. A list of condonable breaches is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1927/78].

The misuse of a premises comes to notice of the Land and Development Office on inspection of the premises. These inspections generally used to be made whenever there was a complaint of misuse or whenever the lessee asked for mutation or permission for transfer or sale. Hence details of all misused residential buildings are not available. Government have recently decided that the Land and Development Office undertakes periodical inspections of the leased properties.

(c) Collection of information will take considerable time and effort which may not be commensurate with the result.

Development and Preservation of Tribal Dialects and Languages

4346. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) programmes adopted and provisions provided by his Ministry for the development and preservation of tribal dialects and languages in the year 1977-78;

(b) total number of tribal languages found in India and how many of them have invented the script of their own so far; and

(c) programmes for the development and preservation of scripts particularly Savara language script invented in Gunupur area of Orissa State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI): (a) The undermentioned programmes have been undertaken

through the Central Institute of Indian Languages, Mysore:

- (i) Preparation of instructional materials in tribal languages;
- (ii) Publication of phonetic readers, grammars, multilingual dictionaries and folk literature etc.;
- (iii) In-service training in language teaching;
- (iv) Organisation of orientation camps, workshops for material production and training in language teaching for language teachers.

The financial provision for work on tribal and border languages is Rs. 3.25 lakhs approximately.

(b) The total number of mother tongues returned by Scheduled Tribes in 1961 census is 304 which have been classified into 101 languages by the linguists of the census. Three languages viz. Santhali, Saveria and Kurukh are said to have invented a new script or discovered an old script.

(c) Since from the point of view of educational and economic advantages, the speakers of tribal languages must transfer to the State language at some point in their education, the State Government and others have been advised that the tribal languages may follow a modified version of the script of the State language for educational purposes.

Rehabilitation of Local Tribal persons in Dandakaranya Project

4347. SHRI GIRIDHAR GOMAN-GO: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) steps taken by his Ministry and Government of Orissa to rehabilitate the displaced and misplaced local tribal persons in Dandakara Project and Potteru Irrigation project so far;

(b) total number of refugee families rehabilitated in that zone and left the place so far; and

(c) allocation made for the year 1977-78 for refugee development and tribal development by his Ministry?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The question of rehabilitation of local tribals likely to be displaced as a result of the Satiguda Dam Project in Dandakaranaya is being considered by the Dandakaranaya Development Authority in consultation with the Government of Orissa. No such tribals have been displaced in the Potteru Irrigation Project areas.

(b) 12,821 families were rehabilitated in Malkangiri Zone as on 31-1-1978 of whom 3,687 had deserted by that date. In addition, 3,772 settlers left rehabilitation sites between 1-2-1978 and 18-3-1978.

(c) An amount of Rs 440 lakhs has been provided for refugees and tribal development in Dandakaranya Project during the year 1977-78.

उर्कई सिंचाई परियोजना

4348. श्री छीतुनाई गामित : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्कई सिंचाई परियोजना पर अब तक हुए व्यय और बायें होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना के दाएं और बाएं किनारों पर नहरों से कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई होगी तथा इस समय इन नहरों से दोनों किनारों पर कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है;

(ग) समूचे कमांड क्षेत्र में भूमि पर पानी के उपलब्ध न होने के क्या कारण

हैं तथा कमांड क्षेत्र की समूची भूमि के लिए पानी कब तक उपलब्ध होगा तथा इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करण का विचार है, और

(घ) क्या यह सच है कि बाध स कुछ दूरी पर नहर के बाग किनारे में दो बार दरार पड़ी और यदि हा ना उमका व्योम क्या है और क्या भारत सरकार बाध तथा नहरा क कर्म को जाव करने हेतु प्रसिद्ध तकनीकी विमेयज्ञा क केन्द्रिय दल पुन अजेगी और यदि हा, ना उमका कब तक मचा जाएगा ?

छवि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इम समय उकई सिंचाई परियाजना पर 121 कराड रुपय को लागत आने का अनुमान है। 1977-78 के अन्त तक इम परियाजना पर 118.42 कराड रुपय खर्च हा जाने की प्रत्याशा है। इम प्रकार बाकी 2.58 कराड रुपये खर्च किय जाने है।

(ख) इम परियाजना में 1.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई करने की परिकल्पना की गई है। 0.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र दायें किनारे पर और 0.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बायें किनारे पर। 1977-78 के अन्त तक 1.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की 0.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की दायें किनारे पर और 0.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की बाग किनारे पर-सिंचाई शक्यता का सुजन हा जाने की आशा है। लकिन वस्तुतः 33000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई।

(ग) कमान क्षेत्र विशेषकर बायें नहर प्रणाली के अन्तगत क्षेत्र मैदानी है जिसमें फील्ड चैनला के निर्माण के अलावा भूमि को समतल बनाया जाना और मही रूप दिया जाना जरूरी है।

अब तक सुजित सिंचाई शक्यता का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से कमान क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए कमान क्षेत्र विकास-प्राधिकरण की स्थापना की गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तगत अधिक जग आन-फार्म विकास कार्यों पर दिया गया है जिनमें सिंचाई और जल-निकास के लिए फील्ड-चैनला का निर्माण करना और भूमि को समतल बनाना/मही रूप देना शामिल है। अगले पांच वर्षों में इम परियाजना के समूचे इपि कमान क्षेत्र का आन-फार्म विकास कार्यों के अन्तगत लाने का विचार है।

(घ) गुजरात सरकार म सूचना एकत्र की जा रही है और महापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों में सुविधायें

4349 श्री बपाराम शाक्य : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्बास मंत्री यह बताने की श्रपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1976-77 में दिल्ली विकास प्राधिकरण न कितन जनता फ्लैटों का निर्माण किया,

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 4500 रुपये मूल्य का एक कमरे वाले फ्लैटों में शौचालय, जल और बिजली जैसी सुविधायें नहीं है

(ग) क्या यह भी सच है कि 30 वर्गगज के 2200 रुपये वाले फ्लैट जिनमें, उपर्युक्त सभी सुविधायें है वष 1971 में गांधी शताब्दी क अष्टम पर जनकपुरी, पश्चा राड, और सफदरजग और विवेक बिहार में अलाट किए गए थे, और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण

द्वारा वर्ष 1976-77 में कम क्षेत्र में निर्मित फ्लैटों जिनमें उक्त सुविधायें नहीं हैं, के अधिक मूल्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या जनता सरकार ने इस बात का पता लगाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है कि क्या उक्त फ्लैट उन निर्धन लोगों के रहने योग्य हैं जिनके इनकम बच्चे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वासि मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क)
440।

(ख) इन टेनामेंन्टों का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्वासि कालानिया में बनाया गया था। सामे शौचालय बनाकर और पानी के नल और/या हैण्ड पम्प पुनर्वासि क्षेत्रों में लागू शुष्क शीपडी हटाया योजना के उपबन्धों के अनुसार सभी ब्लॉकों में उपलब्ध कराया गया है। मड़का की बिजली दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी। व्यक्तिगत कनेक्शन अलाटिया द्वारा यदि वे चाहें, स्वयं लेन होते हैं लेकिन योजना में इसकी व्यवस्था नहीं है।

(ग) जी हा।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित फ्लैट 1969-70 के दौरान एक विभिन्न राजभा के अन्तर्गत बनाए गए थे। जबकि भाग (ख) में उल्लिखित क्वार्टर 1976-77 में बनाए गए थे। पुन उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित फ्लैटों का मूल्य 1100 रुपये प्रति फ्लैट की सीमा तक सहायता के अन्तर्गत था। इसमें तथा निर्माण की लागत में वृद्धि के कारण उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित फ्लैटों की बिक्री का मूल्य बढ़ गया है। उपलब्ध करायी गयी सुविधायें शीजुदा शुष्क शीपडी हटाया योजना के उपबन्धों के अनुसार हैं। इनमें भागे सुधार स्वयं प्राकृतियों द्वारा किया जाना होता है।

Imparting Religious and Moral Education in all Faith

4350 SHRI MADHAVRAO SCINDIA Will the Minister of EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state

(a) whether Government propose to consider the proposal about imparting religious and moral education in all faith in regional languages, to make the children moral, patriotic and faithful to their religion throughout the country,

(b) if so, whether Government propose to consult all State Governments in this regard and if so when, and

(c) Government's reaction in the matter?

THE MINISTER OF EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR PRATAP CHANDRA CHUNDER) (a) Moral Education has been given an important place in the curriculum. The school curriculum will have a core centering around the objective of character building. The emphasis will be however, on the development of human values in Education and not on religious education.

(b) and (c) The NCERT has developed the framework of the school curriculum which has been recently reviewed by the Ishwar Bhai Patel Committee. These documents have been circulated to all State Governments. The State Governments will be preparing detailed curricula based on these guidelines.

Damage due to Hailstorm in M.P.

4351 SHRI MADHAVRAO SCINDIA Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether Government are aware that in the recent hailstorm a number of districts in Madhya Pradesh were adversely affected;

(b) if so, whether the Government have received a request from the State Government for Central assistance in this regard;

(c) if so, the total loss assessed by the State Government and total assistance sought therefor; and

(d) the reaction of the Central Government?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir

(c) and (d). Do not arise.

Group Housing Societies in Delhi

4352. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the names of the group housing societies so far registered in Delhi, with their date of registration;

(b) what is the total amount deposited by these societies so far,

(c) the manner in which the amount is being utilised by the DDA;

(d) the names of societies who have been given possession of land with the dates of possession; and

(e) by when the remaining societies who have deposited full cost are likely to be given possession?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The details are furnished in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1928/78].

(b) Rs. 333,56,180 have been received as cost of land so far. Out of

this amount Rs. 4,42,519 has been refunded as some societies were not interested in allotment of land.

(c) The amount is being utilised for development activities of the Delhi Development Authority

(d) Details are given in the statement laid on the Table of the House [Placed in Library See No. LT-1928/78].

(e) 51 societies have deposited full cost of land. 40 of these have been given possession of land. The remaining are expected to be offered land by 30th April, 1978.

दिल्ली में सार्वजनिक तरण ताल

4353. श्री बीनेन बट्टाचार्य : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली के विभिन्न स्थानों में सार्वजनिक तरण-ताल बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, और

(ख) क्या ऐसे स्विमिंग पूलों के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय सिंह गुजराल) : (क) सरकार के पास एक योजना है, जिसके अन्तर्गत राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों/संघ आसित क्षेत्रों के प्रवासनों से सार्वजनिक तरणतालों के निर्माण सहित खेलों तथा शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं के विकास के लिए समाज आंदार पर वित्तीय सहायता देने हेतु प्रायः प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत स्टेडियमों और तरणतालों के निर्माण जैसी परियोजनाओं की प्रस्ताव खेल के मैदानों के विकास एवं

राष्ट्रीय खेल केंद्रों की स्थापना के प्रस्तावों को उच्चतर श्रेणी दी जाती है। दिल्ली प्रशासन श्रमिका दिल्ली राज्य खेल परिषद् की धार से दिल्ली में तरण-ताल के निर्माण के लिए इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जो नहर।

Ministry-wise Quota of D.D.A. Flats

4354. SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the details regarding the number of residential plots released during the last one year for the middle and low income groups in Delhi;

(b) whether Government would like to fix some quota in this regard Ministry-wise, for Central Government Employees, and

(c) whether there is any quota for an out of turn allotment of these flats and plots also?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) No plots were released for allotment by draw of lots.

(b) There is no such proposal.

(c) No, Sir.

Rehabilitation of Refugees in Madhya Pradesh

4355. SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) places where the refugees from East Bengal are being rehabilitated in Madhya Pradesh;

(b) whether the Government of Madhya Pradesh have sent to the Central Government various proposals with regard to the rehabilitation; and

(c) if so, the number of such proposals and their description and action taken by the Central Government?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) New migrant families are being settled both in agriculture and small trades. For agricultural settlement there are three projects known as Betul, Panna and Sarguja administered through the State Government. Settlement is also taking place in the old colonies of Dharamjaigarh (District Raigarh) Ajaibnagar (District Sarguja) and Usrar (District Satna). There is a centrally administered scheme viz, Dandakaranaya a portion of which lies in Bastar District. The Madhya Pradesh portion of the Dandakaranaya Project consists of two zones namely Kundagaon and Paralkote. In regard to Small Trade settlements the places where the schemes have been framed are Indore Ujjain, Nagda, Rajnandgaon Kandwa, Gwalior, Dewas, Jabalpur, Neemuch, Morena and Khar gaon.

(b) Yes, Sir.

(c) The number of proposals for agricultural families is 5 and these have been approved. The number of proposals for small trade families is 16, out of which 11 have been approved and the remaining 5 not considered necessary at this stage. The assistance sanctioned by Government of India for agricultural families provides for housing, bullocks, agricultural implements, bunding, subsidiary occupation, purchase of seeds and fertilizers etc., as well as grant for maintenance assistance for 6 months; for small trade families loans for housing, shops and business as well as grant for maintenance assistance for 3 months.

Irrigation Facilities to Refugees in Shahpur

4356 SHRI PARMANAND GO VINDJIWALA Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Government have received from the Government of Madhya Pradesh a proposal known as Bichua-Latia Project for providing irrigation facilities to the refugees in Shahpur, District Betul, M P,

(b) whether it is also a fact that the Government of Madhya Pradesh has consented to share the expense of the above project as demanded by the Government, and

(c) if so, whether the permission to construct the above project has been granted?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) Yes Sir

(b) Yes Sir to the extent of 20 per cent

(c) It has examined and not found necessary by Government of India to financially participate in the execution of this Project

Central Government Offices in Barracks in New Delhi

4357 SHRI DURGA CHAND Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) the names of Central Government offices which are located in barracks in New Delhi,

(b) whether it is a fact that the Government have formulated or propose to formulate any proposal to construct buildings on the pattern of various Bhavans for housing these offices, and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) Names of Central Government Offices in general pool located in barracks in New Delhi are given in the attached statement

(b) and (c) While assessing the total requirement of office accommodation to be constructed, the requirement of office accommodation for offices located in barracks, which may have to be demolished in due course, is being kept in view. At present, office buildings are under construction in Plot No 35 in New Delhi (part of which has been completed), in Rama Krishna Puram and Badarpur-Mehrauli Road Complex. Proposals are also under consideration for the construction of office buildings in general pool in Lodhi Road area in New Delhi

Statement

- 1 Ministry of Defence (Partly)
- 2 Ministry of Finance (Defence) (Partly)
- 3 Army Headquarters (Partly)
- 4 Naval Headquarters (Partly)
- 5 Air Headquarters (Partly)
- 6 Border Road Development Board
- 7 Research and Development Organisation (Ministry of Defence)
- 8 DG Air Force Medical Service
- 9 D G Inspection Organisation
- 10 D G B R Headquarters
- 11 Directorate of Standardisation
- 12 D T D & P (Air)
- 13 C M O Directorate
- 14 Directorate of Planning and Co-ordination
- 15 Ordnance Factory Cell
- 16 Heavy Vehicles Factory Cell
- 17 Northern Directorate Survey of India
- 18 Directorate of M L & C

- 19 Directorate of Public Relations.
 20. Chief Administrative Officer (Ministry of Defence)
 21. Security Office (Ministry of Defence).
 22 Armed Forces Film Photo Division
 23 Joint Communications Electronics Committee
 24 School of Foreign Languages
 25 Services Sports Control Board
 26 DCDA I/c Pay Section
 27 Unit Accountant (CAO)
 28 L A O (AF)
 29 L A O (AHQ)
 30 Directorate of Audit Defence Services (Partly)
 31 Pay and Accounts Office (Rehabilitation)
 32 Pay and Accounts Office (Supply)
 33 Pay and Accounts Office (Agriculture)
 34 Cabinet Secretariat (Partly)
 35 Pay and Accounts Office (Department of Food)
 36 Controller General of Accounts (Ministry of Finance) (Partly)
 37 Ministry of Chemicals and Fertilisers (Partly)
 38 Department of Social Welfare (Partly)
 39 C P I (Partly)
 40 Department of Personnel (Partly)
 41 Enforcement Directorate (Partly)
 42 Central Vigilance Commission (Partly)
 43 Monitoring Organisation (Ministry of Communication)
 44 Ministry of External Affairs (Partly)
 45 Foreigners' Regional Registration Office
 46 Directorate of Sugar
 47 Directorate of Fats, Oils and Vanaspathi
 48 Directorate of Economics and Statistics (partly).
 49 DGS & D (Partly)
 50 Department of Heavy Industry (Partly)
 51 Intelligence Bureau (Partly)
 52 Border Security Force (Partly).
 53 Settlement Commission (IT & WT)—Ministry of Finance
 54 Northern Zonal Council (Ministry of Home Affairs)
 55 Regional Settlement Commissioner's Office
 56 Department of Rehabilitation (Partly)
 57 Directorate of Inspection, Northern Circle (DGS&D)
 58 Central Road Research Organisation
 59 Publication Branch (Ministry of Works & Housing) (Partly)
 60 Press Information Bureau (Ministry of I & B)
 61 D V P (Partly)
 62 Photo Division (Ministry of I & B) (partly)
 63 Registrar General of India (Partly)
 64 Ministry of Education (Partly)
 65 Central Hindi Directorate (Partly)
 66 Central Plant Protection Unit
 67 Social Welfare and Rehabilitation Directorate
 68 Bureau of Police Research and Development
 69 D G AIR (Partly)
 70 Central Ground Water Board
 71 National Saving Organisation
 72 Institute of Secretariat Training and Management (Partly)
 73 The concerned maintenance units of the CPWD are also located in practically all the barracks

Constructional Programme in D.I.Z. Area, New Delhi

4358. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that only type II and type I quarters are being constructed in the DIZ Area, Gole Market, New Delhi;

(b) if so, what are the reasons for which type III and type IV quarters are not constructed in this area; and

(c) whether it is proposed to construct higher type of quarters in the rest of DIZ area, if so, what are the details thereof, if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) No, Sir

(b): Does not arise, as type III and type IV quarters are also under construction in the D.I.Z Area.

(c) No, Sir, at present, it is proposed to restrict the construction of new quarter, in general pool during the next two years, mainly to the three lower types. This is because of a very large shortage of quarters in these types

Rice Rotting in Tripura

4359. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be please_d to state:

(a) whether it is a fact that a huge stock of about 1300 metric tonnes of rice has been rotting in the Government godowns in Tripura since 1974 and lately this stock has been declared unfit for human consumption by the Public Analyst; and

(b) if so, the total amount of loss so incurred; and the reasons for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) and (b). A quantity of about 13,000 tonnes of rice has been built up in the Tripura godowns of Food Corporation of India mainly due to lower off-take than anticipated. Some of the stocks required reconditioning and this has been undertaken. No stock out of this has been declared unfit for human consumption.

क्षारीय भूमि में फसलें उगाना

4360. श्री सुरेश त्वा सुमन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षारीय बजर भूमि पर फसल पैदा करने के लिये सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है, और

(ख) क्या इस क्षारीय भूमि के बारे में सभी उपाय जैसे कि कृषि अनुसन्धान, वैज्ञानिक अध्ययन दल भेजना तथा जिप्सम उत्पादन आदि सभी उपाय कर लिये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) "सहज क्षेत्रों में क्षारीय तथा अम्लीय मृदा के सुधार के लिये मार्गदर्शी परियोजना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत पाचवी योजना के दौरान पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में फसलें पैदा करने के लिए क्षारीय भूमि का सुधार सम्बन्धी कार्य शुरू किया गया था। इस योजना में 3 हेक्टेयर तक की जोत रखने वाले किसानों के लिये जिप्सम तथा सुधार की अन्य सामग्रियों की लागत पर 50 प्रतिशत के हिसाब से और अन्य किसानों को 25 प्रतिशत के हिसाब से राज सहायता देने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा सभी किसानों को 25 प्रतिशत राज

सहायता प्रदान होने की सम्भावना है। पांचवी योजना के दौरान, 64,000 हेक्टायर क्षेत्रीय भूमि का सुधार करने के लिये कुल 7 करोड़ रुपये का नियतन किया गया था। वर्ष 1977-78 तक कुल 28,000 हेक्टायर क्षेत्र का सुधार किया गया है। वर्ष 1978-79 के दौरान लगभग 1 लाख हेक्टायर क्षेत्र का सुधार करने का अंतिम लक्ष्य है।

(ख) जी हाँ। किन्तु इन तीनों राज्या में जिम्मेदार का उत्खनन नहीं किया जाता है, अतः राज्य की एजेंसियों द्वारा इन राज्यों में बाहर के क्षेत्रों में इसकी सफाई की व्यवस्था की जा रही है।

Urban Development and Slum Clearance Schemes in Maharashtra

4961. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) with a view to accelerate the development in the fields of Urban

Development and Slum Clearance in Maharashtra what schemes are initiated by the Central Government; and

(b) how much amount has been provided for the said schemes in Maharashtra during a period of last three years and how much amount is proposed to be provided in the year 1978-79?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Under the Central Scheme of Integrated Urban Development loan assistance to supplement resources of the State Governments is provided for implementation of selected urban development projects. There is no Central Scheme for slum clearance which is in the State Sector

(b) In Maharashtra, assistance under the Integrated Urban Development Programme has been provided to the Government of Maharashtra as follows:—

Name of City	Amount of assistance provided upto 20-3-78 (in crores)
1. Bombay & New Bombay	20.02
2. Pune	0.20
3. Nagpur	0.20
4. Sholapur	0.10
5. Kolhapur	0.20

Since the assistance is sanctioned and released on the basis of assessment of the progress and availability of funds, quantum of assistance in 1978-79 has not yet been determined.

Teaching of International Trade . in Universities

4962. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) which Universities and Management Institutes in the country are offering (1) specialised diplomas or degrees in International Trade or International Marketing; and (2) courses on International Marketing as a part of other business education courses;

(b) how many students were taught such courses during the current academic year and what was this figure at the end of the Third Five Year Plan;

(c) whether the University Grants Commission has received any proposal from the Indian Institute of Foreign Trade regarding introduction of International Trade courses in Universities at under graduate and post graduate levels and

(d) if so the action taken by the U.G.C. in this regard?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR PRATAP CHANDRA CHUNDER) (a) According to information available no University or Management Institute is offering a special degree or diploma in International Trade or International Marketing. These subjects however form part of the courses in the Departments of Commerce, Economics and Management in most Universities, and also the Institutes of Management.

(b) Information is not available.

(c) and (d) The Indian Institute of Foreign Trade made a proposal to the University Grants Commission in July, 1976 regarding reorientation of syllabi for Foreign Trade courses in different Universities. The suggestion was considered by the Commerce Panel of the Commission and on its recommendation the courses suggested by the Institute were placed for scrutiny by the Workshops on Commerce to which the representatives of the Institute were also invited. The final recommendations of the Panel are expected to be available in the next academic session.

क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल और जिल्मम का उत्पादन

13+3 श्री सुरेन्द्र झा सुमन का कृषि और सिंचाई विभाग प्रश्न उत्तरांचल प्रदेश में कि

(क) क्या वगैरे में क्षारीय भूमि बजर भूमि का कोई परीक्षण किया गया है,

(ख) यदि हा, तो ऐसी भूमि कितने एकड़ है और उसका राज्यवार व्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी भूमि का उपजाऊ बनाने में जिल्मम का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हुआ है और

(घ) भूमि उपजाऊ बनाने के लिए जितने जिल्मम के उत्पादन का आवश्यकता है और उस प्राप्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) जी हा ।

(ख) लगभग 25 लाख हैक्टर क्षेत्र की मृदा का क्षारीय मृदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है । इस मृदा का व्यापक नीचे दिया गया है —

राज्य का नाम	क्षेत्र (लाख हैक्टर)
उत्तर प्रदेश	9 0
पंजाब	4 5
हरियाणा	3 5
अन्य राज्य	8 0

(ग) जी हा ।

(घ) 25 लाख हैक्टर क्षेत्र की क्षारीय मृदा का क्रमिक रूप में सुधार करने के लिए मिट्टी का सुधार करने वाली लगभग 125-150 लाख मीटरी टन सामग्री की आवश्यकता होगी । वर्ष 1978-79 के दौरान लगभग 1 लाख हैक्टर क्षेत्र को क्षारीय मृदा का सुधार करने का प्रस्ताव है । राज्य सरकारों का इस बात के लिए प्रेरित करके मल्टी सुनिश्चित की जा रही है कि वे अपनी आवश्यकताएँ सरकारी को समय से पहले ही बता दें ।

सरकारी क्वार्टर अलॉट करने संबंधी नियम

4364. श्री नबाब सिंह चौहान :
मया निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन से वर्ष के लिए टाइप दो, तीन और चार के क्वार्टर अलॉट किए जा रहे हैं ,

(ख) करणामूलक कारणों के आधार पर क्वार्टर अलॉट करने संबंधी नियम क्या हैं , और

(ग) बिना बारी के हॉस्टल आवास किस प्रकार आवंटित किया जाता है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वासि मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :

(क) 1. टाइप II	1955
2. टाइप III	1954
3. टाइप IV	1953

(ख) और (ग). अनुकम्पा के आधार पर आवंटन करने के बारे में कोई विशिष्ट नियम नहीं है । प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है । तथापि, वर्तमान नियमों के अधीन, आवंटनी की सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण अथवा आवंटनी की मृत्यु पर उस के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर तदर्थ आवंटन करने की व्यवस्था है । उपरोक्त तथा कैम्प जैसी गंधीर बीमारियों में चिकित्सा के आधार पर और अगम व्यक्तियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर तदर्थ आवंटन किए जाते हैं ।

Additional Emoluments to Electricity wing Employees of N.D.M.C.

4365. SHRI RAJ KESHAR SINGH: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5910 on the 3rd August, 1977 regarding additional emoluments to Electricity Wing employees of N.D.M.C. and State:

(a) whether the information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time by which the same will be laid on the Table of the House?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHAT): (a) to (c). The statement containing the required information in fulfilment of the assurance was laid on the Table of the House on 23rd February, 1978, a copy of which is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1929/78].

Requirement and Supply of Fertilizers to Madhya Pradesh

4366. SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) what was the total fertiliser requirement of the State of Madhya Pradesh during the last three years;

(b) how much quantity of fertilizer was supplied to the State in the same period; and

(c) is it not a fact that much less quantity of phosphate and sulphate were supplied to the State?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a)
The total net agronomic requirements of fertilizers of each State are assessed before each cropping season on the basis of the projected area

under various crops and an assumed percentage increase in the consumption. The requirements of fertilizers of Madhya Pradesh estimated before the cropping seasons on this basis work out to following figures during the last three years

(In lakh tonnes)

Year	N	P	K	Total
1975-76	1.50	0.64	0.40	2.54
1976-77	0.98	0.35	0.92	1.35
1977-78	0.95	0.41	0.00	1.40

(b) The entire requirements indicated above were allocated to the State partly from domestic production and partly from imports. Against

this allocation, the actual consumption of fertilizers by the State during these years was as under —

(In lakh tonnes)

Year	N	P	K	Total
1975-76	0.77	0.30	0.66	1.13
1976-77	0.91	0.39	0.07	1.37
1977-78 (Estimated)	0.93	0.44	0.00	1.46

(c) Yes, Sir

स्त्रियों का श्रमनैतिक व्यापार

4367. श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार को पता है कि स्त्रियों के श्रमनैतिक व्यापार को रोकने के लिए वर्ष 1956 में बनाया गया कानून प्रभावी नहीं सिद्ध हुआ है और यह व्यापार अभी भी देश में चल रहा है तथा यह व्यापार एक विशेष गली तक सीमित न हो कर फ्लैटो तथा बंगलो में चला गया है ,

(ख) यदि हा तो क्या सरकार का विचार उक्त कानून में संशोधन करने का है ताकि इस काले व्यापार को समाप्त किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) (क) और (ख) व्यक्तियों में व्यापार तथा दूसरी की बेव्यावृत्ति के शोषण से सम्बंधित

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सिफारिशों के अनुसरण में संसद द्वारा सिमेंट और लड़कियों में प्रौद्योगिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया गया था। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे सिमेंट और लड़कियों में प्रौद्योगिक व्यापार दमन अधिनियम को अधिक प्रबल रूप में लागू किया जाना सुनिश्चित करे। कानून को अधिक कारगर बनाने के लिए अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किए जाने के लिए एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**Loss suffered by Administrative staff
College of Hyderabad**

4368 SHRI DINEN BHATTACHARYA:

DR. SARADISH ROY:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the Administrative Staff College of India, Hyderabad is running in loss of over Rs. 9 lakhs even after receiving huge grants from the Ford Foundation during the years 1972 to 1977 amounting over Rs. 22 lakhs and grants received from the Central Government of about Rs. 30 lakhs during the same period,

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

वर्ष 1977-78 में चीनी मिलों की विकास के लिए बिये गये ऋण

4369. श्री रामधारी शास्त्री : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में 31 जनवरी, 1978 तक किन-किन चीनी मिलों को विकास एवं वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा ऋण दिया गया :

(ख) उन में से कितनी-कितनी चीनी मिलें सार्वजनिक, सहकारी और नियमित क्षेत्रों की हैं, और

(ग) क्या यह सच है कि प्राइवेट चीनी मिलों की तुलना में उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित चीनी मिलों को कम ऋण दिया गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय वित्त संस्थानों द्वारा जिन मिलों के लिए ऋण मंजूर किया गया है मंजूर करना मान लिया गया है, का विवरण संलग्न है।

(ख) 3 चीनी मिलें सार्वजनिक क्षेत्र में, 13 चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में और 9 चीनी मिलें निजी क्षेत्र में।

(ग) निजी चीनी मिलों के लिए कुल ऋण का केवल लगभग 33 प्रतिशत ऋण मंजूर किया गया है, जबकि शेष 67 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र की मिलों के लिए मंजूर किया गया है।

विवरण

पहली छत्रल, 1977 से 31 जनवरी, 1978 की अवधि के दौरान आई०एफ०सी०आई०, आई०डी०बी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई०, यू०टी०आई० एल०आई०सी० आदि जैसे केन्द्रीय वित्त सस्थानों ने जिन चीनी मिलों को ऋण मंजूर किए गए हैं और अथवा मंजूरी देने की सहमति प्रकट किए हैं, की सूची बताने वाला विवरण ।

क्रम मिल का नाम तथा राज्य
मख्या जिन म प्रोजेक्ट स्थित है

सरकारी क्षेत्र

- 1 तमिलनाडु गगन कार गेशन लि० जिना थन्जबूर (तमिलनाडु)
- 2 नदगज मिहारी शुगर कम्पना लि० जिला राय बरेली (उत्तर प्रदेश)
- 3 गगानगर शहर मिल्स लि० श्री गगानगर (राजस्थान)

सहकारी क्षेत्र

- 4 श्री सयान विभाग एम० क० यू० एम० लि०, जिला सूरत (गुजरात)
- 5 कल्लाकुरोची कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि० जिला माउथ ब्रकट (तमिलनाडु)
- 6 जय भवानी एस० म० के० लि०, जिला भीर (महाराष्ट्र)

सहकारी मिल के नाम तथा राज्य जिन क्षेत्र में प्रोजेक्ट स्थित हैं

- 7 श्री तालावा तालुका एस० के० यू० एम० लि०, जिला जूनागढ, (गुजरात)
- 8 बलसाद एस० के० यू० एम० लि०, जिला बलसाद (गुजरात)
- 9 रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि० जिला मेरठ (उ० प्र०)
- 10 श्री राम एस० एस० के० लि०, जिला मैसूर (कर्नाट)
- 11 चुडावरम कोआपरेटिव शुगर लि०, जिला विशाखापटनम (आन्ध्र प्रदेश)
- 12 मधुकर एम० एम० क० लि० जिला जलगाव (महाराष्ट्र)
- 13 यशबन्न एस० एम० के० लि०, जिला शोलापुर (महाराष्ट्र)
- 14 नेशनल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि० जिला मधुराई (तमिलनाडु)
- 15 इतिकाप्याका कोआपरेटिव एग्री० एण्ड इड० सोसायटी लि० जिला विशाखापटनम (आ० प्र०)
- 16 शंकर एस० एस० के० लि०, जिला शोलापुर (महाराष्ट्र)

सहकारी मिल के नाम तथा राज्य जिन
क्षेत्र में प्रोजेक्ट स्थित है

ग्राहबैंड निगम क्षेत्र

17. दिल्ली कलाथ गण्ड जनरल मिल
कम्पनी लि०, जिला मेरठ
(उ० प्र०)
18. ई० आई० डी० पैरी लि०, जिला
माउथ ब्रकट (तमिलनाडु)
19. गंगेश्वर लि०, जिला सहारनपुर
(उ० प्र०)
20. मार्दी इंडस्ट्रीज लि०, जिला
गाजियाबाद (उ० प्र०)
21. बनरामपुर चीनी मिल्स लि०,
जिला गाडा (उ० प्र०)
22. तुलसीपुर शुगर कम्पनी लि०,
जिला गोंडा (उ० प्र०)
23. गहन गन्ना इंडस्ट्रीज लि० जिला
दरभंगा (उ० प्र०)
24. बलसूद शुगर कम्पनी लि०,
जिला सीतामढ़ी (बिहार)
25. मोतीलाल पद्मपत उद्योग लि०,
जिला पश्चिमी बंगाल
(बिहार)

Provision of Drinking water in the States

4370 Shri C. K. CHANDRAPAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) how many States have not used the interest free loans sanctioned by the Central Government to implement drinking water schemes in rural areas in the States, names and details thereof;

(b) how many States have drinking water facilities at present; and

(c) how many villages and rural areas Government are going to cover with the drinking water facilities during the Sixth Five Year Plan?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) No interest-free loan is given by the Central Government for the implementation of drinking water supply schemes by the States. However, the Central Government has given 100 per cent grant assistance to the States for provision of drinking water to problem villages under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme launched during the current financial year. No State Government has expressed its inability to utilise the grant-in-aid released to them.

(b) If it is meant as to how many villages in the States have drinking water facilities at present, then the answer is that safe drinking water is available in 64,000 villages in the country as on 31st March, 1977.

(c) This will be known only after the next Five Year Plan has been finalised.

गत तीन वर्षों के दौरान कितरित भूमि

4371. श्री लालजी भाई :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्यवार कितनी कितनी भूमि भूमिहीन व्यक्तियों का आवागंत की गई है, और

(ख) उन में से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों से हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1975, 1976 और

1977 में जात की अधिकतम सीमा से फालतू हुई भूमि का कुल 17 30,326 एकड़ क्षेत्र का वितरण किया गया था। इसका राज्यवार व्योरा विवरण-1 में दिया गया है। ये अनुमानित आंकड़े हैं क्योंकि मुख्य रूप से कुछ राज्य-सरकारों ने जा जानकारी भेजा है वह विभिन्न अवधियों के सम्बन्ध में है।

इस के अनिश्चित, वर्ष 1976-77 के दौरान राज्य सरकारों ने 21,11,995 एकड़ परती भूमि का वितरण किया था। राज्यवार विवरण -II में दिया गया है। भारत सरकार के पास पहले वितरित किए गए क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जात की अधिकतम सीमा से सशोधन बानूना क अतगत अब तक अनुसूचित जातियों के 3,70,283 व्यक्ति तथा और अनुसूचित जनजातियों के 1,16,727 व्यक्तियों का जात की अधिकतम सीमा से फालतू हुई भूमि का आवंटन किया गया है। कुल लाभानुभागियों की संख्या 9,37,566 है। वर्ष 1975-77 के दौरान उन समुदायों के जितने व्यक्तियों का भूमि अनाट की गई उन की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है परन्तु जोत की अधिकतम सीमा के सशोधन बानूना क अतगत 1975 में पहले वितरित किया गया क्षेत्र ज्यादा बड़ा नहीं था अतः 1975 तक लाभानुभागियों की संख्या भी बहुत कम होगी। जोत की अधिकतम सीमा से सशोधन अतगत में पूर्व के जानना और परती भूमि के वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम के अतगत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनाटियों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण—I

अधिकतम सीमा से फालतू हुई भूमि का राज्यवार वितरण

राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	वितरित क्षेत्र (एकड़ में)
आन्ध्र प्रदेश	1 59,920
असम	4 06 521
बिहार	1 25,978
गुजरात	6,709
हरियाणा	21 648
हिमाचल प्रदेश	4,143
जम्मू और कश्मीर	
कर्नाटक	15,674
केरल	38,600
मध्य प्रदेश	41,261
महाराष्ट्र	28 1 990
मणिपुर	
उड़ीसा	9 1,200
पंजाब	14 700
राजस्थान	2 67,724
तमिलनाडु	14,141
त्रिपुरा	215
उत्तर प्रदेश	1 47,832
पश्चिमी बंगाल	1 49 207
दावर और नगर हवेली	2,202
दिल्ली	101
पाण्डिचेरी	6 60
कुल	17 30 326

विवरण—II

राज्यवार परती भूमि का वितरण

राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	वितरित क्षेत्र (एकड़ में)
आन्ध्र प्रदेश	18 6,884
असम	उ० न०
बिहार	उ० न०
गुजरात	1,327
हरियाणा	240

राज्यवार परती भूमि का वितरण वितरित क्षेत्र
राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम एकड़ में

जम्मू और कश्मीर	—
कर्नाटक	30 न०
केरल	24,257
मध्य प्रदेश	30 न०
महाराष्ट्र	1,24,500
मणिपुर	18,770
उड़ीसा	31,421
पंजाब	30 न०
राजस्थान	7,00,919
तमिलनाडु	39,065
बिहारी	18,386
उत्तर प्रदेश	8,66,081
पश्चिम बंगाल	36,929
बादर और नागर हवेली	कुछ नहीं
दिल्ली	1,992
गोवा, दमन और दीव	1,905
प्रायद्वीप	कुछ नहीं
कुल	21,11,995

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

4372. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या
निर्माण और आवास तथा पूर्ति और
पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
कि :

(5) अब तक आवंटित किए गए दिल्ली
विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की श्रेणीवार
सख्या क्या है ,

(ख) इस समय रजिस्टर्ड व्यक्तियों
की श्रेणीवार सख्या कितनी है जिन्हें
अभी तक फ्लैट आवंटित नहीं किए गए हैं
और तत्सम्बन्धी पूरा व्यौरा क्या है ,
और

(ग) निकट भविष्य में दिल्ली विकास
प्राधिकरण के श्रेणीवार कितने फ्लैट
पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित किए
जाने का प्रस्ताव है और इन्हें कब तक
आवंटित कर दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बल्ल) :

(क) मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता/सी० एस० पी	योग
11493	12456	8848	32787
(ख) 9599	8829	6311	24739

(ग) मध्यम आय वर्ग के 366, निम्न
आय वर्ग के 268 2 और जनता/सी० एस०
पी० के 1108 फ्लैट लगभग पूर्ण होने वाले

हैं और निकट भविष्य में आवंटित करने
का प्रस्ताव है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के जनता और सी०एस०पी० क्वार्टरों का भूमि कर माफ करना

4373. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बेचे गए जनता और सी०एस०पी० क्वार्टरों का भूमि कर माफ करने का है; और

(ख) यदि हा, तो इस संबंध में सरकार अनिम निम्न कब तक कर लेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बल्ल) :
(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि जनता और सी०एस०पी० क्वार्टरों पर जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बेचे गए हैं, कोई भूमि कर एकत्र नहीं किया जा रहा है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण वार्षिक भूमि कराया वसूल करती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Views of USSR Scientists about Inferiority of Indian Wheat

4374 SHRI SARAT KAR:

SHRI MUKHTIAR SINGH
MALIK:

SHRI MOHINDER SINGH
SAYIANWALA:

SHRI G. M. BANATWALLA:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Soviet Scientists, attending the World Wheat Symposium in New Delhi stated that Indian wheat is definitely inferior to the Soviet wheat in quality;

(b) whether it is not a fact that the quality of our wheat is the highest in the World; and

(c) if so, the details regarding the report of this symposium and whether any remedy has also been found regarding the rust diseases which are generally found as a major threat to the wheat crop?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) A report entitled "Indian wheat inferior to that of Russia" appeared in some newspapers. It was reported to be based on a statement by Academician N V Turbin and Dr M. A. Fedin. In a letter addressed to the ICAR these two Soviet Scientists have stated as follows:—

1. "We have innumarated in the interview some Soviet varieties of winter and spring wheat which possess a very high cooking quality of grain. It does not mean, and we have never said it, that these varieties are the best in the world, because the certain variety can be considered the best only under certain environmental conditions.

2. We have not given a negative estimate to the Indian Wheat varieties, as it can be soon from the above-mentioned headline. In fact, semi-dwarf varieties of spring wheat developed in India represent significant achievements of our colleagues—Indian plant breeders."

(b) The quality of wheat is influenced by variety, location as well as by various agronomic practices including the use of chemical fertilizers. It has to be related to the manner which the grain is used. Indian wheats have excellent chapathi making quality. For automatized

bread making, the wheat variety should have very strong gluten and the varieties in North America, USSR and Western Europe are usually selected for this purpose. In nutritive qualities, several of our wheats are as good as those cultivated elsewhere.

(c) They symposium death in great length on quality aspects relating to high protein and high lysine content and a number of desirable characters like resistance to disease for improving our wheat crop. Use of multi-lines of commercial varieties of wheat like Kalyan Sona, Sonalika etc. in reducing the rust epidemics in the country for stabilizing production of wheat was discussed. A few multi-lines have already been developed by the Indian Wheat Scientists which are expected to play an important role in reducing the hazards of rust epidemics in India. It was further emphasized that the high yield potential of the wheat varieties should also be protected by incorporating genes for disease resistance from species allied to wheat to the commercially cultivated common wheats.

Revaluation of Housing Site at Chittaranjan Park

4375 SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the housing site at Chittaranjan Park in New Delhi which was allotted by Government to the displaced persons of East Pakistan (now Bangladesh) was purchased by these people at the Government's rate;

(b) whether Government have sent Reserve Bank challans to the people of Chittaranjan Park to pay more money for the site as Government has revalued the lands at Chittaranjan Park;

(c) if so, the reasons and details thereof;

(d) whether Government are aware that this has been resented to by all sections of the people in Chittaranjan Park;

(e) if so, what is Government's reaction on it; and

(f) reasons why this revaluation of the land at Chittaranjan Park was taken?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) to (c): Plots were allotted in Chittaranjan Park to eligible Displaced Persons from former East Pakistan (now Bangladesh) at a provisional premium of Rs. 30/- per square yard, representing Rs. 12/- as the cost of acquisition of land and Rs. 18/- as cost of development. The allottees were liable to pay the difference between the premium as finally determined and the provisional premium. The premium has been finally determined at Rs. 36.20 per square yard, representing Rs. 12/- per square yard of plotted area for cost of acquisition and Rs. 24.20 per square yard of plotted area for cost of development. Accordingly Reserve Bank challans were sent to the allottees requesting them to pay the difference.

(d) and (e): Government have received representations in this regard. The question regarding cost of acquisition of land is being further looked into.

(f) The position is explained in the reply against (a), (b) and (c) above.

कोसी परियोजना के कार्यान्वयन के कारण विस्थापित हुए व्यक्ति

4376. श्री बिनायक प्रसाद यादव : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कोसी परियोजना के कार्यान्वयन से लगभग 5 से 6 लाख व्यक्ति विस्थापित हो गये हैं यानी उजड़ गये हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए अभी तक कोई कार्रवाई और ठोस कार्रवाई नहीं की गई है

(ग) यदि उपरोक्त (क) और (ख) का उत्तर हाँ में है तो इस सबंध में सरकार कब तक व्यवस्था कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कोसी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों के कारण 301 गांवों में लगभग 2,58,000 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं ।

(ख) और (ग) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि बिहार सरकार द्वारा 1957-58 में तैयार की गई पुनर्वास स्कीम में आवास गृहों की अधिक सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की लेफ्टिन लोगों को अपनी आजीविका के पुराने साधनों को अपनाये रखने की अनुमति देने की परिकल्पना की गई थी । जिस प्रकार कोसी परियोजना के निर्माण से पहले दोनों तटबंधों के बीच की जमीन पर खेती की जाती थी उसी प्रकार अब भी खेती किए जाने की छूट है । परियोजना अनुमानों में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 2 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी इसमें न लगभग 1 78 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है । 1 13 करोड़ रुपये मकानों के

निर्माण के लिए अनुदान देने पर और 0 65 करोड़ रुपये सड़को, तालाबों, कुओं, सामुदायिक केन्द्रों, स्कूलों और मन्दिरों आदि जैसी सुविधाओं पर । इन लोगों के पुनर्वास के लिए तटबंधों के बाहर 3,060 एकड़ भूमि प्राप्त की गई है जिसमें 1278 एकड़ में भूमि आवंटित की जा चुकी है । अब तक 3,759 परिवारों को मकान बनाने के लिए श्रृणु दिए जा चुके हैं ।

हेलीकाप्टरों से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव

4377. श्री बयाराम शाक्य : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) कीटनाशक दवाइया छिड़कन के लिये किन-किन राज्यों में हेलीकाप्टरों का उपयोग किया गया तथा जेष्ठ राज्यों में छिड़काव करने के लिये सरकार ने क्या तरीके अपनाए हैं और

(ख) क्या सरकार ने कीटनाशक दवाइया के छिड़काव के लिये बिमानों के अन्य साधन उपलब्ध कराने के लिये भी कोई उपाय किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान पंजाब हरियाणा, राजस्थान गुजरात आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र केरल, कर्नाटक तथा गोवा राज्यों में कीटनाशी दवाइया के हवाई छिड़काव करने के लिये हेलीकाप्टरों का प्रयोग किया गया था । जेष्ठ राज्यों अर्थात् उड़ीसा मणिपुर तथा उत्तर प्रदेश में (जहां हवाई छिड़काव किया गया था) हवाई छिड़काव हुआ था, फिफ्ट विंग के जहाजों का काम में लाया गया था । पंजाब हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक

में भी फिक्स्ड विंग के वायुयानों को काम में लाया गया था। कीटों तथा रोगों का नियंत्रण करने के लिए भूमि में भी कीटनाशी दवाओं का छिड़काव किया जाता है। यह पद्धति लगभग सभी राज्यों में अपनाई जा रही है।

(ख) भारत सरकार के पास फिक्स्ड विंग के वायुयानों तथा कुछ हेलीकाप्टरों का एक काफी बड़ा बेड़ा मौजूद है। सरकार इसे मजबूत बनाने की सम्भावना की जांच कर रही है।

निरक्षरता को दूर करने के लिये केन्द्रीय अनुदान

4378. श्री हय्याराम शक्य : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बनाने की उपाय करेंगे कि।

(क) देश में निरक्षरता का दूर करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा राज्यवार कितनी प्रौढ पाठशालाएँ चलाई जा रही हैं, और

(ख) क्या एम याजना का बढ़ावा देने के लिए कार्ट अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान दिया गया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) देश के सभी भागों में प्रौढ शिक्षा केन्द्र बड़ी संख्या में चलाये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार किसान कार्यात्मक माधुरता तथा 15-35 आयु वर्ग के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की योजनाओं के अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा केन्द्रों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ आसित क्षेत्रों के प्रशासकों का 100 प्रतिशत अनुदान

प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की प्रौढ शिक्षा परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

समाज कल्याण विभाग और विदेशों से अनुदान प्राप्त करने वाली सामाजिक संस्थाएं

4379. श्री हय्याराम शक्य : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बनाने की उपाय करेंगे कि।

(क) देश के अन्दर ऐसी कितनी सामाजिक संस्थाएँ हैं जिनको मन्त्रालय के समाज कल्याण विभाग में तथा विदेशों से अनुदान मिलता है, ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में उनको प्राप्त वित्तीय सहायता का व्यौरा क्या है, और

(ख) क्या केन्द्र सरकार इन संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनुदान में से किये गये खर्च की लेखा-परीक्षा कराती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) अर्पेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

Slum Clearance and Slum Improvement Programmes

4380 PROF P G MAVALANKAR: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government have intensified and/or accelerated the programmes of slum improvement and slum clearance in all major urban

agglomerations in the country during the last three years—1975, 1976 and 1977,

(b) if so, broad details thereof including moneys spent directly by the Government and Central Financial assistance given to one or more States and

(c) whether Government have taken any new and imaginative steps at solving this vexed problem and

(d) if so main indication thereto?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHAT) (a) to (d) The Schemes of Slum Clearance/Improvement and Environmental Improvement in Slum Areas are in the State sector with effect from 1st April 1969 and 1st April 1974 respectively. No direct financial assistance is provided by the Central Government for these schemes after their transfer to the State sector. During the 5th Plan period, the scope of the Scheme for Environmental Improvement in Slum Areas was extended to cover cities with a population of three lakhs and above.

Agricultural Universities in Union Territory

4361 **PROF P G MAVALANKAR** Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether Government propose to establish one or more Agricultural Universities in one or more Union Territories in the foreseeable future,

(b) if so broad indication thereto, and

(c) if not reasons for not doing so?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) No, Sir

(b) Does not arise

(c) The Government had decided to establish one Agricultural University in each State as per the recommendations of the Education Commission. This goal has been achieved (except in the case of J & K) by establishing 21 Agricultural Universities in 16 major States in the country. The establishment of Agricultural Universities is a costly venture and the requirements of trained manpower in Agriculture in Union Territories are too small to justify a full-fledged Agricultural University in any of them.

Minor Irrigation Target in Andhra Pradesh

4382 **SHRI G S REDDI** Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether minor irrigation target in Andhra Pradesh for 1977-78 will be reached,

(b) if so, details thereof, and

(c) if not whether this is due to inadequate allocation of Central funds to the State for minor irrigation?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) Yes, Sir

(b) The target set for creating additional irrigation potential during 1977-78 from minor irrigation schemes including surface water flow/lift irrigation schemes and ground water schemes (including public tubewells) was for 47 thousand hectares. During the discussions held with the State representatives on 9th January, 1978 to

discuss the Annual Plan proposals for 1978-79, it was ascertained that this target will be fully achieved.

(c) Does not arise in view of (a) and (b) above.

Housing Schemes by HUDCO

4383. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) the State-wise details of the 19 Housing schemes at a cost of Rs 42.22 crores approved recently by the Housing and Urban Development Corporation,

(b) the total, on date of financial commitment of HUDCO to the housing schemes in the States; and

(c) the amount of loan that has so far been given to the States (State-wise) for housing schemes?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) During the period from 16th November 1977 to the 10th February, 1978 HUDCO had sanctioned 59 and not 19 Schemes, costing Rs 42.22 crores. These Schemes involve construction of 19,306 Dwelling Units, 701 Non-residential buildings and development of 2,114 plots. State-wise details are shown in the Statement-I attached

(b) and (c). The total loan commitment of HUDCO, as on 15th March 1978, was Rs 309.23 crores involving 726 Schemes. State-wise details, including the loan assistance involved and the loan assistance so far released, are shown in the Statement-II attached.

Statement I

Details of 59 Schemes sanctioned by HUDCO (During the period 16th November, 1977 to 10th Feb., 1978)

State	No. of Schemes	Project Cost	Loan sanctioned
			(Rs in Crores)
Andhra Pradesh	1	0.090	0.50
Assam	1	0.816	0.595
Bihar	2	8.759	5.911
Gujarat	9	1.319	0.962
Haryana	2	2.115	1.579
Karnataka	6	2.582	1.824
Madhya Pradesh	1	0.142	0.123
Maharashtra	5	7.182	1.181
Punjab	1	1.171	0.760
Rajasthan	3	2.117	1.175
Tamil Nadu	12	1.091	635
Uttar Pradesh	15	8.911	6.686
West Bengal	1	2.733	840
13 States	59	42.215	28.671

Statement II

State-wise details of the Schemes sanctioned by HUDCO and the assistance released therefor as on 15th March, 1978

States/ Union Territories	No. of Schemes	Loan sanctioned (Rs. crores)	Loan amount released (Rs. in crores)
Andhra Pradesh	42	14.993	5.10
Assam	1	0.595	..
Bihar	15	14.075	2.07
Gujarat	102	31.556	18.70
Haryana	47	19.997	10.85
Himachal Pradesh	12	1.455	1.10
Jammu & Kashmir	4	4.186	1.05
Karnataka	47	21.953	9.88
Kerala	23	9.677	3.87
Madhya Pradesh	55	18.973	14.57
Maharashtra	43	29.505	13.79
Orissa	14	4.938	1.97
Punjab	22	10.447	6.27
Rajasthan	52	21.397	14.62
Tamil Nadu	130	36.258	20.14
Uttar Pradesh	80	38.600	22.46
West Bengal	20	14.165	4.84
Union Territories :			
Chandigarh	5	3.433	0.91
Delhi	9	12.748	10.62
Goa, Daman & Diu	2	0.106	1.10
Pondicherry	1	0.174	..
TOTAL	726	309.231	162.91

Use of Sea Water for Agricultural purposes

4384. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA. Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether his Ministry have conducted any experimental survey in the use of sea water for agricultural purposes;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the comparative cost in the use of sea water and other normal water resources?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The Indian Council of Agricultural Research under the Ministry of Agriculture and Irrigation had sanctioned one of the centres of the All India Coordinated Project on Use of Saline Water for Agriculture at the Central Plantation Crops Research Institute, Kasargod (Kerala) where experiments have been conducted to examine the effect of sea water irrigation in varied dilutions on coconut. Subsequently an *ad hoc* scheme on the use of sea water for irrigation has been sanctioned by the ICAR for implementation at this Institute

In addition to this work on use of sea water for irrigation has also been conducted by the Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar, which is functioning under the Council of Scientific and Industrial Research.

(b) The sea water contains more than 3 per cent of salt and this much concentration of salt is harmful nearly to all the agricultural crops. Sea water could be used only if some fresh water for dilution is available. However, the experimental results so far available are as under:

Under the All India Coordinated Project for Research on Use of Saline Water for Agriculture work has been

conducted at the Central Plantation Crops Research Institute, Kasargod (Kerala). Different dilutions of sea water with good quality water were tried for irrigation with Coconut Palms.

It has been observed that the use of sea water alone increased the salinity level of the soil, but its effect was comparatively reduced as the proportion of good quality water to sea water was increased.

At the Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar under the CSIR work has been in progress to evaluate the varieties of cereals, pulses, oilseeds, millets and forage crops for their tolerance to diluted sea water. It has been observed that at germination stage, these crops are more sensitive. But once if good germination can be started with application of good quality of water, the cereal crops could tolerate upto 10000 ppm of salt in water nearly i.e., 1/3rd of the concentration of salt in sea water.

In case of Wheat Kharchia variety has been observed to be more tolerant to diluted sea water irrigation. In case of Tapioca varieties H-99 and H-266 were found to be tolerant to diluted sea water of 15000 ppm.

(c) No specific work has been done on this aspect.

Appointment of Administrator to manage the affairs of Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society

4385. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA. Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the High Court of Delhi in the interim order in Civil Writ No. 581/77 had directed the Registrar, Cooperative Societies, Delhi to appoint an Admi-

nistrator to manage the affairs of Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society,

(b) if so, the contents and date of the above orders,

(c) the action taken so far by the Delhi Administration to implement the above orders of the Delhi High Court,

(d) the reasons for delay on the part of Delhi Administration in implementing those orders

(e) the action taken or proposed to be taken against those responsible for deliberate delay in the matter, and

(f) the latest position of Civil Writ No 581/77 and No 659/77 relating to the above Society filed in the High Court of Delhi?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) No, Sir

(b) to (e) Do not arise

(f) Civil Writ No 659/77 is fixed for hearing on 3rd April 1978. No date has been fixed for hearing Civil Writ No 581/77

Memorandum Submitted by the Members of the Delhi School Teachers Co-operative House Building Society, Delhi

4386 SHRI RAM NARESH KUSHWAHA Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) the points raised in the memorandum submitted by some Members of the Delhi School Teachers' Co-operative House Buildings Society Delhi before the Lt Governor of Delhi in this public Durbar on 25th May 1977 and action taken so far or proposed to be taken thereon,

(b) full particulars of those persons whose names did not appear in the list of 1489 Members who filed affidavits before the Registrar in 1974 which was placed on the Table of Rajya Sabha in 1975, but who have now been included in the Membership list released by the Society on 31st August, 1977 alongwith the reasons for a such inclusion in each case and

(c) the relevant provisions of law under which the Membership of a House Building Society can be transferred, the date on which Membership of a transferee becomes effective and the number of transfer cases in the Membership of the above Society?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) to (c) Information is being collected

डाल्टेनगज, बिहार स्थित भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ की सप्लाई

4387 श्री राम बेनी राम क्या कृपि और सिबाई मंत्री यह बतान की कृपा करेगे कि

(क) क्या उनका ध्यान कुछ समाचार पत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि डाल्टेनगज (बिहार) स्थित भारतीय खाद्य निगम की लापरवाही के कारण निगम व जिला भंडार में 60 हजार विबटन गेहूँ का स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो घुना खोखला और मिट्टी भरा है तथा इसके बदले खाने योग्य गेहूँ भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं भेजा गया है

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि लापरवाही के कारण दिसम्बर, 1977 और जनवरी, 1978 के दौरान उपभोक्ताओं

को गेहूँ और चावल निर्धारित मात्रा से बहुत कम दिया गया था और छात्रों के अभाव में वहाँ उपभोक्ताओं में असन्तोष है, और

(ग) क्या 24 फरवरी, 1978 को डाल्टेनगज रेसर्वे स्टेशन पर भारतीय म्हाछ निगम द्वारा उपभोक्ताओं के लिए जो गेहूँ भेजा गया था उसमें केवल दो बैगन गेहूँ ठीक था जबकि शेष घुना हुआ था, और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह). (क) में (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और ममा के पटल पर रख दी जाएगी।

Closure of Sardar Vallabhbhai Patel Regional College of Engineering and Technology

4388. SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to some epidemical disease Sardar Vallabhbhai Patel Regional College of Engineering and Technology, Surat has been closed for fifteen days;

(b) if so, the nature of the disease; and

(c) whether any deaths of students have also occurred?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). The students of Sardar Vallabhbhai Patel Regional College of Engineering and Technology, Surat, started becoming sick from the second week of February 1978 onwards, most of them getting high fever. The Institute's Doctor

who was treating most of the student patients, identified the cause to virus infection of the nature of influenza. The College, therefore, was closed for two weeks from 27th February, 1978 to 12th March, 1978 and re-opened from 13th March, 1978. The College is running in a normal way.

(c) A student of First year viz., Shri Krishna Kumar, was admitted in Sir P. T. General Hospital, Surat on 1st February, 1978. He was having fever and later on started bleeding. The student died on 5th February, 1978 when his parents were by his side. This student was not keeping well earlier also.

राज्यों में आवास सुविधाएँ

4389. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में आवास सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त राज्यों को वर्ष 1977-78 और 1978-79 में राज्यवार कितनी सहायता दी जा नी है, और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं और उन स्थानों पर, जहाँ पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की भारी संख्या है आवास सुविधाएँ उपलब्ध करने की प्रस्तावित योजनाएँ क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) बागान कर्मचारियों की सहायता प्राप्त आवास योजना के अलावा इस मंत्रालय द्वारा बनाई गई सभी सामाजिक

आवास योजनाएँ राज्य क्षेत्र में हैं। आवास तथा नगर विकास निगम केन्द्रीय सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मकानों के लिए आवास अभिकरणों को वित्तीय सहायता देते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम भी आवास के लिए राज्य सरकारों और एपेक्स कोऑपरेटिव हाउस फाइनेन्स सोसायटियों को वित्तीय सहायता देता है।

(ख) सभी राज्य क्षेत्र प्लान योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता जिस में आवास भी शामिल है, राज्य सरकारों को उनकी किसी विशेष योजना या विकास क्षेत्र से सम्बद्ध हुए बिना 'समेकित ऋण' और 'समेकित' अनुदानों के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार, आवास सहित, विभिन्न राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए निधियों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

वर्ष 1977-78 के लिए सभी राज्यों। सब राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिये अनुमोदित प्लान परिषदों 133 20 कराड़ रुपये हैं। इस के अलावा राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए 19 50 कराड़ रुपये की राशि जीवन बीमा निगम ऋण के रूप में नियत की गई है। 1978-79 के लिए प्रस्तावित प्लान परिषदों 137 22 कराड़ रुपये हैं।

(ग) जहाँ केन्द्रीय सरकारों कार्यालय स्थित है वहाँ इस मंत्रालय ने बहुत से स्थानों में केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल के रिहायशी मकानों की व्यवस्था की है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का और रिहायशी मकान देने की बात का ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि मकानों के

निर्माण का एक त्वरित कार्यक्रम हाथ में लिया जाए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए गए फ्लैट

4390. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बातें बताने को कृपاً करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शीतक श्रेणीवार कितने फ्लैट निर्मित किए गए हैं,

(ख) विभिन्न नामों में बेंचे गए अथवा पञ्जीकृत किए गए फ्लैटों की श्रेणीवार संख्या क्या है, और

(ग) आगामी दो वर्षों में इस प्रकार के कितने और फ्लैट निर्मित किये जानका प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बल्ल)

मध्यम निम्न जनता/
श्राय श्राय सी० योग
वर्ग वर्ग एस०पी०

(क) 11547 12499 8961 33007

(ख) 11483 12456 8848 32787

(ग) 16,669 फ्लैट निर्माणाधीन है। दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रत्येक वर्ष 10,000 फ्लैटों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

कालकाजी में प्लाट

4391. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रो यह मतों को कृपा करेंगे :

(क) क्या वर्ष 1973 में पुनर्वास विभाग ने कुछ प्लाटों की कालकाजी (दिल्ली) में नीलामी की थी;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को आवश्यक धनराशि जमा करने पर प्लाट आवंटित किये गये तथा उन के कब्जे दिये गये ; और

(ग) कितने लोगों को अभी भी प्लाट आवंटित किये जाने बाकी हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग). जी, हां। वर्ष 1973 में "जैसा है जहाँ है के आधार पर" कालकाजी कालोनी में 50 प्लाटों की नीलामी की गई थी। एक प्लाट की बोली अस्वीकार कर दी गई थी। अन्य 49 मामलों में बोली स्वीकार कर ली गई और विक्रय मूल्य की वसूली के पश्चात्, 48 मामलों में पट्टे नामे जारी कर दिए गए थे। शेष एक मामले में खरीददार ने अभ्यावेदन दिया कि उसे बेचा गया प्लाट तीन तरफ से खुलता है न कि दो तरफ से। यह दावा उचित नहीं पाया गया। फिर भी, उसी कालोनी में उसे वैकल्पिक प्लाटों की पेशकश की गई थी परन्तु उस ने स्वीकार नहीं किया। विधिसम्पत्त सलाह लेने के पश्चात्, विक्रय को रद्द कर दिया गया और खरीददार को विक्रय मूल्य वापस लेने की पेशकश की गई थी परन्तु अब तक उस ने यह राशि वापस नहीं ली है।

बाढ़ नियंत्रण के लिये सहायता

4392. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : ख्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में और वर्ष 1977 के अन्त तक विभिन्न राज्यों को बाढ़ नियंत्रण के लिए कितनी सहायता दी गई है ;

(ख) विभिन्न राज्यों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग ने बाढ़ों के नियंत्रण के लिए किन-किन उपायों के सुझाव दिए; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में और क्या कार्यवाई की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकारों को राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक इयों ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह किसी विशिष्ट विकास शीर्ष अथवा स्कीम से संबंधित नहीं होती लेकिन बाढ़ की समस्या के विशाल आकार और जटिलता एवं अचिलम्बनीयता को देखते हुए असम और उड़ीसा राज्यों को ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्यों और रेंगाली बांध परियोजना के लिए विशेष मामले के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है। 1976-77 और 1978-78 में प्रस्तावित सहायता की जानकारी नीचे दी गई है :—

राज्य सरकार 1976-77 1977-78
का नाम (करोड़ रु० में)

असम	6	7.756 (प्रस्तावित)
उड़ीसा	1.75	2.77 (प्रस्तावित)

इसके अलावा 1977 की बाढ़ों के कारण किए गए खर्च के संबंध में 1977-78 के दौरान केन्द्र द्वारा राज्यों को आवंटित / दी गई अग्रिम योजना सहायता का व्यौरा नीचे दिया गया है -

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	राज्य	विपत्ति	अग्रिम योजना सहायता	
			आवंटित	दी गई (16- 3-78 तक)
1	आन्ध्र प्रदेश	चक्रवात	56 52	25 00
2	असम	बाढ़	3 23	3 00
3	गुजरात	बाढ़	10 43	3 00
4	है य णा	बाढ़	11 00	3 00
5	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	2 70	1 00
6	केरल	चक्रवात	3 64	2 00
7	उडान	बाढ़	8 52	2 00
8	राजस्थान	बाढ़	7 97	2 00
9	तमिलनाडु	चक्रवात	29 31	16 00
10	उत्तर प्रदेश	बाढ़	10 00	3 00
11	पश्चिम बंगाल	बाढ़	4 41	4 00

(ख) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग न अभी तक विभिन्न राज्यों में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई उपाय नहीं मुभाए हैं।

(ग) बाढ़ नियंत्रण राज्य जंत्र का भाग है और इसलिए बाढ़ नियंत्रण स्कीमों को शुरू करने, तैयार करने और क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारी को है। देश व्यापी स्तर पर बाढ़ नियंत्रण के उपाय 1954 में शुरू किये गये थे, तब से लेकर 10,400 मी० लम्बे तटबंध, 17,850 कि० मी० लम्बी ड्रेनेज चैनले बनायी जा चुकी है, 250 नगर सुरक्षा स्कीमें क्रियान्वित की जा चुकी है और 4700 गांवों को ऊंचा उठाया गया है। इन सब कार्यों पर अनुमानत 533 करोड़ रु० व्यय हुआ है। इन उपायों से देश के कुल 250 लाख हैबटेयर के बाढ़-प्रवण क्षेत्र से लगभग 95 लाख हैबटेयर क्षेत्र को

युक्तिसंगत सुरक्षा प्राप्त हुई है। कई मुख्य नदियां पर बहुत से जलाशयों का निर्माण किया गया है जिस से बाढ़ों से सुरक्षा की व्यवस्था हुई है। विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के लिए व्यापक योजनाएँ तैयार की जा जा रही हैं। अपेक्षाकृत अधिक बाढ़-प्रवण नदी-बेसिन के लिए ऐसी योजनाएँ तैयार करने के वास्ते विशेष सगठनों की स्थापना की गई है। ये सगठन हैं—असम सरकार द्वारा स्थापित ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित उत्तर बंगाल बाढ़-नियंत्रण आयोग। केन्द्रीय सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना तैयार करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की है।

भारत सरकार ने 1954 सेहाय में लिए गये बाढ़ नियंत्रण उपायों की समीक्षा करने

और देश में बाढ़ नियंत्रण की समस्या के प्रति एक समन्वित, एकीकृत और वैज्ञानिक कार्य पद्धति का विकास करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की भी स्थापना की है ।

Expenditure on agriculture and allied research work

4393. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) what is the total amount spent on agriculture and allied research work in the current year;

(b) whether any new inventions have been made and, if so, the details thereof; and

(c) the manner in which their applications is likely to strengthen the country's agricultural economy?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The Indian Council of Agricultural Research is likely to spend an amount of Rs 62 65 crores during 1977-78. In addition, the research on agriculture and allied field is also carried out under the auspices of State Governments in their Agricultural Universities and State Research Stations, for which allocations are made from State Budgets.

(b) Yes, Sir. The research on agriculture and allied fields is pursued by the I.C.A.R. through 31 Central Institutes, 4 Project Directorates, 51 All-India Coordinated Research Projects and 21 Agricultural Universities besides a few public, quasi-public and private Institutions in the country. The new research inventions made in the field of crops, commodities, animal sciences and farming systems, etc. are published annually in the form of

Research Reports, Research Highlights, bulletins and books on specialised subjects. A few of the important findings during the last year are mentioned below:

A number of high yielding varieties of rice, namely 'Akashi' and 'Rasi' were released for problem soils specially those with low phosphate and for rainfed upland conditions of U. P., parts of M.P., Bihar, Orissa, West Bengal and Karnataka. A short duration variety CRM 30 maturing in 70 to 75 days was also identified for rainfed—upland areas. For low land areas where the submergence does not exceed 50 cms, CR 1006, CR 1009, CR 1012, CR 1014 were identified as promising varieties. These varieties are expected to stabilise rice production in problem areas during kharif.

Research programme in wheat achieved significant success in terms of production and gaining confidence of farmers. Six new varieties were recommended viz. HD 2204 and IWP 72 for North-Western Plain zone including Punjab, Haryana, Rajasthan, Western UP and J&K; K-7410 and HUW-12 for North-Eastern Plain zone including Bihar, West Bengal, Assam, Orissa, Manipur, Tripura and Meghalaya; HW 657 for Penninsular India including Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu; and VL 421 for Northern Hill areas of U.P., Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh.

In pulses two high-yielding varieties of gram BG 203 for North Plain West Zone and K-468 for North Plain East Zone and one variety of Kharif Moong ML 5 and two Lentil varieties Panth 209 and Panth 406 were released.

In National Demonstrations conducted in farmers' fields, it was possible to obtain a total foodgrain production of 10 tonnes or more per hectare per year with assured inputs and improved technology, by growing two to three crops in rotations. Rice-Rice-

Rice, Rice-Wheat-Rice, Rice-Maize-Rice and Rice-Wheat are some of the rotations found profitable.

Azolla, a water fern, has been found to be a good source of bio-fertilizer in rice fields as it contains nitrogen-fixing blue-green algae on its leaves.

Mixing of powdered groundnut shells and rice husk in Red Chalka Soils of Andhra Pradesh improved the soil physical condition and yields of groundnut, bajra and wheat.

Considerable progress has also been made in animal sciences and fisheries research. A Purse Seine has been developed to increase marine fish catch especially of varieties like sardine and mackerel from small class fishing vessels.

(c) The agricultural economy of the country is under-going transformation as a result of the introduction of new agricultural technology. The production of wheat alone during 1966-67 to 1976-77 has increased to nearly two and a half times its initial value. The country has now stopped importing foodgrains and has built up a comfortable buffer stock.

Schemes under Rural Employment Projects

4394. SHRI S R DAMANI Will the minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) what are the schemes adopted under the Rural Employment Projects;

(b) how much money was spent during the current year on these schemes in each State and the new employment generated thereunder; and

(c) what further schemes are thought of for the coming years together with their employment potential?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH). (a) to (c). With a view to creating additional employment in the rural areas by utilisation of stored foodgrains, a scheme has been taken up with effect from April 1, 1977. Under this scheme wheat and/or milo is made available to States to pay part or full wages to labourers in kind for creation of durable assets. During the current year foodgrains worth Rs. 25.70 crores have been released to the State Governments of Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Kerala, Maharashtra, Orissa, Karnataka, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. A statement showing the quantity of wheat and milo allocated to different States is enclosed.

During the year 1978-79, it is proposed to take up 2,000 out of the 3,000 blocks already covered by one or more of the special area development or beneficiary oriented programmes for intensive coverage. In addition, 300 blocks per year will be taken up for detailed area planning for full employment. A budget provision of Rs 20 crores has been made for the next year for block area planning.

These Central Schemes are in addition to the various special programmes that are going on the States which are also generating rural employment.

Statement

Statement showing the quantities allocated to various States

State	Quantities allocated (Metric tonnes)		Money Value (Rs. in lakhs)
	Wheat	Milo	
1. Assam	7,500	..	93.75
2. Bihar	30,000	..	375.00
3. Karnataka	1,000	1,000	19.50
4. Kerala	6,000	..	75.00
5. Maharashtra	11,940	450	152.40
6. Madhya Pradesh	10,000	.	125.00
7. Himachal Pradesh	940	..	11.75
8. Orissa	30,000	..	375.00
9. Uttar Pradesh	42,000	400	527.80
10. West Bengal	51,200	.	640.00
11. Rajasthan	6,000	.	75.00
12. Punjab	8,000	..	100.00
TOTAL	2,04,500	1,850	2570.20

U.S. aid for agricultural sector

4385 SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government of USA has agreed to extend help for agricultural sectors during the meeting of Indo-US joint commission in New Delhi;

(b) if so, facts thereof; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). The meeting of the Indo-US Joint Commission held in January, 1978,

reviewed the progress made by its three Sub Commissions, namely:

(1) Economic and Commercial Sub-Commission;

(2) Sub-Commission on Education and Culture; and

(3) Sub-Commission on Science and Technology

The Agricultural Inputs Group under the Economic and Commercial Sub-Commission has made useful exchanges of information and data on various agricultural topics of mutual interest. The Sub-Commission on Science and Technology agreed that cooperative research in new fields, including agriculture, was of priority mutual interest and recommend that experts from the two countries may meet to define specific objectives and elaborate joint programmes. A final

view in regard to the areas of co-operation and the extent and methodology of assistance is yet to be taken

Central Housing assistance to U.P.

4396 SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Uttar Pradesh Government have approached the Central Government for financial assistance for a massive housing Scheme for the hutment dwellers who got the right of ownership of Land due to implementation of land reforms, and

(b) if so, facts thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) No, Sir

(b) Does not arise

Allotment of Govt accommodation to the Govt. servants on the retirement of parents

4397 SHRI NARENDRA SINH. Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to stop allotment of Government accommodation to the Government servants on their retirement of their parents from Government service,

(b) if so, the reasons thereof, and

(c) expected time by which these orders are to be implemented?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) to (c). A proposal is before the Government but no decision has yet been taken

रिंग रोड बिल्लो में स्मारक

4398. डा० रामजी सिंह : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार राजघाट, गांधी संग्रहालय, गांधी दर्शन तथा शांतिवन एवं विजयघाट के प्रबंध के लिए एक मयुक्त समिति गठित करना उपयोगी समझती है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयाजन के लिए कोई विधेयक लाने का है,

(ग) क्या प्रशासनिक दृष्टि में राजघाट, गांधी संग्रहालय और गांधी दर्शन के लिए अलग अलग प्रबंध समितियाँ का हाना उचित है, और

(घ) क्या सरकार का विचार उनके लिए मयुक्त प्रबन्ध करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) राजघाट समाधि समिति का गठन एक अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है : निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा शांतिवन और विजयघाट के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया था, किन्तु इन दोनों समितियों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए

फरवरी, 1978 में इन दोनों समितियों की एक ही समिति बना दी गई है। गांधी धर्मनिरपेक्ष मंत्रालय के प्रश्नों हैं।

(घ) इस बारे में इस समय कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है :

पेय '77'

4399. श्री राधकृष्ण : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) माईन बेकरीज ने पेय '77' की बिक्री कर अब तक कितनी आय प्राप्त की और इसकी बिक्री किन-किन नगरों में की गई ;

(ख) पेय '77' को काका काला के समान लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस वर्ष 1 अप्रैल से पेय '77' सब राज्यों में उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) माईन बेकरीज पेय '77' मीठे नहीं बेच रही है। वे केवल उन वाटलरो का इस पेय का उत्पादन करने के लिए मिश्रण सप्लाई करती हैं जो इस पेय का विपणन कर रहे हैं और इससे अब तक लगभग 6 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इस पेय का उत्पादन करने के लिए जिन वाटलरो को विशेष अधिकार दिया गया है, वे इस पेय को आगरा, भोपाल, भुवनेश्वर, कटक, दिल्ली, जामनगर, कानपुर, मद्रास, मेरठ, नागपुर, राजकोट, सहारनपुर और इन शहरों के आस पास के क्षेत्रों में बेच रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर, जिसने इस मिश्रण का विकास किया था, ने उस उत्पाद का विपणन

करने हेतु आवश्यक विभिन्न परीक्षण किए थे। माईन बेकरीज ने मद्रास, बम्बई और दिल्ली में उत्पाद परीक्षण किए हैं। इस पेय का दिल्ली में हुए एग्जी-एक्सपो '77' में परीक्षण के रूप में भी विपणन किया गया था। कम्पनी वाटलरों द्वारा उत्पादित पेय पर कड़ा कित्म नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। विभिन्न मार्केटों में इस पेय की शुरुआत करने के समय पर ही विज्ञापन अभियान शुरू किए गए हैं।

(ग) कम्पनी ने पेय '77' का उत्पादन करने के लिए विशेषाधिकार देने के लिए वाटलिंग कम्पनियों के साथ समझौता किया है। अब तक 14 वाटलरों को नियुक्त किया जा चुका है। आशा है कि शीघ्र ही कुछ और वाटलरों को भी नियुक्त किया जाएगा। कम्पनी द्वारा विभिन्न राज्यों में वाटलरों के जाल के माध्यम से इस पेय को यथा सम्भव शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

Durfi Chandramukhi and Jyoti Potato Seed

4400. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the famous varieties of potato seed like durfi, chandramukhi and jyoti produced in the State of Uttar Pradesh is increasing; and

(b) if so, the facilities extended by Government to the States in this regard to make available these varieties to the States and the number and names of the States which are taking advantage in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Yes, Sir.

(b) Supply of disease free seed is one of the most important factors in increasing production. The breeders seed of improved varieties is produced by the Central Potato Research Institute, Simla at their various Research Stations/Centres. The programme of seed multiplication development and distribution in the country is monitored twice every year in collaboration with C.P.R.I., Simla through the National Potato Seed Committee at the centre. The representatives of all the potato producing States, Organisations and Agencies are invited to attend these meetings to put forward their programme of variety-wise seed production and requirements. Thereafter, the Variety-wise production programme of breeders, foundation stage I, foundation stage II and certified seeds by different organisations, C.P.R.I. and States of the country is carefully drawn up for potato production programme of States. In addition, the Centre extends advice and technical guidance in regard to replacement of less productive varieties, package of practices etc. to States for increasing potato seed and potato production in the country.

As many as 23 States including Union Territories are taking advantage in this regard and their names are Andhra Pradesh, Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi and Mizoram.

Dairy Farm

4401. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the number of Government dairy farms in India towards the end of 1977;

(b) the quantum of milk being produced by these dairy farms; and

(c) the number of new dairy farms proposed to be set up by Government in each State during the next Five Year Plan period?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). The information is being collected from Animal Husbandry Departments of the States/Union Territories. The same will be placed on the Table of the Sabha as soon as received by this Ministry.

Central Schools

4402. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the number of cities where Central Schools have so far been opened; and

(b) the expenditure incurred on these schools during the last year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI): (a) At present 244 Kendriya Vidyalayas (Central Schools) are located at 172 stations.

(b) Rs. 14,98,96,000/-.

Development of Rural and Backward Areas

4403. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the programmes initiated and under the level of execution during 1977-78 for the development of rural and backward areas including hill and tribal areas by his Ministry;

(b) how many of them discontinued and included in new development strategy by the Government of India, and

(c) achievement made by the different schemes and allocation provided for the same by the States and his Ministry in 1977-78 and for 1978-79?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI DHANU PRATAP SINGH) (a) The following special programmes are being implemented by the Ministry of Agriculture and Irrigation during 77-78 for the development of rural and backward areas including hill and tribal areas

- (i) Drought Prone Areas Programme
 - (ii) Tribal Area Development Programme
 - (iii) Hill Area Development Programme
 - (iv) Small Farmers Development Agency/Marginal Farmers and Agricultural Labourer Projects
 - (v) Village development Programme
 - (vi) Integrated Rural Development Programme (Area Planning for full employment)
 - (vii) Desert Development Programme
- The following programmes were initiated during 1977-78
- (i) construction of rural roads
 - (ii) utilisation of food-grains for gainful employment and
 - (iii) Desert Development Programme

(b) Only one programme viz construction of rural roads has been discontinued by the Ministry of Agriculture and Irrigation as a Central Sector Scheme. The reason for the discontinuance of this scheme is that it is being provided under the State Sector by the State Governments. Also the Integrated Rural Development Programme which was initiated in 1976-77 has been restructured and is to be implemented as 'Area planning for full employment'

(c) Statements showing achievements made and allocations provided in 77-78 and 78-79 under different schemes mentioned under Part (a) of

the Question above are laid in the Table of the House. [Placed in Library See No LT-1930/78]

Orissa Government's view on Rehabilitation of Refugees in Malkangiri Zone of Koraput District

4404 SHRI GIRIDHAR GOMANGO

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Government of Orissa sent the view to his Ministry not to send more refugees for the rehabilitation in Dandakaranaya area of Malkangiri zone of Koraput district, Orissa

(b) if so the content of the view expressed by the Government of Orissa and

(c) the reaction of the Government of India on this issue?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) to (c) Yes Sir In January 1978 the Government of Orissa had written to the Government of India that movement of more families in Malkangiri Zone of the Dandakaranaya area of Malkangiri expedited until reclamation of land made available for settlement programme is speeded up and a final decision is taken in regard to pattern of Tribal assistance. The Government of Orissa were informed that while the land identified and released by the State Government for tribal settlement had been duly reclaimed and the position in regard to quantum of assistance to tribals could be reviewed after mutual consideration settlement of displaced persons should keep to schedule synchronising it with availability of reclaimed land and irrigation potential created for which budgetary allocations had been considerably stepped up

Setting up of Crop and Weather Panel

4406 DR VASANT KUMAR PANDIT

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether it is a fact that Indian Council of Agricultural Research has suggested to Government to establish crop and weather watch panels for all States to guard cooperative management, pest control and ecological regeneration,

(b) whether Government have any machinery to help assessment of damage to crops through droughts, floods and pestilence

(c) what help does the Department of Agriculture or Meteorological Department give to the Central Crop Committee in order to draw a comprehensive plan for the above and

(d) what is in general the policy of the Government in the above respect with a view to encourage cooperative production and reduce crop destruction?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) Yes Sir The Indian Council of Agricultural Research has established a Crop Weather Watch Group to study the meteorological elements in relation to its application to agriculture. The Department of Meteorology provides information on rainfall temperatures snowfall wind velocity etc with respect to most of the States in the country. This information is interpreted in terms of its application to agriculture such as for incidence of drought floods pest and diseases etc. The following agencies are represented in the Crop Weather Watch Panel established by the Council —

1 Indian Council of Agricultural Research New Delhi

2 Department of Meteorology, New Delhi

3 Department of Agriculture & Irrigation, New Delhi

4 Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi

The Indian Council of Agricultural Research has also recommended to establish Agro-Meteorological Divisions with each of the Agricultural Universities so as to correlate weather information with agriculture and to make best use of this information in terms of taking remedial measures for drought, pest control and ecological regeneration etc. Forecast and weather warning system would be strengthened by establishing Control Rooms at each of the Agricultural Universities

(b) Yes, Sir The information with respect to assessment of damage to crops through droughts, floods and pest and disease is basically done by the State Governments. However the Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage of the Ministry of Agriculture and Irrigation has established a net work of National Surveillance Stations to cover the incidence of major pest and diseases in 16 States in the country with the objective of monitoring the pest and disease situation. 19 Pest and Surveillance Stations have been established in 16 States with a view to keep a watch and ward on the incidence of pest and diseases and to provide timely information so as to take necessary remedial measures. More such stations are likely to be established to cover the remaining part of the country.

(c) The Meteorological Department through its substations all over the country brings out Weather Bulletins giving forecast for 36 hours and outlook for next two days. Such forecasts concern important meteorological elements such as temperature, rainfall high wind velocity, frost, snowfall and warnings for heavy rains

Weather bulletins are also sent to State Departments of Agriculture, All India Radio and Telegraphic Weather Summaries to distant agencies interested in such information

Based on the information received from the Department of Meteorology, Departments of Agriculture of the States undertake necessary measures so as to safeguard against weather vagaries

(d) There is no policy or proposal under consideration with the Government of India in this respect

Panel to Study Khandsari Units Problems

4407 SHRI PRASANNBHAI MEHTA

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be yeased to state

(a) whether it is a fact that Government have set up a panel to study problems of Khandsari units in the country,

(b) if so who are its Members

(c) what kind of problems will be solved by them

(d) to what extent the problems of the khandsari has been solved by the panel, and

(e) whether the representatives of the khandsari units have also been included in the panel?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) (a) to (e) Action is being taken to constitute a team of experts to go into the cost of production of khandsari and related problems A decision is expected to be taken shortly

Food Deficit in West Bengal

4408 SHRI CHITTA BASU Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Government of West Bengal has since informed the Central Government about its total food deficit for the year 1978-79,

(b) if so, the quantity of deficit,

(c) whether the Government propose to meet the entire deficit,

(d) whether the Government of West Bengal suggested that instead of making piece-meal allocations from month to month allocation might be made on six monthly or annual basis, and

(e) if so the reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) (a) and (b) Food and Supplies Minister, Government of West Bengal had intimated on 26th November 1977 that the nett food deficit of West Bengal was around 25 million tonnes per annum No specific reference has been received from the West Bengal Government about the total food deficit for the year 1978-79

(c) The demands of the West Bengal Government for foodgrains are at present met in full The Central Government will continue to assist the West Bengal Government with allocation of foodgrains from the Central Pool to the extent necessary, subject to availability of stocks in the Central Pool

(d) Yes, Sir

(e) The allocations of foodgrains to the State Governments/Union Territories are being made on a monthly basis taking into account the require-

ments intimated by the State Governments every month, the availability of stocks in the Central Pool, the availability of stocks with the State Governments from local procurement etc., supply position of foodgrains in the open market at reasonable prices, the off-take by the State Governments against the earlier Central allocations, relative needs of other deficit States and other relevant factors. In view of this, it is not possible to make bulk allocations of foodgrains on six monthly or annual basis as proposed by the West Bengal Government.

Service Charges payable by Calcutta Corporation on Central Government Property

4409. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Government of India has an outstanding dues to the Calcutta Corporation for the Service Charges for the Central Government properties, in Calcutta; and

(b) if so, whether Government have since cleared the dues?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) Part of the dues have been cleared. For the remaining, the Ministries/Departments have been asked to clear the dues.

Rehabilitation problem of former East Pakistani Refugees

4410. SHRI SAMAR BUHA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a report published in Calcutta Anand Bazar Patrika dated the 3rd March, 1978 quoting the statement of Chief Minister of West Bengal regarding rehabilitation problems of former East Pakistani refugees;

(b) if so, main issues raised by the Chief Minister of West Bengal; and

(c) the reaction of Government thereabout?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) The Chief Minister, West Bengal met Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation on 6th March, 1978 and discussed the following issues:—

(i) Reasons for desertions.

(ii) Scope for resettlement in Andaman and Nicobar Islands.

(iii) Sending a delegation of Members of Parliament and Members of Legislative Assembly to visit Dandakaranaya to assuage the situation and to have first hand knowledge of the conditions there.

(c) The Chief Minister, West Bengal has been informed that we welcome the visit of the delegation of Members of Parliament and Members of Legislative Assembly to be sent by the Government of West Bengal to study the situation in Dandakaranaya and to persuade the settlers to stay on there, that there is no scope for further settlement of displaced persons in Andaman and Nicobar Islands because of ecological and other conditions and that alleged reasons for desertions have been looked into and not been substantiated. He has, however, been assured that if any specific points are

referred to us after the visit of the Team, we will examine them to see what can be done in regard to those suggestions.

Criticism of Sugar Policy in West Bengal Assembly

4411. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether attention of the Government has been drawn to a speech made by the Finance Minister of West Bengal in West Bengal Assembly on 2nd March 1978 criticizing the sugar policy of the Central Government;

(b) if so, main points of criticism; and

(c) the reaction of the Government thereabout?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) to (c). Information has been called from the Government of West Bengal and a reply will be placed on the Table of the Sabha as and when received.

Employees on Ad-hoc basis in Delhi Milk Scheme

4412. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) total number of employees of the Delhi Milk Scheme, holding appointments on *ad-hoc* basis showing

S.C./S.T. employees separately, for more than one year, from 1 to 2 years, from 3 to 5 years, from 5 to 10 years and above 10 years;

(b) the reasons for the abnormal delay in regularisation of these appointments; and

(c) the steps taken to safe-guard the interests of the incumbents?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) At present, 490 officials are holding appointments on *ad-hoc* basis in Delhi Milk Scheme. A statement showing the break-up of such *ad-hoc* appointments is laid on the table of the Sabha.

(b). It has not been possible to regularise the *ad hoc* appointments mainly due to the following reasons:

(i) Non-finalisation/notification of the amendments to recruitment rules for some of the posts;

(ii) Non-finalisation of the *inter-se* seniority of the employees;

(iii) Vigilance cases are pending against some of the individuals.

(c) The following steps have been/are being taken to regularise the *ad-hoc* appointments:

(i) Expeditious finalisation/notification of the recruitment rules;

(ii) Expeditious finalisation of the enquiries in respect of individuals against whom the vigilance cases are pending; and

(iii) Early finalisation of the *inter-se* seniority of the employees.

Statement

No of employees of Delhi Milk Scheme holding appointments on ad hoc basis for the period

1 to 3 years	3 to 5 years			5 to 10 years			More than 10 years			Total				
	SC	ST	Others	SC	ST	Others	SC	ST	Others		SC	ST		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
135	30	3	70	21	2	196	31	47	7	397	89	4		

Breakage of Bottles in Delhi Milk Schem_e

D.M.S. during 1972-73 to 1977-78 is indicated as below:—

Year	Total No. of bottles broken
1972-73	29,51,037
1973-74	31,90,003
1974-75	33,80,454
1975-78	28,13,719
1976-77	27,98,536
1977-78	27,56,203
(upto 31-1-1978)	

4418. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the yearly breakage of bottles in the D.M.S. since 1972 and the quantity of glass scrap disposed of since then during each year together with rates thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): The total number of bottles broken in the process of filling, storage and handling in the

The requisite information in regard to the quantity of the glass scrap sold by the D.M.S. and rate thereto during the period 1972-73 to 1977-78, is indicated in the enclosed statement.

Statement

Categories of Glass	Period	Quantity sold in quintals	Rate (per quintal) at which sold
1	2	3	4
			Rs.
1972-73			
Glass Scrap	1-4-72 to 8-3-73	10,136	20.15
1973-74			
Glass Scrap	5-6-73 to 31-3-74	9,722.2	22.30
Glass Scrap (mixed with mud)	23-6-73 to 13-8-73	1,554	2.00
	1-1-74 to 31-3-74	1,674.5	7.00
	TOTAL	11,950.7	
1974-75			
Glass Scrap	1-4-74 to 31-5-74	2,059.8	22.30
	1-6-74 to 31-3-75	6,007.2	40.50
Glass scrap (mixed with mud)	1-4-74 to 31-12-74	3,901.5	8.10
	TOTAL	11,968.5	

1	2	3	4
1975-76			
Glass Scrap	1-4-75 to 15-5-75	534' 1	40 50
	3-7 75 to 31-9-76	4,590 5	34 50
Glass scrap (mixed with mud)	31-3-76	91 7	
	TOTAL	5,216 7	
1976-77			
Glass scrap	1 4 76 to 4 6-76	1,034 4	34 50
	22-5-76 to 26 6-76	3,302 9	22 10
	1-1-77 to 11 1-77	3,508 1	22 16½
Glass Scrap (mixed with mud and soaked with oil grease and rotten waste	1-4-76 to 24 4-76	1,447 1	13 15
	16-6-76 to 12-7-76	3 527 2	13 56
	TOTAL	12,819 7	
1977-78			
Glass scrap (Composite quality)	1-4-77 to 17 3 78	18,433 5	22 16½

**Setting up Institute for study of
Tantrik in Ladakh**

4414 SHRIMATI PARVATI DEVI
Will the Minister of EDUCATION,
SOCIAL WELFARE AND CULTURE
be pleased to state

(a) whether Ladakh is known from
ancient times for Tantrik,

(b) if so, whether Government pro-
pose to set up an Institute in Ladakh
for the study of Tantrik which enjoys
the distinction of still preserving it,
and

(c) if so the details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION,
SOCIAL WELFARE AND CULTURE
(DR PRATAP CHANDRA CHUN-
DER) (a) No such survey has been
carried out by the Government of
India in that region

(b) and (c) Does not arise

Teaching of Buddhism in Universities

4415 SHRIMATI PARVATI DEVI
Will the Minister of EDUCATION,
SOCIAL WELFARE AND CULTURE
be pleased to state

(a) the names of the Universities
and Institution where Buddhism is
taught, and

(b) the steps being taken to pro-
mote the teaching of Buddhism, its
rich culture and heritage?

THE MINISTER OF EDUCATION,
SOCIAL WELFARE AND CULTURE
(DR PRATAP CHANDRA CHUN-
DER) (a) According to information
furnished by the University Grants
Commission, Delhi University,
Marathwada University and the Sam-
purnanand Sanskrit Vishwavidyalaya

have provision for Buddhist Studies. Besides, the School of Buddhist Philosophy, Leh, and the Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, also offer facilities for Buddhist studies.

(b) For promoting Buddhist Studies in Universities, the UGC has decided to institute readership and fellowships in this area in selected universities. Accordingly, 11 universities were requested to send proposals. Of these, the proposals made by the Universities of Poona, Andhra and Saugar have since been accepted by the Commission.

Representation and Promotion of Ladakh Culture

4416 SHRIMATI PARVATI DEVI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state-

(a) what steps Government have taken or propose to take to preserve and promote the culture of Ladakhis, their music, dancing, specially marked dances, clarinets, cymbals and other instruments, and

(b) the contribution made so far by National Book Trust, Akademies and other Government Agencies in this direction?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b) To preserve and promote the culture of Ladakhis, the Government have taken the following steps:-

(i) The School of Buddhist philosophy was established in 1959 to impart education in modern and classical Tibetan Studies on the Monastic pattern in Leh.

(ii) A research report entitled 'Ethnographic and Culture change study of Ladakhis' has been brought out by the Anthropological Survey

of India. They have also produced coloured cine film on "Hemis Festivals (Ladakh)."

(iii) Song and Drama Division has on its strength one performing troupe named 'Gumpha' exclusively for programmes in Ladakh region. Since August, 1973, the troupe has presented 107 shows in Ladakh areas and 289 programmes in other parts of the State.

(iv) Authentic Ladkhi Costumes, jewellery musical instruments, head-gears etc., of Ladakh people have been acquired by the Song and Drama Division in consultation with local experts.

(v) National Book Trust has published in its India—the Land and the People series, a monograph on the State of Jammu and Kashmir which contains information, *inter alia*, on the land and the people of Ladakh and various facets of its cultural heritage. The Trust also intends to publish shortly a book on the Folklore of Jammu and Kashmir, under its series Folklore of India, which will include a feature on the Ladakhi folklore.

(vi) Under their scheme of Survey and Documentation, the Sangeet Natak Akademi propose to undertake a survey and to document the various music and dance forms in Ladakh in collaboration with the Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages.

दायरीं पर रबड़ चढ़ाने के बारे में नीति

4417. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या निर्माण और स्यावास तथा सुति और पुवर्वाल यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आयुध डिपों में वाहनों के दायरीं पर रबड़ चढ़ाने के बारे में कोई नई

नीति बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो पुरानी नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं,

(ख) क्या यह सच है कि कुछ कारखानों के मामलों में ठेके की पूर्व-श्रवधि, टेडर शामिल किये बिना बढ़ा दी गई है, उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनके ठेके की श्रवधि बढ़ाई गई तथा कितनी बढ़ाई गई और किन तारीखों को बढ़ाई गई तथा इसके क्या कारण थे, और

(ग) क्या मन्त्रालय ने उक्त फर्मों को ठेके की श्रवधि बढ़ाने के बारे में कोई पत्र जारी किया है और यदि हां, तो क्या कुछ फर्मों ने पत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन करने से इन्कार किया है और यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त शर्तों को स्वीकार करने से इन्कार किया है तथा उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त शर्तों को स्वीकार किया है?

निर्वाह और आवास पूर्ति और पुनर्वासि
मंत्री (श्री सिकन्दर बकत) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी

Adult Illiteracy

4418. SHRI D. D. DESAI Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state.

(a) whether any new scheme of adult education has been formulated to remove adult illiteracy,

(b) if so, the details thereof, and the cost of the scheme and

(c) whether Government intend to appoint part-time teachers for this purpose

THE MINISTER OF EDUCATION,
SOCIAL WELFARE AND CULTURE

(DR PRATAP CHANDRA CHUNDER) (a) to (c) Government have formulated a National Adult Education Programme which is proposed to be launched from 2nd October, 1978 and has a target of covering the entire illiterate population of about 10 crores in the age-group 15—35 within about 5 years of its launching. The instructional work would be assigned on part-time basis to school teachers, students educated village youth, ex servicemen, retired personnel, field level Government and other functionaries and voluntary social workers

Conversion of Leasehold Land into Free Hold Lands in Delhi

4419 SHRI VIJAY, KUMAR MALHOTRA Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) whether there is any proposal to convert leasehold lands in Delhi into freehold lands in the names of the present lessees holding the lands,

(b) what is the Government's estimate of land rent that will be given up as a result of this transfer every year and how can the Government make up for the loss in revenues, and

(c) how many leasehold properties would be involved in Delhi in such a transfer and by what time would such a transfer or conversion materialise?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a): A Committee has been set up to consider the matter

(b) and (c) Till the report is received and a decision thereon is taken by Government, these questions do not arise

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएँ

4420. श्री छविराज वर्माल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) मध्य प्रदेश में राजघाट बाणसागर और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं किम स्थिति में है ; और

(ख) उन परियोजनाओं के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) । (क) और (ख) राजघाट और बाणसागर परियोजनाओं का निर्माण शीघ्रता से करने के लिए केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में बेतवा नदी बोर्ड और बाणसागर नियंत्रण बोर्ड गठित किए

एए हैं। इन परियोजनाओं के प्रारम्भिक निर्माण-कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश को अन्य महत्वपूर्ण बृहद निर्माणाधीन स्कीमों पर 1977-78 के अन्त तक होने वाले सम्भावित व्यय, अद्यतन अनुमानित लागत और उक्त स्कीमों के पूर्ण होने की सम्भावित सतारीखों की जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

उक्त परियोजनाएं धनराशि के उपलब्ध होने पर, जैसा कि बताया गया है, भगली पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण हो जायेंगी। राजघाट और बाणसागर परियोजनाओं के 6—8 वर्ष के समय में पूर्ण होने की सम्भावना है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अद्यतन अनुमानित व्यय	1977-78 तक होने वाला सम्भावित व्यय	पूर्ण होने की सम्भावित तारीख
1.	चम्बल, चरण—एक और दो	68.38	62.91	1978-79
2.	महानदी जलाशय दौर—एक	40.02	30.71	1978-80
3.	तवा	91.42	70.31	1980-81
4.	बरना	14.60	13.33	1978-79
5.	हसदेव की दाएं किनारे वाली नहर	13.39	12.48	1978-79

बिहार और उत्तर प्रदेश में संकटग्रस्त चीनी मिलें

मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के अन्तर्गत भण्डार गृह

4421. श्री मधुबन प्रसाद वर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

4422. श्री हुकम चन्द कच्छवाय : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसी चीन मिलें कौन-कौन सी और कहाँ-कहाँ पर हैं जो अक्टूबर 1977 तक संकटग्रस्त घोषित कर दी गई थी या मान ली गई थी, इस वर्ष कौन-कौन सी मिलें किस किस प्रबन्ध के अधीन चालू हो गई हैं और शेष बन्द पड़ी मिलों में से उनके नाम क्या हैं जिन्हें आगामी वर्ष चालू करने का प्रस्ताव है और शेष मिलों के बन्द पड़े रहने के क्या कारण हैं जिनके चालू होने की कोई सम्भावना नहीं है, और

(क) मध्य प्रदेश में इस समय खाद्य निगम के अन्तर्गत कितने भण्डार गृह हैं और इनमें से प्रत्येक भण्डार गृह की क्षमता कितनी है और राज्य में कितनी भण्डारण क्षमता की आवश्यकता है,

(ख) क्या निगम के अन्तर्गत कुछ भण्डार गृह किराये पर लिये गये हैं और यदि हाँ, तो इनकी संख्या और क्षमता क्या है और इन भण्डार गृहों को किन शर्तों पर किराये पर लिया गया है, और

(ख) उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं जो इस वर्ष अर्थात् 1 नवम्बर, 1977 के बाद संकटग्रस्त घोषित की गई थी और उनको फिर से चालू करने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार ने इन भण्डार गृहों को किराये पर लेने के लिये कोई नीति निर्धारित की है और यदि हाँ, तो नत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश में कितने भण्डार गृहों की आवश्यकता है और इस समय कितने सरकारी भण्डार गृह हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन् प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन् प्रताप सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के अधीन भण्डारगारों की संख्या और एजेंसी वार क्षमता इस प्रकार है —

एजेंसी का नाम	भाण्डागारों की संख्या	मीटरीटन में क्षमता
1. निजी (भा० खा० निगम)	36	3,94,613
2. प्राइवेट पार्टियां (सामान्य किराये पर)	117	1,28,042
3. प्राइवेट पार्टियां (गारंटी के आधार पर)	20	2,68,520
4. राज्य सरकार और डिपॉजिट	37	1,45,980
5. राज्य भाण्डागार निगम	92	61,080
6. केन्द्रीय भाण्डागारनिगम	8	54,832
	310	10,53,067

वसूली, वितरण संचालन और अन्य संबंधित आवश्यकताओं जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भण्डारण सम्बन्धी आवश्यकताओं की समय समय पर समीक्षा की जाती है : अतः किसी राज्य की भण्डारण क्षमता समय समय पर भिन्न भिन्न होगी। प्राइवेट पार्टियों तथा राज्य सरकार से किराये पर लिए गये गोदाम प्राप्तियों सहमति से निर्धारित किराये के आधार पर है।

(ग) सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है। समय समय की आवश्यकताओं पर अधारित यह भारतीय खाद्य निगम का परिचालन सम्बन्धी मामला है। देश में भारतीय खाद्य निगम के निजी गोदामों की कुल संख्या 374 है।

बाहनों के टायरों पर रबड़ चढ़ाने के लिए टैंडरों का रद्द किया जाना

4423. श्री हुकम चन्द कश्यप : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय के वाहनों के टायरों पर रबड़ चढ़ाने के कार्य हेतु वर्ष, 1977-78 के लिए टैंडरों को रद्द करते हुए एक पत्र जारी किया था और यदि हां, तो क्या सभी टैंडर रद्द कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समय कितनी फर्मों इस कार्य को कर रही हैं और इस पत्र को जारी करने का प्रयोजन क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बजल) :
(क) जी, नहीं।

(ख) इस समय पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में 1-12-77 से 30-11-78 तक की अवधि के लिए केवल दो फर्मों को दर ठेके दिए गए हैं। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में 16 फर्मों के पास 30-11-77 तक जो दर ठेक उन्हें 28-2-78 तक बढ़ा दिया गया। 1-12-77 से 30-11-78 की अवधि लिए दर ठेक के लिए नये टैंडर

भाग गए थे, परन्तु बीच में ही रखा मन्त्रालय ने विशिष्टियों में परिवर्तन कर दिया, उसके कारण नये दर ठेको को तय करने में कुछ और समय लग जाने की सम्भावना है।

घसम में केन्द्रीय फारेस्ट सर्विस कालेज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना

4424. श्री सुभाष झाजूजा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताना की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार आसाम से बरनहाट स्थित केन्द्रीय फारेस्ट सर्विस कालेज को वहा से हटा कर किसी अन्य स्थान पर ले जाने का है, और

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार इस कालेज को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो इस कालेज के लिये सभी दृष्टिकोणों से सबसे उपयोगी है स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री श्रीपुरजोत सिंह बरनाला) : (क) जी हा। बरनहाट से राज्य बन सेवा महाविद्यालय को दूसरे स्थान पर ले जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

स्वायत्तशासी गन्दी बस्ती बोर्ड की स्थापना

4425. श्री महीलाल : क्या निर्वाण और धावास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक स्वायत्तशासी गन्दी बस्ती बोर्ड की स्थापना के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

(ख) यदि इस बिना में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त बोर्ड की स्थापना कब तक की जायगी ?

निर्वाण और धावास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से- (ग). दिल्ली स्वयं स्थायत बोर्ड के गठन का एक प्रस्ताव पहले रद्द कर दिया गया। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि गन्दी बस्ती सफाई कार्य को दिल्ली नगर निगम की हस्तान्तरित कर दिया जाए।

Expenditure incurred on Union Ministers Bungalows

4426 SHRI MAHI LAL Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) the break up of expenditure incurred on renovation furnishing and fixtures on the residential accommodation of each Cabinet and State Minister of the Central Government during the last six months, and

(b) whether the expenditure was within the prescribed ceiling and if not, whether the excess expenditure was met by the concerned Ministers?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) A statement showing expenditure incurred from 1st September, 1977 to 28th February, 1978 is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. LT-19314 78]

(b) There is no ceiling on expenditure on repairs, maintenance etc, of houses. However, the Ministers pay rent if they have furniture in excess

of the prescribed ceiling of Rs. 38,500. There has been no such case so far in 1977-78.

Cases of Misappropriation in DDA

4427 SHRI MAHI LAL Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) the number of embezzlement and misappropriation cases which occurred in the Delhi Development Authority during the last five years, and

(b) the details and the persons and the amount involved in each case separately?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The Delhi Development Authority have reported three cases

(b) The details are as under:—

(i) Shri Bishambar Dayal, UDC, while working as rent collector in Najafgarh (JJ) colony during the year 1976 misappropriated a sum of Rs 2,435/- collected as rent on behalf of the Department The Metropolitan Magistrate, Delhi sentenced him to rigorous imprisonment of nine months and a fine of Rs 500/- In view of this judgement, he was dismissed on 14th December, 1976.

(ii) Shri S. N Swami, Cashier, misappropriated Rs. 330/- deposited by three allottees of Wazirpur towards water charges He was charge-sheeted on 3rd December, 1973, Later, he tendered his resignation which was accepted on 15th February, 1977

(iii) Shri K. D Rana, U.D.C., misappropriated Rs 300/- He has been suspended on 11th January, 1978. The case is under investigation by the policy authorities.

Retrenchment of Muster Roll Workers from Indian Schools of Mines, Dhanbad

4428. SHRI A K. ROY: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state

(a) whether there has been large scale retrenchment of muster roll workers from Indian School of Mines, Dhanbad, and if so, the number of such workers and reasons therefor,

(b) whether there was a Dharna against this retrenchment,

(c) whether it is a fact that Harijan workers have also been victimised,

(d) whether it is a fact that in the same period new workmen have been recruited against law, and

(e) whether Government propose to probe into these irregularities and take necessary steps against the persons responsible for all these irregularities?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR PRATAP CHANDRA CHUNDER) (a) to (e). Information is being collected from the Indian School of Mines, Dhanbad and will be placed on the Table of the House.

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन नियमों की धारा 3(3) की कियान्वित

4429. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या निर्वाण और अवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राजभाषा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत बनाये गए नियमों की धारा 3(3) पूरी तरह से कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हा, तो वर्ष 1977 की अन्तिम छमाही के दौरान कुल कितने सामान्य भादेश, परिपत्र, नोटिस टेडर परमिट जारी किए गए और उनमें अंग्रेजी के साथ हिन्दी में जारी किए गए भादेशों आदि की संख्या क्या थी, और

(ग) यदि उपर्युक्त धारा का पालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है, तो उसके क्या कारण हैं और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :

(क) जी, हा ।

(ख) 165 ।

इन सभी को अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जारी किया गया था ।

(ग) प्रश्न ही नही उठता ।

निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा निकाले जाने वाले प्रकाशन

4430 श्री नवाब सिंह चौहान क्या निर्माण और आवास तथा पूति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उनके मंत्रालय/विभाग ने 1977 के दौरान कौन कौन से प्रकाशन और पत्र-पत्रिकायें निकाली,

(ख) उपर्युक्त प्रकाशनों और पत्र-पत्रिकाओं में से कितने प्रकाशन हिन्दी में निकाले गए और जो हिन्दी में नहीं निकाले गए उसके क्या कारण हैं ,

(ग) क्या ऐसे सभी प्रकाशनों एवं पत्र-पत्रिकाओं को हिन्दी में निकालने का विचार है जो अंग्रेजी अंग्रेजी से निकाले जा रहे हैं; और

(घ) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ? ।

निर्माण और आवास तथा पूति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) निर्माण और आवास मंत्रालय ने वर्ष 1977 के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले —

(I) हेबोट्ट ड्रिफ्टिया (सूचना पत्र) त्रैमासिक प्रकाशन)

(II) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974—पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक रचनात्मक कदम (चौपत्रा)

(III) ई० एस० सी० ए० पी० के लिए समुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आवास केन्द्र (पुस्तिका)

(ख) यद्यपि सूचना-पत्र 'हेबोट्ट ड्रिफ्टिया' में लेख अंग्रेजी तथा हिन्दी में थे किन्तु यह एक नितान्त द्विभाषिक प्रकाशन नहीं था तथा, अब यह प्रकाशन बन्द कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में सम्बद्ध कालेजों के लिए विकास निधि

4431. श्री युवराज : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में सम्बद्ध कालेजों के लिए विकास निधि से कोई राशि स्वीकृत की गई है ;

(ख) यदि हा, तो उन कालेजों के नाम क्या हैं और इन में से प्रत्येक कालेज के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है, और

(ग) ऐसे कौन-कौन से कालेज हैं जिन के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई, और उन के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई मूचना के अनुसार, पाचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में विभिन्न विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध 76 कालेजों को आयोग द्वारा विकास सहायता स्वीकृत की गई थी । इस के अतिरिक्त 29 कालेजों के प्रस्ताव या तो विचाराधीन हैं या अस्वीकार कर दिये गये हैं । मन्वीकृत अनुदानों से संबंधित व्यौरे और उन प्रस्तावों की स्थिति जिन्हें अस्वीकार नहीं किया गया है, मभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है । [प्रश्नांश में रखा गया । देखिये सख्या एन टी—1932/78] शेष कालेजों ने

विकास सहायता के लिए आयोग को आवेदन नहीं किया है ।

लघु कृषक विकास एजेंसी और प्रायः सूबा रहने वाले क्षेत्रों के लिये कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत शामिल किये गये हैं

4432. श्री सुबराज : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु कृषक विकास एजेंसी, सूबा-अस्त होने वाले क्षेत्र कार्यक्रमों, समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रमों और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कितने खंडों को शामिल किया गया है और उन के कार्यान्वयन से लेकर अब तक इन योजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) इन खंडों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है और गैर-सरकारी लघु-सिंचाई योजनाओं के लिये राजसहायता के रूप में इनकी कुल सख्या कितनी है और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) आवश्यक व्यौरे नीचे दिये गये हैं.—

कार्यक्रम	कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत लाये गये खंडों की सख्या	प्रारम्भ से लेकर कुल व्यय (लाख रुपयों में)
1	2	3
1. छोटा किसान विकास एजेंसी (एस० एफ० डी०ए०)	1820	13174.37 (नवम्बर, 1977 तक)
2. सूबाअस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी० ए० पी०)	535	24685.00 (जनवरी 1978 तक)

1	2	3
3 गहन आदिवासी विकास कार्यक्रम (आई०टी०डी०पी०)	584 (पूर्णत) 270 (आंशिक रूप से)	11828 66 (1976-77 तक वास्तविक+ 1977-78 प्रत्याशित)
4 आदिवासी क्षेत्र विकास परियोजनाए (टी०ए० डी०)	46	1293 85 (दिसम्बर 1977 तक)
5 कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी० ए० डी०)	938	6656 00 (21 मार्च, 1978 तक)

(ख) उपर्युक्त विशेष कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार की ओर से सहायक अनुदान परि-
योजनाओं का बटित किया जाता है और, इसलिए, खण्ड-वार आर्बंटन से संबंधित
आकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, लघु सिंचाई योजनाओं पर किया गया व्यय निम्न प्रकार
है —

कार्यक्रम	व्यय (लाख रुपये में)	कैफियत
1 छोटा किसान विकास एजेंसी (एस० एफ० डी० ए०)	3607 79	169 परियोजनाओं में से 143 परि- योजनाओं से सम्बन्धित।
2 सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्य क्रम (डी०पी०ए०पी०)	12236 00	सिंचाई योजनाओं पर कुल व्यय। छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए उपदान के अलग आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
3 गहन आदिवासी विकास कार्यक्रम (आई०टी०डी०पी०)	4015 00	लघु सिंचाई के लिए आर्बंटन संबंधित आकड़े से
4 आदिवासी क्षेत्र विकास परियोजनाए (टी०ए० डी०)	अप्राप्य	
5 कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी० ए० डी०)	587.00	

D.D.A. Flats, Janakpuri

4433 SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 48 on the 14th November, 1977 and state:

(a) whether the requisite information has since been collected; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) The matter has been examined in consultation with DDA and the Municipal Corporation of Delhi. These flats were allotted between 1971 and 1974. The defects pointed out by the allottees at the time of handing over the flats were attended to by the DDA. Most of the defects now pointed out are reported to be largely due to improper maintenance. Maintenance is the responsibility of the individual allottees or common welfare agencies. In view of this position, the demand of the allottees that they should be allowed rebate of one monthly instalment of Rs. 175 has not been accepted.

The Municipal Corporation of Delhi took over the services of this colony in 1976. It has since increased water supply from two to four million gallons per day. Three works of replacing sewers in defective portions have also been carried out by the Municipal Corporation of Delhi.

A High Powered Committee on Delhi School Teachers Cooperative House Building Society

4434. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the full contents of the orders reconstituting the three-member High Powered Committee appointed by Lt. Governor to decide the membership issue of the Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society;

(b) when the meeting of the reconstituted High Powered Committee was held on which the recommendations made by it were forwarded, and to whom and the details of those recommendations;

(c) when the Managing Committee of the Society considered the above recommendations, the members present in the meeting and the decisions taken therein;

(d) when the Managing Committee communicated its decisions to the Registrar, date on which Registrar appointed an Election Officer and on which he sent a notice to the press; and

(e) the action taken or proposed to be taken against those officials of Registrar's office who have been working collusion with the Managing Committee illegally elected during emergency?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) A copy of the order dated 31st August, 1977 is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1933/78]

(b) The meeting was held on 31st August, 1977. The recommendations were forwarded to the Secretary of the Society. The Committee's findings

in regard to 283 objections received by it by due date are as under:—

(i) Non-School Employees in excess of 20 per cent quota	77
(ii) Cases which are under consideration of crime Branch pertaining to receipts books Nos B3200 and C-3500	60
(iii) Cases referred back to society for reconsideration	91
(iv) Cases under Arbitration proceedings	25
(v) Persons who have already been accepted as members	3
(vi) Membership being accepted on award in arbitration proceedings	1
(vii) Membership claims rejected	26

(c) and (d) The Managing Committee of the Society considered the report on 31st August, 1977. The following members participated.—

(1) Shri Dalip Singh Baus	(President)
(2) Shri S S Panwar	(Secretary)
(3) Shri M L Sharma	
(4) Shri R D Sharma	
(5) Shri Baldev Raj	
(6) Shri P C Aggrawal	
(7) Shri Braham Singh	

The Managing Committee communicated their decision on 1st September 1977 to the Registrar. The Election Officer was appointed on 1st September 1977 and he sent notice to the press on 2nd September, 1977.

(e) No official of the office of the Registrar is reported to have colluded with the Managing Committee.

Kapurthala Plot

4435 SHRI P K KODIYAN Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the remaining portion of the Kapurthala plot belonged to the Kerala State Government but the possession thereof has not yet been handed over to the State Government, and

(b) if so, the details and what steps are being taken in this regard?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) Yes, Sir

(b) On a portion of the land out-houses/servants quarters are under occupation of the Security Police. Action is being taken to get these structures vacated and to release the

land thereunder. The balance land will be released after alternative accommodation is built for the present occupants. Land for construction of alternative accommodation has been allotted.

Evaluation of progress of operation Flood

4436. SHRI OM PRAKASH TYAGI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have appointed or planned to appoint a Committee to evaluate the progress of the 'Operation Flood' launched in 1970;

(b) if so, the personnel of the Committee, terms of reference and whether any interim report has been received;

(c) what are the main features of the Operation Flood, its achievements and spill-over schemes; and

(d) has the Central Government consulted the concerned as well as other interested State Governments about objectives and working of the Operation Flood and about its management by the National Dairy Development Board/Indian Dairy Corporation?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). Appointment of a Committee to evaluate the progress of the Operation Flood I project launched in 1970 is under consideration of the Government.

(c) The main objectives of Operation Flood I Project were to increase milk supply in the 4 metropolitan cities, resettlement of city-kept cattle and buffaloes, development of basic transportation and storage network, development of milk procurement sys-

tem in rural areas and overall improvements of dairy farming aimed at increased milk production. An indication of its broad achievements and spill over schemes is brought out in attached statement.

(d) The matter is being examined.

Statement

Broad achievements of operation Flood I

The expansion of the existing dairies as also setting up of four Mother Dairies at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras have been completed. It has also been agreed to set up an additional dairy at Bombay with a capacity of 4 lakh L per day.

Work on 17 Feeder/Balancing dairies have been completed and 5 Feeder/Balancing Dairies are still at proposal/planning stage.

Storage and long distance milk transport facilities

30 broad gauge rail milk tankers for long distance transport of milk have been procured. Order has been placed for fabrication of 10 meter gauge rail milk tankers.

The godowns for storage of skim milk powder have been completed at Delhi, Madras and Calcutta. Construction of cold storage facilities at Madras and Delhi is complete. The cold storage at Calcutta is under construction. The Government of Maharashtra have also decided to make available land at Aarey Milk Colony for construction of Indian Dairy Corporation godown and cold store. This construction will be started as soon as the land is formally handed over.

Resettlement of city-kept cattle

For a variety of reasons, resettlement of city-kept cattle has been given

a low priority by the Corporation, as it is felt that due to economic pressure created by the expanded milk supply that the owners of cattle would resettle their animals in rural areas on their own. Some of the funds originally earmarked for this item have accordingly been diverted for other more pressing projects.

A pilot project for resettlement of 1000 animals in rural milksheds in West Bengal has however been taken up by the West Bengal authorities aimed at resettlement of Calcutta cattle in rural areas.

Farmers' organisations rural milk procurement and input programmes for increasing milk production

The progress of these items has varied from State to State. Three cattle feed plants of 100 M Tonnes per day capacity have been commissioned in Punjab, Bihar and Gujarat. 4 additional feed plants are under construction in Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Gujarat. It is also proposed to set up one feed plant each in Rajasthan, West Bengal, Western UP, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Gujarat.

Bull Mother Farms

14 Bull Mother Farms have been set up. These farms have supplied 357 pure bred exotic bulls so far. The small herd strength in the bull mother farm has been the main constraint in achieving their economic viability. It is proposed to bring up the herd strength in each to 100 breeding animals.

Stud Farms

Stud farms and artificial insemination centres have been established in milksheds except in Guntur, Patna, Meerut and Varanasi. The Corporation has initiated action to establish semen freezing facilities at one stud farm in each State by supplying the necessary equipment. It is hoped that

the availability of frozen semen will enable extension of coverage of insemination programme to larger areas.

Project Planning, Implementation and Manpower Development

Planning, designing and standardisation of chilling centres, feeder balancing dairies, mother dairies and cattle feed plants have been completed. The Corporation has also commissioned a Continuing Information System and a Systems Development Programme for Operation Flood Facilities. have been created at the NDDP for training personnel from the participating States. For Operation Flood programmes 362 persons were trained during the year and the total number trained upto 31st March 1977 comes to 895. The training programmes cover following subjects—

- (1) Training of jav inseminators, stockmen, laboratory technicians and officers in artificial insemination.
- (2) Training of procurement and technical inputs wing personnel.
- (3) Executive development programme for cattle feed plant operators.
- (4) Training programme in dairy plant operation for plant operators.
- (5) Farmers orientation programme.
- (6) Special training programmes for dairy engineers, marketing officers, dairy extension workers and veterinary officers.

सबू सदस्यो से लिये जाने वाला फनीबर का किराया

1137 श्री नवाब सिंह चौहान क्या निर्वाच और सवास तथा पूति और पुनर्वास मंत्री यह बतान की क्या करेगे कि

(क) संसद् सदस्यों से इस समय लिये जा रहे फर्नीचर के किराया का आधार क्या है और क्या इस संबंध में ब्यौरे से उन्हें सूचित किया जाता है ;

(ख) नये और पुराने फर्नीचर में कैसे भेद किया जाता है और किसी विशेष भेद की खरीद के वर्ष का निर्णय किस प्रकार किया जाता है ; और

(ग) फर्नीचरों के पुराने मर्दों के हास मूल्य का किस प्रकार निर्धारण किया जाता है और क्या उनका किराया भी तदनुसार घटता रहता है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) संसद् सदस्यों को दिए गए फर्नीचर का किराया 25 प्रतिशत छूट के आधार पर इस प्रकार अंका गया है :—

(I) टिकाऊ

6,000 रु० के मूल्य तक के फर्नीचर की लागत 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ।

6,000 रु० से अधिक मूल्य पर फर्नीचर की लागत का 13.75 प्रतिशत प्रति वर्ष ।

(II) गैर टिकाऊ

1,500 रु० मूल्य तक के फर्नीचर की लागत का 16.5 प्रतिशत प्रति वर्ष ।

1,500 रु० से अधिक मूल्य पर फर्नीचर की लागत का 24.5 प्रतिशत प्रति वर्ष ।

उन्हें दिए गए फर्नीचर का विवरण भी दिया गया है ;

(ख) 1952-58, 1968-69 और 1976-77 के दौरान संसद् सदस्यों के निवासों

की साज सज्जा के लिए फर्नीचर तीन हिस्सों में खरीदा गया था । प्रत्येक हिस्से में फर्नीचर की औसतन लागत के आधार पर किराया वसूल किया गया है ।

(ग) फर्नीचर के लिए मूल्य हास को ध्यान में नहीं रखा जाता है क्योंकि इन्हें निरन्तर मरम्मत तथा अच्छी उपयोगी हालत में रखा जाता है । यदि मूल्य हास को भी ध्यान में रखा जाए तो किराए की दर तदनुसार बढ़ेगी ।

11.57 hrs.

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT
FIRING ON BHEL WORKERS AT HARD-
WAR.

SHRI KRISHNA CHANDRA HAL-
DER (Durgapur): Sir, let me be
heard first

MR. SPEAKER: You will also be
heard. He is on a point of order. Let
me hear it. Shri Basu.

SHRI CHITTA BASU (Barasat):
Sir, I am on a point of order. I have
given notice of an adjournment mo-
tion on the firing at BHEL....

SHRI KRISHNA CHANDRA HAL-
DAR: I should be heard, Sir.

SHRI CHITTA BASU: Sir, I have
given an adjournment motion under
rule 60 for discussing the firing on
the BHEL workers at Hardwar which
had taken place on the 23rd of March
last.

Sir, under Rule 60, you have got
only two options. You have to state
the reason why you have not accep-
ted it.

MR. SPEAKER: I have stated;

SHRI CHITTA BASU: But, I have been communicated in a whispering way. It was communicated and the reason stated here is that since the Demand of the Ministry of Home Affairs is likely to be discussed ...

MR. SPEAKER: Ministry of Industries—not Home Ministry.

SHRI CHITTA BASU: It does not concern the Industries Ministry.

MR. SPEAKER: I have said, the concerned ministry.

SHRI CHITTA BASU: I think you should give me an opportunity to explain my position and also listen to the Minister concerned, under Rule 60. And then you can decide whether you will admit my motion or not. I rise under Rule 60, proviso (2). Before deciding whether you will reject or not you may ask for my explanation. My adjournment motion is not directed against the Industries Minister. It is directed against the Home Minister because the Central Industrial Security Force is under the direct control of the Home Ministry.

Sir, under our Constitution, the Law and Order falls under the State Government. But, the Central Industrial Security Force is under the administrative control of the Home Ministry of the Government of India. Secondly, Mr. Speaker, Sir, you would also know that the Central Industrial Security Force are not to take orders from the local police.

MR. SPEAKER: Mr. Basu, you are not to argue that matter.

SHRI CHITTA BASU: I want that the adjournment motion should be accepted and I should be given the chance to discuss it. You discussed the question of Lucknow. This is a very important matter. CISF has

run amuck and created trouble. They have injured a number of workers. One worker has been killed.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Mr. Speaker, Sir, I have also given notice of an adjournment motion on the similar subject. The Central Industrial Security Force comes under the Home Ministry. BHEL is also a public undertaking. We want to have a discussion and, as such, you should allow our adjournment motion. It is a very serious matter. We want CISF should be abolished and withdrawn from BHEL.

MR. SPEAKER: You are now going into the facts of the case.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Either you allow our adjournment motion or I have also given notice of a Calling Attention motion. *(Interruptions)*

Since yesterday Central Industrial Security Force has again been deployed in the factory. There may be breach of peace again. So, Sir, we want your ruling.

MR. SPEAKER: I have already given my ruling.

SHRI CHITTA BASU: What is the argument for your rejection?

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: It is a Central force and it comes under the Home Ministry.

SHRI CHITTA BASU: You cannot brush it away. I draw your attention to Rule 60 proviso (2). I want to know your ruling.

MR. SPEAKER: I have already made my observation. Proviso 2 merely says 'if the facts are not clear.' Nothing more. Now, I call Mr. Fernandes.

12 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—
Contd.

DETAILED DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79 OF THE MINISTRY OF INDUSTRY

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): Sir, on behalf of Shri George Fernandes, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Industry for 1978-79. [Placed in Library. See No. LT-1900/78].

ANNUAL REPORT AND REVIEW OF TECHNICAL TEACHERS' TRAINING INSTITUTE, CALCUTTA FOR 1976-77 AND STATEMENT FOR DELAY

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI): I beg to lay on the Table—

(1) (i) A copy of Annual Report (Hindi and English versions) of the Technical Teachers' Training Institute (Eastern Region) Calcutta, for the year 1976-77.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Technical Teachers' Training Institute (Eastern Region), Calcutta for the year 1976-77.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above documents. [Placed in Library. See No. LT-1901/78].

ANNUAL REPORT OF KHUDA BAKSH ORIENTAL PUBLIC LIBRARY, PATNA FOR 1976-77 AND A STATEMENT

**श्रीमान्, समाज कल्याण तथा संस्कृति
संरक्षण के लिये (जो खयाल है)**

बुलबुल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा
पटल पर रखता हूँ :—

(1) खुदा बखश ओरियन्टल लाइब्रेरी
प्रतिनियम, 1969 की धारा 2 की उप-
धारा (4) के अन्तर्गत खुदा बखश
ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी पटना के
वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन
(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक
प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे :

(2) यह बताने वाला एक विवरण
(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) कि उपरोक्त
प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और
इसलिए पृथक समीक्षा सभा पटल पर
नहीं रखी जा रही है : [Placed in
Library. See No. LT-1902/78].

**NATIONAL SAVINGS CERTIFICATES (5TH
ISSUE) AMDT. RULES, 1978 AND NATION-
AL DEVELOPMENT BONDS (AMDT.)
RULES, 1978**

**THE MINISTER OF STATE IN
THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI ZULFIQUARULLAH):** I beg
to lay on the Table a copy each of
the Notifications (Hindi and English
versions) under sub-section (3) of
section 12 of the Government Savings
Certificates Act, 1959:—

(1) The National Savings Certi-
ficates (Fifth Issue) Amendment
Sabha I am directed to return
tion No. G.S.R. 338 in Gazette of
India dated the 11th March 1978.

(2) The National Development
Bonds (Amendment) Rules, 1978,
published in Notification No. G.S.R.
339 in Gazette of India dated the
11th March, 1978. [Placed in Li-
brary.. See No. LT-1903/78].

12.03 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha —

(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha I am directed to return herewith the Appropriation Bill, 1978 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st March 1978, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill"

(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha I am directed to return herewith the Appropriation (No 2) Bill 1978, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st March 1978 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill"

(iii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha I am directed to return herewith the Mizoram Appropriation (Vote on Account) Bill 1978 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st March 1978 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendation and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill"

(iv) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule

186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha I am directed to return herewith the Mizoram Appropriation Bill 1978, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st March 1978 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill

(v) In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha I am directed to return herewith the High Denomination Bank Note (Demonetisation) Bill 1978, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st March 1978 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendation to make to Lok Sabha in regard to the said Bill"

(vi) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 21st March 1978 agreed without any amendment to the Hindustan Tractors Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1978 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd March 1978

12 05 hrs

CALLING ATTENTION TO MATTER
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

OBSTRUCTIONS IN THE FUNCTIONING OF
GROVER COMMISSION

SHRI HARI VISHNU KAMATH
(Hoshangabad) Mr Speaker Sir, may I now call the attention of the Minister of Home Affairs, to the following matter of urgent public importance

and request him to make a statement thereon.

"Reported serious situation arising out of impediments being put in the way of smooth functioning of the Grover Commission, and its Chairman, Shri Grover, former Judge of the Supreme Court, being threatened with dire consequences allegedly by the supporters of the Chief Minister of Karnataka, thus obstructing the Commission in the proper discharge of its lawful functions."

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): The proceedings of the Grover Commission of Inquiry held at Bangalore on the 8th March, 1978 were interrupted for about ten minutes, at about noon by a handful of demonstrators who, shouting slogans "Grover Go Back" came along the corridor leading to the Court-room and tried to enter the Court Hall. The Secretary to the Commission and other staff immediately closed the door to prevent the demonstrators from entering the Court Hall. But before they could do so, one of the demonstrators brought out a black cloth from his pocket and waved it before the Commission.

Since the sittings of the Commission were open to the public, the local police could not, initially, prevent the persons, who made the demonstration, from approaching the Court-room through the corridor, but as soon as the intentions of the demonstrators became known, they were pushed back by the local police and 18 persons including a Member of Legislative Council, by whom the demonstrators were led, were arrested by the police and were produced before a Magistrate. Later on, they were released on bail by the Magistrate. The demonstrators were seen to be accompanied by a photographer with a flash-gun and a photograph was taken and published in the 'Indian Express', Bangalore.

An unsigned post-card purported to have been written by the Youth Wing of the Congress (I) were received by the Commission on 9th March, 1978, in which a threat was held out to Shri A. N. Grover to wind up the Commission within 48 hours or to face the consequence of death either in Bangalore or in Delhi. There was also a threat to place a bomb in the Court room of the Commission. The matter was placed in the hands of the Commissioner of Police, Bangalore, by the Secretary to the Commission for necessary action. As advised by the State Police, arrangements were made to regulate the entry to the Commission's premises by pass. Further security arrangements were made by the State Police for the safety of Shri Grover and Commission's officers and personnel and the smooth functioning of the Commission at Bangalore. The Chief Minister of Karnataka made a Press statement in which such demonstrations were condemned.

There was another demonstration before the premises of the Commission on the morning of 18th March, 1978, when some leaf-lets were thrown by them. The demonstrators were prevented by the police from entering into the compound and about 20 persons were arrested.

The State Government has stated that the demonstrations were peaceful and that there was no cause for any alarm. The Commission has been proceeding with its work.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Mr. Speaker, Sir, the happenings set forth in the lucid statement of the Home Minister, are, to say the least, execrable. Are there reasons to believe, that these happenings and these demonstrations, etc. like the one at Lucknow which was discussed in the House last week, are part of a foul conspiracy and nefarious design hatched by the former fascist mini-dictator....

AN HON MEMBER Why Mini-dictator? Why not full dictator?

SHRI HARI VISHNU KAMATH
Aided by her-henchmen and hatchet-men**

SHRI VASANT SATHE (Akola)
Like Mr Kamath

SHRI HARI VISHNU KAMATH
To create lawlessness violence and di-order as was suggested by the Home Minister last week in this House The ex-Prime Minister has made a statement I find in the newspapers denying the charge made against her But knowing as we do Sir her low credibility, her built in allergy to truth and flair for speaking the untruth her statements need not be taken at their face value And therefore may I ask whether the Home Minister is in a position to assure the House and through the House the entire nation that these despicable and desperate attempts on the part of the fallen fascist mini-dictator and her henchmen and hatchetmen to create disorders

SHRI VASANT SATHE On a point of order Let me make it clear The other day you stopped me when I just said that some people suffer from moon stroke and I gave the dictionary meaning of the word one who is struck by luna, you said do not even by implication say this

Now Mr Kamath has used all these words in the call attention In the reply the Home Minister says alleged letter alleged to have been signed unsigned letter, alleged to have been sent by Youth Congress, that is the maximum that he has gone Now by what stretch of imagination in this call attention can Mr Kamath refer to the ex-Prime Minister whatever may be his hatred? How does it come in here

They are defamatory calling her mini and whatever he wants to call her . (Interruptions) These are undignified, defamatory per se remarks All of them must be expunged because they are completely out of context

Either they are expunged or you allow us and I will just now on this very floor utter the same things and***

MR SPEAKER Do not record
(Interruptions) Nothing is recorded

Mr Sathe has not even the patience to ask for an order He raised a point of order and ended in a point of disorder He went on abusing somebody I do feel that some of the remarks of Mr Kamath are irrelevant in the context he should not have used them But the behaviour of Mr Sathe is totally deplorable

(Interruptions)

SHRI B P KADAM (Kanara) On a point of order Under Rule 353, no allegation can be made against a person who is not present and capable of defending It is substantiated in page 777 of 'Kaul and Shakdhar' Whatever Mr Kamath has said has to be expunged

MR SPEAKER I shall examine the matter I shall go through the proceedings

CHOWDHRY BALEIR SINGH (Hoshiarpur) On a point of order

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur) Mr Sathe's remarks are highly objectionable

MR SPEAKER It is not recorded please

(Interruptions)

**Expunged as ordered by the Chair

***Not recorded

SHRI C. M. STEPHEN (Indukki): Now that the matter has been raised, I am rising on a point of order.

MR. SPEAKER: Let me hear him first. He has raised it first.

श्रीवरी बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है । अभी साठे साहब ने आपकी ओर सारे हाउस की मीजिंगों में कामत साहब के बारे में जो प्रलफाब इस्तेमाल किए हैं ...

MR. SPEAKER: It has not been recorded.

श्रीवरी बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आप सुन लें । (अव्यवधान) मैं एक बात कह रहा हूँ, आप उसमें किसी और को न बोलने दें । मैंने यहाँ एक बात कही है, आप मेरी बात पूरी सुनें वर्यं कभी उसे आगे रूक कर सकते हैं ?

मेरा प्रॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि साठे साहब ने इस हाउस में कामत साहब के बारे में सारे हाउस के सामने जा कुछ कहा है यह बाजारी गुंडों की जवान है और मध्य लॉग इस किम्म की जवान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं । इन्होंने जो प्रलफाब कहे हैं, यह उन प्रलफाबों को बर्बाद लें और उस के लिए माफी मांगें, नहीं तो मैं प्रिबिलेज मोशन भ्रूष कर रहा हूँ कि इन्होंने हाउस के एक सीनियर मेम्बर को तोहीन की है । उन के लिये आप इस प्रिबिलेज मोशन को बलाऊ कबे ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): On a point of order. I want to invite your kind attention to Rule 380. Rule 380 says:

"If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent

or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House".

This is Rule 380. What was said by my colleague, Mr. Kamath against Shrimati Indira Gandhi was not unparliamentary. He used the words 'mini-dictator, 'Mini-dictator' is not unparliamentary. About the other adjectives they were not used against Mrs. Gandhi, but against her demonstrators, who went there to do all sorts of mischief. Nothing was said against Mrs. Gandhi. If I say that Mrs. Gandhi is a mini-dictator, it is not unparliamentary.

SHRI VASANT SATHE: Why not?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: What was said by my colleague, Mr. Sathe was

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I can hear only one. How can I hear everybody?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, what was stated by Mr. Sathe was not only unparliamentary, but was not dignified for a Member to use such words. I think no Member of this House, no decent person even outside, will use these words which were used by my colleague, Mr. Sathe, against Mr. Kamath. May I request you to see the record and if those words are undignified, they should be expunged.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I will consider.

श्रीवरी बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है, आप पहले उसके बारे में फैसला करें ।

MR. SPEAKER: I am considering all the matters.

SHRI C. M. STEPHEN: I am rising under the same rule that has been cited here.

श्री सुविनयार सिंह भिलक (सानीपत):
जिम तरह की बात हाउस में कही जा
रहा है, पहले कमी यहाँ नहीं कही गई है।
(अवधान)

... But he should not be allowed
to utter those words.

MR SPEAKER You better hear him
and then talk about it.

SHRI C M STEPHEN I am rising
under the same rule that has been
cited here. The Calling Attention was
here and Mr Kamath had, under the
Rule which is a question that has got
to be put made certain comments
which had absolutely no relevance to
the matter before us. One thing may
be very clearly understood. We are
human beings we have got our feel-
ings. Here is a party which you have
recognised as the Parliamentary Party.
There is a person who is our Presi-
dent whoever it be. Now, when you
make certain remarks about the Presi-
dent of a political party, which has
got its wing here as a recognised
political party, let it be very clearly
understood that such remarks if not
warranted and disparaging will not
be taken lightly.

(Interruptions)

श्री कंचर लाल गुप्त : उन्होंने लाग्या
लोगा का 18 महीन जेल मग्खा ।

Hundreds of persons were killed

SHRI C M STEPHEN No cer-
tain words were used here. There are
two questions. One is, whether the
words used with reference to whom-
soever is concerned were dignified and
parliamentary hoodlums, hooligans
etc. You will kindly go through those
words. Whether those words are
parliamentary or not is a matter which
you may judge. If those words are
parliamentary with reference to any-
body, they can be parliamentary with
reference to anybody else also. There-
fore, if those words once used by them

allowed to remain on record, then
you are giving a ruling that those
words are perfectly in conformity with
the dignity of the House and are
parliamentary and therefore person
whom we may judge to be a bad per-
son with reference to him we also can
use those words. In the judgement
of my friends there A may be a bad
person. In my judgement B on the
other side however respectable may
be a bad person. The question is
whether this epithet can be used on
the floor of the House with reference
to anybody. Now I plead with you
to consider whether those words can
be adjudged as parliamentary or not.
If you judge that they are parliamen-
tary then the retention of those words
uttered by Mr Kamath on the one
hand and expunction of those words
uttered by Mr Sathe on the other
hand is obviously discriminatory and
will not be possible at all. Therefore
I do plead with you to consider the
parliamentariness of those words and
to order the expunction of those words.
(Interruptions)

Secondly, my point of order is that the
comments made by Mr Kamath were
absolutely irrelevant to the matter be-
fore the House. Therefore such re-
ferences to matters which are not re-
levant will not be permitted and those
must be expunged.

THE PRIME MINISTER (SHRI
MORARJI DESAI) May I say that all
this does not at all bring in dignity to
this House? When Shri Kamath used
the word hooligans for those who
created that kind of scene before the
Commission I cannot say that was
unparliamentary. Let us have some
sense of discrimination. If one refers
here to robbers" should we not refer
to them as robbers? If one refers to
some rioters could we not refer to
them as hooligans? Therefore what
Shri Stephen has said with all due
respect to his parliamentary acumen,
I must say, when he says that that
word should not be used for anybody
well then we will not make any de-
bate truthfully. But I do say, when

Shri Kamath referred to the leader of that party, may be outside and not here, he should not have done that. There I agree readily. He need not have brought that into this at all. Whatever may be the aversion of anybody, that should not be brought in. But my friend, Shri Sathe's conduct is thoroughly indefensible. He abused him here in the House; he abused in so uncertain terms. Therefore, that cannot be justified by anybody. But I do not want to raise a point. (Interruptions) He cannot go beyond his nature.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I am grateful, Sir, to the Prime Minister for his profound observations by which we will all be guided. May I say, in all humility, with all earnestness, I will not descend to the low level to which my hon. friend, Shri Sathe, has sunk. But when I said that the ex-Prime Minister is a Fascist, was a Fascist mini-dictator, that was no term of abuse at all. I called her a mini-dictator, small dictator, not a big dictator.

SHRI C M STEPHEN: The matter is before you, Sir. If you say that the matter is— (Interruptions)

बीधरी बलबीर सिंह: इन का वे शब्द नाम लेने चाहिए। (व्यवधान)

MR SPEAKER. Chowdhry Balbir Singh, why do you want to use so much lung power?

SHRI HARI VISHNU KAMATH: May I ask whether the Home Minister is in a position to assure the House, and through the House the entire nation, that these desperate and despicable antics and gimmicks on the part of the demonstrators, the hooligans—I do not refer to the ex-Prime Minister at all—will be firmly countered, because I have also seen reports to say that there have been slogans raised "Wind up CBI" "Grover Commission, pack up and go

home." These slogans have been raised. Therefore, will the Home Minister assure the House and the entire nation that these antics and gimmicks, these wild demonstrations, these despicable desperate attempts to create lawlessness and disorder, to which the Home Minister referred last week in regard to the Lucknow demonstrations will be firmly countered and, further, the Grover Commission, which was appointed, which has been appointed, by the Central Government will be afforded adequate protection in the discharge of its lawful functions and all obstructionists, miscreants, hooligans and hoodlums will be firmly dealt with, brought to look and sternly dealt with.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, what about your ruling?

MR SPEAKER: After the Prime Minister's statement, I thought it was not necessary.

श्री नरूप सिंह (बोहा): जा इन्तोंने कहा उन के लिए इन को हाउस में भागी मानने चाहिए।

SHRI CHARAN SINGH: As at present advised, that is, according to the information received from the State Government, I hope the Grover Commission will be able to work peacefully.

श्री गौरी शंकर राय (गजौपुर): अध्यक्ष महोदय, प्राइम मिनिस्टर के बयान नहीं है लेकिन जो प्रश्न लॉर्डरी शब्द रिपोर्ट पर क्ले गये हैं, आपने एक्सपोज भी नहीं किये हैं उनके लिए माननीय सदस्य का काम से कम रिप्रेट करना चाहिए।

MR. SPEAKER: You are under a wrong impression. None of those abusive words have gone on record. I am again going into the matter. If any of them have gone into it, I shall direct expunction. But I must ex-

[Mr. Speaker]

press my total unhappiness with the behaviour of Mr. Sathe because he used abusive language.

SHRI VASANT SATHE: On a personal explanation.

MR. SPEAKER: It is one thing to use strong language and another to use abusive language.

SHRI VASANT SATHE: You will remember that all I said was that if you allow...

MR. SPEAKER: It is on the tape. If you want, I will give you a copy. It is all on the tape. You have used very abusive language.

SHRI VASANT SATHE: No, no, I have not.

MR. SPEAKER: I shall give you an extract of it.

SHRI VASANT SATHE: All I said was that if you allow those words to be used, then you must allow the same words to be used by me.

MR. SPEAKER: No, no. In your excitement, you have forgotten.

SHRI VASANT SATHE: Even in my excitement, all I said was that if you allow those words to be used against the ex-Prime Minister, all those words used by Mr. Kamath...

MR. SPEAKER: No. You said much more, you said, "You are mad..."

SHRI VASANT SATHE: Again, what the Prime Minister has said is all right...

MR. SPEAKER: Please don't record.

SHRI VASANT SATHE: **

SHRI S. NANJESHA GOWDA (Hassan): I have heard very carefully the statement of the Home Minister on the Calling Attention. This is a matter concerning my State. Kindly give me two minutes extra, that is all.

Our senior leader has already enlightened us about the situation. The hon. Minister has also given some assurance. I would like to ask who is doing all this demonstration first. It is those against whom the enquiries are being conducted, it is those against whom the CBI investigations are pending, it is those against whom the cases are pending. In this we can very well see.

SHRI CHARAN SINGH: The rules allow only questions to be put to the Government, and not a speech. He is delivering a speech.

MR. SPEAKER: The Direction given by the Speaker says that in a Calling Attention, the Member can have three minutes to speak.

SHRI S. NANJESHA GOWDA: I will finish within three minutes.

We have seen the interim report as reported in the newspapers, that cases have to be registered against Devraj Urs for having shown undue favour to his son-in-law, Dr. Nataraj. Dr. Nataraj was the Commander of the Indira Brigade, you must be knowing. He was the Chief Commander in the State.

SHRI C. M. STEPHEN: On a point of order. There are two matters—one matter being pending before the Grover Commission. The matters pertaining to Mr. Devraj Urs, allegations against him are being inquired. Rules prohibit discussion or references to those matters anything that is before the Tribunal. The second matter is about disturbances created and allegations against them. The Home Minister has told us that those persons have been arrested, cases have been registered against them. Therefore, any reference to those incidents, to those persons, is not permissible on the floor of the House as they are sub-judice. Therefore, either way with reference to the matter pending before the Shah Commission is not permissible being a matter before the

Tribunal and the other being sub-judiced not permissible under rule of sub-judice. Any such observations can be permitted which have references except to these two matters. What my learned friend is now saying has got direct reference to the matter before the Grover Commission and statements are being made about it. This I would submit should not be permitted on the floor of the House.

MR. SPEAKER: There is a misconception. What the statement merely says is that the demonstrations were arrested.

SHRI C. M. STEPHEN: Admitting of that is absolutely all right. I am not objecting to that. But references to those persons, details of the incidents, identification of persons, characterisation of them, are all wrong.

SHRI MORARJI DESAI: What has been referred to the Commission or what the Commission was enquiring into, that should not be discussed. There he is right and I agree with him. I would appeal to my hon. friend not to bring in these things here.

MR. SPEAKER: Mr Stephen's contention that the matter is sub-judice may not be correct because what the Home Minister's statement says is that they were merely produced before the Magistrate and they have been released on bail. The case is still under investigation. The case is not before the court.

SHRI C. M. STEPHEN: One is before the Magistrate. The persons have been produced. Absolutely sub-judice.

SHRI S. NANJESHA GOWDA: I am only referring to one thing.

MR. SPEAKER: Do not refer to the matter pending before the court.

SHRI S. NANJESHA GOWDA: I am only referring to those persons who are organising these demonstrations. It is the Chief Minister and his other Ministers who are organising it. There is truth in that. And these people, Dr. Natraj and his another colleague, Shri Srikant Rao... (Interruption)

MR. SPEAKER: Please do not go into the substance of the matter.

SHRI S. NANJESHA GOWDA**** (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am not allowing him to go into the matter. If he goes into it, I will take it out. (Interruptions) If it is there, I will remove it.

SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY (Kanakapura): Even in spite of the request made by the hon. Prime Minister, even in spite of the ruling by the hon. Chair, the hon. Member is defying. Steps will have to be taken against him. Under Rule 353 of the Rules of Procedure, nothing can be said against a person who is not present in the House. This is substantiated on page 777 of Kaul & Shakhder's Book. Therefore, steps will have to be taken against him.

MR. SPEAKER: I will not allow any defamatory or inflammatory statement.

SHRI S. NANJESHA GOWDA: If whatever is told by me is untrue or if there is anything false uttered by me...

MR. SPEAKER: Even if it is true, you cannot make defamatory statement.

SHRI S. NANJESHA GOWDA: I will come to the question. These people, whoever they are, however big they are, these demonstrators

[Shri S Nanjesha Gowda] must be dealt with firmly I want this assurance from the Home Minister Shri Grover is humiliated, the hon Governor is humiliated, they are humiliating everybody You can very well see how Mr Sathe behaves here His friends behave in the same way

MR SPEAKER Please do not go into these matters

SHRI S. NANJESHA GOWDA I want an assurance from the hon Home Minister that all possible steps would be taken against the economic offenders At the same time I want the Grover Commission to function smoothly Advocates must go and present their cases freely and frankly Witnesses must go and speak frankly This must be looked after

SHRI CHARAN SINGH I have already given a reply

MR SPEAKER Prof P G Mavalankar—not here

Shri Ainthu Sahoo—not here

SHRI VASANT SATHE Are the remarks against the Chief Minister which were made by the hon Member Shri Gowda allowed to remain?

MR SPEAKER I shall examine if there are any defamatory remark

SHRI VASANT SATHE Not only defamatory remarks Rule 352 says, even against persons in high authority" which includes Chief Minister, no such words can be used Kindly see that

MR SPEAKER I will see that

श्री गौरी शंकर राय • म न्यत्र निवे-
नन यह करना है कि अभी हमारे मित्रों न
प्लाइड आफ आर्डर उठाया है कि उस
आदमी का जिक्र न हा जा यहा मौजूद न
हो । लेकिन जितने कर्प्ट नागों के खिलाफ
कमीशन देने हैं वहा इनकी तरह हर
आदमी को बुनाया जायगा यह सम्भव
नही है ।****

MR SPEAKER: No, not don'tt record that I am expunging

12 42 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

- (1) REPORTED STRIKE BY EMPLOYEES OF
INDIAN OIL CORPORATION ON
22-3-78

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मदतोर)
अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से नियम
377 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण विषय
प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गत 22 मार्च
को इंडियन आयल कारपोरेशन के
लगभग तीन हजार अधिकारियों ने
अपनी कुछ मांगों का ले कर यकायक आक-
स्मिक अवकाश पर चले गये और हडताल
कर दी। इसने कारण बरौनी हल्दिया,
गौदाटी स्थित रिफाइनरीजका मारा काम-
काज ठप्प हा गया और टम वाम-काज
के ठप्प होने से वाग्पारेशन का कराडा
रुपय की हानि हुई। इस सम्बन्ध में जो
सूचना प्राप्त हुई है उसमें लगता है
कि इंडियन आयल कारपोरेशन के
अधिकारियों ने यह भी कहा है कि
अगर उनकी बाता का स्वीकार नहीं
किया गया तो आगे चल कर ऐसी परि-
स्थिति फिर पैदा हा सकती है और
रिफाइनरीज से सम्बन्धित अधिकारी
फिर के सामूहिक अवकाश के जरिये
हडताल कर सकते हैं। इसलिए और
उससे अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हो
सकते हैं। इसलिए इस विषय को गंभीरता

से लिखा जाना चाहिए। अगर इन रिफाइ-नरीज का काम ठप होता है तो हमारे देश की करोड़ों रुपये की हानि होगी। इसलिए इस विषय पर मंत्री महोदय बताय कि इस सामूहिक अवकाश के क्या कारण थे, उन अधिकारियों की क्या मांग थी और अगर इस हड़ताल को न होने देने के लिए और उन अधिकारियों की मांगों की पूर्ति की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं। तथा एक हड़ताल या सामूहिक अवकाश के कारण कितनी हानि हुई।

(ii) MEDICAL OFFICERS OF NATIONAL HEALTH SERVICES

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, नियम 377 के अन्तर्गत, 484 नेशनल मेडिकल आफिसर्स जो नेशनल हेल्थ, सर्विसिज में हैं, के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आपको मून कर आश्चर्य और दुःख होगा कि इन डाक्टरों में से कुछ की गत दस वर्षों में और कुछ की गत 13 वर्षों से कन्फर्मेशन नहीं की गयी है और न उन को कोई प्रमोशन दी गयी है। नियम के अनुसार, इनकी नियुक्ति के पाच वर्ष के पश्चात् इनका नाम डी० पी० सी० या डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में भेजा जाना चाहिये था। 13 वर्ष के पश्चात् भी इनका नाम डी० पी० सी० को नहीं भेजा गया। इसके सम्बन्ध में मैंने सदन में प्रश्न भी पूछा था और स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था लेकिन आज तक इन डाक्टरों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरे पत्र के उत्तर में कहा गया था कि दिसम्बर, 1977 में डी० पी० सी० होगी लेकिन वह भी काम अभी तक नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति देंगे तो इन सारे 484 डाक्टरों की सूची जिनका गत 10 या 13 वर्षों से कन्फर्मेशन या प्रमोशन नहीं हुआ है, मैं सभा पटल पर रख दूंगा। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप स्वास्थ्य मंत्रालय को यह नदेश दे कि सरकार नियमों का इन डाक्टरों के मामले में पालन करे। और उन का शीघ्र से शीघ्र कनफर्म करें। नियमों के अनुसार उन का प्रमोशन भी होना चाहिए।

बहुन दुःख की बात है कि ये जो डाक्टर हैं ये यू. पी. ए. सी. के जरिये रिक्त हो कर आए हैं और इन के बाद आए हुए जो दूसरी जगह चले गए हैं वे फिर आकर उन से सोनियर हो जाते हैं। जा निष्ठापूर्वक सी. जी. एच. एम. में काम कर रहे हैं उन की दस से 13 वर्ष तक पदाव्रति का सवाल तो चल रहा उनको आज तक कनफर्म भी नहीं किया गया है।

इन 484 डाक्टरों की सेवाओं को शीघ्र म शीघ्र नियमों के अनुसार कनफर्म किया जाए और उन का जल्दी से जल्दी डी० पी० सी० के पास भेजा जाए। इन डाक्टरों को यह शक है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में कुछ प्रशासक बैठे हुए हैं जो उन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इन के केसिम वे डी० पी० सी० के पास नहीं भेजे रहे हैं। यह बहुत दुःख की बात है कि क्वालिफाइड डाक्टरों को दस बरस तक अने कनफर्म रखा जाए।

(iii) REPORTED DISCONTENTMENT AMONGST CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES FOR NON-PAYMENT OF ADDITIONAL DA IN CASH.

श्रीमती ग्रहिल्या पी. रांगनेकर (बम्बई उत्तर मध्य) : केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को जो किश्त मिलनी चाहिये थी

[श्रीमती ग्रहिल्या पी० रंगनेकर]

वह केन्द्रीय सरकार ने उन को नहीं दी है। पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार वह इन को मिल जानी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने एभी भी कर लिया है लेकिन अभी तक वह इन को नहीं दे रही है। गवर्नमेंट ऐसा भी सोच रही है कि यह जो मंहगाई भत्ता है उस के उन का बाड्ज दिये जायेंगे जो दस साल के बाद इनकोश किए जा सकेंगे। मंहगाई भत्ता पगार या बतन को बढ़ातरी नहीं है। चीजों की कीमतें बढ़ती है तो उन की परबोजग पावर को कायम रखने के लिये यह भत्ता दिया जाता है। सरकार द्वारा प्रमाणित किए हुए भी दो महीने हों गए हैं लेकिन अभी तक उन को यह भत्ता नहीं दिया गया है। इस कारण से उन में बहुत असन्तोष है। इस के बारे में सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। जो कीमते बढ़ी है उन के लिए वे जिम्मेवार नहीं है। वे गवर्नमेंट की नीति के कारण ही बढ़ी है। इन के लिए उन को दंडित करना उचित नहीं है। इस डी० ए० की किरत के बारे में जल्दी से जल्दी धारा ५५ फंसला करना चाहिए और उन को इस को देना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो उन में व्याप्त असन्तोष और ज्यादा बढ़ जाएगा और उस में एडमिनिस्ट्रेशन भी इफैक्ट होगा।

(iv) REPORTED CLASH BETWEEN SENIOR OFFICER OF LAKSHDEEP ADMINISTRATION AND STUDENTS OF J. N. COLLEGE

SHRI P M SAYEED (Lakshadweep). Mr Speaker, Sir, it has now become my painful duty to bring to your kind notice an apparently innocent request to the officials by the students of Jawaharlal Nehru College at Kavaratti in the Union Territory of Lakshadweep and their parents not to have inauguration of the official function within 11 feet away from the college function on 3rd March, 1978. The students of the college were celebrating their college day on 2nd & 3rd of March

within the college premises with the permission of the authorities. On the same day just 11 feet away from the students stage in the college premises, the government officials constructed a stage for the inauguration followed by cultural functions of the 'Kerala Samajam' consisting of only government officials of the island. This was naturally not very much to the liking of the students as they were afraid that the government officials function might mar their college day. So this matter was discussed by the students and their parents and they have decided to send a deputation to the officials to shift their venue to somewhere else. This decision was taken solely for the reason that the students were not in a position to shift their function anywhere else away from the college. Apart from this, it appeared to the parents as well as the students that the decision of the officials to have their function very close to the college day function is only an accident and if requested, good sense would prevail over them and they would shift their venue from the college premises. With this in view a deputation of parents approached the senior most officials available on the island as on that day neither the administrator, nor the collector was available in the island, and conveyed the feelings of the students and humbly requested that the official inauguration may not be near the college premises where the students college day celebrations were going on. This request, to the utter dismay and disappointment of the island community, evoked only hatred towards the deputationists and students instead of sympathy. In the result, simultaneously when the official function of inaugurating their samajam was taking place, some miscreants threw a chappal on the stage from amongst the audience which totally irritated the official community. Somebody hurled abuses from the stage in reaction to the incident. Suddenly the lights went off, and in a few minutes, pandemo-

niun prevailed over the entire scene. In the process, seventeen students, including seven girls, were severely hurt. I am ashamed to say that the girls were actually molested, and this has happened with the active help and connivance of the police. I am informed by responsible people from the island that those who have actually given a lead to this are (1) Settlement Officer, (2) Director of Fisheries, (3) Tahsildar, Kavaratti, (4) Junior Lecturer in Malayalam, J.N.C., (5) another Junior Lecturer, (6) Junior Engineer, P.W.D., and (7) Poultry Farm Manager. This incident has caused great agony and apprehension in the minds of the islanders about their very existence in the island. They are afraid that the official machinery will be let loose for repressive action against them, and as a prelude to this, section 144 has already been imposed and the help of the military was sought; and to add insult to the injury, the officials have started giving official statements implicating the innocent islanders. The communications of messages to other islands were stopped. This has further embittered the feelings of the islanders towards the above officials. This state of affairs, in my humble opinion should not be allowed to continue in the national interest. I am also sorry to state in this context that the above-said ugly incident was engineered by the above officials who cannot even now tolerate the up and coming population who are till now a downtrodden people.

It is a typical example of how a handful of people can completely spoil an extremely good relationship established between two classes of people because of the sincere and good work of people with foresight over the years. In this context I may also say that the Kerala Samajam is not coming to the island for the first time; this Samajam is functioning with the sincere cooperation of the

islanders in all the other islands. Therefore, no one can accuse that the islanders are against the Kerala Samajam and that this has caused the incident.

As I have stated earlier, this incident has created extreme tension and apprehension in the minds of the island community, especially so among the student community of the island. The people in the island are showing enough restraint, but their feelings may erupt in any shape unless their grievances are redressed by immediate government action.

I, therefore, request that; the Government may immediately institute a judicial inquiry by a High Court judge into the matter and pinpoint the culprits. Pending the inquiry, the Government may keep the officials mentioned above under suspension as they are *prima facie* guilty of offence of assault on students, both boys and girls, and may also send a goodwill mission to the islands to re-establish rapport and good relationship between the islanders and the Keralites. A fact-finding mission of Parliament consisting of Members from all the Parties may be sent to the islands and the facts ascertained.

The incident might apparently look like a simple one, but is deeper than what it appears on the surface. An element of pre-planning cannot be altogether ruled out.

I, therefore, request the hon. Minister of Home Affairs to make a statement on the floor of the House accepting the above-mentioned legitimate demands of the islanders to prevent the recurrence of such incidents and to create a sense of confidence among them.

12.55 hrs.

DEMANDS* FOR GRANTS 1978-79**MINISTRY OF DEFENCE**

MR SPEAKER The House will now take up discussion and voting on Demands Nos 19 to 24 relating to the Ministry of Defence, for which four hours have been allotted

Sarvashri P Rajagopal Naidu and Baldev Singh Jasrotia have tabled cut motions to the demands for grants relating to the Ministry of Defence I would like to know if they are present and desire to move their cut motions

SHRI P RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor) Yes, Sir, I am moving

SHRI BALDEV SINGH JASROTIA (Jammu) I am also moving

MR SPEAKER Motion moved

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1978, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos 19 to 24 relating to the Ministry of Defence"

Demands for Grants 1978-79 in respect of the Ministry of Defence submitted to the vote of Lok Sabha

No of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 16-3-1978		Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House	
		Revenue Rs	Capital Rs	Revenue Rs	Capital Rs
MINISTRY OF DEFENCE					
19	Ministry of Defence	14 78 76 000	11 71 73 000	73,93 78 000	58 58 67,000
20	Defence Services—Army	316 32 08,000		1581,60,39 000	
21	Defence Services—Navy	34,25 62,000		171,28,08,000	
22	Defence Services—Air Force	97 68 98 000		488 44 92,000	
23	Defence Services—Pensions	25 10 46,000		125 52 29 000	
24	Capital Outlay on Defence Services		48 89 86 000		244,49,28,000

*Moved with the recommendation of the President

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Defence be reduced by Rs. 100."

[Need to modernise army to contain even the first rate nations (1)].

"That the demand under the head of Ministry of Defence be reduced by Rs 100."

[Failure to make our own planes necessary for our needs (2)].

"That the demand under the head Ministry of Defence be reduced by Rs 100."

[Need to provide more funds to conduct research in Bharat Electronics Ltd. for the development of new products which are comparable with the best available in the world market (3)].

"That the demand under the head Ministry of Defence be reduced by Rs. 100."

[Need to improve Praga Tools Ltd. (4)].

"That the demand under the head Defence Services-Army be reduced by Rs. 100"

[Need to strengthen Research and Development Organisation (5)].

"That the demand under the head Defence Services-Navy be reduced by Rs. 100"

[Need to strengthen our Navy (6)].

SHRI BALDEV SINGH JASRO-TIA: I beg to move:—

"That the demand under the head Defence Services-Army be reduced by Rs. 100."

[Need to increase avenues of promotion in the Army (7)].

"That the demand under the head Defence Services-Army be reduced by Rs. 100."

[Need to increase pension in the Army (8)]

"That the demand under the head Defence Services-Navy be reduced by Rs. 100."

[Need to re-appoint ex-Navy persons (9)].

"That the demand under the head Defence Services-Navy be reduced by Rs. 100."

[Need to increase ration in the Navy (10)].

MR. SPEAKER: The cut motions are also before the House.

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur): Mr. Speaker, Sir, may I request you and, through you, the House and the Minister of Parliamentary Affairs that Defence being a very important subject on which a number of hon. Members would like to speak, the time allotted to it may please be extended from four hours to at least six to seven hours or eight hours, if need be.

PROF. SHIBBAN LAL SAKSENA (Maharajganj): I support this.

MR. SPEAKER: Dr Karan Singh.

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Mr. Speaker, Sir, before I start my speech on the demands, I would like to point out to you that the report of the Defence Ministry for 1977-78 was released only on the evening of Thursday Friday, Saturday and Sunday being holidays, the report has become available to the Members only this morning. You will agree that a report of 180 pages, unsatisfactory though the report is, nonetheless needs some time for the Members to study, and if the reports are released so late, I am sure the hon Members from all sides of the House will join me in saying

[Dr. Karan Singh]

that this makes a mockery of the entire report. Would you be kind enough to direct the Government that they should release the reports for the concerned Ministries at least ten clear days before the demands are taken up so that the Members can do their home work and take advantage of the report?

MR. SPEAKER: Minister for Parliamentary Affairs may kindly take note of this.

DR. KARAN SINGH: Sir, I would like to open this debate on the Defence Ministry grants by paying a very warm tribute to our armed forces for the magnificent role that they have been playing ever since we became independent. Even before that, the Indian Army and many of the State forces had very good war records, but it was after 1947 that really the glory of the Indian Army began to develop. I have had the occasion to be associated from the very first plane that flew into Kashmir in the air lift and on every occasion subsequently, whether it was the war of 1962, whether it was the war of 1965 or 1971, I landed with the Air Force in their first major landing on the highest airport in the world in Chushul, and coming as I do from a border State with battles fought within five to ten miles of our habitation, I would like to say how proud the entire nation is of our armed forces which we consider to be among the best fighting forces in the entire world.

श्री विनायक प्रसाद यादव : (सहरसा) : डाक्टर साहब, आप तो इससे अच्छा हिन्दी में बोल सेते हैं ।

डा० कर्ण सिंह : मैं कई भाषाएँ बोल लेता हूँ लेकिन आज आप अंग्रेजी में ही सुन लीजिये ।

MR. SPEAKER: Please do not raise the language issue in every matter.

DR. KARAN SINGH: India's location geographically and geo-politically

is a crucial one. Because of the vast Himalayan ranges and the three oceans that lap our shores, over 21,000 kilometres of our land and sea border is available, and for that reason, geo-political realities demand and dictate that we have strong defence force. We have no territorial ambitions, but we must always be prepared to defend our territorial integrity and our sovereignty and our honour. I would go even further and say that a country like India must be in a position to deter any potential aggressor and, therefore, our defence policy has got to be closely linked with our foreign policy.

We welcome the steps taken, not new steps—this has been our policy all along—to improve relations with our neighbours and settle outstanding disputes peacefully in the broader national interest, but I would submit that there is no contradiction between a friendly policy towards our neighbours and a strong and efficient defence forces. In fact, I would like to go to the extent of saying that both are necessary, because if we have a defence force in keeping with our geo-political situation, our size and our population, then alone can our relations with our neighbours and other powers in the area come on to a rational basis.

13 hrs.

Then, Sir, because of the close links between the foreign policy and the defence policy, I have a suggestion for the hon. Defence Minister. And that is that the Policy Planning Division in the Ministry of External Affairs, as far as I know, does not have any representative of the Defence Ministry on it. I think it is important that the Policy Planning Division should have a representative of the Defence Ministry so that there can be full co-ordination at the policy level.

The outlays on defence amount to roughly Rs. 3000 crores. They are very considerable for a developing

nation like ours but they will not be grudged by the people and by this House provided we have an assurance that the gaps in our defence structure will be filled and also an assurance of optimum use of the money that is voted.

At this point I would like to say that it is essential that our defence policy should be planned at least for 20 years, at least till the year 2000. There has got to be a perspective planning, because defence is not a field where you can turn on the tap or turn off the tap at will. You have got to have an integrated approach towards defence, and whether our Plans under the new Janata dispensation are going to rock or going to roll, we do not know, but as far as the defence plan is concerned, I would like to submit very respectfully that there should be no rocking and rolling. There must be a clear-cut and an integrated plan of development for 20 years...

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): It has been a rolling plan.

DR. KARAN SINGH: It must roll

MR. SPEAKER: He wants, it must both rock and roll

DR. KARAN SINGH: I said it should not rock but roll it must. The defence capacity is, in the ultimate analysis, a function of the totality of our resources, our material resources, our human resources, our intellectual and even, I would say, our spiritual resources and, therefore, it has got to be looked upon in its totality and in a long range. There are a number of very important points which can be raised, but, because of the limited time, I will try and concentrate only upon a few highlights.

With regard to weaponry, this is a technical matter, and although I do hold the honorary rank of a Major General in the Indian Army, I do not consider myself to be an expert on weaponry. But I would like to say that as far as the Army is concerned,

there should be more stress upon mechanised formations with mobility and striking power. These are two aspects of any defence situation. There is a static aspect and there is an aspect when you want to punch and strike. That striking power is largely represented by Armoured Divisions and the mechanised formations and that is, I feel, where we need a little more special attention. And also mobility. Whether it is on the plains or on the mountains, mobility is of the essence of any defence plan. Therefore, it seems to me a broad point that in the next 20 years, in the next development of our defence planning we should move towards a greater emphasis on mechanised units and on high mobility units.

As far as the Air Force is concerned, we are very proud of its achievements. But, of course, it has to be given the equipment that it requires in order to fulfil its tasks. We have a reasonably good interceptor capacity, but the problem, which has been debated for some years now is the whole question of a deep penetration strike aircraft or, in brief, DPSA. It brings in a multiplicity of problems into which perhaps at this stage one need not go, but I would only say that if after a overall review of our strategic problems and plans which, of course, are naturally and essentially defensive, but, even a defensive plan, as you know, Sir, requires an offensive capacity, and if as a result of that, it is decided that a DPSA is required, then the decision must be taken soon. There have been endless negotiations on this matter with various countries, and I think the time has come when this whole matter should be finalised. A delegation has recently returned from abroad, but whatever plane is ultimately bought, an important thing is there must be ultimate capacity for indigenous manufacture and we must be ensured of an adequate supply of spares in the event of war. We simply cannot take the risk of our spare parts or ammunition being

[Dr. Karan Singh]

cut of for political reasons when we are fighting for our territorial survival. This has happened on many occasions. It may not be necessary for me to go into those. Whatever now we purchase, it must be made absolutely clear—indigenous manufacture, ultimately we have the technological capacity, and also an assurance on spares and ammunition.

With regard to the Navy, with 6 000 kilometres of coast line, the navy has a vital role to play. Many of us land locked people who come from the areas which are not close to the ocean have an insufficient awareness of the importance of the ocean and the vital role that the Navy has to play in safeguarding our coastal installations, our off shore oil installations and our shipping and trade links in the Arabian Sea and elsewhere. India is to a very large extent an oceanic country and, I think even if you look at the financial outlays, you will still find the Navy as sort of third in the row. I think that our submarine capacity is insufficient and must be augmented, and also what is urgently required is a fast frigates equipped with helicopters, because they alone can give us that mobility in the ocean which is necessary if Navy is to fulfil its obligation.

The Indian ocean we want to be a zone of peace. We have reiterated that, and the new Government has reiterated that policy. But I would submit that as far as India is concerned the naval capacity is absolutely essential for any viable overall defence plan that we may have. It requires a great deal more of attention than has been paid to it.

In the Army, in the Navy and in the Air Force one vital and fundamental fact to all these is the necessity of modernisation. Science and technology is developing very fast and the obsolescence rate has now greatly increased. Previously a piece of equipment would have been useful for let us say 25 years or a quarter of a

century. Now the new obsolescence rate has grown and, therefore, we have got to keep our Armed Forces modernised. That in turn brings in the importance of self-reliance, because in the ultimate analysis a country like India with the second largest population in the world cannot remain dependent upon foreign sources for vital equipment. We have got to be in a position to prepare that equipment ourselves and, therefore, modernisation and self-reliance should be the watch-words of our Defence Policy. This brings me directly to two points—one is defence production and the other is Research and Development.

I have had occasion to visit several of these units in these two areas. Our defence production is now, I believe, upto a value of about Rs 1000 crores a year. There has been a commendable growth over the last ten years particularly since the dramatic events of 1965 when our defence policy was re-shaped and re-gearred, there has been a considerable development in import substitution and in self-reliance. But a great deal more can be done. I think our industrial capacity which has been built up now over 30 years largely as a result of the foresight of leaders like Jawaharlal Nehru who realised as soon as we became independent that unless we made the necessary investments in heavy industry, we would not be able to stand on our own feet. There was an argument at that time whether we should put more into consumer goods or more into heavy industry, and even at the risk of some difficulty or some unpopularity Pandit Jawaharlal Nehru realised that the industrial base was the basis not only of our industrial production but of our Defence also.

As a result of that, there is a great industrial capacity in this country. And, I feel that the Defence Minister should pay more attention now to the defence production and try, as rapidly as possible, to indigenise every

equipment. There are some items I believe—I had mentioned some to him but I cannot go into them in detail—which are still being imported from abroad which can be, with great advantage, produced here. Also the whole structure of your defence production organisation needs to be streamlined. We have, as you know, thirty major departmental Ordnance Factories, 9 public sector corporations and three Defence Shipyards. Now, the organisational structure in these is still somewhat obsolete. There are the departmental problems, and anybody who has been in Government and who has dealt with the departmental units realises the amount of redtape and the amount of rigidity that is involved in these organisations. A total view should be taken of the defence production. New methodology should be introduced. Special attention should be paid to the labour relations in these units because what they produce is something of vital importance for the nation and the thrust and move towards self-sufficiency should be carried on and, in fact, accelerated.

As far as Research and Development are concerned, this is another area in which the common man does not generally seem to realise that it is of vital and crucial importance to our defence. Research and development should not be looked upon as some kind of an esoteric undertaking which is imposed from above. In our defence production mechanism, there are several thousand scientists working. It is not sufficient. That is why I mentioned that in our aircraft, if we buy it, unless from the beginning you associate research and development, you will not get the desired results. I remember as regards the Avros which I was dealing with as a Minister for Civil Aviation. One small problem of torque shift developed and the whole of Hindustan Aeronautics went into a flat spin for three years and they were not able to put it right. The simple, almost

old fashioned and obsolete aircraft like the Avro, we are not in a position to handle. Why? Not because we have all the know how. We simply cut out what is given to us and we assemble it. India is too sophisticated a nation simply to do assembling. We have got some of the best scientists in the world. Indians are working in some of the most sensitive and most highly sophisticated American defence and technological institutes. Why is it that we cannot do this in this country?

I would say that it is important that the research and development must be involved in every aspect. There are certain interesting things. For example, take the high altitude research in Ladakh. Excellent work has been done. I am very happy to know—the House will be very happy to know—this. As a result of the research work which has been done the high altitude casualties have dropped very considerably. Similarly, in nuclear medicine, this is a new field, there is an Institute in Delhi. Then there is the psychological stress upon the human material and upon the works they are called upon to do. The R. and D. (Defence) must interact with the other major research institutions in this country whether it is the Bhabha Atomic Research Centre, or the Indian Space Research Centre, or the Indian Council of Medical Research or the Indian Meteorological Department; Defence research should not be a closed shop but it must act and interact upon other institutions and defence should be able to call upon scientists from all over India to work on defence projects. They do not have to be employees of the Defence Ministry because, after all, defence is a national commitment; it is not a departmental commitment or a party commitment.

[Dr. Karan Singh]

Therefore there should be a directorate whereby the best Indian brains at home and abroad can be called upon in times of need in order to strengthen our own research and development potential

Sir, there are two or three other aspects. On the question of stores and equipment, as you are aware, in the armed forces hundreds of crores of rupees are necessarily tied up in spares and spare parts. Unless there is an adequate inventory control, and unless it is computerised now, what happens is that these stores do not move at the rate in which they should move, as a result of which not only do they age, not only do they tend to become obsolete, but they also take up space which is required for fresh stocks. The old concept of the store as a sort of "godown" to open the door and dump everything, is not there now. The whole concept of storage and inventory control has become very much more sophisticated. Although some steps have been taken in this direction, yet this is one area where the Defence Ministry can introduce some of the latest methods. The Rajyadhyaksha Committee is looking into this matter and, I hope something concrete will emerge.

Sir, another aspect apart from equipment is the whole question of intelligence services. Anybody who has had something to do with Defence will realise that intelligence feedback is sometimes even more crucial than an increase in armaments. If you do not know what the enemy is doing, then you are paralysed and if you know, on the other hand, you can in such a way deploy your limited forces as to have the maximum impact. There is a plethora of agencies involved. There are civilian agencies; there are Defence Ministry agencies; there are para-military agencies and there are State Government agencies. I do not want to go

into too much detail in this matter because it is a very sensitive area. I will simply make this point that it is my conviction that there is a lack of coordination with regard to collation, particularly and with regard to intelligence collation for defence in the border areas. There are some very sensitive border areas—most sensitive being the tri-junction where Bangladesh, Burma and India meet. Do we really know what is happening there? Are RAW and other agencies functioning, or is everybody sitting on this little empire and saying "This is my bit of information. I am not going to pass it on. The level to which there are rivalries within the intelligence agencies is quite amazing—I will make this particular point and leave it at that. I will only say that this point needs going into."

With the best equipment in the world and with the best intelligence and best storage system let us not forget that ultimately it is the human material which is critical and central to any effective defence mechanism. This has been brought out time and again in the Vietnam War. You had a small nation pitted against the technologically most advanced, most sophisticated nation, and all sorts of weapons were used. Why the Vietnamese won was because of the will of their people to fight. So let us not forget the importance of the human material.

MR SPEAKER Please, try to conclude now.

DR KARAN SINGH Sir, I will only take another five minutes.

I have some doubts with regard to the whole question of whether our training is adequately linked with technological developments in the defence field. For example, you take the whole theory of missiles. We are now moving into a missile age, which means that new concepts of strategy and tactics have got to be developed.

to meet with the new technology. When we were fighting with swords the basic theory may be the same but the adaptation of that theory was different. Then we moved to automatic weapons. Now, we have missiles. Is there anybody who is looking into its totality and ensuring that our training programmes are being adequately re-oriented to meet the new requirements which flow from technological development? Sir, our jawans, NCOs, JCOs and officers are very sharp and bright but this training is a long-range thing and it has got to be re-oriented.

This brings me to the welfare of the jawans and the officers, and the importance of service conditions being improved. Unlike many of the more vocal segments of the civil employees in the country, the Defence Forces are a disciplined force and, therefore, are not able to have demonstrations and luckily for us they do not resort to that. By and large, I must say that the service conditions have steadily improved, but there are some aspects which require special attention. The first point in this connection which I would like to make is this whole question of prohibition. I do not want to go into controversial aspect of prohibition in peace stations but I would like to say that in the high altitude areas where people have to live for months on end it is not a question of paying a visit to Ladakh we all go as Ministers, and I am sure when the hon Minister goes we go muffled up and shake hands with the people there and the photographs are taken and we come back. It is correct that we have been to Ladakh but staying there in a place like Kargil—as you know it is the second coldest inhabited place in the world—where there are 15 to 20 feet of snow, is a very difficult task. Whatever may be the view on prohibition, as far as these people in those areas are concerned, if the rum quota is required for them it should not be denied.

न जाने आप जनता पार्टी के राज में भारतवर्ष के लोगों को क्या-क्या पिलायेंगे ? लेकिन, कृपा करके, जहाँ तक डिफेंस कॉर्पोरेशन का सवाल है, उन पर कृपा दृष्टि रखिये । आप जो मर्जी हो पीजिएना और हमें पिलाइयेगा ।

So, I would like in all seriousness to say that it would be entirely wrong in the cold areas, in the high-altitude areas, to withdraw the rum quota just because of some theory with regard to prohibition. It is going to be resented, whether or not it is represented to the hon Minister. The Defence forces are very disciplined. But I can tell you that this is going to be resented, and I would like to make a forceful plea to the hon. Minister to kindly keep this in mind.

The second point is about their welfare and family accommodation. I was glancing through the report. The report concedes that 50 per cent of the target for family accommodation has still not been made available. You will agree that there is nothing more important for morale than family accommodation in those areas where they can conveniently be accommodated. (Nobody can say that he wants family accommodation on the mountains of Chushul.) For family accommodation, we are not spending as much as is necessary, but you are spending hundreds of crores for weapons. We should spend a little more money on family accommodation and make up this deficit within a few years.

Now, the Cantonment Areas, I am afraid, in India are getting deteriorated. Previously, when we used to enter the Cantonments, whether it is in Bangalore or elsewhere, we could feel that the roads were clean and nicely swept. Now, the distinction between the cantonment area and our general cities is beginning to get blurred, and the Cantonment areas

[Dr. Karan Singh]

are not being well maintained. Therefore, I would urge that when you have the Contonments, adequate funds for maintenance should also be provided.

Now, I have only two points left. One is the question of resettlement of ex-servicemen. We have to keep our defence forces a young force because of the very requirements of their fighting. At the age of 35 the defence personnel start retiring whereas the civilians retire comfortably at the age of 58. Here are the young people who spend the best years of their life on the frontiers day and night, keep a vigil so that you and I sleep in peace. We do not get as much peace in Delhi now that the law and order has deteriorated—but we are able to sleep in peace...

MR. SPEAKER Not even the Parliament.

DR. KARAN SINGH. This is also because of these people. Now, about a lakh of ex-servicemen retired every year. The figure is given here as 60,000 or 70,000, but if you add on the other para-military organisations, you get a lakh. Now, what happens to these people is that when they retire at the age of 35 they are thrown out of their job. They go to their village, but their lands are taken away because they were not the tillers of the lands, and their lands are gone. They do not often possess enough educational qualifications. They are either under-matric or matric, and therefore they do not have necessary qualifications. The job-quota reservation supposed to be fixed is never fulfilled. Even if it is fulfilled, it is much below the quota needed to really absorb all these people. Now, it is not a question of compassion, it is not a question of mercy. I think it is the moral, political and spiritual commitment of the nation to see that these people are properly looked after.

There is also some anomaly with regard to pensions. People who retired

before 1973 are not getting the revised rates of pension, although they fought in the Chinese operations and the Kashmir operations. The hon. Minister is a man of wide experience and he has handled this portfolio ably for many years; I suggest to him that he should set up a Pension and Resettlement Commission for the armed forces which would include some army officers of appropriate rank as well as some civilians. Let us have a report of the Commission and take a new look at the totality of the problem that should be considered for the welfare of the armed forces. I am sure that it would be something which the nation will not grudge. We are spending about Rs. 3000 crores a year in the defence budget, another Rs. 4-5 crores for ex-servicemen is not going to make any great difference.

I come from a state where the role of the armed forces is very important, and I should like to express my deep appreciation for their role and for the army civilian liaison, airforce civilian liaison in Jammu and Kashmir. On every occasion they have gone out of their way to help civilians. I myself broke my leg in front of an army hospital and I was carried straight into that hospital; this was some years ago. I have visited almost every area in the state, where there are no schools, they open up their schools; where there are no hospitals they help people. In national calamities they extend their help. But there are one or two points which should be kept in mind. One irritation for which the Army is not directly responsible, is about land. Lands are acquired for army purposes or airforce purposes to make an airfield or for a cantonment or for some manoeuvres in the border; payment of compensation is greatly delayed because they have got to go through the state government and the state government goes through the Defence ministry; endless time is taken. In my constituency nobody grudges land for defence purposes; people are prepared to lay down their lives. But

the point is that they take a plot of land; they do not always buy that land, they take it on some nominal lease. What is the poor agriculturist to do? He gets neither land nor decent compensation. He does not know what to do, he is virtually on the streets. Therefore, where there is reason to believe that it is a permanent requirement, land should be acquired and land acquisition proceedings should be expedited.

One point with regard to Ladakh, since the hon. Member from Ladakh will not be able to speak. Local inhabitants are trying to develop their farms so that they can supply vegetables to the army there instead of the Army having to bring vegetables all the way from the plains. This needs to be sympathetically looked into. Then there is no air service to Ladakh; the Air Force kindly places at the disposal of civilians a certain number of seats, these are not adequate. As a result civilians or even Members of Parliament who want to go to Ladakh do not always get seats when they are required. These two aspects require consideration.

I will conclude by saying that the nation is passing through very difficult times. Defence is a national commitment; it cuts across party barriers or barriers of region, race, religion, caste and creed. The Defence forces are a major force for national integration and therefore at a time when all sorts of disruptive forces are raising their heads, let the entire House pay its homage to the Armed Forces and let us hope that they continue to defend our honour and integrity.

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur): Mr. Speaker, before I say anything let me congratulate the Defence Minister.

13.30 hrs.

[Dr. Sushila Nayar in the Chair.]

Within the given parameters and the outlook of the nation, he has tried through his budget, though in a small way, to project the picture of our defence needs in the next decade and 1980s. I heard with great concentration my friend Dr. Karan Singh speak. I expected a better performance from an hon. Major general and ex-minister of the ex-government. May I with all humble submission and politeness, ask him, what he did in those thirty years? We are suffering from their legacy, or if I may use a historical parallel, the Girondists of the French Republic suffered the sins and acts of omission and commission of the Bourbons of the past.

DR. KARAN SINGH: In thirty years we won four wars and we maintained the integrity of the nation. I hope the hon. Member will realise that. That is what we did in thirty years.

SHRI YADVENDRA DUTT: He said, "We have maintained the integrity of the nation." If that is the case, may I ask—

MR. CHAIRMAN: You please continue your speech. You have only ten minutes. Please concentrate on your points.

SHRI YADVENDRA DUTT: On such an important subject, Madam, ten minutes will not be enough.

MR. CHAIRMAN: I am sorry, everyone will have only ten minutes, because there are a large number of speakers on the list.

श्री यद्वेन्द्र शर्मा (गुरदासपुर) : सभापति महोदय, इस का मतलब तो यह हुआ कि समय इतना घट रहा है कि बार बालो के लिये भी धाघा मिनट रखा जाएगा, जिस स्पीड से चल रहे हैं। क्योंकि पहले बालो में ज्यादा समय निकलता है।

सभापति महोदय : पहले बालो की हुनेवा ज्यादा समय मिलता है जो डिबेट एनीमिड कर रहे हैं। उस के बाद 10 मिनट कर देते हैं। आप कृपा कर के अपने पाइड्स पर घाइये।

SHRI YADVENDRA DUTT. He has asked the Janata Government to make a Defence Scheme for twenty years and in the same breathe he has said that the weapons become obsolete very quickly. May I ask him, how can you expect a scheme for twenty years when the weaponry is becoming obsolete in five years? With this may I request the Defence Minister to look into the very conception of our defence? We have been suggested that there should be more stress on tanks—agreed I am not anti-tank. But with the development of new missiles, weaponry and the results that we have watched in the Sinai War in 1973, have we not learnt the lesson that a new conception of warfare is coming up where the semantics and cybratics are more important? The targets are hidden, the enemy attacks you from a hidden position how do you know where he is? Mass tanks can always be destroyed by missiles, lasers and what Americans have now developed what they call "Knitic energy bullets" which are actually atomic bullets. They do not come under the so called legal definition of atomic bombs because after extracting 235 238 remains and they say it is only knitic energy. What we really need is therefore a fresh outlook and a new conception of warfare and then on that conception dictate our weapon and on that basis to the extent our Defence Minister has gone it is admirable but we would like him to go the whole-hog and not by piece.

What is more important is that we have thrown Aryabhata in the air, but have we got the necessary vehicle for it? The coming war will be more warfare of the lasers, rockets and knitic energy bullets and so on and even the nutronic cruiser missiles will be used and arms and armaments will be transported. What have the Russians done recently in Berbera and Somalia and in Ethiopia. I may say

that they have used M-16 helicopters which are in a position to carry....I quote:

"Their General used his Mi-6 helicopters which can lift 15 tons to carry men, enormous stockpiles of fuel and ammunition and by some accounts, 14-ton PT-76 tanks"

I hope that this role of the helicopter which is, like a flying cavalry at times, will be more stressed upon because after all ultimately the success will depend on the mastery of the air. If you are the master of the air, you will succeed. That has been the lesson of the Israeli war of their great success probably in 197A, if I am right, and that too is the result of

SHRI B P KADAM (Kanara) Did Americans succeed in Vietnam?

SHRI YADVENDRA DUTT. Forget it. I am now talking of the Arab-Israeli war. Madam I will give them all the arguments, but I cannot give them intelligence to understand.

What I am saying is that the result of the 1973 Israeli war is a very clear result and it is a great pointer to the coming of a new concept of war and new weapons. Israel relied itself on that old conception in which they crashed through and that conception was totally destroyed. My friend has said about intelligence. I quite agree that we should lay more stress on intelligence because no army can fight blindly. Every victory or every battle or every effort has to be made with the prior knowledge of what your enemy has or what he is going to do and for that intelligence has to be compiled from all sources. I would not like to say more about it but I just hint. Even newspapers have intelligence even economic reports have intelligence and so on and so forth. Our make-up and the structure of our intelligence should be all-comprehensive and integrated. For the training, I would suggest that with the coming of the new conception where more

mechanical gadgets are being used, where electronics is being used, guided missiles are coming in and probably the latest is, as my friends, the supporters of the Russians, have put in, the new weapon, the guided atomic particle B. The Americans are also working on it. These guided weapons are more important because they are more destructive. The new, coming war will be short and more destructive, but it would not be politically decisive. That we have to make clear. So, for that purpose we must have more integrated training of our officers. Ultimately, if the officers who have to decide or who have to take decisions were to lead, and if they are not up-to-date, if their knowledge is not according to modern weapons and modern conception of warfare, I am afraid we may be in trouble. As for what my friend says about goe-politics that is true but may I hope that he goes to its logical conclusion? Because geographically situated as we are, we are at a very strategic highway—there is the Indian Ocean, the Bay of Bengal and the Himalayas and all that and there are the oil routes also. So, do not forget, or shall I just only hint and quote a very famous poet about 2500 years back, Homer:

“Trojans, beware of the gift-bearing Greeks”.

We are having too many gifts. Let us beware of these gifts and for that we have to have a very broad concept. The entire thrust of the Budget to my mind, Madam, is a localised affair—800 to 1000 miles. But our defence perimeter does not lie there. It is much farther. With the modern destructive weaponry our defence perimeter will be much broader. For that broadness the new conceptions of warfare and missiles and weaponry have to be taught and for that it is necessary that special colleges are created for the training of our officers. With that it is also necessary because modern warfare is an integrated warfare. It is neither a naval warfare nor a aerial warfare nor a military

warfare. This is all the three combined. At times the stress may change here and there, but there is bound to be a combination of the three. Therefore, a joint staff is needed where each one must know the problems of the other and the problems co-relate and through that joint staff the defence conception may come out. May I hope that the Defence Minister will be good enough to look into this point of view?

I wish to bring one thing to the notice of the hon. Defence Minister? There was one Shri Goyal in the Defence Ministry, who was an Under Secretary or Additional Secretary, who has just disappeared into the blue for six months, or eight months or a year. We do not know, but speculation is rife that he has become a sanyasi. If anybody becomes a sanyasi, he does not disappear like this. May I only leave this matter at this with a hint that looking into it, it will not be another case of Guy Burgess, Maclean, and your secrets may not be out. Greater counter-intelligence is necessary. I will not go any further into this matter. I will only draw the attention of the Minister to the fact that if we were to take a morning walk at 4.30 or 5 a. m. from the side of the Delhi Gate to wards India Gate or the Parliament House, you will see highly-powered diplomatic cars running here and there. What business have they at this hour 4.30 or 5 a.m. to run here and there? Please look into it. Counter-intelligence is very necessary.

There is a talk of a deep penetration plane. Since you are not giving enough time, I cannot go into the details. I just do not understand what is meant by a deep penetration plane. There are fighters, bombers and fighter-bombers. We should call a spade a spade. What we need is a fighter-bomber. We also need replacement for interceptors. Apart from that, we also need reconnaissance planes. Being a country with limited resources, we cannot have separate plans for all

[Shri Yadvendra Dutt]

there are other foreign companies reconnaissance with fighter-bombers. But their performance must be above 70,000 to one lakh feet. They must be highly easily handleable with greater range of fire power. Speed is also essential. Though I have got all the details, I would not go into them for want of time. I have got the details of Viggen, Jagaur, American 5 FE and F-5, and Russian MIG-25. Besides, there are other foreign companies which are hankering for these contracts. I only want the Defence Minister, when he goes in for this, to remember that speed is essential, as also manoeuvrability, the capacity to fight and come back and load fuel. They should be easily maintainable. These three things must be kept in mind. Suppose you have side-winders and rockets. If you use all your rockets, then what happens to the plane when it is returning?

MR. CHAIRMAN: Will you kindly conclude?

SHRI YADVENDRA DUTT: I want another five minutes.

MR. CHAIRMAN: You have already taken 15 minutes.

SHRI YADVENDRA DUTT: I will conclude in two or three minutes.

When you go in for these deep penetration planes, be careful. There should be one condition that these planes will be manufactured in collaboration with us in India. We do not want to be at the mercy of somebody else for spares or anything. I am sorry to say that for the past thirty years we have been at the mercy of others. May I suggest that there are certain countries, which are the makers of certain excellent planes, which have got mach. 3.2 and longer range. The manufacturers of such planes may be induced to come and set up factories here for the production of the spares. They should also be compelled to purchase 75 per cent of the spares for their manufacture in their own country

The deal has to be inter-linked so that we will not be at the mercy of anybody.

Coming to our navy, I would say that our navy is sadly looked after. I am sorry to say that. Our commitments are huge. On one side we say that our territorial jurisdiction should extend to 200 miles in the blue ocean. At the same time, we do not have enough of frigates. The frigates are good. They have a purpose like the race horse, but they do not serve the purpose of absolute kill in the battle. Therefore, we must have frigates, submarines and cruisers. There is a nation with which we can repeat the Rapallo Treaty of 1921. They can come and build ships here in partnership. We must have capital ships, not battle ships but small pocket battle ships which can be used as aircraft carrier, as a mother ship for small submarines, which can stand up and fight it out and come back.

The Indian Ocean is named after us, but it is astounding that there is every ship other than Indian in that Ocean. As the Minister of Defence knows, there are weapon systems as also individual weapons. We must have the RS-20, because that can be used to replace our anti-aircraft guns.

With these few words, I thank the Defence Minister and support the Defence Budget.

SHRI P. V. G. RAJU (Bobbili): We cannot discuss defence without some reference to foreign affairs. So, I would request you to excuse me for bringing in an element of foreign affairs into the Defence Budget.

As you know, we cannot discuss defence unless we know the nature of our neighbours. As a matter of fact, in the last 30 years we have been to war with Pakistan on a number of occasions. Even now, there is a dispute over Kashmir. Therefore, I would be right in referring to it.

When the Janata Government came to office last year, the Foreign Minister made an offer to Pakistan to have a no-war pact. I would like that to be revived so that we know where we stand so far as Pakistan is concerned because Pakistan today is ruled by Gen. Zia-ul-Huq on behalf of the Pakistani Army. Of course, he says there will be elections in Pakistan very soon. Even then, I feel that a no-war pact with Pakistan is a must, because, whether we admit it or not the nature of defence expenditure will be determined by the nature of our neighbours, whether they are friendly to us or not, because, if we have a no-war pact with Pakistan, defence expenditure can be rationalised. I do not say that it can be cut down. I do not want defence expenditure to be cut down, but I would like that greater emphasis should be placed on science and defence research expenditure because defence research is a prerequisite for the future.

As you know, whether we admit it or not, our nuclear capacity is such that we are capable of setting off a blast on any nation in the world. For the blast, we require rocket or nuclear propellant. Therefore, the capacity of nuclear research without the military offtake is only national and not factual. Therefore, I would like to know what our neighbours spend, for it will be possible to increase our defence research budget. I am happy, Dr. Ramanna is now in the Defence Service Research Wing. I am mentioning his name because he has been heading the Bhabha Atomic Research Centre and he is one of the greatest scientists who are capable of producing nuclear energy in our country.

Apart from this, I would like the peaceful nuclear explosion issue to be well managed with Americans. I use the word 'Americans' because I feel the Americans are more anti to us so far as nuclear capacity is concerned.

How we are going to do it, I do not know. I leave it to the Prime Minister. While speaking to the Canadian Broadcasting Corporation on 18th May, the Prime Minister said that when we detonated the blast, we should have informed the Canadian Government of our capacity or of our desire to detonate the atom bomb. I do not think, a person of the Prime Minister's status should have mentioned this to the Canadian Broadcasting Corporation but he has done it. The matter is now over. But I feel, there are many points on which we should be in a position to question the Americans not only in nuclear weapons capacity but in nuclear, biological, chemical protection capacity also. The Americans were engaged in war with Vietnam for over 10 to 12 years and the whole of Vietnam had been bombed not only with bombs but also with chemical weaponry. As a matter of fact, the whole rice fields in Vietnam had been devastated. It is not possible to grow rice for the next three years after the use of these weapons. Therefore, between America and Russia, they have a nuclear biological chemical protection treaty. According to this treaty, no gas will be used against the enemy. In the same way, I feel that they should enforce it strictly. It is one thing to talk about nuclear capacity and another to talk about chemical capacity. We should not separate the two things. As a matter of fact, we will be within our moral right to question the American opinion on nuclear explosion and say that as long as they do not control their own nuclear capacity, they should not discuss our nuclear capacity.

I come from the Vishakhapatnam district. Therefore, I have two direct personal interests so far as defence is concerned. One is that on the border of the district Koraput, we have an Air Force factory which assembles MIG aircraft. Also, in Vishakhapatnam, we have a Shipbuilding Yard in the defence budget, we find that out of Rs 100, Rs. 48 are spent on the

[Shri P. V. G. Raju]

Army, Rs 21 on the Air Force and Rs 7 on the Navy. The total is Rs 76. The balance Rs 24 are spent on defence research and other aspects of defence expenditure. These are the figures which were given in the last budget. I am sorry to say that I have not been able to read the present Report because, as Dr Karan Singh pointed out, it is over 150 pages and it was given only a few days back. The figures that I am quoting are the figures of last year. I may point out, of course, depending on the attitude of the neighbouring countries that we can rationalise expenditure. But the expenditure of 7 per cent of the total expenditure on defence on the Navy seems to be very low. I would say that we should spend a little more than 7 per cent on the Navy because we have a large coast line. Spending a larger amount does not mean on the weapons, ships etc but on the infrastructure of naval ship-building yards.

As a matter of fact the Vice Admiral Krishnan is in-charge of the Ship-building Yard in Cochin and, I am told—I am subject to correction—that a Japanese company called Mitsubishi is helping in the development of the proposed shipyard and that it will be possible after a few years to convert the shipyard into a naval establishment. I do not know whether this is a fact or not. But I do know one thing. The Shipyard builds the maximum tonnage of 75 000 tonnes. Therefore, using the Cochin Shipyard as the naval base, I think, the Navy should be asked to take a greater interest in the development of the base for the production of heavy vessels—you may call it, cruiser vessels—I am not a military man, I cannot reel off the technical names—you may call it, aircraft carriers, destroyers, rockets, etc. We can convert the whole of the Cochin Shipyard into a good naval base. I would request the hon Minister to think of this because the infrastructure of defence is a must as far as the future of the country is concerned.

With these words, I conclude.

श्री पद्मवत शर्मा (गुरदासपुर) :
 मैं दो बातों की शीघ्र विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सुरक्षा के सम्बन्ध में बजट के प्रावधान का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि कम बजट रखा गया है। सत्ता पक्ष से इस तरह की बात कहना मैं समझता हूँ कि ज्यादा शोभा की बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार की अपनी मुश्किल है। स्वर्गीय सरकार ने इस मामले में गत बीस तीस वर्षों में इस शीघ्र ध्यान नहीं दिया। उस के कारण से हमारी कठिनाई है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। हमारी सरकार की जो समस्याएँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सेनाओं के ऊपर हमारा जितना पैसा खर्च होना चाहिए शीघ्र जितना पैसा खर्च करने को हमारे लिए जरूरत है उसमें अमूल्यूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। उस के प्राधुनिकीकरण की दृष्टि से जितने धन की जरूरत है उसका भी ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि सुरक्षा के सवाल का हम ताक पर रख कर नहीं चल सकते हैं। दुनिया में जीने की दृष्टि से हमें इस मामले में विशेष सतर्क रह कर चलना पड़ेगा। दूर उत्तर के अन्दर चीन और पाकिस्तान बैठे हुए हैं। मैं मानता हूँ कि प्रधान मंत्री या जनता सरकार या बिदेश मंत्री महाशय की नई वार्ताएँ सद्भावनापूर्ण यात्राओं या सद्भावनापूर्ण नीतियों के कारण एक नया मोड़ आया है, कुछ रख में बदल आया है। चीनी लिफ्ट ब्रडल भी यहाँ आया था। हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा भी की है। इससे कुछ न कुछ स्थिति के तनाव में कमी आई है, हल्का सा माइ दिखाई देता है। लेकिन अभी तक भी पाकिस्तान ने काश्मीर पर से अपना दावा छोड़ा नहीं है। अभी तक भी चीन ने हमारी भूमि के ऊपर से अपना अधिकार नहीं छोड़ा है। इस कारण ये दोनों समस्याएँ अभी की त्यों कायम हैं। तिब्बत के अन्दर चीन का

जितना सैनिक क़ैलाब या बह ज्यो का त्थो कायम है। दूर दक्षिण के अन्दर भी जो भारतीय हिन्द महासागर है जिन को हम शान्ति का क्षेत्र बनाए रखना चाहते हैं। यू.एन. ओ. के दावे के बावजूद भी, मोरगाओ के बावजूद भी वहाँ पर बड़ी शक्तिशाली को मुसैद कायम है। उस के साथ साथ अरब सागर की तटवर्ती शक्तियों को अपनी सैनिक शक्ति है दूर पूर्व में नागानैड विशोरम में रहने वाले हमारे भाई हैं। लेकिन वहाँ पर धातुरिक-नोड फोड की स्थिति चलती रही है इस को भी हम जानते हैं। उनके प्रति हमारा व्यवहार सद्भावना पूर्ण हाना चाहिये। वे हमारे नागरिक भाई हैं। हमारा व्यवहार उन के प्रति मैत्री पूर्ण है और होना चाहिये। जिस सावधानी और दखता के साथ हमारी सरकार उनके साथ डील कर रही है उसकी मैं सराहना करता हूँ। लेकिन जा सकट है उसको हम दृष्टि से अज्ञान नहीं कर सकते हैं। इस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमें अपनी मोमाओ के सम्बन्ध में, सैन्य शक्ति के सम्बन्ध में, सुरक्षा के सम्बन्ध में प्राथमिकता दे कर चलना होगा, फस्ट प्रायोरिटी इस को हमें देनी होगी। इस नाते मैं कहता हूँ कि हमारे बजट की यह एक कमी है। मैं मानता हूँ कि इस कमी में हमारी विवशता है, राष्ट्र के समस्त साधनों को दृष्टि में रख कर, समर्थता के अन्दर, टोटेलिटी के अन्दर हमें इसके ऊपर विचार करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में शीघ्र ही हमें इस बारे में तत्परतापूर्वक अपनी कमी को पूरा कर लेने की ज़रूरत है।

जहाँ तक सेना का सवाल है मैं दो बात ही कहना चाहता हूँ। एक व्यवस्था सम्बन्धी है, यानी फवशनल प्रेजेन्ट और दूसरी सेना की स्ट्राइकिंग कैपेसिटी, मारक शक्ति, उनकी युद्ध शक्ति के सम्बन्ध

में है। जहाँ तक व्यवस्था सम्बन्धी बात का सवाल है, पिछली बार भी मैंने कहा था और फिर अब मैं उसको दोहरा देना चाहता हूँ कि हमारी सेना के अन्दर एक उच्चस्तरीय और एडीशनल प्रेजेन्ट की ज़रूरत है। तीन सैन्य प्रमुख हैं। उन के अन्दर एक चीथा होना बहुत जरूरी है। दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है। तालमेल की दृष्टि से भी यह बहुत आवश्यक है। बूक समय थोड़ा है इस वास्ते में विस्तार में नहीं जाता हमारे पास योग्यतम व्यक्ति बैठे हुए हैं, अच्छे-अच्छे रिटायर्ड लोग भी हैं। अपने देश में आप किसी और चीज पर तो विश्वास कर सकते हैं लेकिन युगों में मैं इस बात को मान कर चला आ रहा हूँ कि अपने सैनिकों के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई ग़ुआइश नहीं है, सैनिक देवता की तरह पूज्य है, प्रामाणिक है। इस वास्ते मैं समझता हूँ कि उच्च स्तरीय व्यवस्था हमें का करनी चाहिये, हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत है।

साथ ही समय रहते सेनाध्यक्षों का, आने वाले सैन्य अध्यक्षों के बारे में हमें तय कर देना चाहिये। लास्ट मामेंट पर तय किया जाए, ता अनसरटेनटी बनी रहती है। इनस्टैबिलिटी बनी रहती है, डटरनल टग आफ वार चलता है। और उन के लिये घुसपैठ चलती है। मैं यह नहीं कहता कि किसी प्रकार की और तन्दरुस्त हवा आनी है मैं ऐसी पिज्जा की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह मान कर ज़रूर चलता हूँ कि व्यवस्था का सुधारने की दृष्टि से यह बहुत जरूरी है कि हम समय रहते इसकी घोषणा करें।

दूसरी बात हमें यह कहनी है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सुरक्षा सेनाध्यक्षों के मुख्यालयों

[श्री यशदत्त शर्मा]

के बीच जो दोहरापन है इस को समाप्त कर के एकीकरण होना चाहिये सना मंत्रालय एक धीरे काम कर रहा है और सनाध्यक्षों को मुख्यालय एक धीरे काम कर रहे हैं। इनका एकीकरण होना चाहिए। इससे लाभ होगा। ऐक्सपर्ट ओपीनियन मिलेगा और हमारी कार्य दक्षता और क्षमता में लाभ होगा और धन की भी बचत होगी। और सब से बड़ी बात यह है कि हमारे सेनाध्यक्षों को, टेक्नाक्रेट्स और विशेषज्ञों को जो सिविल अधिकारी पीड़ा देते हैं, जो सिविल अधिकारियों की मोनोपली है वह बहुत तकलीफ देती है, जो कि एकीकरण की व्यवस्था से टूटेगी और एक सीहान्द का वातावरण पैदा होगा। इसलिए एकीकरण होना बहुत जरूरी है।

उच्च स्तरीय एक मलाहकार समिति बननी चाहिये। यह मैं इसलिये कह रहा हूँ कि हमारे जैसे देश के लिये किसी भी संकट का प्रकार और विस्तार, एक-एक क्षण में बदल रहा है। हमारे पास कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है जो आने वाले किसी भी प्रकार के संकट के बारे में निश्चित सूचना दे। मेरे विचार से एक ऐसी इंस्टीट्यूशन खड़ी की जानी चाहिये जिससे अन्दर हमारी सेना का गुप्तचर विभाग, उस के मुख्य अधिकारी या उच्च स्तर के व्यक्ति और विदेश विभाग के व्यक्ति, इसके प्रतिरिक्त अन्य काबिल व्यक्ति जो वहाँ कार्य कर सकते हैं और प्रति क्षण एक योग्य परमानेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर आँख रखें कि हमें किस प्रकार का संकट हो सकता है, आज उस की दिशा किस ओर मुड़ रही है और प्रतिक्षण हमारे राजनीतिक अधिकारियों को, सुरक्षा मंत्री, प्रधान मंत्री, या देश के नेताओं को इस मामले में मार्गदर्शन करता रहे। और उस की रोशनी में

हमारी सेनाओं के प्रमुख या रक्षा मंत्री महोदय या बाकी के नेता हमारे सेनाध्यक्षों को बहुत एग्जैक्ट टर्मों के अन्दर गाइडेंस दे सकें और वह उस के आधार पर एक नतीजतुली अच्छी प्रकार की संचालन योजना बना सकें। और फिर उन के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी डाली जाय . . (घंटी बजने पर)

मैं बन्द कर देता हूँ अपना भाषण। समापति महोदय, मैं धींगामस्ती के स्वभाव में नहीं हूँ।

समापति महोदय : पहली घंटी 1, 2 मिनट कानोटिस देने के लिये हांती है।

श्री यशदत्त शर्मा : मुझे 5 मिनट का समय और दें।

इस सदन के अन्दर एक बात निश्चित रूप से माननी पड़ेगी आज सेनाध्यक्षों पर यह जिम्मेदारी डाली जाये कि किसी प्रकार से फिर उन के परफ़ोरमेंस में कमी न पड़े। जितने स्थान हैं योग्यता और पूरे तौर पर उन के ऊपर दायित्व डालना चाहिये। इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ऐसी उच्चस्तरीय एक मलाहकार समिति हमारे लिये आवश्यक है।

एक और बात है, जो मौलिक बात है, हो सकता है आपत्तिजनक लगे, लेकिन बाबू जगजीवन राम जो लोक सभा के अंगार और सब प्रकार की योग्यता रखने वाले महान नेता से हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि वह इस बात को एक ऐतिहासिक ढंग से मांड देंगे। हमारी सेनाओं के संबंध में जो बजट का आबंटन होता है और फिर सदन में उसका अनुमोदन लिया जाता है और फिर प्रत्येक वर्ष खर्च के ऊपर उसको सही साबित करता पड़ता है सदन के सामने।

में समझता हूँ इस प्रक्रिया को थोड़ा सीधा करना चाहिये, और वह यह कि एक बार जब बजट पास हो जाए और सदन से उसका अनुमोदन हो जाय उस के बाद एक एक प्राइम को ले कर पुन वित्त मंत्रालय की ओर दौड़ने की जो प्रक्रिया है यह मैं समझता हूँ कि ठीक होनी चाहिये ।

सेना के भ्रगो की जो दोहरी प्रक्रिया है वह भी ठीक होनी चाहिये । आज मेरी चाहती है कि हमारे कुछ प्लेन होने चाहिये । मैं समझता हूँ कि उन के अन्दर अच्छे प्रकार के सम्बन्ध पर जोर दिया जाय । इस बात के लिये जोर न दिया कि प्रत्येक भ्रग पर एक एक चीज अलग से खरी करने के लिये दौड़े । यह चीज खरम हानी चाहिये ।

जहा तक मैने स्ट्राइकिंग कैपेसिटी की बात कही, उम के बारे में मैं दूधने मुट्टे पर आना चाहता हूँ । बात यह है कि हमारी सेनामा का या हमारे सारे डांचे का यह पुराना है । यह 20 साल पुरानी है । वायुसेना के बारे में भी मैं यह कहूंगा कि मिग विमान का छोड़कर जितन भी विमान हमारे पास है वह सब पुराना है । आज दुनिया के देशों में दीड चल रहा है दुनिया के एजेन्ट यज्ञा बँडे हुए है कोई कहता है हमारे बजिन ला, कोई कहता है कि जायगवार ला । यह ता सरकार तय करेगा । लेकिन इस सरकार को अनिर्णय का शिकार नहीं होना चाहिये । यह इन-डिस इमिबनेस हमें मार जायेगी । एक समय में हम एक चीज 1 ह० की लं सकने थे, लेकिन आज हमारे ऊपर उसकी कीमत 100 रुपये पड रही है । अगर अब भी निर्णय नहीं करेंगे तो इसकी कीमत 200 रुपये हो जायेगी । इसलिए हमें इस सम्बन्ध में तत्काल कोई निर्णय लेना चाहिये ।

वायुसेना के सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि फोर-फ्रंट पर काम करने की दृष्टि से फोर्स को मजबूत और भारी हेवी-कोर्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है । उस की बढ़ोतरी होनी चाहिये । इस में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है ।

हम सेनाओं की प्राइजिन्स फैक्टरीज में सब की सब चीजें तैयार करे, मैं समझता हूँ कि इस की जरूरत नहीं है । कपडा बा और बाकी की चीजें हम दूसरे सैक्टो में, सिविल सैक्टर्स में भी बनवा सकते हैं । कुछ को आइजिनेशन करें, एन्सीलरी इडस्ट्रीज खोलें । मैं इसके विस्तार में ही जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में हमें विचार करना पड़ेगा ।

जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता कह चुके है जल सेना में हमारे पास भारी-भारी पोत है, यह अच्छी बात है । लेकिन स्ट्राइकिंग कैपेसिटी की, हमें इस प्रकार की मिमाइल्स की जरूरत है जा सेना में अच्छा काम कर सके ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक्स-मविसमेंत, जो छोटी आयु में सेना से छुट्टी लेता है, या उसका मुक्ति दी जाती है वह इसलिये नहीं कि वह काम नहीं कर सकता है बल्कि इसलिये कि वह चाहता है कि लडन की ताकत के दौरान ही वापिस हट जाऊ ताकि अगली कमजोरी से देश को किसी तरह का नुकसान न पहुँचाऊ, इसलिये वह वापिस आता है । आज उस का एडजस्ट करने की या योग्य प्रकार से स्थान देने की जरूरत है । लेकिन आज एक्स सर्विसमेंत के बारे में जो कुछ हो रहा है, मैं इनना ही कहना चाहता हूँ कि जवान और भगवान सकट के समय में याद आता है । मुझे इस सदन में यह कहते हुए कष्ट होता है कि

[श्री यशवन्त शर्मा]

सड़क के दिनों से लोग बही भी चाय का प्याला या सप्सो का गिलास लेकर बड़े होते हैं लेकिन आज दिल्ली में एक्स-सर्विस-मैन को दुर्बला हो रहो है और वह बहुत डरावा थाकून हैं। किसी ने भी एज ए नैमन या एज ए गवर्नमेन्ट इस बात को ध्यान नहीं किया है कि एक्स-सर्विसमैन को हम धानरेवली एडजस्ट करें और ये अपने जीवन से कही सकट में नहीं बूमगे।

समापति महोदया, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने कृपा की और धंटी नहीं बजाई।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) Madam, Chairman I have read in the newspapers recently about the speech made by our Defence Minister that the percentage of defence expenditure to the total expenditure in the Central Budget has been going down progressively. I think this is pure arithmetical calculation. Defence budget is getting increased year after year. This year's defence budget is about 200 crores more than that of the last year. It has not been reduced in any way.

As far as the relations with our neighbours are concerned the tension has come down. A goodwill tie from China visited our country and our people and our Government gave them a hearty welcome. Our relations with Pakistan have changed recently. Shri Vajpayee, our hon. Foreign Minister visited that country and he had cordial talks with the Pakistani leaders. Then what is the necessity to increase the defence budget? I cannot understand this.

Madam we want the defence of the country to be strengthened, but by increasing the armed forces only you cannot think that the defence of the country is safe. The country can be defended effectively only if the people's support is there. The modern

war is a total war. So, without the co-operation of the people we cannot defend our country effectively. In this connection, I want to say that our people and the youth should be given military training so that at the time of need we can mobilise our whole people for the defence of the country.

In the Navy there is discrimination between the ordinary sailors and the officers. There is dissatisfaction amongst the ordinary sailors for the last 6-7 years. More than one thousand sailors were dismissed or discharged in many cases without even ascribing any valid reason. The sailors were treated like slaves. The Naval Headquarters issued an order in 1970 that all sailors had to clean the toilets not only their own but also of the officers. They were forced to do that after abolishing the Topas branch who were recruited to clean the toilet which sparked off a wave of dissatisfaction and protest against the working conditions in the Indian Navy. The sailors were threatened, tortured and forced to sign confessional statements. They were put to solitary confinement in small cells and finally after obtaining confessional statements they were dismissed and sentenced to imprisonments. At the time of dismissal, none of them were paid their dues or even issued the discharge certificates.

Similarly in the Army the ordinary soldiers are treated badly. Some of them are even forced to work day and night as servants in the residences of Army officers. They are instructed to salute the wives of highly placed Army officers failing which they are harassed and even punished. Even in the matter of extending medical facilities there is discrimination. Higher officers are carefully examined in hospitals and supplied fresh stock of medicines. They are given sufficient and a high quality of food but the ordinary soldiers are not carefully treated. Adulterated and bad food-stuffs are supplied in military hospitals to the ordinary soldiers and jawans.

Even in regard to allotment of quarters there is discrimination. Ordinary soldiers are allotted unhealthy and dirty houses without sufficient sanitary arrangements. These can be found all over the country.

New avenues of promotion for the jawans should be opened and discrimination in any matter should be removed.

You know, Madam, every year a good percentage of the Armed forces are released from our defence forces after rendering a long and arduous service and in bad working condition. Out of them a maximum of 15,000-20,000 are given jobs after retirement while a majority of them are unemployed during their young age and the pension they get for all their service is quite meagre. I demand, Madam that their pension should be increased and this should be available for all ex-service-men including those absorbed in some other jobs. There is much talk about self sufficiency, but it is not all true. We depend on others for vital things. Some sophisticated weapons and stores are being purchased from abroad, whereas it has been proved repeatedly that with our existing Engineering skill, we can produce them. Our GNATS, Vijayant and small arms have proved their efficiency. There is also a trend to reduce the strength of the workers and employees in defence industry. On the other hand Government is purchasing defence items required for forces from private sectors. Some Inspectorates under Directorate General of Inspection are set up in Calcutta, Madras, Bombay for the purpose of inspecting the stores. Meat factory in Agra was closed and tinned meat is being obtained from private firms.

The three engineering factories—SAF Kanpur, RFI, Ishapur, Ordnance Factory Tiruchirappalli, where small Arms were being produced, are now running below capacity. More than 4000 workers are now enlisted surplus in these three Ordnance factories. Most

of all the establishments of all the five factories producing war materials, their existing capacity is not fully utilised. The Ordnance factories are day by day depending on private supply and imports. Recently 300 employees have been declared surplus in 515 EME workshops, Bangalore and Panagarh. By getting the work done through private contracts by which some corrupt officers can earn some money, the workload in the EME workshops are reduced, some works are being done by the private contractors.

In the Ordnance factory schools this year 2515 boys are undergoing training. But on the other hand, owing to the wrong policies in the production sphere more than 1000 trained boys of all industrial trades are unemployed. The large number of trained boys are unemployed.

There is a process or militarisation in the civil post in some depots/establishments. Recently it has been done in R&D Organisations and MES and EME Depots. This will ultimately result in immediate surplus of employees and industrial relations.

To increase the productivity, one of the main criteria is good industrial relations. But it is not so in the defence industries. In many Establishments, Works Committees are not being allowed to function. In CODs, Works Committees have been abolished on the plea that they are not industrial establishments. Workers' representatives are not considered. They are not taken into confidence. They are rather ignored. Some Unions have been deregistered and some other issued notices for that purpose.

Hundreds of Trade Unionists were victimised in defence industries during the internal emergency. Prior to the emergency also, during the dictatorial regime of the Congress, many trade union office bearers were removed. 35 Defence employees related to

[Shri Krishna Chandra Halder]

the unions of Ichapur, Cossipore, and DUM were removed from service by Article 310(1) & 300 of the Constitution of India and by Rule 5 of CCS (Temporary Service Rules of 1965)

No opportunity for self-defence was given to them. Forty-five numbers of trade unionists belonging to Avadi, Madras, Jabbalpur and Delhi area were removed from service. Local unions and All India Defence Employees' Federation have made representations for reviewing each case. All these cases have not yet been reviewed as they are being done in the Railways and P&T. In Ambarnath three cases of dismissals and one in Purulia have not yet been taken back.

So, I would request the hon. Minister to take back all those employees in Railways those employees were taken back. I request him again to take them back. Another thing is this. Once there was a theory that the martial race should be taken in the defence forces. But now it is highly mechanised and so, this theory should be given up.

In Air Force specially, the recruitment from Bengal has come down very considerably. I would request the hon. Minister to recruit from Bengal. Sir, Bengal produced heroes like Shri Surya Sen and Shri Subhas Chandra Bose. For sufficient number of Bengalis to be recruited in different forces, it is high time that the Bengal Regiment should be organised so that the youths from Bengal can defend our country in times of need.

With these observations, I conclude my speech. Thank you.

MR CHAIRMAN: Mr Rudolph Rodrigues.

SHRI RUDOLPH RODRIGUES (Nominated-Anglo-Indian): Madam, Chairman, I rise to support the Defence Budget. I rise happily and also somewhat in surprise, because it is always a great pleasure to rise in support of any money spent on our armed

forces in whose hands lie not only the integrity of our country but also the glory of India.

I rise also, somewhat surprised, because in the list of speakers, I was supposed to be in the second line of defence on this side of the House. I find that you are now calling in some people from among the lesser guns.

I would also like to begin with one observation. Madam, Chairman, last year, in this very House the Defence Minister said that there was in fact a great deal of unnecessary secretiveness about defence. This is confessed. One would expect that this year at least in the annual report, there would be a great deal more of data given to us than in the previous years.

I submit that though there has been some additional data given, it is not in those areas where we need it. Otherwise we should have been better equipped to participate in the debate in this House. Therefore my request is that in the very near future bearing in mind the physical and financial parameters within which we have to operate, bearing in mind the need for a strategic doctrine bearing in mind the harsh realities not only of the global but also of the regional military and landscape, bearing in mind the need for certain capabilities, some kind of white paper should be given to us so that we may come better prepared to this House. I also want to say that this does not mean in any way that I am asking for more information to strengthen the hands of either the doves or the hawks inside or outside this House. I think in matters of Defence all of us are doves when it comes to our attitude to our neighbours and all of us are hawks when it comes to the defence of our beloved country.

This Report and, in fact, this Defence budget on the surface indicates that we have decreased our share of the Central Government expenditure from 23 per cent in 1971-72 to 18 per cent this year. I would suggest that

though this figure and the fact that we do not even spend 4 per cent of our GNP on defence indicate that we are not a leading expenditure country as far as Defence goes, the fact is that in this Defence budget there are two hidden cushions. One is that nowhere in this Defence budget have we included what will become a sizable item of expenditure, that is, the proposed purchase of DPS planes and manufacture of spare parts. I understand that this will come to Rs. 200 crores at the lowest level.

The second cushion is that we do not include the expenditure on BSF which is supposed to under the Home Ministry but whose functions-for all practical purposes-are defence functions.

Having said that by way of introduction, I come to what is on my heart this afternoon. Most people begin the discussion on Defence with military hardware whereas I want to mention at the outset about the military "heart ware." I am concerned with the heart of our troops. One factor which weighs very heavily in warfare is the intangible factor of morale. I begin with the morable aspect of our armed forces. Sir, in most of the effective armed forces of the world where morale is high one will find that in those armed forces the promotional prospects are also very high. If a common soldier or a junior officer knows that there is a prospect of his one day holding the General's baton then his morale and fighting ability is affected favourably. I am suggesting when you look at the promotional prospects of our armed forces officers you will find after thirteen years service a junior officer becomes a Major at the most whereas in other IAS or Allied Services people in that period rise several ranks higher. This is a cause of heart burning in much of our armed forces. We should find out ways and means of telescoping this time-gap. This can be done if we have

the necessary will to do it, and also by setting up a Committee to look into this matter.

Turning to the various wings of the armed forces, I should like to begin with the Army itself. I begin with a very familiar quotation—the whole strategy of Cassius Clay, one-time world heavy-weight boxing champion,—and a familiar saying: "Float like a butterfly and sting like a bee". Our Army should not only be an Army which should be able to float like a butterfly but it should also be able to sting like a bee. Unfortunately, I feel, in so far as "floating" is concerned our tail is so heavy and our troops are so numerous that it becomes a little difficult for us to float. This is so even though our teeth-tail ratio has risen from 62.38 in 1971 to 67.33 in 1978. There is another aspect of our Army and that is....

and that is obsolescence with regard to different types of weapons. We have spent a sizeable amount of money for producing the prototype of an armed personnel carrier. Today it is no longer required by the armed forces because of a new type of warfare projected in the immediate future.

Now, we have a sizeable parachute brigade. One wonders whether we still need these kind of parachute troops when we have high mobility available to us through helicopters. Of course, a nucleus of parachute troops will always be necessary. In the army itself, I would ask the hon. Defence Minister to have a look at some of our costing. I am suggesting that at least in three things we can cut down our expenditure. One is that we have a number of military installations scattered all over the country. Perhaps consolidation of a few and dismantling of others would cut our costs a great deal.

Secondly, many of our officers and men suffer from a very high fre-

[Shri Rudolph Rodrigues]

quency of transfers. Each transfer costs the army a sizeable amount of money.

Thirdly about personnel I will not go into that in detail. Early last year on Christmas Day, the hon. Minister said that the size of the army should not be reduced because of the unemployment problem. I would submit that if unemployment is the main consideration, we can utilise our heavy tail in other ways, to help as a land army, for instance

Turning to the Navy, speaker after speaker, has mentioned the fact that we need to allocate additional funds to the navy. I am suggesting that around the word, the allocations between the three wings of the armed forces, particularly in those countries that are supposed to be the leading military nations, are more or less equal. Here we spend on our navy only 7 per cent. This may be an improvement. Today military strategy is largely an oceanic strategy not only because of missiles and manoeuvrability but because of weapons development out of all their proportion in the navy as compared to other wings of the armed forces. One has only to read the naval writings of strategy by both the major powers to realise that they have a tremendous interest in the Indian Ocean area, despite their talk of a proposed peace-zone and withdrawal from this area. If one reads the writings of the father of the Soviet Navy, Gorskov, and if one reads, for instance, the writings of Zumwalt, one of the think-tank people of the United States Naval Strategy, one will find a tremendous interest and importance given to the Indian Ocean. I do not want to go into the reasons. Now, the time has come that we should spend a far greater amount of money on our navy, even though it is the 9th largest in the world

Now, we have heard about Harriers. I think some hon. Members

mentioned about the development of M.S.A.—maritime surveillance aircraft—and I do not touch upon that.

Turning to our Air Force, we have heard so much about D.P.S.A. and the tremendous work it will do. We have Hunters and even Canberras which are more than 20 years old. We have certain types of transport equipment like Dakotas, for instance, which are more than 30 years old. The average life-span of an aircraft is not more than 15 years. So, we need to look at the expenditure and the replacement of aircraft, not only of D.P.S.A. but right across the board at all types of aircraft, particularly of what we call our METAC—(Medium Tactical Transport Aircrafts)—Division of the Air Force.

I shall conclude with one observation. Much has been said in this report about defence production; I do not want to add to that. We all know that we are perhaps the third largest manufacturer of armaments in the world. But what bothers me a little bit—I said this recently in another context—is the Conference with trade and industry to discuss ways and means of accelerating the pace of indigenisation of defence stores, in other words bringing the private sector more into the armaments production in so far as various parts are concerned. I sounded a warning before and I should like to repeat it here. Despite the fact that today the private sector is only touching upon—Rs 80 crores at the most in defence production, I should submit that with the growing possibilities of private sector participation in our defence production, we shall soon have to face a military industrial complex. One knows the amount of lobbying they are capable of; one has only to turn the pages of history to find out in Europe or in the Western hemisphere or even in the Soviet Union how much of weightage is given to them. I should only

ask our Defence Minister to assure this House that this danger is really not ahead of us in our country.

Finally, we heard one speaker mention about a no-war pact with Pakistan. Our objective should not only be a no-war pact with Pakistan or a no-war pact with any of our neighbours; a time has come for us to move to something more positive. We need a defence strategy based on a common pact for all of south Asian countries. With this statement, I should like to support the budget presented by the Defence Minister. -

SHRI B. P. KADAM (Kanara): I thank you for giving me an opportunity to speak on this subject. We are a very proud people. As our late beloved Prime Minister Nehru once said we belong to a tradition which defeated Alexander's ambition of world domination. Alexander had a sweeping victory in the Middle East but when he came to India he had to take a disastrous defeat. He had to return. Greek historians Plutarch and Deodaras had written about the Indian discipline and morale being very high. Ours is indeed a vast and powerful country and history shows that whenever discipline and unity was displaced, no aggressor either singly or in combination with others could overpower any of our rulers. Renaissance fathers right from Raja Rammohan Roy and Swami Vivekananda always spoke highly of our great past traditions. Vivekananda once said that India must be a very powerful country like a lion whose tail no aggressor would dare to tread.

With these preliminaries, I should like to make a few suggestions. In Ramayana we have great praise for our northern border, the Himalayas. Now, of course, it is not going to be a defence line. Times have changed. Apart from the Air Force, Chinese have demonstrated that it is not inviolable. Our oceans are very vast.

In this context, we have to be self-reliant, determined and disciplined and of course, equipped with the most modern equipments. Everyone is very proud of our defence forces because it is one of the best fighting forces in the whole world and this cannot be disputed. It has also helped the cause of national integration. Our defence policy is well linked with the external policy which we maintain, and this has to be accordingly viewed. Unfortunately, our neighbours, Pakistan and Bangladesh, have military rule and this is going to be a big headache for us. The late Mr. Rusel often said: "Military Dictators often find fault with the ruled because they cannot go on well and keep themselves in power; so they will try to rub with their neighbours." This happened thrice with Pakistan and this was to happen with Bangladesh also soon after liberation at our hands. Bangladesh was trying to rub us very hard in getting a solution for water dispute and everybody knew why it was doing so; it was playing in the hands of some big international powers. The difficulties with the Pakistan should not be lost sight of. Last time in 1971, the dictator said that that is going to be the last war. But unfortunately it was only the last war for the dictator who had to resign and who had to be in exile. Therefore one cannot predict well with the military dictators. The civil rule in Pakistan is still far off and in maintaining themselves in power, the military dictators may be unpredictable. Therefore we have to be in full preparedness. With the striking power and the aerial strength which they have gained from the western powers, we have to be still more vigilant and we must be having the best of intelligence on that border.

We have to be equally careful with Bangladesh and where the military rule continues. Things will not be bad with Nepal because it is a very good neighbour and things will

[Shri B. P. Kadam]

always be smooth. Our relations will not be bad with Sri Lanka, equally so with Burma. I am sure that, with a goodwill mission which has just visited our country and our Foreign Minister going to China, things will be better with our great ancient friendly neighbour. Once the Ambassador of USA advised that the Indian Ocean can be named as the sea of Madagaskar. Our Defence Minister said here and he warned that Americans need not advised us on the terminology of the names. The difficulty is that America, after its humiliation in the South Vietnam, is bound to be active in the Indian Ocean for it wants to maintain its balance and supremacy by rubbing somewhere and by some hallucination. Therefore, on the Indian Ocean we have to be very careful and under no circumstances compromise on the Diego-Garcia base.

I would like to mention one or two things about the weaponry. It is our beloved late Prime Minister Nehru himself an eminent historian, who said: "We were defeated due to the weakness of our armed forces, but we were vanquished by the better moulded weapons of the foreigners". If that is so, we have to be efficient in the striking power i.e., the aerial power, accurate in dealing with the enemy targets, deep penetration into the enemy territory, the same thing with better submarines sophisticated weapons and equally with other striking force.

Then I come to the welfare of the Ex-Army Personnel i.e., the ex-Servicemen. Their lot has to be considered. It is a humanitarian issue. And unless they are given honourable treatment, it will not be said that everything is well. The morale has to be maintained by giving a very good treatment to the ex-servicemen.

SHRI NARENDRA SINGH (Damoh): Madam Chairman, after a

long persuasion I am given the opportunity to speak a few words on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Defence for 1978-79.

I am immensely pleased to see the increased figure in the Defence Budget for which I am sure the honourable Defence Minister will find no difficulty to purchase any kind of aircraft from any part of the world the reason being that the foreign exchange earnings of Defence public undertakings have progressively increased from Rs. 2.27 crores to Rs. 29.47 crores.

The mighty little GNAT aircraft are made durable and sturdy in performance and they have proved to be one of the best for the Air Force. Besides this, we have Hunters, MIG Fighter plane etc., but still we need more deep penetration aircraft like Mirage of France. Efforts should be made to purchase and manufacture the aircraft like the MIGs in the country itself. Are we self-sufficient enough regarding the radars installed in all the border areas together with military bases? It is said that the installation of the first high power radar was successfully completed and the installation of the second is in progress. A high power radar and communication base has been installed. The armour capability of the army has improved by adding to it the Vijayanta tanks produced by the Heavy Vehicles Factory. The Annual Report of the Defence Ministry claims that these tanks have proved good from the mechanical point of view as well as from the point of reliability and offensive potential. Instead of L-60 guns we have introduced now L-70 guns and this along with other measures has improved its low level air defence capability.

In the same way, we are substantially well-equipped with modern weapons in all the three wings.

With these few words, I again convey my thanks to the hon. Defence Minister, who has shown considerable interest in ensuring modern amendments for all the three wings.

श्री मुस्तियार सिंह बलिक (सोनीपत) : सभापति महोदया, मैं डिफेंस की डिमांड्स को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुछ लोग यह कहते हैं कि डिफेंस के ऊपर बड़ा खर्च खर्चा हो रहा है और इसके लिए बहुत ज्यादा जो एलोकेशंस किए गए हैं यह देश के हित में नहीं है। इस किस्म की जो बाने कहीं जाती है मैं तो अपनी तरफ से उन को एंटीनेशनल कहने के लिए मजबूर रहूंगा। डिफेंस के ऊपर जितना भी हम खर्चा करें, मैं तो यह कहूंगा कि कम है। बहुत से लोग कहते हैं कि यह अन-प्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर है। लेकिन एक दफा हमारे डिफेंस मिनिस्टर बाबू जगजीवनराम ने यह राइटली आवजवं किया था कि डिफेंस के ऊपर जो खर्चा किया जाता है इस में ज्यादा प्रोडक्टिव और कोई हानि नहीं सकना क्योंकि डिफेंस फोर्सेज के द्वाँर न देश की सेक्योरिटी कायम रह सकती है न एकोनामिक प्रॉब्लम हों सकती है न प्रोडक्शन हों सकती है। डिफेंस फोर्सेज के बलबूते पर ही हमारे देश को किसी किम्म का बाहर से खतरा नहीं हो सकता और इन सारी चीजों का रखने हुए देश की सेक्योरिटी, देश के ग्रंदर प्रोडक्शन एकोनामिक प्रोडक्शन बड़े प्राराम से चल सकती है। इसलिए जितना भी खर्चा डिफेंस के ऊपर किया जाता है वह प्रोडक्टिव है। उस को अन-प्रोडक्टिव कहना उस के साथ नाइंसाफी होगी।

वैसे, मैं अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि हमें इस डिफेंस के मामले में कोई काम्प्लेसिटी नहीं होनी चाहिए। यह ठीक है कि हमारे

नेबर्स के साथ हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमारे ताल्लुकात बगैर ठीक है लेकिन उस के बावजूद

Let us not repeat the history; let us learn some lessons from history.

क्योंकि 1950 से लेकर 1962 तक जो हमारे देश के साथ हुआ और हमारी डिफेंस फोर्सेज को कोई मार्डन वेपन्स बगैर रह नहीं दिए गए तो उसका खमियाजा सारे देश को भुगतना पड़ा। कांग्रेस गवर्नमेंट की एक गलती से जिसे कि मैं कहूंगा कि गलती ही नहीं बल्कि मुजरिमाना गलती थी, उसकी वजह से देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और इन्ही चीजों को देखते हुए मुझे याद याता है, जो हमारे बड़े मशहूर श्चि चाणक्य हुए है,

He once observed: think every neighbour, take every neighbour to be a potential enemy.

तो इन चीजों को देखते हुए हमारे ताल्लुकात नेबर्स के साथ में ठीक है—इसमें हमें नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमें किसी नेबर के साथ लड़ाई करनी चाहिए या लड़ाई के लिए किसी किस्म की तैयारी करें लेकिन अपनी सिक््योरिटी के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। हमारे देश के लेन्ड बार्डर्स कितने लम्बे चौड़े हैं और जो हमारे नैबल बार्डर्स हैं, सी के बार्डर्स है वह कितने लम्बे चौड़े हैं। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, नेबी में हम बहुत तरक्की कर रहे हैं लेकिन उस के बावजूद हमारी नेबी में बहुत कमी है। नेबी को मार्डनाइज करना चाहिए, उस को मार्डन हथियार देने चाहिए और जितना भी हम नेबल फोर्सेज को बढ़ा सकें, बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी नेबी को मार्डन हथियार दे कर दुनिया में फस्ट रेट पावर

[श्री मुंडियार सिंह कलिक]

बनाना चाहिए। अभी हमारी नेवी में बहुत ज्यादा कमी है इसलिए मैं अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब से भर्ज करना चाहता हूँ कि नेवी के मामले में वे खास तौर से ध्यान दें।

15 hrs

एक दरखास्त मैं और करना चाहता हूँ और सजेक्शन देना चाहता हूँ कि जो हमारी बांडर सिक्वोरिटी फोर्स है—यह बात मेरी भाज तक समझ में नहीं आई कि वह होम मिनिस्ट्री के अन्डर में क्यों हैं बांडर सिक्वोरिटी फोर्स का बिल्कुल मिलिट्री का काम है, यह फोर्स देश के बांडर पर है, वहाँ उन के पास बीपनरी हैं, वही उन के पास हथियार हाते हैं लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसका कंट्रोल है वह होम मिनिस्ट्री के अन्डर में है। यह बात मेरी समझ में नहीं बाहर है इसलिए डिफेंस मिनिस्टर साहब से मेरी दरखास्त है कि अपनी गवर्नमेंट को इस चीज के लिए मजबूर करें और इस फोर्स का होम मिनिस्ट्री में डिफेंस मिनिस्ट्री में लिया जाये।

एक चीज और है कि हमारा मिलिट्री आफिस के लिए हाउसिंग की बहुत बड़ी प्राब्लम है। हम बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो हमारा डिफेंस फोर्स के आफिसर्स फार्वर्ड एरियाज में जाते हैं उनके बच्चों के लिए पीछे रहने के लिए भकाना की बड़ी प्राब्लम रहनी है। हर जगह पर बड़ी जबर्दस्त हाउसिंग प्राब्लम रहती है। इसकी तरफ भी डिफेंस मिनिस्टर को जबर्दस्त ध्यान देने की जरूरत है। मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब से मुझद्वारा गुजारिश करूंगा कि डिफेंस फोर्स की हाउसिंग प्राब्लम को हल करने के लिए अब तो बजट

में काफ़ी प्राब्लम हुआ है लेकिन अब उसकी तरफ बहुत ध्यान र उसको पूरा करने की जरूरत है।

इसके साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो प्रोहिबिशन की पालिसी है उस के सिलसिले में मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब से भर्ज करना चाहता हूँ कि जब तक सारा कट्टी ड्राई न हो जाये तब तक डिफेंस फोर्स पर इसका फोर्स न किया जाये। हमारी डिफेंस फोर्स में भी इसी धरती के पुव हैं, वह भी इस देश के सिटीजन हैं, जब सारा देश प्रोहिबिशन की तरफ चला जायेगा ता वे भी बेसफुली इसका एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन उस से पहले उन के ऊपर हमको फोर्स नहीं करना चाहिए। मिलिट्री का नम्बर सब से बाद में आना चाहिए। जब सारा कट्टी प्रोहिबिशन का अखतियार कर लेगा तो डिफेंस फोर्स भी इसमें किसी से पीछे नहीं रहेंगे। वे भी उतना ही रैम्पस देगे, जितना दूसरे देगे। लेकिन एक चीज मैं एक्स्पेक्शन के लिये जरूर भर्ज करना चाहता हूँ। फार्वर्ड एरियाज में, ग्रीमोट एरियाज में, पहाड़ों के अन्दर जा हमारी फोर्स है, उन के लिये प्रोहिबिशन की पालिसी को लागू नहीं करना चाहिये। उन का इसके लिये एक्स्पेक्शन जरूर देना चाहिये।

हमारे यहाँ पचास हजार के करीब मिलिट्री पर्सनल हर साल रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद उन के लिये री-एम्प्लायमेंट की बड़ी ज़बरदस्त प्राब्लम है। जो हमारे दूसरे इन्वारे हैं, जैसे होटल इन्डस्ट्री है दूसरी इन्डस्ट्री है, पब्लिक अन्डरटेकिंग है, इन में सिक्वोरिटी के काम पर उन का री-एम्प्लाय करने के लिये हुकूमत को जोर देना चाहिये। हमें उन को कहना चाहिये कि जो हमारे मिलिट्री के लिये रिटायर होते हैं, उन को इन कामों पर भरती किया जाय। रिटायर होने के

बाद उन के सामने बहुत सी मुश्किलत पैदा हो जाती हैं, थोड़ी सी पैमान में उन का गुजारा नहीं होता है, एक कमाने वाला होता है, लेकिन उस के पीछे बच्चों की एचकेसन है, दूसरी प्रावलम्ब होती है—इस तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब को खाम ध्यान देना चाहिये।

इन सरकार के साथ मैं उम्मीद करता हूं हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब मेरी सजेसचन्स पर जरूर शोर करेंगे और मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स को फुली-सपोर्ट करता हूँ ।

SHRI D. D. DESAI (Kaira): Our long history has taught us many lessons. Sometimes, we have learnt and sometimes, we have forgotten. Post-Independence wars that were forced on us, give us new experience. One of the important lessons has been self-reliance. Unfortunately, I cannot say that today we have self-reliance so far as defence requirements are concerned. The narrow view being taken is related to our early 50s' position when our industrial capabilities were very limited. At that time, we thought that we would provide arms from the core sector. But limitations are hurting us today. We did not anticipate such an industrial base at that time. This industrial base provides us fantastic possibilities and capabilities. To disregard that would be hurting our own defence forces. No one today would argue that the capabilities that we have established in the public sector are adequate to meet our defence requirements. We are importing thousands of crores worth equipments over a period and the supplies of their components are cut off amidst fighting. We had the problem of foreign exchange. But that restraint is no more valid now. However, to be independent we should

make use of our capabilities within the country. The criteria that we apply for producing heavy tanks, big vessels, etc. are obsolete. For example, we are thinking in terms of heavy tanks, bigger ships, etc. These are worthless things so far as I am concerned. Many of the people who have read the value analysis done by Robert McNamara and other specialists have come to the conclusion that anti-missiles and striking missiles provide greater defence at lesser cost.

After all, intelligence is not the monopoly of any sector, public sector or private sector. It is a God given gift. It could be anywhere. If that could be used to the best of our advantage, we will be in a very strong position. Therefore, I would expect the cost-benefit analysis to be made. For example, today, we are running in Defence Ministry so many establishments, industries, even piggery, farms, poultry and such other things. Are these things necessary? Once a person or an organisation identifies with such things, it has to live with them and, it has to defend them. Under the circumstances, it would not be engaging itself in self-criticism. To that extent, this disadvantage is built into our system which we should get rid of at the earliest.

We are very well equipped in electronics. Whether one likes to say so or not, electronic devices, including satellite spying system, will be of great help to this country. But, unfortunately, our restricted outlook is preventing us from making use of advances that are being made in this field. Most of the technology has passed on to text books or, in the case of more advanced technology, to the professional journals. We have to develop our own capabilities. If anybody has any doubt about our capabilities, I may point out that over 20 per cent personnel in the NASA are Indians. Even in the MARS MARINER programme undertaken by

[Shri D D Desai]

the California University, some of the group leaders were Indians. This shows that our capabilities are there. The question is one of organising and putting to use these capabilities with in our country. We can do it provided we remove the shackles which many of the advanced countries have removed. For example, in the United States, the United Kingdom, West Germany, Japan and other advanced countries excepting the Soviet Union, in none of these countries these restrictions are imposed on human capabilities to develop things and provide the necessary advancement in this field.

There the question might be put: Why should we go in for these things because they cost a hell of a lot of money? But the fact is that it costs less money. With the same tonnage or with the same weight and amount we can have far more destruction and we can have far more capability. That means if we really make use of our talent then the weight or the amount could be greatly reduced and that could be one of our important contributions which we should expect from our own base that we have created.

There is again a question of logistics like communications and other things for transmitting to or communicating with different places. We all know that most of the satellites which have been in the space—there are over a thousand of satellites in the space—have been built in the private sector. The satellites could be manufactured in India in other sectors also. But unfortunately we do not still undertake these things. For example, the General Electric, the Western Electric, the ITT and in Europe others contribute to make satellites. In fact we have ourselves ordered for satellites from the private companies in the international world. This shows that we are ready to order for satellite and other defence equipments from pri-

vate companies in the outside world, but not in India. Therefore, we are denying ourselves the possibility of developing our capabilities in the field of chemical warfare, bacterial warfare and all that, we have got the capability to counter but if we think only in terms of a limited approach towards it, then probably we may end up in a disastrous manner which may not be proper.

In the last war with Pakistan we lost *Kukri* with all the crew and some of the best people abroad because we did not have the proper sonar detection system. Our detection range was limited. For example if we had developed indigenous Sonar and it was fitted in the submarine *Kukri* and with very high power range that could be made in this country—we would have saved *Kukri*. Similarly for sinking *Gazi*, we had to depend on fishermen to inform us that there was a Pakistani ship or submarine. Some fishermen gave information about the submarine *Gazi* and then we attacked and sank it.

We have been talking about research and development. Really speaking I would say that all that we urgently need today is the development work and that could be done within the country because most of our people are well equipped. If some of the establishments and industrial units which are required to be managed by the Defence Department are taken away and the Defence Department was freed entirely to make their own purchases on the basis of scientific objective evaluation for minimum cost maximum destruction in the shortest possible time at the greatest possible range and so on then there is a possibility for us to make a selection completely different from self-imposed limitations which we are making today. Our effort should also be to build up some sort of capability in our universities in our country. Our Profes-

and boys have plenty of time and possibilities to take to some of the research and development works and some of these things could be well taken care of

When we are talking of research and development in our universities, one of the items is metal. Recently, we have seen the report on the Soviet Union's new MIG. Their MIG 25 was heavy and it was found that it was not comparable with USA F 15 Planes metal. Therefore, when we are talking of MIG or when we are talking of striking or when we are talking of penetration or of space and all those things, metal is of considerable importance, particularly, when we deal with extremely high temperature and pressure, metal has a definite role to play

Similarly, in the case of designs, we have a large number of engineers to work on designs. As far as testing is concerned it is also not difficult in our country. So far as electronic equipments are concerned I can assure you we are very well equipped. But unfortunately we have put self imposed limitations which are causing us a certain difficulties. In the case of computer and other things if we are freed from our present restrictive conditions including red tape and various other matters than we would be in a much better position. I would conclude my speech by thanking you for giving me this opportunity.

श्री नाथू सिंह (दोसा) : महापति, जिस देश की रक्षा पक्कि मजबूत होता है जिस देश की सेनाएँ मजठित और सुशिक्षित हानी है वह देश उतना ही मजबूत और शक्तिशाली होता है। उतना ही देश का मौरल ऊचा होता है। 1962 की पिटाई के बाद, भारत ने भी इस और ध्यान दिया। उसी का परिणाम यह निकला कि 1971 के युद्ध में हमने विजय प्राप्त की। लेकिन उस के बाद

हम ने यह समझ लिया कि हमारी ताकत बढ़ गयी है और हम लोग मजबूत हो गये हैं। हमने साचा कि हम ने अपनी सेनाओं को बहुत मजबूत बना लिया है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम देखे तो आज भी हमारी सेनाएँ जितनी मजबूत होनी चाहिए थी, उतनी मजबूत नहीं है। जिस तरह के प्राधुनिक हथियार हमारी सेनाओं के पास होने चाहिए थे, वे नहीं हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान से हम ज्यादा मजबूत हों, बगलादेश से अधिक ताकतवर हों लेकिन अगर हम अमरिका, रूस और चीन के मुकाबल में खड़े होते हैं।

15 20 hrs.

[SHRI N K SHEJWALKAR in the Chair]

सामने टिक नहीं पाते। इतना बड़ा देश लेकिन फिर भी हम अपनी तुलना उगला देश और पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे देशों से करते हैं। आज हमारे पास नए हथियार नहीं हैं। परमाणु तथा अणु बम बनाने से हम डरते हैं। हमारे दिल में जैसे सारी दुनिया का डेका ल लिया है हमीने सारी दुनिया की शान्ति का डेका ल लिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि शान्ति व्यवस्था हम तभी कायम रख सकते हैं जब हम मजबूत होंगे। अगर कोई गुंडा छेड़ रहा होता है ना उसका मुकाबला तभी किया जा सकता है जब सामने वाला उस से ज्यादा ताकतवर होता है। अधिक ताकतवर सब भय खाएगा। अगर हम ज्यादा ताकतवर होंगे तो वह गडगडगी नहीं कर सकेगा हिम्मत भी करने की नहीं दिख सकेगा। उसका तब हम जब चाहेंगे दबोच लेंगे। हम शान्ति के पुजारी हैं, यह ठीक बात है।

[श्री नाथ सिंह]

लेकिन विश्व की शांति का संदेश भी हम तभी दे सकते हैं जब हम मजबूत होंगे। हमारी ओर कोई धाँख उठा कर न देख सके और उसको पता हो कि उसने धाँख उठाई तो उसकी धाँख निकाल ली जाएगी, तभी हम शान्ति स्थापित रख सकते हैं। कोई भी खतरा आए उनका मुकाबला करने की हम में क्षमता होनी चाहिये।

आप थल सेना को देखें। कौन से टैंक आप के पास हैं। हमारे पास एक ही टैंक है जो हमने बनाया विजयन्ता। कितने ही बरसों के बाद बनाया है। इसी तरह से हमारे पाम कैनवरा और हटर विमान ही हैं। काफी दिनों से हम सोच रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। बीस साल पुराने य विमान है। य घाउट डेटिड, घाउट माडिड हा चुके हैं। सुरक्षा मंत्रालय पिछले पाच साल से काशिश कर रहा है नए विमान खरीदने की अच्छे अच्छे नडाकू विमान खरीदने की बनान की लेकिन अभी तक खरीदे नहीं गए हैं। अभी ना बातचीत ही चल रही है। स्वीडन के पास विगार है स्पेन के पास मिराज है ब्रिटेन के पास जागवार है। उन विमानों का जिन का हम खरीदने की सोच रहे हैं उनका कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारी सनाए आधुनिक बन मुसज्जिन बने इस के लिए जरूरी है कि हम पाकिस्तान को न देखे अमरीका रूस आदि का देखें। हमारे पाम किस बाज की कमी है हम का अपनी सनाया का मुसज्जित करना होगा नई टैकनालाजी के आधार पर नए अजारा में नए अस्त्र अस्त्रा से उन का मुसज्जित करना होगा दुनिया के साथ का बान्धन कर के हम लाग चल तभी हमारी रक्षा पत्रि मजबूत होगी।

हमने राजस्थान के जैसलमेर जिन में एक एटामिफ एनास्ट किया कई वर्ष पहले। उनके बाद हम उस का भूल गए। वह हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके तुरन्त बाद

पूरे विश्व में हमारी धाँक जमी। चीन भी हम से डरने लगा। वह भी समझ गया कि भारत भी परमाणु क्षीर अणु बन बन बना सकता है। उसके बाद हम चुप हो कर बैठ गए। आज भी हमारी चौदह हजार बर्ग मील भूमि चीन दबाए बैठा है। उस की बिना चिन्ता किए हुए हम उस की तरफ दोस्ती का हाथ कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा पत्रि को मजबूत करने की बान नहीं सोच रहे हैं। इस तरह दोस्ती का हाथ दूसरे देशों के साथ बढ़ाने के बजाय हम अपने आप का मजबूत करें। यदि हमने ऐसा किया तो अपने आप दूसरे देश मजबूर हो कर हमारी तरफ दान्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इस के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होगी। पैसा खर्च करना होगा। हमें चाहिए सब में अधिक बजट हम रक्षापत्रि का मजबूत करने पर खर्च करें। ताकि हमारी सीमा के ऊपर कोई दुश्मन धाँख उठा कर न देख सके। और जा भी ऐसा करने की गलती करता है उस का पता हाना चाहिये उस की धाँख फूट जाएगी। इस के लिए हमें अपने में ताकत पैदा करनी होगी। मरी मांग है कि हम परमाणु तथा अणु बम अविलम्ब बनाना चाहिये। हमें धापणा करनी चाहिए कि यह लडाई के लिए नहीं विश्व शान्ति के लिए विश्व में शान्ति बनाए रखने के लिए हम बना रहे हैं। हम विश्व में शान्ति के पुजारी हैं और इसके लिए हम इन का बना रहे हैं। नए नए हथियार विमान आदि बनाने लिए चाहे प्राइवेट सैक्टर हा या कोई और हा हम का सहयोग उमका लना चाहिए और साथ ही साथ उम का सहयोग देना चाहिये। आधुनिकतम हथियार हम भारत में ही बनाना प्रारम्भ करें। दूसरे देशों के ऊपर हम आश्रित न हों। मान ले वल का लडाई हा जाती है तब जिन देशों से हम आज हथियार ले रहे हैं वह देश किसी कारण से हमें हथियार या सामान देना बन्द कर देते हैं फिर हमारी क्या स्थिति होगी? हमारे के सामने हमें

झोली कौमानी पड़ेगी और उस की उल्टी-सीधी शर्तें माननी पड़ेगी। इस के लिये जरूरी है कि अभी से हम होशियार हो जायें और अपने को मजबूत बना लें ताकि अगर कोई दूसरा देश जैसे चीन, अमरीका, रूस आदि हम पर हमला करे ता बिना किसी दूसरे देश की सहायता के हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। इतनी तैयारी हमें कम से कम जरूरी करना पड़ेगी। रक्षा से संबंधित जो भी आवश्यकता के साज सामान हैं उस के सम्बन्ध में हम देश को आत्म निर्भर बनाना पड़ेगा तब जा कर के हम कह सकते हैं कि अब हम संसार में गौरव व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं।

1971 का युद्ध हुआ, मैं कहना चाहता हूँ कि इन्दिरा जी ने उस समय जीत का मेहरा सिपाहियों के मर न बाध कर अपने सिर पर बाध लिया। और जनरल भानिकशा को बुला कर कहा था कि अगर हम जीत जायेंगे तो तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूँगे। और वैसा किया भी। लेकिन एक सैनिक के साथ खिलवाड़ किया। आज तक जा सुविधाएँ एक रिटायर्ड फील्ड मार्शल को मिलनी चाहिये वह उन का नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? उस के साथ धाखा किया गया है। यदि हम किसी सैनिक को सम्मान देने है तो ईमानदारी के साथ वह सम्मान देना चाहिये इस के अलावा उस युद्ध में करीब 4000 सिंधी शरणार्थी बिना भारत की नागरिकता के यहाँ पड़े हुए हैं। उन की कोई नहीं मुनता है। जा लडाई के दिनों में हमारे देश में आते है हमारे ही देश के हैं और यहाँ रहना चाहते है, हमें उन की सुरक्षा और जीवन यापन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो।

जो सैनिक हमारे देश की सीमाओं पर लडते है, पहचान देते है उन की स्थिति यह है कि उनके पास पूरा सामान नहीं है। अच्छी कपड़े नहीं है उन के पास। कटीती करते जा रहे हैं। जब उनका रिटायरमेंट होता है तो उनके

जीवन यापन की कोई गारन्टी नहीं है। उनको पूरा रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। वह लोग नौकरी के लिए इधर-उधर मारे मारे फिरते है। सरकार इस बात को जिम्मेदारी ले कि पर्स भी सैनिक जो वापस लोटता है उस के जीवन यापन की सुविधा देंगे, चाहे नौकरी लगे या न लगे, उन्हें भत्ता देंगे, उन के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, उन्हें जमीन देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि उन सैनिकों को जो जमीनें दी गई है पहाड़ों और टीलों पर बड़े क्लास जमीनें दी गई हैं। उन का क्या नहीं अच्छी जमीन दी जाती है? इसलिए मेरा निवेदन है कि उन के अज्वात के साथ खिलवाड़ न करे। हम नारा देते है और वह लोग अपना खून बहाते हैं। हम लोग बड़े बड़े मिमला समझौता कर लेते हैं एयर कंडीशन्ड कमरों में, और जवान बरसात, गर्मी में बन्दूक लेकर लडते है अपने परिवार की परवाह किये बगैर। उन जवानों के खून के साथ हम खिलवाड़ करते है, उन के खून के साथ होली खलने हैं और जब वह लौट कर आते है ता उन के जीवन यापन की कोई गारन्टी नहीं देते है।

आज हमें देखने को मिल रहा है कि एन० सी० सी० का जो एक विंग है या इसी तरह में मिलिटरी के अन्दर जो प्रोमोशन देते है, 13 वर्ष के अन्दर एक आदमी मेजर बनता है। उधर 13 साल में मेजर के रैंक पर पहुँचता है और इधर 13 साल में जो सिविल सर्विस में है वह डिप्टी सैक्रेटरी बन जाता है। जो देश के लिये लड रहा है, रिश्कत से लड़ रहा है, ईमानदार है वह मेजर बनता है और इधर जो रिश्कत लेता है दूसरी सुविधाएँ भी मिल जाती हैं वह डिप्टी

[श्री नाथ सिंह]

सैक्रेटरी बन जाता है। दोनों की 13 साल की सविस होती है लेकिन मेजर को डिप्टी सैक्रेटरी के बराबर मुवित्राएं नहीं होती है। यह भेद भाव क्यों है? एक तो रिस्क लेकर वहां बैठा होता है और दूसरा बिना रिस्क के वहां बैठा रहता है, उभर भो इधर-उधर से मुवित्राएं मार लेता है। मेजर डिप्टी सैक्रेटरी से नीचे माना जाता है। मेरा कहना है कि उसे डिप्टी सैक्रेटरी से ऊपर माना जाना चाहिये। यह भेदभाव मिटना चाहिये।

एन० सी० सी० को विंग चल रही है। मैं भी एन० सी० सी० में था जब कि पढ़ता था। मेरो फौज में जाने तो इच्छा थी, मेरा सलैक्शन भी हो रहा था, लेकिन उम्र नमय इन्डिरा जी ने मुझे जेल भेज दिया जिस के कारण मुझे आज यहां लोक-सभा में आना पड़ा। अगर वहां चला जाता तो मैं देश की रक्षा पर देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता लेकिन आज मैं यहां डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ रहा हूँ। इधर देश में लोकतंत्र को रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। और उधर बाउंडर पर देश की रक्षा के लिए लड़ता हूँ। और, मैं आज भी खुश हूँ कि लोकतंत्र को रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन एन० सी० सी० में वही और वूट नहीं दिए जाते हैं। जब कि उनका ट्रेनिंग भी जानी थी, उन के छट्टेबमेंट होते थे। एन० सी० सी० के लड़कों ने एम-जेंसी के दौरान 5-सूत्री और 20-सूत्री कार्यक्रम में जगह जगह ताणियां बनवाई गईं, सड़कें खुदवाई गईं। उन्हें यह नहीं बताया गया कि गॉ-नाट-याँ राइफल क्या होती है, टैंक क्या होते हैं। थल सेना, नैवी या एयरफोर्स क्या होती है, यह भी नहीं बताया गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि एन० सी० सी० को बाकायदा सड़कें बनवाने, ताली साफ कराने और

शहर की सफाई कराने मात्र तक ही सीमित न रहें बल्कि भ्रमरीका की तरह प्रत्येक नागरिक के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य की जाये। हर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के लिए एक साल या 2 साल की सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये। एन० सी० सी० के छात्रों को अनिवार्य रूप से पूरी सैनिक शिक्षा दी जाये कि टैंक के साथ कैसे लड़ाई की जाती है। हमें उस समय यह सिखाया गया था। मुझे पता है कि विजयन्त टैंक के साथ कैसे ऑपरेशन किया जाये। अगर आज मैं बाउंडर पर चला जाऊं तो 5, 7 दिन की ट्रेनिंग लेकर सैनिक के रूप में वहां लड़ सकता हूँ। यह इसलिए कि उस समय ट्रेनिंग देने थे, लेकिन आज हाजिर यह है कि जो पैसा हम एन० सी० सी० पर खर्च कर रहे हैं वह बेकार जा रहा है। मेरा कहना यह है कि एन० सी० सी० पर अधिक पैसा खर्च किया जाना चाहिये और नव को मिलेरी ट्रेनिंग दी जानी चाहिये।

सलैक्शन के मामले में एज का भ्रवाल आता है, परन्तु 21 साल एज भी अब 23 वर्ष है। इस से ज्यादा उम्र की जानी है तो उसको गार्ट सविस कमिशन में भेते हैं। वह वहां पर 2, 3 साल रहता है। और बाद में उसका वहां से निकाल देते हैं। उस तरह से देखिए कि उसका भविष्य क्या है। 2, 3 साल गार्ट सविस कमिशन में रहने के बाद निकाल दिए जाते हैं तो उस के बाद वे क्या करेंगे? गांव के लड़के 21 साल तक अंग्रेजी पढ़े नहीं होते हैं और वहां अंग्रेजी जानने वालों का सलैक्शन होता है। मेरा मुझाब है कि आयु सीमा को बढ़ाया जाना चाहिये या फिर अंग्रेजी उसमें कंपलसरी नहीं रहनी चाहिये। गांव का लड़का जब पढ़ने के लिये जाता है तो ब्राह्मिसे से उसकी एज लगा देते हैं और सलैक्शन के बन्त उसकी एज

ज्यादा हो जाती है। वह हट्टा-कट्टा होता है, लड़ाई में लड़ सकता है, लेकिन एज के कारण सौजन्य नहीं हो पाता। उसके माता-पिता 5, 6 दिन या महीने, बी महीने एज ज्यादा लिखवा दें तो उनकी आयु की गड़बड़ हो जाती है इसलिए आयु सीमा बढ़नी चाहिये और 25 वर्ष करनी चाहिये।

एक सुझाव यह है कि सेना में बहुत से रेजीमेंट बने हुए हैं जैसे जाट रेजीमेंट, सिख रेजीमेंट, राजपूत रेजीमेंट। दूधरी जाति के लोग जो कि मेना में हैं वह भी अपनी-अपनी रेजीमेंट की मांग कर रहे हैं। मेरे पास कुछ लोग प्राये, उन्होंने कहा कि अहीर रेजीमेंट हो, गुजर रेजीमेंट बननी चाहिये। रक्षा मंत्री में भी उन्होंने इस बात की मांग की है। मेरा तर्कना है कि जाति के आधार पर जो रेजीमेंट बने हुए हैं, उनको समाप्त किया जाये या बाकी लोग जो मेना में हैं, उनके नाम में भी रेजीमेंट बनाये जायें उनका धमनाप दूर हो।

मे एक बात और कहना चाहता हूँ, हालांकि मुझे कहनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बात में विश्वास करता हूँ। कुछ दिन पूर्व निलपत रेज में एयरफोर्स का शक्ति-प्रदर्शन हुआ था, जिस को देखने के लिए बहुत सी 'पब्लिक

गई थी। मैं मानता हूँ कि मंत्री एयरफोर्स के विमानों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन की फीमिलीज और यार-दोस्तों के लिए वे विमान नहीं हैं। वहाँ इतना भद्दा प्रदर्शन हुआ कि एक-आध घंटे तक मंत्री, उन की फीमिलीज और उन के यार-दोस्त विमानों में चढ़ने-उतरने रहे। यह देख कर पब्लिक को बड़ा गुस्सा आया। इस तरह का प्रदर्शन कम से कम जनता सरकार के मंत्रियों को नहीं करना चाहिए। जनता में बड़ा आक्रोश था। आखिर एयरफोर्स के विमान मंत्रियों की फीमिलीज और उन के यार-दोस्तों के लिए मस्ती मारने के लिए नहीं है, मंत्री स्वयं भले ही उनका उपयोग करें। इस लिए जनता पार्टी के मिनिस्टर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेना के विमान उन के परिवार वालों और यार-दोस्तों के लिए काम में न लाये जायें।

मैंने अभी कहा है कि एन० सी० सी० को कालेज और स्कूल लेवल पर अधिक सहायता देनी चाहिए। लेकिन केवल कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवक ही एन० सी० सी० में जा सकते हैं। इस बात की आवश्यकता है कि अनिवार्य नैतिक शिक्षा देने के लिए गावों में भी एन० सी० सी० जैसी कोई व्यवस्था की जायें, ताकि गावों के कम पढ़े-लिखे लोग भी सैनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्हें ऐसी बातों का प्रशिक्षण दिया जाए कि जब बम गिरे, तो कैसे बचाव किया जाए, और शत्रु की सेना के आन पर कैसे उभरना प्रभावना किया जाय।

1924 के कैनटूनमेंट एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। कैनटूनमेंट में रहने वाले कई निविनियन लोग मेरे पाम आये थे। नमीरावाद के लोग भी आये थे। पहले तो उन लोगों को बहाल जा कर बसाया गया, लेकिन आज यह स्थिति है कि उन के परिवार बढ़े हो गए हैं, लेकिन उन्हें विजली नहीं

[श्री नाथ सिंह]

लगान दो जानो है पानी नहीं दिया जाता है, बायस्कम और अगम कमरे नहीं बनाने दिये जाते हैं। इसलिए इस एक्ट में मशाघन होना चाहिए, ताकि उन लोगों की परेशानी दूर हो।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी सेनाओं को मजबूत नहीं बनाया जायेगा, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता है, और हम दूसरे देशों का मुँह ताकते रहेंगे, उन से डरते रहेंगे। इस लिए सब से पहले देश की सेनाओं, देश की रक्षा-शक्ति, को मजबूत करना चाहिए और फिर दूसरे देशों की धोर दोस्ती और शान्ति का हाथ बढ़ाना चाहिए।

श्री केशवराव धोंडगे (नांदेड) - सदन साहब, डिफेंस का सबजेक्ट बहुत ग्रहणियत रखता है। अपनी डिफेंस फोर्सिज की कुर्बानी पर हम लोगों को नाज है और उन की वजह से हमारी आजादी महफूज है और हम यहाँ पर हैं। अफमोस की बात यह है कि हमारी आजादी और हमारी बाउडरीज तो महफूज है, लेकिन जो लोग मुल्क की आजादी की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं उन के मकानात और घर-बार गैर-महफूज है। वे हमारा संरक्षण करते हैं लेकिन उन के मकानात और परिचार वालों का हुकूमत संरक्षण नहीं कर सकती है। वे लोग बाउंडर पर दुश्मन का मुकाबला करते हैं, लेकिन जब उन के घरों में खतून आने हैं कि उन के धर्म पर हमला होता है, उन की मा-बहनों की इज्जत पर हमला होता है, ना उस वकत उन जवानों के दिलों में यह ख्याल पैदा होता है कि हम तो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, बाहरी दुश्मन का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के अन्दर जो दुश्मन है, उन के खिलाफ लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। हुकूमत तो बड़ों का डिफेंस करती है। हमारे बाग़ वाला की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती। फिर यह आजादी किसकी ? ऐसा

ख्यान फौज के जवानों में धाता है। खिलाजा गरीब मुल्क के अन्दर गरीबी, गुरुबत, जहालत, फिकरपरस्ती, बेकारी ये भी बहुत जबरदस्त दुश्मन है और इस दुश्मन का मुकाबला अगर इन्टर्नल गवर्नमेंट न कर सके तो हमारी मिलिट्री कितनी भी ताकतवर हो वह अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो सकती। अफसोस की बात है कि जो मिलिट्री में जाते हैं अकमर उस में ध्येयवाद से जाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जा बिस्कुल गरीब लोग होते हैं, भ्रष्टलिस होते हैं, जिन को कहीं काम नहीं मिलता है ऐसे लोग उस में जाते हैं। उन के अन्दर ध्येयवाद होना बहुत जरूरी है कि मैं किस मकसद के लिए सैनिक हुआ और लड़ रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है? समाजवाद के अन्दर हर मिलिट्रीमैन के अन्दर यह चीज होनी चाहिए। मैं रेजीमेन्टेशन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि उन में यह चीज होनी चाहिए कि मुल्क मेरा है, यह काम मेरी है और मैं काम का हूँ। वह तो वे करते ही हैं उन की कुर्बानी पर ही हम और आप यहाँ मौजूद हैं। वे विचारे सही हैं। मगर अफसोस की बात है कि हम ऐसे लोगों को ट्रेनिंग अच्छी तरह में नहीं दे पाते। उन में समाजवादी ध्येय ला नहीं सकते। तो मिलिट्री का आधुनिकीकरण होना बहुत जरूरी है। चाहे दुश्मन आज रहे या न रहे मगर यदि मेरी मान में हमका अपनी कामयाबी और अपनी आजादी मजबूत करने है तो हमें अपनी मिलिट्री के परमानेस का मजबूत करना चाहिए। हायर रैंक्स में होते हैं उन में बड़े-बड़े लोग होते हैं, दलित समाज और बैकवर्ड समाज के लोग उस रैंक में कभी नहीं जा सकते। यह बड़े अफसोस की बात है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब एक दलित समाज के हैं। हमें बड़ा फायदा है। मगर देश में दलित समाज का भी वह डिफेंस नहीं कर सकते। हायर रैंक्स के

अन्दर देखा जाये तो हिन्दुस्तान में गरीब तबके का अन्दर, उन के बाल बच्चे कभी बड़े से बड़े सेनापति नहीं बन सकते। यह अफसोस को बात है क्योंकि उन को ट्रेनिंग ही नहीं मिलती। उन को परम्परा निर्माण करने का अवसर ही नहीं मिलता। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ जनता हुकूमत से कि आप कुछ करना चाहते हैं या नहीं? क्या वे महज मरते रहें, लड़ते रहें, कुर्बानी उन की होती रहे? आर्डर देने वाले कोई और हैं, मरने वाले कोई और हैं। मरणोत्तर पारितोषिक लेने वाले कोई और हैं और फंडेशन के अन्दर बड़े बड़े मेहमान बनने वाले कोई और हैं। अगर यही चीज हिन्दुस्तान के अन्दर होने वाली है तो मिलिट्री के अन्दर भी ऐसा तबका है जो समझती है कि कुर्बानी किस लिए कर रहा है। वह समझती है कि कुर्बानी मेरे मुल्क के लिए है। लेकिन मुल्क के माने भूट्टी भर लोग नहीं हैं। मुल्क को शान के माने चन्द अफसरों की शान नहीं है। मुल्क की अहमियत, उस की इज्जत सिर्फ मिनिस्ट्री की इज्जत नहीं है, करोड़ों लोगों की इज्जत है, गरीब और दलित लोगों की इज्जत है। उन की उस इज्जत को बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट की क्या पालिसी है? उसको भी सफाई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट की पालिसी पर मिलिटरी चलती है। आर्यभट्ट ऊपर घूमता है। कहा जाता है कि आर्यभट्ट को देखिए, गाँव-गाँव में घूम रहा है, हम ने कितनी तरकीबी की है इस पर फय्र किया जाता है। मगर वह सैनिक कहता है कि मेरे घर पर, देहात में, गाँव-गाँव के अन्दर गुरबत का भी आर्यभट्ट फिर रहा है, महंगाई का भी आर्यभट्ट फिर रहा है, फिरकापरस्ती और वर्गाश्रम का आर्यभट्ट फिर रहा है, हर महलने महलने हर घर में फिर रहा है, उस आर्यभट्ट के खिलाफ आप कौन सा ठेक इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सा बड़ा ऐटम बम बनाने वाले हैं? इसका जवाब हुकूमत के पास क्या है? ऐंटाधिक एनर्जी से तरकीबी

होनी चाहिए, हमें मंजूर है। मगर उस ऐटम बम के साथ भूख का भी ऐटम बम यहां मौजूद है, भूखमरी का, गुरबत का, बेकारी का रिशवत-खोरी का ऐटम बम, फिरकापरस्ती का ऐटम बम मौजूद है। और तैयार किया जा रहा है। उस ऐटम बम के खिलाफ लड़ने के लिए ये टैक्स काम नहीं आएंगे। वह सैनिक और फौज का हर सिपाही जानना चाहता है कि हम कितने साल तक गुरबत में रहें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है रिटायर होने के बाद वह सैनिक इसी इंटरनल क्राइसिस के अन्दर आ जाता है, इसी गुरबत के ऐटम बम के नीचे आ जाता है। वही महंगाई के रन्गाड़े और टैंक उस रिटायर्ड मिलिट्री मैन पर आ जाते हैं। वह बेचारा खामोश रह जाता है। हर वक्त उस को संज फायर एग्जीमेंट करना पड़ता है। लिहाजा हिन्दुस्तान का माशी निजाम, और हिन्दुस्तान के मिलिट्री निजाम, इन के अन्दर जब तक आप कोई ईक्वैलिटी न बनाएं तब तक म सही मूने में आजाद और मजबूत नहीं हो सकते। हमें पुराने सरभायादारी समाज को तोड़ना होगा, जलाना होगा। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि देश के अन्दर कम्प्लेसरी मिलिट्री एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। चाहे कोई देहात में रहे, या शहर में रहे, सब यूवाओं के लिए यह होना बहुत जरूरी है। आज मिलिट्री की ट्रेनिंग लेने की मोनोपली चन्द लोगों की हो गई है। दलित और पिछड़ा हुआ समाज पीछे उपेक्षित रहा है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मिलिट्री के अन्दर भी फिरकापरस्ती वर्गाश्रम व्यवस्था बहुत बढ़ रही है। वहां पर भी सिफारिशें-आली और रिशवतें-आली का बाजार बहुत बड़ा है। जिन के लिए सिफारिशें-आली और रिशवतें आली है उन के लिए सब कुछ है। वे लायक अली बनते हैं। मगर जहां पर जिस के लिए कोई नहीं है वे नालायक अली बनते हैं। वहां पर उस के लिए सिर्फ लड़ने और इशमन को देखने के लिए भीत के

[श्री केशवराव धोंडग]

सिवाए और कुछ नहीं है। तो वह कहता है कि म क्यों मरू ? मैं गरीब हूँ इसलिये मरू ? लिहाजा मिलिट्री के अन्दर हर तबके को मालूम होना चाहिए, एक छोटे से छोटे जवान का भी मालूम होना चाहिए कि मरे और बड़े से बड़े अफसर के अन्दर कोई फरक नहीं है। वह भी देशभक्त है और मैं भी देशभक्त हूँ। मगर ऐसा अब तक नहीं है। फिरकापरस्ती बढ़ रही है, यह मुझ अफसरों के साथ कहना पड़ता है। दूसरी चीज—फिरकापरस्ती का जहाँ तक सवाल है, मराठा रेजिमेंट और महार रेजिमेंट, ये मिलिट्री के अन्दर हैं, क्या यह जानपात और फिरकापरस्ती नहीं है ? उन के ऊपर हम फरक करते हैं। मालाना जलसे के अन्दर मराठा और महार रेजिमेंट को मालगिरह हम मानते हैं। महार रेजिमेंट के बारे में हमें बड़ा फरक है। अगर किसी का महार हम बाहर कहते हैं तो हम पर अनटच-बिलिटी गेक्ट के तहत केम हाता है, मगर वहाँ हम जान के नाम पर फरक करते हैं। यह अजीब बात है, यह जातिवाद और अनटच-बिलिटी को खत्म करने वा उसूल क्या मिलिट्री के लिए नहीं है ? अगर मिलिट्री के अन्दर जाति के धर्म के लिहाज में, धर्म के लिहाज में ऐसे ही भेद बनाते रहेंगे तो मरे ख्याल में वह दीमक है और यह फिरकापरस्ती का दीमक मिलिट्री के अन्दर भी लग जाये तो इस में बड़े अफसरों की बात और क्या हो सकती है इसमें आजादी को भी दीमक लगेगी ? लिहाजा मैं हुआत में गुजरागि बरुगा कि इस को तोड़ना चाहिए और इन्क्वैलिटी की वेसिस पर क्रान्ति और समाजवाद की वेसिस पर इस का मताना चाहिए। हम बदलती हुई दुनिया का देश और बदलती हुई दुनिया के इन्क्लाब के लिहाज में हमारा मुक्त हमारी जनता मजबूत वगे। मजबूत हमारा सैनिक भी होना चाहिए और हमें यह देश जा गये है वह भी मजबूत होना चाहिए। मजबूत उन लोगों को भी होना चाहिए जो कर्मचारी हैं जो करौड़ों लोगों के

के हाथ कमजोर रख कर मिलिट्री मजबूत नहीं बन सकती। देश की जनता को गरीब और बेकार भखा रख कर फौज कभी मजबूत नहीं हो सकती है। चाहे हजार एटम बम क्यों न बना दिये जाए, जब तक भूख का एटम बम हर मोहल्ले में घूमता है, हम भी कभी कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा जो युद्ध का मामला है, ऊँच नीच का मामला है उस को भी हमें ताडना है। उसके साथ-साथ मिलिट्री में जो प्रेशर-ज है, इनडक्वैलिटीज है, उन को भी दूर करना है। महाराष्ट्र में गय-जमाने से बारिडम की परम्परा थी। अफसरों की बात है—आज इन्दुमता में मिलिट्री में भी अन्दर स्टेट्स की भोनापाली हो रही है। अब समय आ चुका है जब हर स्टेट्स के लिये भी रिजर्वेशन की जरूरत है। महाराष्ट्र में मिलिट्री में दिन-ब-दिन परसेन्टज कम हो रहा है, जैसे कि गरीब दलित लोग गवर्नमेंट सर्विस में चतुर्थ श्रेणी में तो 90 फीसदी है लेकिन प्रथम श्रेणी में 00 परसेंट ही उन की संख्या है। क्यों ? कहते हैं कि लोग ही नहीं मिलते। यही हालत मिलिट्री में भी हो रही है। लेकिन हम हालत का नाडना चाहिए। महाराष्ट्र में मिलिट्री परमोनल मिल सकते हैं, लेकिन उन के लिये ट्रेनिंग का कोई रास्ता नहीं है, कोई मिलिट्री के स्कूल नहीं है। बड़े-बड़े लोगों के बच्चे तो मिलिट्री कानिजेज में शहरो में घर के पास जा सकते हैं पाँच माल की उम्र के बाद जा सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे, किसान के बच्चे, देहाती बच्चे, दलित के बच्चे, चाहे वे किसी भी मजबूत या मिललत के हों, वे भी चाहते हैं कि हम देश की खिदमत करें, आजादी की वरकरारी के लिए हम भी कुरानी दें, लेकिन उन के लिए कोई मौका नहीं है। मैं जनता गवर्नमेंट में पूछना चाहता हूँ—क्या आप में कोई रेडिकल चेन्ज बताया है, जिस में एक दलित कह सक कि मिलिट्री में मेरी है, अह-बज-होरा है और मुक्त

की हिफाजत करने का काम भी मेरा है ? इसकी मोनोपोली किन्हीं चन्द लोगों की नहीं होनी चाहिए । जनता पार्टी इस बजट में किस का डिफेंस करती है ? सरमायादारों का पूजीपतियों का और उच्च वर्गियों का बाहर दुश्मन के खिलाफ हमारे देश का डिफेंस करती है और घन्दर बड़े-बड़े मोनोपोलिस्ट लोगों का डिफेंस करती है । यही जनता सरकार की संपूर्ण नीति की नीति है ? एक साल गुजर गया, कौन सा आमूल परिवर्तन हुआ । 30 साल तक कांग्रेसी हुकुमरानों ने नहीं किया अगर क्या कर रहे हैं । यह मैं जनता सरकार से पूछना चाहता हूँ । आपका भी वही रास्ता नजर आ रहा है । लिहाजा मैं गुजराण करूंगा कि महाराष्ट्र में श्रीरूसरी कर्ट स्टैटम म, बगाल, पंजाब, उड़ीसा गुजरात में, हर जिले में मिलिट्री स्कूलों में मिलिट्री कालिजिज खाने की जहर है । खाने और पर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में अगर हर जिले के लिए भी आप मिलिट्री स्कूल कायम करें, तो बहुत अच्छा होगा । दिवानी नोजवाना का अगर आप मिलिट्री का तालाम नहीं देते, वह क्या चीज है, यह नहीं बताएँ बरतुलम म और तालिम व काम में मिलिट्री का गवर्नमेंट नहीं रखते, तो काम कैसे चलेगा । मेरी गुजराण है कि मिलिट्री का नब्जेक्ट प्रस्पलस हाना चाहिए । हर स्कूल और कालिज में पढाना चाहिए । जब जग शुरू होती है तब संवशन आता है कि हम सब एक हैं । देश भक्ति उभरती है । जब कोई हमला करे, हमारे जमीन लेले, हमारे जवान मारें जाएं, तब हमारा मुख जाग उठता है । कोई शहरी गीत बना जाते हैं और रडिंग पर समर्थित गाए जाते हैं तब क्या समर्थित बनाने से हम बहादुर बनते हैं ? उम स हमें चन्द लोगों में जाय पैदा कर सकते हैं, लेकिन जग नहीं जीत सकते । प्रमल में जग जीतने के लिए भजदूरी और देहाती नवके के लोगों के हाथों में बन्दूक देनी चाहिए और उन्हें देशभक्त बनाकर उन में

पस की समझ भी पैदा करनी चाहिए । लिहाजा महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा विद में हर देहान में, हर जिले के लिये, कम से कम एक मिलिट्री स्कूल और मिलिट्री कालिज बनाने का आप इन्तजाम करे । यह भाग मैंने कई बार को है ।

एन सी सी के बारे में क्या कहें, उसका तागवार तो बहुत ही बुरा है । सही मायनों में अगर इनकलाब चाहिए, चन्द लोग कहते अलिक अफार अच्छा है इसलिए मिलिट्री अच्छी है तो आपके रिमार्क से हमको खुशी नहीं है । देहात का आम गरीब आदमी चाहता है कि मिलिट्री हमारी हा, उस पर हमारा भगाना हा । यह चीज तभी हो सकती है जब उसका प्रहमाम हा कि मिलिट्री हमारी है । जिनक वच्च मँदाने जग में कुर्बान ता जाते हैं, शहीद हा जाते हैं, वह अफमाम करना है तबेग बच्चा शहीद हा गया लेकिन मैं नस्बूलएन पूरा नहीं कर सकता मैं बच्चा को तालीम नहीं दे सकता, रहने के लिए मकान नहीं है और खाने के लिए इन्तजाम नहीं है । उसका हम कब तक बर्दान्त करेगे ? आग निया का माहाय बदला है, इनकलाब का जमाना है, चीन और रूस बड़े हुए हैं, अगर हमारा चीन में जमीन निकालनी है तो शेकहैड करने और डिनर पार्टी देकर गसला ल ल ह हागा । महारागी और टी० बी० के हाथ में शेकहैड कौन करेगा ? और हमारी इज्जत और शान क्या रहेगी ? कमजोर हाथ का शेकहैड गिफ्टन की गिनाती हाती है । उनका माथ शेकहैड जरूर करना चाहिये, लेकिन शाहहैड में हमारी धरतीता मिलने वाली नहीं है । मुस्क ता कमजोर रख कर आजादी को जरूर नही गया ता गता, जा हमारी धरती चीन ने छीन है या पाकिस्तान में हमारी जिन भाग पर काश्मीर में कब्जा किया हुआ है, उग ता वापस नहीं लाया जा सकता है । अगर हम को अपनी मातृभूमि के हिस्से का वापस लेना है तो पूरे मुस्क को जाग्रत करना

[श्री केशवगव घोषणे]

होगा। अगर करना होगा। आजादी को बरकरार रखने के लिए मिनिस्ट्री का हाफ जॉर्न नहीं है, हमारे यहां उम का ट्रेनिंग जो जल्द है, तालिम जो जल्द है हुड्डुलवननी की जल्द है पीर इम की ना आप को सारा डांचा बदलना होगा। मुझे अरुनाम के साथ कड़ना पड़ रहा है कि जो जनता पक्ष की नई इन्कवाबी रोगनी आई है वह इम बजट में दिखाई नहीं देनी है। आप का यहां आये हुए एक साल हो गया है लेकिन यही हालत चलते रहे तो कोई इन्कवाब नहीं आ सकती। इस सैनिक व्यवस्था के अंदर आप को आमूल परिवर्तन करना होगा, मुल्क के हर पक्ष के अन्दर हुड्डुलवननी का माहा पैदा करना होगा, सही किस्म को मिनिस्ट्री तालिम देनी होगी। देश अखिर मातृ प्रेम, इहमन बाहर के देशों से आयात नहीं किये जा सकते।

मेरे नान्देड जिले में एक क-बार तहरील का गांव है। 1971 में हमारे बहादुर नौजवानों ने बंगला देश की जडाई में बहुत बहादुरी दिखाई थी बंगला देश को आजाद कराया था, आक्रामक पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। बड़ी कुर्बानियां की थीं। इस बार मिमोरियल के लिये उन की यादगार में हमने "जय बंगला हुवात्मा विजय स्मारक समिति" की तरफ से बहा विजयनड में सरकारी गायदान सर्वे नं० 21 के स्थान पर एक स्मारक बनाया है, मुजीब पार्क भी बनाया है, मीनार बनाया है। यह मीनार शहीदों को मीनार हमारा देवता है, जो हमारे बहादुर शहीद नौजवानों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। हमने अपने डिप्टी मिनिस्टर से यह दरखास्त की थी कि उस जगह के लिये विजयनड पर मुजीब पार्क हर्बे कोई "पैटन टैंक" का "डैवर जैट" विनाम दें ताकि हब जय को वहाँ पर उस विजय की निशानी के

तीर पर रख सकें। हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री बसंत दादा पाटील ने भी इस के लिये माननीय रक्षा मंत्री महोदय को सिफारिश की है कि यह हमें जरूर दिया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस मांग को जरूर पूरा करेंगे। और इस राष्ट्रीय स्मारक और ऐतिहासिक धार-मेमोरियल का गौरव करेंगे।

इस के अलावा हर स्टेट के अन्दर हर जिले के अन्दर मिनिस्ट्री कालेज और मिनिस्ट्री स्कूल कायम करेंगे और हमारे मिनिस्ट्री के डांचे में मुनियामी तीर पर इन्कलाबी तरमीम कर के उस को सही मायने में मजबूत बनायेंगे, ऐसी मे सरकार से गुजारिश करूंगा।

इन अस्त्राज के साथ "जय क्रांति" कह कर में अपना भाषण खत्म करने से पहले बहादुर शहीदों और शूर जवानों को जयक्रांति में मानना देकर आप में रुबसत लेता हूँ।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० और सिंह) सभापति महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने सुरक्षा के खर्च के बारे में अपने-अपने विचार रखे। कुछ माननीय सदस्यों का यह मत है कि हमको सुरक्षा पर अधिक खर्च नहीं करना चाहिये या इस खर्च को घटाना चाहिये, क्योंकि हमारे सम्बन्ध अपने पड़ोसियों के साथ अब सुधर रहे हैं, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ भी सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है। इस लिये उन का खयाल है कि इस में कुछ कटौती की जाये और देश के विकास के कामों में अधिक पैसा लगाया जाय, तो शायद इस देश के लिये ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा।

दूसरी तरफ कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े जोर से कहा कि अगर हम यह सोच कर फिर सो गये कि अब पड़ोसियों से हमारे सम्बन्ध सुधर रहे हैं और मलक नहीं रहे, हम ने अपनी शक्ति का मजबूत नहीं किया, तो किसी समय भी देश पर आक्रमण हो सकता है और उस वक़्त देश का नीचा दखना पड़ सकता है। दानो विचारो म कुछ कुछ मचाई है। हम यह नहीं कह सकते कि दानो विचारो में कोई बिलकुल गलत है, दोनों विचार अपनी-अपनी जगह ठीक हैं। इसलिये दोनों विचारो का सम्बन्ध करते हुए, साधुचित्त चिन्तन करना बहुत आवश्यक है। हम को देखना है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था क्या है। हम को यह भी देखना है कि विश्व में कौन सी और कौसी परिस्थितियाँ हैं। हमारा देश गरीब है, एक तरफ यह बात सच है और दूसरी तरफ यह बात भी सच है कि ज्ञान्ति के सब प्रयास करने के बावजूद शस्त्रो, अस्त्रो की होड़ अभी तक दुनिया में कम नहीं हो रही है बल्कि वह बढ़ रही है। तीन, चार साल पहले जहाँ 225 अरब डालर शस्त्रो और अस्त्रो के निर्माण पर खर्च होता था, अब वह 300 डालर अरब से भी अधिक उन पर खर्च हो रहा है और ज्ञान्ति के जो प्रयास हैं, वे अभी अफ़स हो रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक और सस्तर की परिस्थितियाँ हैं और दूसरी और हमारे देश की गरीबी है। उन दोनों को ध्यान में रख कर संतुलित चिन्तन कर के भारत ने यह प्रयत्न किया है कि एक तरफ तो अपने देश की सुरक्षा है और हम को अपने देश को मजबूत बना कर, आधुनिकीकरण करके अच्छे हथियार अपने सिपाहियों को, अपनी सेना की देने हैं और दूसरी तरफ विश्व के कर्षण व उर्वर करने लिए जो कामों की आवश्यकता है। अगर कोई पिछले ची के विकास को देखें तो वे भी बहुत

कि 1968-69 में हमारे देश का जिनना बजट था उस का 32.9 प्रतिशत सुरक्षा पर खर्च होना था और उस के दस वर्ष बाद 1978-79 में वह प्रतिशत घट कर 21.5 रह गया है प्रतिशत का अग्र हिनाना लगाए, ता वज़र-तहाई रह गया है और विकास का कामों के लिए पैसा और अधिक हो गया है। प्रतिशत के हिसाब में सुरक्षा के लिए खर्च बहुत कम हो गया है। समाज के ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर राष्ट्रीय आय का 35 और 37 प्रतिशत सुरक्षा पर खर्च होता है। लेकिन हमारे देश में अभी तक यह 4 प्रतिशत से नीचे 3.7 प्रतिशत के करीब खर्च रहा है। इसलिए इन सब बातों पर विचार कर के एक संतुलित चिन्तन कर के सुरक्षा का हमारा काम चल रहा है।

भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत ने कितनी पर आक्रमण नहीं किया, इतिहास इस बात का साक्षी है लेकिन कोई आक्रमण करे ता उसका मुह-तोड़ जवाब दे सके यह शक्ति जरूर रहनी चाहिए और इसका भारत ने प्रमाण दिया है हमारे सैनिक सस्तर क सैनिको में बहुत ऊँचा दर्जा रखते हैं और यदि हम यह कहे कि भारत वर्ष के मुकाबले में शायद ही किसी देश के इतने और सैनिक मिलेंगे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी पर हमारे जो सैनिक हैं, उन को अगर हम ठीक ढंग से नये हथियारो से सुसज्जत न करे तो उनकी जा बीरता है, उस से जो लाभ हो सकता है, वह राष्ट्र को नहीं मिलेगा, पूरा लाभ हम उनकी बीरता का राष्ट्र को नहीं दे सकेंगे।

सबानत नहीं देय, इस देश की सुरक्षा को बार बुझाएँ हैं। तीन बुझाएँ ही हमारी जानें हैं, यह सैन्य सेना और नौ सेना

[प्रो० भोर सिंह]

श्रीर चौथी भुजा है रक्षा-उत्पादन। अगर हमारी फौज बोर हो, बहादुर हो और पूरी ट्रेड हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उम के पाय माधन ठीक न हो और हमारी वह चौथी भुजा कमजोर हो चतुर्भुज विष्णु के रूप में हमारे सामने सुरक्षा का जो सारा सगठन है, तो हमारा काम नहीं चल पाएगा और हमारे सगठन में यह आवश्यक है कि चौथी भुजा भी मजबूत होनी चाहिए।

16.00 hrs.

मैकेन चौथी भुजा का सम्बन्ध में ही कुछ निवेदन करना। बाकी जा तीन भुजाएँ हैं उन के सम्बन्ध में रक्षा मन्त्राजी कल अपने विचार रखेंगे और विस्तार से बताएंगे और जो प्रश्न उठाए गये हैं उनका उत्तर भी दूँगे। रक्षा उत्पादन के मामले में हमारे देश में पिछले 15 वर्षों में बहुत बढ़ाव हुआ है। उस समय हमारे देश में 32 डिपार्टमेंट्स फेक्ट्रीज हैं और उन में जो चीजें पैदा होती हैं प्रायः सभी आकाश में उन के बारे में पढ़ कर मनासारा। बैटल टेकम, हाटली माफिस्ट्रीकेटिंग मम, राकेट, वेर्यायटी आफ बेरीकलम, एक्सप्लोसिबल प्रोपेलेंट्स, एम्पुनिशन, क्लॉडिंग, पेरशूटम, लेजर आउटटम जैसी बहुत सारी चीजें जिनकी हमारी मनासारा के लिए आवश्यकता है, हमारी 32 फेक्ट्रीज में बन रही हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि हमें आधुनिक होना चाहिए और मनासारा की आवश्यकता की चीजें हमें अपने देश में उत्पादन करनी चाहिए। इस बात में मैं बता दूँ कि हमारी इन फेक्ट्रीज में जो चीजें पैदा होती हैं उनके लिए बहुत थोड़े हिस्से पुराने हैं और मनासारा में पड़ते हैं। पूरा की पूरी चीजें हम नहीं लेनी पड़ती हैं। हम अपने देश में जिनकी चीजों का बनाने के साथ-साथ हमें पढ़ना है, हम सबके से मैं

निवेदन कर दूँ कि हमने शक्तिमान और निशान के मामले में 96 प्रतिशत और 94 प्रतिशत तक भारतीयकरण हो चुका है। टेक जो हम अपने देश में बना रहे हैं उनमें भी हम 95 प्रतिशत तक भारतीयकरण हो चुका है आडिनेंस फेक्ट्रीज में जितने हम छोटे हथियार बनाते हैं, उनके लिए गोला-बारूद बनाते हैं, आर्म एण्ड एम्पुनिशन बनाते हैं, अगर हम हिसाब लगायें तो केवल हमें 9 प्रतिशत ही सामान का उनके लिए आयात करना पड़ता है। कुछ रा मेटेरियल है, कच्चा माल है जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, उनके लिए जिम डग की धातुएँ चाहिए, वे धातुएँ हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं, वे हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं यह जरूरी नहीं है कि हमें बनी-बनाई ही चीजें लेनी पड़ती हैं, थोड़ी जरूर लेनी पड़ती हैं लेकिन अधिकतर हमें कच्चा माल लेना पड़ता है जोकि इन चीजों के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह सब केवल 9 प्रतिशत तक ही लेना पड़ता है, बाकि 91 प्रतिशत हम अपने देश में ही बनाते हैं।

उनके अलावा हमारे 4 पब्लिक अण्डर-टेकिंग हैं जो कि रक्षा उत्पादन के काम में लगे हैं। जैसे हिन्दुस्तान एरनाटिक्स है जो कि हवाई जहाज बनाता है, कई प्रकार के हवाई जहाज बनाता है। वहा ट्रेनिंग के लिए भी हवाई भते हैं। नट हवाई जहाज जो कि इनका मण्डल हवाई जहाज है, उसकी इम्प्रूव्ड वर्सन अजित हवाई जहाज वहा बन रहा है। हेलिकाप्टर भी वहा बनते हैं। एच० एस० न० 748 बनता है, मिंग हवाई जहाज बनता है और उसका जो नया रूप है वह भी वहा बन रहा है। इसी तरह से जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना है उससे रेडार और दूसरी सैकड़ों चीजें जो कि आवश्यक हैं वे वहा बनने लगी हैं। इसके साथ-साथ हमारे देश में अहा, बनावे सिग्रेट्स

बनाने, सर्व बेसल्स बनाने और दूसरी जितनी भी नेवी की आवश्यकता की वस्तुएँ हैं वे वहाँ बनने लगी हैं। सबमेरींस वगैरह तो अभी नहीं बनने लगे हैं। वे भी बनने लगेंगे। उनके लिए प्रयास चल रहा है, बातचीत चल रही है। सब प्रकार के सर्व बेसल्स, फ़िगैट्स इन सब में हमारा राष्ट्र काफी आगे बढ़ रहा है और इनके लिए हम 60 प्रतिशत चीजें अपने देश में ही बनाने लगे हैं।

इसी तरह में जो हवाई जहाज हमारे देश में बन रहे हैं, उनके भी हजारों पुर्जे ऐसे हैं जो कि हमारे देश में बनने लगे हैं। मिग के छोटे-बड़े कोई 2300 पार्ट्स आज हमारे देश में बन रहे हैं और भी पुर्जे बनाने का काम बहुत आगे बढ़ रहा है। यह जो रक्षा उत्पादन का उद्योग है, उसके बारे में यदि हम हिमाब लगायें तो हमारी इन 32 फैक्ट्रीज में और 9 पब्लिक अण्डर-टैकिंग में माटे आठ सौ करोड़ रुपये के करीब का उत्पादन किया जाता है। डा० कर्णसिंह जी ने कहा कि एक हजार करोड़ रुपए का हम उत्पादन कर रहे हैं। एक हजार करोड़ रुपए का उत्पादन शायद हम साल में 1978-79 में हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपने देश में ही बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। हम अपनी थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के लिए जहाँ हम हथियार गोला बारूद बनाते हैं, उनके साथ साथ हम जहाज, हवाई जहाज, मिसाइल, राकेट्स भी अपने देश में बनाने लगे हैं। उसमें प्रगति और आगे हो रही है। इंडिजनाइजेशन का जो काम है उस में और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में इस समय हम केवल 22 प्रतिशत बाहर से लेते हैं, बाकी 78 प्रतिशत अपने देश में ही बनने लगे हैं। भारत अर्थ भूवर्ज में 20 प्रतिशत केवल बाहर से हिस्से पुर्जों का शकल में लेते हैं, बाकी देश में बनते हैं। इसी तरह शिप

बिल्डिंग के ज़ेब में 26000 टन वेट तक के टनेज के जहाज हमारे देश में अपने ही डिजाइन से, सब कुछ अपने ही तौर पर हम निर्यात करने लग गए हैं। लिफ्टर क्लास के जो जहाज हैं वे भी बने हैं। फ़िगैट में 60 प्रतिशत के करीब हम अपने देश में बनाने लगे हैं और 40 प्रतिशत के करीब बाहर से लेते हैं। भ्रमले पांच साल के प्रोग्राम में दस करोड़ रुपये हिन्दुस्तान ऐयरनोटिक्स ने इसी काम के लिए रखा है, इंडिजनाइजेशन के लिए रखा है।

पिछले दिनों एक प्रदर्शनी लगी थी जिसमें हमने दिखाया कि कौन-कौन सी चीजें हमारे अपने देश में बनने लगी हैं और कौन-कौन सी चीजें नहीं बनती हैं और कौन-कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने देश में बना सकते हैं। उनका प्रदर्शन वहाँ हमने किया। जितने भी प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर में लोग लगे हुए हैं जैसे एच एम टी है, बी एच ई एन है, इसी तरह से बड़े-बड़े और हमारे पब्लिक सैक्टर अंडरटैकिंग्स हैं उनसे भी हम सहायता लेते हैं। उन सब से निवेदन किया कि वे आ कर देखें कि कौन कौन से कल पुर्जे हैं जो बना सकते हैं उनके पास क्षमता है तो हम उनको बाहर से क्यों मंगाएँ, क्यों न अपने देश में जो क्षमता है उसका इस्तेमाल करें। डा० कर्ण सिंह ने कहा कि जो रिसर्च डिवेलपमेंट का काम करते हैं, निर्माण का काम करते हैं उस में केवल जो रक्षा से संबंधित हमारे संरक्षण हैं हम केवल उन्हीं तक उत्पादन को सीमित रखें यह ठीक नहीं होगा क्योंकि सारे राष्ट्र का काम है, राष्ट्र के पास जितने भी साधन हैं उन सब साधनों का उपयोग किया जाना चाहिये। उन्हीं में यह ठीक बात कही

[प्रो० शेर सिंह]

है। इसी दृष्टि में एक सम्मेलन भी हमने बुलाया था सभी उद्योग धंधा में लगे हुए लोगों का। जिनकी धीर जा-जो भी क्षमता उनके पास है हम ने उन से चाहा है कि वे सारी क्षमता का लाभ उठाए और जा-जो हमें बाहर से लेनी पड़ती है उसको अगर हम यहीं बना सकते हैं, उसका टेक्निकल नो हाऊ हमारे पास है, किसी के भी पास है, तो हम उसने आधार पर निर्माण के काम अपने देश में शुरू करें, पब्लिक सेक्टर में हो सके तो वहां धीर वहां न हो सके तो प्राइवेट सेक्टर में।

एक प्रश्न श्री रोडिंग्स ने उठाया है धीर बड़े खतरे की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को बीच में ले आते हैं और उन के द्वारा अगर आप इनका निर्माण करवाना चाहते हैं तो बेलाबी बन कर किसी दिन भी आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। यह प्रश्न पहले भी उठाया गया है। राज्य सभा में भी धीर लोक सभा में इसको उठाया गया था। तब स्पष्ट कर दिया गया था कि जो हथियार है, जो एण्ड प्रोडक्ट्स (end Products) है वह केवल जो सरकारी फैक्टरियां हैं या जो पब्लिक सेक्टर अडवर्टेकिंग हैं डिफेंस की बच्ची बनाएंगी लेकिन सब असीम्बलीज है, कोई पार्ट्स हैं, कोई कम्पोनेंट्स हैं वे सिविल सेक्टर के अन्दर भी बन सकते हैं चाहे वे पब्लिक सेक्टर में ही हो या प्राइवेट में हों। उनकी हम सहायता ले सकते हैं। लेकिन केवल कम्पोनेंट्स बनाने में, सब असीम्बलीज के बनाने के धीर उन में भी जो कम्पोनेंट किटिकल कम्पोनेंट होंगे, जिन की वजह से काम रुक सकता है अचानक अगर उनकी सप्लाई ठीक से धीर समय पर न हो तो वे सिविल सेक्टर में नहीं आएंगे वे डिफेंस सेक्टर में होंगे। इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। सिविल सेक्टर में जितनी चीजें बनेंगी वे

भी केवल एक पार्टी तक सीमित रह जाएं, एक ही भावभी बनाए ऐसा नहीं होगा। जितने भी लोग, दो चार पाच होंगे उन सब को प्रोत्साहन देंगे। सिविल सेक्टर में जिसने लोफ सामने आए जितने बना सकते हैं हम समझते हैं कि एक से अधिक सोर्स हमारे पास रहना चाहिए। एक ही सोर्स हो तब तो खतरा हो सकता है। लेकिन अगर हम इस सोर्स के बजाय कई सोर्स बना लें, धीर जो हमारी नीति प्रोत्साहन केवल एक सांस तक सीमित नहीं रखते हैं, जितने सोर्स होते हैं उन सबका प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए यह भाषणा नैर्बुनवादी है। राष्ट्र के पास जा भी क्षमता है डिफेंस में या उस के बाहर आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए अपने देश में सारी क्षमताओं को मिला कर, उन सब का लाभ उठा कर आत्म-निर्भरता की धीर बढ़ सकें इस दृष्टि से यह सब काम किया गया। तो इस में कोई खतरे की बात नहीं है। धीर सब लोगों ने काफी सद्भावना इस में दिखाई है। पब्लिक सेक्टर धीर प्राइवेट सेक्टर अडवर्टेकिंग्स में काफी रुचि ली है धीर चार हजार के करीब हमारे पास मार्ग फला-फला चीज बनाना चाहते हैं हमको सहायता धीर गाइडेंस दी जाय, टेक्निकल नो हाऊ दी जाय, स्पेसिफिकेशन्स दी जाय। उन बारे में हिदायतें हैं धीर हमारे जितने भी अधिकारी इस लेवल में काम करने वाले हैं, साइटिस्ट है वह सब लगे हुए हैं धीर हम सब का प्रयास होगा कि जो चीजें अपने देश में पैदा कर सकते हैं वह जल्दी में जल्दी पैदा करें।

जहां तक रिसर्च धीर डेवलपमेंट का सवाल है हम देश में पिछले दिनों में काफी प्रगति हुई है। इस समय कोई 80 करोड़ से ऊपर एक वर्ष में हम खर्च कर रहे हैं धीर जो हमारे साइटिस्टों

इस काम में लगे हुए हैं, 9, 10 हजार के करीब इंस्ट्रुमण्ट लेबर भी लगा हुआ है, इस प्रकार हमारा रिसर्व और डेवलपमेंट का काम बड़ो तेजी से आगे बढ़ रहा है और मनी दिशाओं में जितने किस्म के हथियार ह मंगने हैं, हवाई जहाज धरौं रह जा भी आवश्यक चीजें हैं उन सब में हर सेक्टर में रिसर्व और डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिये इंडिजिनाइजेशन और आत्म-निर्भरता को तरफ हमको जो बढ़ना चाहिये उसमें मार्च के बाद जब से जनता सरकार सत्ता में आयी तब से इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और एक साल के अन्दर बड़ो सफलता मिली है। और इस गति से चलकर 4, 5 साल में प्राप्ता करते हैं कि सिवाय उन चीजों के जो हम को बहुत थोड़ी मात्रा में चाहियें, और जो दुनिया में आसानी से मिलते हैं, या कोई ऐसा रा-मैटोरियल जा अपने देश में नहीं बना है, जैसे मिश्रित धातु आदि चीजों को छोड़कर, या बहुत हाटली सार्फास्टकेटोड है उनको छोट कर बाकी पश्चिम देश में पैदा होने लगेगी और आत्म-निर्भरता की आर काफ़ी तेजी में आगे बढ़ सकेंगे।

एक बात के बारे में काफ़ी माननीय सदस्यों ने कहा है। नेशनल ऐक्ट 1924 में बना था जिम के चलने बहुत सी जगहों पर काफ़ी कठिनाई हो रही है, उसमें संशोधन कर के एक नया ऐक्ट लाना चाहिये। इसका आश्वासन इस सदन में पिछले वर्षों में दिया था, लेकिन मैं आज फिर कहना चाहता हूँ कि इस सत्र में तो नहीं लेकिन अगले सत्र में हमारा प्रयास होगा कि संशोधन बिल इस सदन के सामने पेश कर सकें, और जो कठिनाइयां लोगों को हो रही है, ऐसे लोगों की जो

सैकड़ों साथों से बड़ा बँट है और पुराना कानून चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का दूर कर सकें यह हमारा प्रयास होगा। इससे अधिक और मैं नहीं कहना चाहूंगा। विशेष तौर पर डिफेंस प्राइव्जन के बारे में अपने विचार मैं रखना चाहता था जो आपकी आज्ञा से मने रखे।

SHRI RINCHING KHANDU KHRIME (Arunachal West): At the outset, let me pay my tribute to the five brave Air Force officers who sacrificed their lives to save the life of the Prime Minister and others. I am paying this tribute again because I was one of the occupants of that ill-fated aircraft.

As I have not received the Annual Report of Defence Ministry, I cannot comment on that, but as I belong to one of the border States of this country, I know the practical difficulties and the merits and demerits of our armed forces as also the facilities and amenities to be provided to them. On the question of the relation between the armed forces and the civilian population, I do not exactly want to blame our armed forces as this is due to our basic policy, basic rules and regulations framed for them, because they are very disciplined forces and whatever they have been asked to do, they will carry out. So, unless we change the basic rules and regulations, I do not think there will be any change for the better in the relations of the armed forces and the civilian population in the interior border areas.

In 1972, Rs. 31 crores was allotted for the construction of married accommodation for the armed personnel in Arunachal Pradesh, but after spending Rs. 13 crores, the scheme was suspended. Thereby, the amenities and facilities that we wanted to give the army personnel staying in the

[Shri Rinching Khandu Khrame]

border areas were not provided at all. Instead of giving them proper facilities and even better amenities and bringing their families nearer to them, we have rather provoked them because we could not provide the required accommodation for them. Hence, I would very sincerely plead through you that more funds should be allotted for the construction of married accommodation for the forces, those who are serving in the interior border areas.

We see their life when they are in the messes, but we do not see their lives, or rather we cannot share it, whatever our friends here may say, when they are on the battle front, when they are having their exercises in the months of December and January in snow at a height of 16,000 feet. I would therefore plead that when they go back to the rear areas in the off-season for a limited time, they should have facilities for utilising it properly.

For providing accommodation, Government needs to acquire land. We have some problems on this score. After 1962 we had to gear up our forces in the border areas. At that time a lot of cultivated land was acquired and also hired. I have personally written to the Defence Minister on this matter. There are certain portions which have to be de-hired. I would draw attention to the fact that it was agreed that a particular plot of land at Rupa would be de-hired and handed over. Accordingly, the land was vacated in December, 1976. But uptill now the handing over and taking over has not been over. Let us see the implication of this. The implication of this is that it will jeopardise the better relations between the army personnel and civil population. Our people do not understand about the handing over and taking over formality. They know the land is vacated and henceforth this should be given to them.

When they go to the field to cultivate on the vacant land, they are threatened and driven out of the land by the army authorities. I have got many memoranda from the people saying that they have been deprived of their rights. I would, therefore, appeal to the hon. Defence Minister through you, to take immediate action on this not because that I have my personal interest to preserve better relations between the forces and the civilian population. We had been supporting them both morally and practically at the time of eventualities. In 1962 when we had been badly betrayed by China, we had supported them all through. At that time also, people had exhibited that they were staunch nationalists. I would say that in that part of the country, there is no such activity like underground activity.

I have a few problems to mention here like marketing of local produce. We thought, our forces are here and we have the ready markets to sell out our products. There are very good senior officers also who take initiative to buy them. In Ladakh people have formed cooperative societies through which they have been supplying local produce to the army. We wanted to do the same. But because of the laid down rules, contract tenders, etc. the local people have been deprived of their produce being disposed of to army personnel. There, the army require vegetables, etc. worth Rs. 20 to 30 lakhs every year but as a result of these difficulties, we cannot sell our vegetables. They say that our people do not supply fresh vegetables like potatoes, etc. whereas vegetables brought by contractors from places like Patna become fresh to them. I would sincerely request the Minister through you, that certain percentage should be kept for the purchase of local produce; thereby we can boost the economy of the people there.

Let me come to some of the problems faced by our Armed Forces personnel. I was one of the occupants of the ill-fated aircraft which crashed on 4th November, 1977. When I was in hospital, I had seen a few problems about doctors and nursing officers. They say that they have been posted at some place although there is a Government rule that the serving husbands and wives should be together wherever they are. If the husband is in a forward area or in an interior area and the wife is in peace area, I can understand that, but if the husband is posted at places like Lucknow or Hyderabad, I do not see any reason why the husband and wife should be posted at different places. I hope, the hon. Minister will look into it.

We are talking about ECOs. When we need them, we call them and when we do not need them, we do not think of their future. After serving in the army, when they are retired, they do not know where to go. At times, it so happens that they join in the lower rank of the para-military organisation. But whenever there arise vacancies in the higher rank equivalent to their rank in the Army, they should be promoted instead of directly recruiting persons to those posts. And the problem of seniority and pay scale will not build up the morale of our forces. I would, therefore, appeal to the hon. Minister, to give proper attention to this.

Education is another problem of the children of Armed Forces personnel. This time when I was coming to Delhi to attend the Session, in the compartment there were few officers who had referred this problem to me not as officers but as citizens of the country. As far as Armed Forces are concerned, we should definitely do something for them. Hostel facility in the Central Schools where it is not available, should be provided, so that when the officers are transferred

from place to place as they are required to do, their children are not affected and they can be kept in the hostels. This is one of the most important points because this concerns the future of the children of Army personnel.

So many people have said so many good things about the Army personnel. They deserve this. I know some of their problems which I do not want to project on the floor of this House because I will bring them personally to the notice of the hon. Minister which, I hope, he will look into.

*SHRI S. D. SOMASUNDARAM (Thanjavur): Mr. Chairman, Sir, I am indeed very happy to participate in the debate on the demands for Grants of the Ministry of Defence.

Sir, it is a matter of deep satisfaction to me to note that we are spending only 3 per cent of our Gross National Product on our Defence preparedness. Our neighbouring countries as also the Great Powers spend 15 per cent to 20 per cent of their Gross National Product on Defence. Even a few of the so-called undeveloped countries allocate 8 per cent to 10 per cent of the GNP on Defence. The very fact that we spend only 3 per cent of our GNP on Defence preparedness, which is among the lowest in the world, confirms beyond any shadow of doubt our commitment to peace and that by no stretch of imagination we have any aggressive designs on anyone far and near.

We are surrounded by sea on our three sides and by high mountains on the fourth side. These natural barriers might have proved impregnable barricades a few centuries ago. But, when the world has made astounding strides in scientific warfare, even nature has become the maid of man's ingenuity. I refer to this here because of the imperative necessity for

[Shri S. D. Somasundaram]

strengthening our Naval Forces. In fact, there is every need for modernising our Navy forthwith. In one of the Andaman Islands, we do not know for how many days and months, some foreigners with their families had been living in great fanfare. By chance this came to our notice. This shows the glaring gap in naval vigilance around these islands. I have referred to this incident just to lay emphasis on the need for strengthening our Naval Force, if we are to be true to the maxim that eternal vigilance is the price of freedom.

Sir, the swirling waters of Indian Ocean have become the place of searing rivalry between the two Great Powers and the vast expanse of Indian Ocean has become the play ground for the gigantic Navies of these two great countries. It must be borne in mind that we are in the immediate vicinity and we will be the first victim of any overflow of international rivalry. This is another case which brings home the necessity for modernising our Navy.

Coming now to Indian Air Force, it is common knowledge that we have only outdated planes and the IAF is in the crying need of updating. A high-power Committee was constituted some 8, 9 years ago to suggest a suitable engine for the IAF's strike-plane. The Report of the Committee is gathering dust in the National Archives of the Government of India. As on date, the Defence Ministry has not decided on a suitable engine for the IAF plane. It is time that we take a decision on the engine and go ahead with its production speedily if our discovery is not to become stale.

In 1962, 1965 and 1971 when our country's independence was threatened and when there was actual aggression on our sacred soil thousands of our young men imbued with the lofty ideal of patriotism joined our Armed Forces to protect the country's honour. Their life was nothing to them before

the country's security. After the cessation of hostilities, most of them were demobilised. They were in fact thrown to the wolves of unemployment and poverty. It is regrettable that the Government have not done anything substantial for their rehabilitation. The Defence Ministry has failed to protect the honour of these vibrant young men for whom the country's honour was higher than their own. I suggest that the Central Government and also the State Governments should create job opportunities for these youngsters. They must be helped and enthused to set up small industries. These demobilised people must be given public land for cultivation. A massive rehabilitation programme has to be initiated by the Ministry for these people.

Sir, I am sorry to say that the Defence Research organisations have become staid. There is every need to energise them if our Armed Forces are to keep abreast of modern scientific progress in armament.

The association and encouragement of private sector in the manufacture of small arms needed by our Armed Forces in fact whether it is the small arm or a sophisticated armament—portends danger for posterity. I would like to recall the days when the Defence Forces were held to ransom by the escalating price of trucks supplied exclusively by TATAS, which provoked Shri Krishna Menon to arrange for the production of Shaktiman Trucks in the public sector. Thus crores of rupees of public money were saved. I demand that the private sector should not be allowed to enter the Defence Sector which is vital to the security of the nation.

Sir, the Ministry of Defence should encourage the NCC set-up in all the colleges of the country, because the NCC is the major source of supply of personnel for the Armed Forces.

Before I conclude, I would stress the need for revamping the Ordnance Factories which are engaged in the production of civilian requirements, while they must exclusively concern themselves with producing defence requirements.

With these few words I conclude my speech.

DR. R. ROTHUAMA (Mizoram): Mr. Chairman, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Defence. Well, I am the representative from the Mizoram which, as you know, has been declared a disturbed area following the uprising by the Mizo undergrounds since 1966. When Mizoram is a border area, I feel that we are having a very important role with regard to the national security of the country. Therefore, I would like to point out some of the problems in Mizoram which are faced not only by the Army but the civilians also. I feel that it is my duty to bring them to the notice of the proper authorities. It may be the fault of the politicians or any other authority. So, I say this without any contempt for anybody.

I have all the appreciation for our defence personnel because, particularly in times of national crisis and in Emergency, they have always stood firm in defending the country against foreign aggression. India has passed through many difficulties; India has faced foreign aggression on many occasions, in 1948, in 1962, in 1965 and in 1971.

I would, particularly, like to point out some of the problems of the people of Mizoram following the 1971 Indo-Pakistan war. At the time of liberation of Bangladesh, Mizoram being a border State with Bangladesh; we were having a lot of infiltration of East Pakistani nationals; particularly after 1971, these people from Bangladesh, particularly from the Chittagong side, have infiltrated into the Chakma area, the extreme south-west of Mizoram. Now, some of the

inhabitants of that area are complaining that these people who have infiltrated into that part of Mizoram have occupied some of the lands which were being occupied before by the local people themselves. I would like to bring this to the notice of our Defence Minister, so that he may see that, if any foreign infiltrators are there, they are pushed back.

Secondly, though Mizoram has a very small population as you know we are having a good number of people in the Armed Forces, in the Defence. Most of the people, particularly the Commissioned Officers, who have retired from Defence are finding difficulty in getting employment after their retirement. This is a problem which they are facing, I feel that preference should be given to these people who have retired from the Armed Forces, particularly the Commissioned Officers who have adequate qualifications also, so that they can look after their children after retirement from the defence service.

Now, I would like to point out an important problem which we have been facing in Mizoram. It is because of the dictatorial rule of the then Congress Government that this difficulty or problem has come up in Mizoram. As the representative of the people belonging to that area, it is my duty to point this out. The problem is this. The security forces have occupied, illegally and forcibly, the private land in the heart of the villages, in almost all the villages—private dwellings, private gardens, etc. After this new Party, the Janata Party, came to power, there is no atmosphere of fear and tension. Now the people feel that they should get back those private lands, houses, etc., from the security forces. This occupation of private land by the security forces has created a lot of bitterness and anti-Indian attitude among the simple people there. Therefore, I feel that all these security forces

[Dr. R Rothuama]

should be shifted from the heart of the villages outside the villages proper—so that better relationship between the military forces and the civilians may be established. I know there have been a number of incidents arising out of too much contact between the military forces and the civilians. Recently before me there was an incident at Durtlanga village when the local people recovered two young girls from the security post. That created a lot of confusion and misunderstanding there. Then it is not purely the fault of the armed forces alone. The tribal people being foolish are taken in quite easily when they approach these people very sweetly and then trouble comes later on.

These security forces are occupying private land, hospital compounds and private houses in villages like Vanengte, Kaunpu, Kolosib, Durtlanga, Sateck, Selang etc. in Mizoram. We are having great expectations from the Janata Government and we want that all these security forces should be shifted outside the proper villages. I would appeal to the hon. Minister for Defence through you, Sir, to consider this problem very sympathetically and find out an immediate solution to this. This is absolutely essential if we want to bring the Mizoram people, particularly the hilly tribal people, in the mainstream of the national life, as the Congress people used to say previously. I would once again strongly appeal that this misrule left over by the regime of the Congress Party be corrected by the new Janata Government.

SHRI V KISHORE CHANDRA S DEO (Parvathipuram) Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the demands for grant of the Defence Ministry. I would like to first thank you for having given me this opportunity to participate in this debate.

The necessity for any country irrespective of whether the neighbours are friendly or unfriendly to have a strong defence is imperative, especially for us. From the experiences of 1962, 1965 and 1971 we have to re-evaluate our defence needs in a new light. The report this year says that our country has moved forward towards cooperation and friendly relations with China and Pakistan but nevertheless the fact remains that from our experience of the past we have to learn and be prepared to encounter them in the event of any war.

The allocation given for Defence is a large chunk of money from the budget and out of the money allotted to Defence sixty-five to seventy per cent goes towards paying allowances, salaries, maintenances, pensions etc. of the armed forces. It is only thirty to thirty-five per cent which actually goes into defence production, modernization of army and other important factors. As far as this thirty to thirty-five per cent of the money that is spent for modernization, new acquisitions for the army etc. is concerned, there is no accountability by the Army to the Parliament or anybody else in this country.

In previous years there have been cases where this money has been misappropriated by certain Generals and I am sure the hon. Minister will recall that a couple of years ago, a General was even court-martialled for having built a mausoleum in a forward area. We do not want to know the specifications of the missiles or armaments or other things on which this money is spent but we would certainly like to know how this money is being spent and for this purpose I would recommend to the hon. Minister for Defence to set up a Commission, called Defence Commission as we have a Commission in

the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which would go into how this thirty to thirty five per cent of money is spent. This would help us utility of this money for improving our defence system.

The most important thing is to have a co-relation between the Defence Ministry and the External Affairs Ministry. Defence production, Defence output or Defence needs all depend on the relationship that we have with the other countries, neighbours and otherwise. So, it is absolutely necessary that there is a Co-ordination Cell in the Defence Ministry which should keep in touch with the Ministry of Foreign Affairs as also with the Ministry of Science and Technology to keep itself informed of developments that take place time and again.

Some members have tried to argue that it is not in the interest of the country to have such a large army but I feel differently. Of course, modernisation has taken place and we are having new machines. But you need men to man the machines. Apart from that, we need a large army also for other reasons. One example is you know after the Chinese war, 25,000 square miles of the Indian territory were occupied by the Chinese in the Aksai Chin area and we have not yet been able to regain this lost territory, why? Only because a vast Chinese army is there and they are literally holding on to the territory. So, it is necessary that we have a sizeable army in keeping with the size of the country and our commitments.

Then, the 'teeth to tail' ratio should also be widened. In this report it says that it has increased by 3.7 per cent. I think it should be increased still more so that our army can be more effective and more mobile and the

striking power and fire power could increase.

Then we have our Navy. What is the role of our Navy? We have a large coast-line to guard. Is the Navy required only to defend the maritime borders of the country? It has also to strike as and when necessary. First of all we have to decide what we want our Navy to do. Apart from guarding the maritime borders and defending the coastline of the country, I personally feel that our Navy should also have a vast number of fast crafts like guided missile boats, etc. The Chinese Navy consists of a large number of fast attack crafts which include guided missile patrol boats, etc., which are very effective and can strike wherever necessary, and are very fast in their movements.

We have an Aircraft Carrier, *INS Vikrant*. This is the only aircraft carrier we have. Is it wise to have aircraft carriers like this? Because when *Vikrant* goes to the sea, there are several other boats and vessels to guard it from aircraft fire and other submarine attacks. We have now the "Through Deck Cruisers" which are capable of handling verticle and straight take-off and landing (VSTOL). Added to it, another advantage is that they do not require escort vessels. I think such fast-moving vessels like "Through Deck Cruisers" should replace the aircraft carriers and other conventional ships.

Then, Sir, so far as the Air Force is concerned, I am glad that our Minister for Defence has made a statement in Bangalore on the 21st of February that the country is going to buy some of these deep penetration strike aircrafts. Three aircrafts have been cited for being acquired. One is the Swedish made Viggen, the second is the French Mirage—we all know that Pakistan has a good force of Mirage plane—and the third, of course,

[Shri V Kishore Chandra]

is the Jaguar with its twin engine which is optimised for low level flying. In modern warfare such an aircraft is a must to combat the surface to air missiles (SAM).

The fact remains that apart from this our other aircrafts have also become obsolete and outdated which also need to be replaced and the need for this Deep Penetration Strike Aircraft is absolutely necessary and I am glad the Minister has taken a decision and I hope he will finalise this in a short time.

Defence so far has been always taken as a separate unit but I think defence should also be taken as part of our developmental planning. It can be included in that.

For example we have the Border Roads Organization for building roads. They should do it in consultation with the Defence authorities and according to their specifications so that in times of necessity these roads could also be used by defence forces.

We have a rocket-launching centre at Tumba and also in Sriharikota. Satellite, are launched to gather data about weather etc. These satellites could also be used for defence purposes. I would like the hon Minister to give a serious thought to this and make optimum use of other civilian projects which are already existing for defence purposes, also apart from their civilian use.

Then we have a Territorial Army which is actually, supposed to be the second line of defence for the country. I would like to state that it is lamentable that the Territorial Army has always been given a step-motherly treatment by the Defence Ministry. I do not know if it is due to any inter-service rivalry. Whatever it is, it is not getting its due from the Armed Force. When the Territorial Army was started, then the strength of the Defence Forces was 2-1/2 lakhs and the strength of the Territorial Army was 49,000. But now when the

strength of the Armed Forces has gone up to 8-1/2 lakhs, the strength of our Territorial Army has decreased to 25,000.

Australia, Switzerland, Russia and many other countries have started having Territorial Army. The strength of the Territorial Army should be more than that of the regular Armed Forces. Territorial Army serves as a sort of para-military force and a base to the Army. They can serve during wars or in emergency. You can recruit them directly. Rather than increasing their strength the opposite has been happening in our country. I hope the hon Minister will take note of this and see that actually the strength of the Territorial Army is increased in proportion to the strength of the Armed forces. It should have been 20 lakhs in a country like ours.

Territorial Army has been used for dumping officers who are not competent who are not deserving who are not wanted in the regular Army. I would like to recommend to the hon Defence Minister that in the Territorial Army they should post officers who have a high average grading. This should be made a criterion for appointment like the appointments in the NCC and certain other cases.

There are some personnel in the Territorial Army who have put in ten years service. These people are supposed to have a civil avocation also. But because the Government needed their service from 1962-72 their civil avocation has been rooted out. These people after ten years of service have not been given any benefit. They should also be given the same benefits that are given to ex-servicemen and they should be given other priorities like Priority III, in Employment Exchanges help in resettlement. They should be given medical and canteen facilities also. They should also be given Constitutional guarantees like those given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

This Report says that 50 per cent of the housing problem of the Army has been solved. Here I would like to say that in old Delhi I have seen many of the old barracks and pre-war buildings have been just renovated haphazardly and given to the Army personnel as residential accommodation. Actually 18 to 19 per cent of the problem has been solved—may be 25 to 30 per cent at the maximum. But nevertheless housing remains a big problem. Serious thought should be given to this also.

I would like to State that the terms of the Defence Services are also not attractive enough to draw brilliant young men from the community. Army is treated as something more than that of the police less inferior to the IAS whereas the stakes of the Army officers at risk are very high. I would like to appeal to the Minister to see that more remunerative perks are given to the people joining the Defence Services

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): But there is no dearth of these people.

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: There may not be any dearth of these people but what we need is to draw the best people. That is not so at present, if I may say so. I hope you will increase the defence awareness of the people in the country and see that more good people come to the services.

I would like to quote General Raina who on the Army Day during an interview said—during the last three or four years no General's son has gone into the Army; Why is it so? If the Army's terms were so attractive and so good, then why has no Army General's sent his son to the Army?

So, Sir, I would like you to see to it that you take further steps in order to draw better men into the armed forces.

With these few words, I thank you for giving me this opportunity to speak.

श्री बलदेव सिंह जसरोठिया (जम्मू) :
 आदरणीय वैंयरमैन साहब, डिफेंस किसी मुल्क की हर तरफकी की गारण्टी है और इसी तरह एक पैरामाउण्ट इयूटी सरकार की दुआ करती है कि मुल्क के अन्दर बसने वाले लोगों की जानमाल की हिकाजत करें। इसलिए सरकार को जनता टैक्स देती है कि सरकार हमारी जानमाल की हिकाजत करे। डिफेंस जिस मुल्क का मजबूत है उस मुल्क की हर तरफकी की गारण्टी है। हमें खुशी है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरह के हालत यहाँ नहीं है। बरहाल पिछली सरकार ने इमरजेंसी के दौरान कोशिश की कि मिलिटरी को पॉलिटिक्स में ढकेला जाये। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ मिलिटरी के जनरल को कि उन्होंने अपने को इस मुल्क के अन्दर पॉलिटिक्स से दूर रखा और अपने इयूटी अंजाम देने के लिए हमेशा नैयाग रहे। आज हम हाउस के अन्दर बैठे हुए हैं और हमारी डेमोक्रेसी सरकार है तो उन्ही लोगों की वजह से है जिनके सामने मेरा सर झुकता है और आपके द्वारा मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए क्या कुछ नहीं किया। जहाँ जनता डेमोक्रेसी के लिए तड़प रही थी उसी तरह अपने मैदान के अन्दर फौज ने कमाल किया है और उनकी वजह से ही इम सदन में बैठे हुए हैं।

आज हमारा पड़ोसी मुल्क फिर आर्म्स रेस में एम्प्लीशन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। 1971 में दूसरे मुल्कों से घसलाह इकट्ठा किया जा रहा था और अब भी पाकिस्तान उस दौड़ में पीछे नहीं है और जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 1971 के लेबिल तक सोफिस्टिकेटेड आर्म्स और एम्प्लीशन हमारा पड़ोसी मुल्क इकट्ठा कर रहा है। जम्मू

[श्री बलदेव सिंह जलरोटिया]

कश्मीर राज्य में आये दिन डैकेती, कौटिल लिफ्टिंग और फायरिंग के केसेज पाकिस्तान द्वारा होते हैं। अगर देखा जाये तो यह एक गम्भीर विषय है। इस तरफ में डिफेंस मिनिस्टर की तबज्जह दिलाना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनसे वह गाफिल नहीं है, लेकिन वहाँ जो बीत रही है उसकी तरफ उनकी तबज्जह दिलाना चाहता हूँ।

यहाँ आर्म्स एम्प्लिशन की तरफकी के लिये बहुत कुछ कहा गया है। मैं मानता हूँ कि डिफेंस के लिये मिसाइल, ऐटी टेक्स गन्म आदि बहुत जरूरी है, हमारी फौजें लटे ट हथियारों में सुसज्जित रहनी चाहिये। लेकिन इन सब में जरूरी चीज है हौसला। मैं देखता हूँ कि जिस तरह बाकी लोग अपने हकूकों के लिये बाट क्लब पर नारे लगाते हैं, उस तरह से फौज बाने नहीं कर सकते। इसलिए उनके हकूक की हिफाजत की गारन्टी हमारे ऊपर आती है और हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उनके हकूकों को बताने की कोशिश करें। इसलिए जो कष्ट उनको हो रहा है चाहे प्रमोशन के बारे में हा, यूनीफार्म के बारे में हा या मकानों के मिलानिये में हा, इन सब बातों पर ध्यान अगर हम दें तो बहुत-सी तकलीफें उनकी दूर हो सकती हैं। और जब उनको खुशी होगी तो उनका मुराल ऊपर उठेगा फोर दी ग्रेटर कोज आफ दी कन्ट्री। 1951 की रिपब्लिक डे पर यह कहा गया था कि फौज में 5 फोसदी में ले कर 80 फोसदी 1980 तक जो प्रमोशन का माप पूरा करना है आफिसर रैंक में लिये जायेंगे। लेकिन आज तक बड़ पुरा नहीं किया। जैसा मुझ में पहले बोलन वाले आदरणीय मेम्बरों ने कहा, मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ कि आज देश के अन्दर फौजों के अन्दर घुटन महसूस हो रही है। जो सरकार सदन में वायदे करती है और जो रिपब्लिक डे पर कहती है कि प्रमोशन रैंक में होगा जो कि हर आदमी चाहता है कि उस भी तरफकी मिले ताकि मुल्क की सेवा

कर सकें, लेकिन अगर कोई अफसर न मिले तो दिल में घुटन महसूस होती है। इसलिये जो वायदे यहाँ किये गये हैं वह पूरे किये जाये। इसी तरह में राशन का मामला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शायद कई मेम्बर साहेबान न जानते हों, तो उनकी जान गरी के लिये कहना चाहता हूँ कि राशन के मिलसिले में 180 ग्राम मीट हर रोज सिपाही को मिलना चाहिये। लेकिन नौवीं में तो दिन में 2 बार और एयरफोर्स में एक बार मिल जाता है लेकिन आर्म्स फोर्स के लिये हफ्ते में तीन बार मिलता है। यह जो डिस्क्रिमिनेशन होता है यह ठीक नहीं है। फोर्स में लड़ाई के मामलों में कोई भी एक दूसरे से पीछे नहीं है। इस तरह की घुटन की नीति थोड़ा पायजन पैदा करने वाली होती है, इसमें कामन काज में टेस पहुचता है और मैं समझता हूँ कि डिफेंस मिनिस्टर साहब इसे अपने टाइम में दूर करने की कोशिश करेंगे।

17 hrs.

नौवीं में रिटायरशुदा अफसरान का रिटायरलाय किया जाता है। जो काम वह करते है अगर 100 या 75 रुपये एलाउन्स मास्टर पैटी आफिसरज को दिया जाये जो कि गाढ़े बगाहे, बकन-फवकन आफिशियेटिंग इयूटी को सरंजाम देते है तो मैं नहीं समझता कि ऐसा न देने से हम कोई ज्यादा बचन कर सकते है। रिटायरशुदा को काम देने के मुकाबले इससे ज्यादा बचत हो सकती है और उस बचन को हम दूसरे मामलों में लगा सकते है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिा गया और यह कारण है कि आज भी इस तरफ उन लोगों के दिनों में एक किस्म की घुटन है।

आसाम, यू० पी० के पहाड़ी इलाके, हिमाचल और जम्मू में जो सोलजरी पैदा

करने वाले इलाके हैं, इनको हमेशा इन्फोर् किया गया है। वह लोग आज महसूस करते हैं कि इस मुद्दे के हिस्सेदार के नाते हम हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उनको पूरा हिस्सा नशे मिन रहा है मैं समझता हूँ कि जनता सरकार और डिफेंस मिनिस्टर इस तरफ ध्यान देकर ऐसे इलाको से जो कि पसमादा है, बैंकबड है, उन इलाको के लोगों की तरफकी के लिय ध्यान देंगे। जिनका पास्ट बडा उज्ज्वल रहा है, मैं समझता हूँ कि वह उन तरफ ध्यान देंगे और उनकी बेहतरी बहबूदी के लिय काम करेंगे।

जो लाग फौज में भर्ती होते हैं, स्टेट सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों के अन्तर्गत उनसे जमीन छिन जाती है और इससे उनमें डिप्रेशन लाइजेशन आ जाता है। इसीलिये लोग फौज में जाने में मुरेज कर रहे हैं। फौज में मिपाही की बर्दी पहनने या कन्ध पर बन्दूक रखने से ही कोई मिपाही नहीं हो जाता है बल्कि उसके पीछे टैडीशन्स, रवायात स्मिट हुआ करती है जिसमें मिपाही अच्छा होता है। अच्छा मिपाही तीन जेनरेशन में पैदा होता है।

एक मिपाही अगर लडार्ड में मारा जाय और उसकी बेवा के पाम कोई बच्चा रह जाय तो वह उस बच्चे का लोरिया और बहानिया मुनाकर कहती है कि तेरा बाप फला जग में मारा गया था। उसके बाद जब वह बच्चा जवा हा जाता है तो वह भी फौज में जाता है और उसका भी यही हथ हां ता इमी तरह से तामरा बच्चा जब फौज में जाता है और उसके दिल में इस तरह की कहानिया मुनकर जो दिलचर्पा पैदा होती है, वही अच्छा मिपाही होता है। यही अक्लमंदो का कहना है, जाती तजुर्बा है। इस प्रकार में मुल्त की फौज के लिय उन बचाव के लिय सरकार का फज बनता है।

आजकल एक्स-सर्विसमें अपने मैडिकल और बर्दी बेचने के लिय मजबूर होते हैं। सरकार ने यह कहा है कि हम 10, 2) फीमदी तक महकामो में नोकरी दगे, लेकिन प्रेक्टिस में अमली तौर पर यह बात कमलियत के कोमो दूर है। उनके दिल में भी यह होता है कि मैरिटोरियम सर्विस मुल्क की खातिर की है, हमारा भी मुल्क ने हिस्सा है, लेकिन उनका वह हिस्सा नहीं मिलता है जिसके कारण वह निराश होते हैं। मेरा मुभाव है कि एक्स-सर्विसमें, जिन्होंने मुल्क में सर्विस की है, उनकी आइन्दा चिन्तगो सुधारने के लिय और बेहतर बनाने के लिये यह सरकार कोशिश करे।

जम्मू कश्मीर की फोर्मो अब डि-मुन्तान की फौज में जज्ज हा गई है और उस पर डिडियन लाज और रेगुलेशन्ज लागू होते हैं। लेकिन सैकडो लोगो की शपैन, तरक्की, एलाउस और दीगर मामलात के झगडे चल रहे हैं। चकि उन लोगो का उनका हक नहीं मिल रहा है, इसलिए उन के दिला में एक आग्न सी प्रज्वलित हा रही है। यह कहा नहीं जा सकता है कि अपने हक हा मिल करने के लिय वे लोग क्या कुछ करे। एक्स-सर्विसमें तो सालजर्ज बोर्ट के जरिये अपने हको के लिए लड सकते हैं। आज भी उन लोगो की मुनवार्द नहीं हो रही है। इमी तरह जम्मू कश्मीर की मिलिशिया, जा आज जम्मू कश्मीर लाइट इनफन्ट्री के नाम से मीसूम है, के लोग भी इन्ही झगडा व शिकायत हैं और उन्हे उन के हक नहीं मिले है।

इन छोटी छोटी सी बातों की वजह में उन लागो के दिलो में फौज के लिए जा इज्जत और प्यार हांना चाहिए, वह न हां कर गुस्सा और निराशा पैदा हा जाती है इसकी वजह यह है कि उन लोगो की बेहतरी और बहबूदी के लिए,

[श्री बलदेव सिंह जसरोटिया]

उन को भलाई योग तरक्की के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए या वह नहीं किया गया ।

17.07 hrs.

[MR SPEAKER in the Chair]

मुझे आशा है कि डिफेंस मिनिस्टर साहब, जाहर लिहाज से काबिल है और माननीय है जिन्हें इन सब बातों का निजी तजुर्बा है, अपनी पहली फुर्त में इन शिकायतों का दूर करने की कोशिश करें और हर स्टेट में मौके पर जा कर इस्पेक्शन कर के देखेंगे कि लागू को क्या दुख है । अगर हम मियाहिदा और एक्स-मिनिस्टर की रिहायिश के लिए मकानों का इन्तजाम कर पायें, तो हम में बहुत बड़ी बेहतरी हो सकती है । और लोगों के लिए सारा साफ एड्रेशन भी बन सकता है ।

देवादा और बच्चा का बच्चीफ मिलते हैं, लेकिन दस महगार्ड बनाने में जिस प्रोपार्शन में उन में टजाफा होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है । हम में उन कदिलो में बेचैनी है और वह तभी दूर हो सकती है, जब कि सरकार इस तरफ ध्यान दे ।

SHRI NIRMAL CHAND JAIN
(Seoni) Sir there are many speakers in the list

MR SPEAKER There are other important subjects and they may be guillotined later Now, how much time are you likely to take?

SHRI JAGJIVAN RAM Minimum of 40 to 45 minutes

AN HON MEMBER, He may reply tomorrow

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
TARY AFFAIRS AND LABOUR
(SHRI RAVINDRA VARMA) It is
only a question of 40 minutes:

MR. SPEAKER Otherwise, a number of other items will be guillotined later

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया अगर कोई फीजी धरैर जरूरी इम्तहान पास किये हुए मर्फ दो साल के लिए एक्टिव रैंक हाल्ट करता है, ता वह उस रैंक की पेंशन का हकदार हो जाता है । लेकिन अगर कोई अफसर सबस्टैटिव रैंक हासिल कर नेता है मगर दो साल की शर्त पूरी नहीं करता है, और सबस्टैटिव रैंक इम्तहान पास करने के बाद हासिल करता है, तो उसे उस रैंक की पेंशन इसलिए नहीं मिल सकती है कि दो साल की शर्त पूरी नहीं हुई है । यह अन्याय है । इन सब बातों में फीजियों के दिलों में सुचीबती का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है । इस लिए इन सब सवालियों का हल करने की जल्द में जल्द कोशिश करनी चाहिए ।

हम में अभी एम्बेडिंग में देखा कि हमारी फीज को नई नई चीजें मुहैया की गई हैं । लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है । जो मुल्क आज तरक्की की राह पर चल रहे हैं अपनी फीज को उन के मुकाबले में लाने के लिए हमें जो कुछ भी कर पायें, वह कम है । डिफेंस मिनिस्टर साहब का बधाई देता हूँ, हमें आशा के साथ कि जो बातें मैंने प्रश्न की हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए वह फीज की मजबूती, मुल्क की सुरक्षा और हम सब लोगों की बेहतरी के लिए जरूरी कदम उठावेंगे ।

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा का प्रश्न देश के सामने सब

से बड़ा प्रश्न रहता है। यह ठीक है कि हम शान्ति चाहते हैं, लेकिन हम शान्ति से तभी रह सकते हैं, जब कि हमारे पास इतनी शक्ति हो कि हम किसी भी आक्रामक को मुहताब उत्तर दे सके। इसके निम्न जहाँ हमें अपनी सेना का मज्जित करना चाहिए, वहाँ हमें यह भी व्यवस्था करनी चाहिये कि हम किसी भी आक्रामक का मुकाबला तो कर सकें, लेकिन साथ ही हम हमेशा तैयार भी रह सकें। हमेशा की तैयारी बहुत आवश्यक अंग है सेना का। गफलत जब हाती है ना वही गभीर गफलत हा जाती है जा हम न 1962 में सही है। इस कारण और इस कारण भी कि जबलपुर में मेरा सबध है, आदरणीय रक्षाभवी मद्बोध्य का ध्यान मैं जबलपुर में जा डिफेंस इन्स्टीट्यूट है उन को और विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूँ। बहुत पहले जबलपुर का मुख्य रूप में इसलिए चुना गया था और वहाँ गन-कैरिज फैक्ट्री बनाई गई थी, आर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई गयी थी, मॅट्रल आर्डिनेंस डिपार्टमेंट खोला गया था कि वह हिन्दुस्तान का मध्य स्थल उमका हृदय स्थल है। वहाँ पर आक्रमण नहीं हा सकता। इस कारण उस को चुना गया था। मुझे खेद है कि उस दिशा में और आगे प्रगति नहीं हा पायी। सन 1942-43 के करीब वहाँ पर जो प्रगति थी वही पर खूब बढ़ स्थिर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा रक्षा मंत्री महादय में, कि जबलपुर की जो के तीन इन्स्टीट्यूट है उन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाय। और न केवल उन की पुरानी परिपाटी के अन्तर्गत देखा किया जाय बल्कि नये नये प्रयागों का भी एक कारखाना वहाँ खोलना बहुत आवश्यक है। आज देश में नये प्रयाग चाहिये। हम शायद उनकी गिनती यहाँ नहीं कर सकते, सेना के लॉग शायद उन की उतनी गिनती नहीं कर सकते जितना कि हम विज्ञान के विद्यार्थियों

को वहाँ पर बैठा कर सेना के बारे में उन में नये नये प्रयोग करा सकते हैं।

गाडार का हमें अनुभव है कि जितना माफिन्टिकेटेड गाडार रहेगा उतना ही हम सक्षमता में यह पता लगा सकते हैं कि दुश्मन हम समय हमारे ऊपर क्या गतिविधियाँ लगाए हुए हैं, वह कितनी दूरी पर है। हमें तैयारी का उतना मौका मिलना है। हमें उस का मुह तोड़ने का अवसर प्राप्त होता है।

उस कारण से और दूसरे कारणों से भी यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने अस्त्र यही हिन्दुस्तान में बनाये, नये नये प्रयोग कर के बनाये। दूसरी जगहा से अस्त्र या और जा कुछ भी लेते हैं उस के बारे में उन का पता रहता है कि उन्होंने हमें कौन भी चीज दी है। लेकिन जा हमारी खुद की बला रहती है विज्ञान रहता है उस के बारे में उन का जानकारी नहीं हा सकती। नैट विमान ने दिखा दिया है कि वह बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। तो य नये प्रयाग निरन्तर चलते चले जाएंगे और उन के लिए मैं पुन दाहराना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमारे डिफेंस इन्स्टीट्यूट काफी मात्रा में है, जबलपुर में वही पर और भी कुछ नयी प्रयोगशालाएँ और नये कारखाने खोलने बहुत आवश्यक है।

श्री जगजीवन राम : जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी होना चाहिए।

श्री विवेक चन्द्र जैन : वह तो होगा। जिन के पास कुछ नहीं है वे तो मांगेंगे ही लेकिन जहाँ पर कि सुविधा है, वहाँ पर

[श्री निर्मल चन्द्र जैन]

एक तो दस दृष्टि से और दूसरे दस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि जितना एक सेंट्रल प्लेस कोई हा सकता है वह उतना ही अच्छा है ।

श्री जगजीवन राम वह जमाना बीत गया ।

श्री निर्मल चन्द्र जैन जमाना भी वही है और निश्चित रूप में हम बार बार उमी जमाने की बात याद आती है ।

ना मैं एक निवेदन ना यह करना चाहता हूँ । दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस समय तट-सुरक्षा का एक अलग संगठन बहुत आवश्यक है । अब समुद्र की सीमा का जो विस्तार हुआ है दो सौ मील तक उस के लिए अभी तक अलग से कोई तट सुरक्षा का संगठन नहीं है । मैं इस और भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वह संगठन एक अलग से बनाना चाहिये और उसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है वह पार्लियामेंट के अदर या सुरक्षा मन्त्रालय के अदर होनी चाहिए ।

अभी हमारा आर्म्ड डिवीजन और सुरक्षा के सम्पूर्ण संगठन पर लगभग 4 प्रतिशत व्यय होता है । जो दूसरी चीज है, जो हमारी गंजी गंटी है वह तो निश्चित रूप से आवश्यक है लेकिन गंजी गंटी बरकरार बनी रह सके उस के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर पुनर्विचार किया जाय और सुरक्षा पर यदि अधिक व्यय करना करने की क्षमता हम प्राप्त कर सके तो बहुत उत्तम होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय सुरक्षा मंत्री महादय को अभी तक जा उन्होंने किया

है उस के लिए बधाई देना चाहता हूँ लेकिन साथ ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बातों की ओर भी विशेष ध्यान दें ।

श्री आर० एल० कुरील (माहनलाल-गज) आदरणीय सभापति महादय, आज डिफेंस मिनिसट्री के बजट पर बात चल रही है । जहां तक सुरक्षा का मवाल है, यह बहुत ही आवश्यक है, सबसे टाप प्रायर्टी पर इसको लिया जाना चाहिये इस में कोई दा मत नहीं है । यह सुरक्षा बजट बहुत ही मराहनीय है । मंत्री महादय ने जैसा बजट रखा है और उस में जो प्रावधान किए हैं वह वास्तव में बहुत मराहनीय है । जिन जिस विभाग में भी हमारे मंत्री महादय रहे हैं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस खूबसूरती और अच्छाई से उन्होंने अपने विभाग को निभाया है । उस विभाग में भी, जहां सुरक्षा सर्वापरि है, तमाम दूसरी बातों से उस को ऊपर रहना चाहिये, उस को ध्यान में रखते हुए जिस ढंग में उन्होंने बजट पेश किया है वह वास्तव में मराहनीय है ।

उसके साथ ही साथ में अरन कुछ मुझाव भी रखना चाहता हूँ । जिन प्रकार में और विभागों में शोइपूट कास्ट्स और ट्राइडज के लिए रिजर्वेशन के हिसाब में मजलियत दी जाती है इस विभाग में उसका कोई कंसिडेशन नहीं है । सेना में जो रेजिमेंट्स हैं वह जातिवाद के आधार पर बनी हुई हैं । इसको तोड़ना चाहिए । या ना एक अलग से हरिजन रेजिमेंट्स बनाई जानी चाहिए या फिर जानिवाद के आधार पर जो एग्जिस्टिंग रेजिमेंट्स बनी हुई हैं उनको तोड़ा जाये । इस प्रकार में जो मिलिट्री अकादमी है, या जो मिलिट्री स्कूल हैं जिन में ट्रेनिंग

दी जाती है, उन में शोड्यूल्ड कास्ट्स और शोड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोई प्रतिनिधित्व ही है। वहाँ पर यह वर्ग बिल्कुल ही उपेक्षित है। इस वर्ग के लिए वहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हर एक सैनिक स्कूल में और अकादमी में इस वर्ग का अच्छी तरह में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जहाँ तक योग्यता और अयोग्यता की बात है, योग्यता कभी मिलने के बाद आती है। आप किसी को माइकिल छूने न दें और कह कि तुम माइकिल चलाना नहीं जानते तो यह ज्ञान समझ मैं नहीं आ सकती। पहले मैं ही यह अनुमान लगा लेना कि इंग्लिश वर्ग उम में सफल नहीं, होंगे में उम बात को नहीं मानता। यह तो वही बात हुई कि किसी को माइकिल छूने न दें और कह कि तुम माइकिल चलाना नहीं जानते। आप पहले ही अनुमान लगा दें कि वह साइकिल चलाना नहीं जानते। पहले आप उम को माइकिल द और फिर देख कि वह उम का चला पाना है या नहीं। उम लिए मेरा निवेदन है कि इस वर्ग का आप विशेष ध्यान रखें। हिन्दुस्तान का इतिहास बनलाना है कि हिन्दुस्तान के केवल 25 प्रतिशत लोग, चार वर्गों में से केवल एक वर्ग, हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए रहा है और दूसी वजह से हिन्दुस्तान गुलाम रहा, विदेशियों ने इस का लूटा, यहा तक कि गुलाम वश तक यहा पर शासन कर गया। इसका क्या कारण है? कारण भाफ है— अन्य तीन वर्गों का सुरक्षा के लिये अयोग्य समझा गया, केवल एक ही वर्ग को युद्ध और रक्षा के लिए रखा गया लेकिन इस को देश की 75 प्रतिशत आबादी को इस तरह से इगनोर नहीं करना है, हर वर्ग के

लोगों को उस में पूरा प्रतिनिधित्व दिया गए, इस बात का ध्यान रखना है। जातिवाद के आधार पर जो रेजिमेंट्स बनाई जाती है, जैसे जाट रेजिमेंट या दूसरी इस तरह की रेजिमेंट्स, उन को समाप्त करना चाहिए या पापुलेशन के हिसाब में उम में कोटा फिक्स किया जाय, जिस में हर वर्ग के लोगों को उस में प्रतिनिधित्व मिल सके।

जो लोग आज देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिये लड़ते हैं, उन को जो सुविधाय प्राप्त है, वे बिल्कुल अपर्याप्त है। वे प्तों सीमाओं पर लड़ते हैं, लेकिन यहाँ उन के बच्चों को परेशान किया जाता है, पुलिस या दूसरे लोग उन को सैकेण्ड-ग्रा या का सिटिजन समझते हैं, यह बात समाप्त होनी चाहिये। उन को उचित सम्मान मिलना चाहिये। जो देश की रक्षा करते हैं, उन के साथ यह व्यवहार बहुत अमानवीय है, गलत है।

मे मंत्री महोदय से एक निवेदन विशेष रूप से करना चाहता हूँ—कास्ट के बंमिज पर जो रेजिमेंट्स बनी हुई है या तो उन को तोड़िये या शोड्यूल्ड कास्ट्स, शोड्यूल्ड ट्राइब्ज और बैकवर्ड क्लासेज, की रेजिमेंट का संना में स्थान दे, जिस में कि इस वर्ग को, जिस की मख्या देश में करीब-करीब 80 प्रतिशत है, यह प्रतिनिधित्व मिल सके।

अन्त में मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ— उन्होंने इतना अच्छा बजट बनाया है। मैं उन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस में

[श्री आर एन कुरील]

कुछ ऐसा प्राविधान रखे, जिस में एम्प्लाइज को, स्पेशली डिफेंस एम्प्लाइज को कुछ और अधिक मिल सके।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम)

अध्यक्ष जी, सदन के चारों तरफ में हमारे सुरक्षा मैनोफो के आफसरो, हमारे जवानों, को जा प्रशंसा दी गई है, उस के लिये मैं इस सदन को धन्यवाद देता हूँ। वे प्रशंसा के योग्य हैं और मैं भी अपनी तरफ से डिफेंस फोर्सों के आफसरो और जवानों की प्रशंसा भेजता हूँ।

अध्यक्ष जी, यह स्पष्ट है कि हमारी नीति शान्ति की नीति है, सभी देशों के साथ मिलता करने की नीति है और विशेषकर जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ प्रेम का व्यवहार हो, मिलना का व्यवहार हो और उन के साथ हम शांति के साथ अच्छे पड़ोसियों के रूप में रह सकें—यह हमारा प्रयत्न है। लेकिन दुनिया के इतिहास में बहुत ही ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जहाँ शांति का अन्दाजा न करते हुए भी कुछ देश दूसरे देशों के साथ छेड़खानी कर देते हैं। उम स्थिति के लिये हम का तैयार रहना है। मैं विस्तार के साथ इस बात में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सदन को यह ज्ञात है, कि हमारी तरफ से बाराबर यह प्रयत्न हुआ है कि पाकिस्तान के साथ हमारा सम्बन्ध मिलता का सम्बन्ध हो जाये, बंगला देश के साथ हमारा सम्बन्ध मिलता का सम्बन्ध हो जाये चीन के साथ जो तनाव है, उम तनाव में थोड़ा डीलापन हो जाय। लेकिन हम कितना भी आगे बढ़ें, जब तक हम दोनों तरफ से नहीं बढ़ाये जाते, तब तक मिलता नहीं हाती है। हम ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया खुशी की बात है, उधर से भी हाथ कुछ बढ़ा है।

हमने आगे बढ़ कर मिलता करने का प्रयत्न किया है श्री राजू ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होगा, इस बात की घोषणा है और इस बात के लिए हम प्रयत्न करें : मैं मानता हूँ कि हम प्रयत्न करें और हमारा और उन का रिश्ता एक माधुर्य रिश्ता बन जाए, उस में कृत्रिमता न रहे लोगों का आदान-प्रदान हान लगे, व्यापार तिजारत हाने लगे, इस के लिए मैं मसझता हूँ कि इस बात की घोषणा न करत हुए यह घोषणा के तुल्य हो सकता है और इसलिए मैं, इस तरह की घोषणा के लिए हम अपनी तरफ से बढ़ा पहुँचे, इस बात की आवश्यकता नहीं मसझता चीन के बारे में बराबर हम न कहा है कि हमारे सम्बन्धों में जो तनाव है उम तनाव का डीला करतू मैं हम लगे और एक दफा तनाव डीला हा जाएगा तो मैं मसझता हूँ कि और भी रास्ते निकल सकेंगे जैसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हमारी भूमि पर जा चीन का अधिकार है उम बात का भी बर्तालाप कर के मुलझाया जा सकता है। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि किसी देश की सुरक्षा नीति उम देश की विदेश नीति के ऊपर निर्भर करनी है और विदेश नीति निर्धारित करने में सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है और उम में वे सब बातें कर ली जाती हैं।

डा० करण सिंह जिन को हमारे अधिकारियों में हमारे जवानों में मिलने का बहुत मोका मिलता है जो उन की आशाओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखते हैं, उन का यह भी जानकारी रहनी है कि जो उन की अवस्था है, उस में उन की मनावृत्ति क्या है—मैं भी कई सुझाव दिये हैं एक ता उन्होंने कहा कि रिमर्च और डिबेलगमेंट के सम्बन्ध में सभी प्रकार के वैज्ञानिकों की मलाह लेने के लिये एक कौमिल होनी चाहिए। उन का मालूम हाना चाहिए कि हमारी एक रिमर्च एण्ड डिबेलगमेंट के लिए एक कौमिल है उसमें

अभियन्तार एनर्जी, स्पेस रिसर्च और सी० एस० आई० आर० के लोगों का सम्बन्ध है और उस कौंसिल में सभी का प्रतिनिधित्व है। और इस में ऊँची और कोई कौंसिल हमारे देश में सम्भव होगा, ऐसा मैं नहीं समझता। ठीक उसी तरह से हमारी सेना के ऊपर कोई कौंसिल हो, इस का मुझाव श्री यशदल शर्मा ने दिया, और उस में कान हों? जा अवकाश प्राप्त आफमर हों, उन का वह कौंसिल हों, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने पिछली दफा बताया था कि हमारी नीनों मेनाओं के अध्यक्षों की एक कमेटी है और वह कमेटी बराबर मिला करती है। उन नीनों अध्यक्षों में जा मद में वर्गित हाता है, सीनियर होता है, वह उस कमेटी का अध्यक्ष हाता है और इन नीनों का समन्वय करने का एक और भी रास्ता हमारे पास है, जिस का कहने है डिफेन्स मिनिस्टर्स कोरिंग मोटिंग। आम तौर पर मप्ताह में एक बार हमारी मोटिंग होती है, जिस में रक्षा मंत्री, हमारे राज्य मंत्री, सचिव उत्पादन विभाग क सचिव, कौबिनट के सेक्रेटरी और हमारी नीनों मेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। उस का कोई एजेन्डा नहीं हाता है। वहा पर बातें होती है, नीति निर्धारित होती है और कही पर अगर कोई रायत आती हों, तो उस का मुलमाने का काम होता है कौमे तीनों में समन्वय हो, इस पर विचार होता है। उस तरह में वहा पर नीनों मेनाओं के काम का समन्वय हाता है। इस में ऊँची और किसी कमेटी का निर्माण नहीं किया जा सकना है और इस कमेटी के रहते हुए मैं किसी और कमेटी की आवश्यकता नहीं समझता ह। सेना का आधुनिकीकरण, माडरना इजेशन एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बराबर ध्यान देने रहना पडता है। जिस गति में आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति हो रही है, उसमें हमें बराबर प्रयत्नशील रहना पडता है। कि कहीं हम पीछे न पड जाएँ, हमारे अस्त्र-शस्त्र पुराने न पड जायें। नये से नये अस्त्र-शस्त्र

हमारे पास हों, पुराने अस्त्र-शस्त्रों का हम नवीनीकरण करते रहे। जब नये अस्त्र-शस्त्र हम लायेंगे तो यह मानी हुई बात है कि जिन लोगों को उन अस्त्र-शस्त्रों का इस्तेमाल करना है, उनको प्रशिक्षण भी देना होगा। अगर हम उनका प्रशिक्षण नहीं देते है तो उन अस्त्र-शस्त्रों का ला कर क्या करेंगे। चाहे ये मिसाइल हों, राकेट हों, नय टैंक हों, नय हवाई जहाज हों, नये नाप हों, जा कुछ भी हम लावे, उनके लिए हमका अपने लागा का प्रशिक्षित करना है। यह मैं कोई गुप्त रहस्योदघाटन नहीं कर रहा हूँ अगर मैं यह बता दूँ कि जहा में हम इन चीजों को धरीदते है, वहा मव से पहले हम अपने लोगों को भेजते है ताकि वे बहा शिक्षा ग्रहण कर लें और उन्हें पूरी तरह से देख लें। डा० कर्णसिंह को यह भी मालम है कि बीच-बीच में हम अपने सैनिकों और आफमरों को प्रशिक्षित करने का प्रबन्ध करते है जिससे कि जो वे सीख चुके है वह उनकी शिक्षा पुरानी न पडने पावे और नया जो कुछ हमारी फौज में आ गया है, उसकी जानकारी उनको हो जावे। इसके लिए हम बराबर प्रयत्न करने रहते है।

नीनों सेनाओं—थल सेना, वायु सेना और नौ सेना—का समन्वय होना बहुत ही आवश्यक है। पाकिस्तान के साथ पिछले युद्ध में केवल अपने देश को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को यह देख कर आश्चर्य हुआ कि भारत में तीनों मेनाओं का किस तरह से सफलतापूर्वक समन्वय किया गया। पैदल सेना किधर चलेगी, वायु सेना के द्वारा उसको किस प्रकार समर्थन प्राप्त होगा और उसकी समय नौ सेना क्या गुजरेगी, इस प्रकार का समन्वय करने का हमारा बराबर प्रयत्न रहता है। तीनों सेनाओं का समन्वय रहे, तीनों का शक्ति संतुलन रहे यह बराबर प्रयत्न रहता है। इसके साथ ही फौज में नये टैंकों का आना,

[श्री जगजीवन राम]

नये सिद्धादलो का आना, नये श्रीजारो का आना भी आवश्यक है और यह हम करने रहते हैं ।

उत्पादन क सम्बन्ध म राज्य मन्त्रा ने बताया, मैं उसके बारे में इस सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन उनका जरूर कहना कि दूसरे मुद्दा से जिस चीज का हम लेते हैं उसका आन प्रदा भी बनाने का प्रयत्न करते हैं और इसका बनाने के साथ साथ अब तो हमने यह कहा है कि उस चीज के पार्ट्स और पुर्जे हम मिर्रु अपने ही उद्योगों के लिए नहीं बनायेंगे बल्कि जिस मुल्क से हमने जा चीज ली है वनने वाली चीज व लिए भी हम अपने पाट्रन और पुर्जे भेजेंगे ।

हवाई जहाज के बारे में यहाँ चर्चा चली । इस सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों का मैं यह बताना कि हमारे कुछ हवाई जहाजों की उम्र कुछ ज्यादा हो गयी है । कुछ हमारे लडाकू हवाई जहाज केनबरा वगैरह, हैं वे पुराने हो गये हैं । यह मानी हुई बात है कि पुरानी चीज का हटाया जाता है और जब पुरानी चीज का हटाया जाता है तो फिर उसी तरह की चीज को नहीं खरीदा जाता है । अगर हमारा पाम माटर गाडी है, वह खराब हो गयी है, पुरानी ही गयी है तो फिर हम यह प्रयत्न नहीं करते कि 27 माडल का शेबरलेट ही खरीदें । हम प्रयत्न करेंगे कि अच्छे से अच्छी आधुनिक माटर कार खरीदें । यह डी० पी० एम० ए० का लेकर के बहुत तरह की चर्चा अब्बावारी में हो रही है । मैं तो यह कहना है कि हमारा जहाज पुराने पड गये हैं । अब उनकी जगह पर जा जहाज हम खरीदेंगे वे उसी मात्रा में नहीं खरीदेंगे, आधुनिक माडल के खरीदेंगे । यह माटा भी बात है । हममें अहसी करने की भी बात नहीं है । हमारे एक्सपर्ट्स म लोग जा इस के माहिर हैं, उनकी टीम तीन दशों में गयी थी और जहाजों का देख कर के आयी है और सम्भवतः

उसने आज अपना रिपोर्ट भी दी होगी । हम जल्दी ही उसके बारे में केबिनेट की कमेटी में विचार करेंगे और फैसला करके इन तीन मुल्का में से जिससे भी खरीदना होगा खरीद लिया जाएगा । लेकिन खरीदने के साथ साथ हमारा यह प्रयत्न होगा कि हम उन्हें अपने ही देश में बनाने के साथ साथ हमने एर शर्तें यह मा रखी हैं कि जा हम अपने देश में लानेंगे उनमें से पाण्डु म और पुर्जे वही बात हममें खरीदेंगे । मय मैरिन पनडुब्बी के लिए भी इसका प्रयत्न रहे है । मान आठ पाठिया में इस सम्बन्ध में भी चर्चा हुई हमारा नाग गए थे देख कर आए है । वहाँ से लाया जाए है कुछ बात हुई है । मिद्वान्त रूप से सरकार का फैसला हा चुका है कि हम पनडुब्बी खरीदेंगे और साथ ही साथ उनको अपने देश में बनायेंगे । आधुनिकता की तरफ जाने का यही तरीका है कि हम खरीदें और फिर उनको अपने देश में बनाने लेंगे और उसके पाट्र पुर्जे सभी बनाएँ और उन्हें दूसरे देशों में निर्यात करें ।

पहले जा कुछ किया गया उस में थोडा सा अभाव, लुटि रही है कि हम तेजी के साथ उनके पाट्र पुर्जे बना कर स्वावलम्बी नहीं हो सके । लेकिन अब तेजी के साथ उस तरफ हमारे कदम उठ रहे हैं और जल्दी हम उस में आत्म निर्भर हा जाना चाहते हैं ।

मिमी माननीय सदस्य ने कहा कि यहाँ पर हवाई जहाज बनाने चाहिये । प्रो० शेर सिंह ने बताया है कि वे तो हम बना रहे हैं । हैलीकाप्टर भी बना रहे हैं । [वाकी जहाज बना रहे] कुछ ऐसी भी जिनका हम लोगो ने किया है बनाया है । उम्र हिमाव में बना रहे हैं । मैं तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं । एक तरह का लाना हमने है कि जहाज इन्डुस्तान को डिबेनरिग कट्टी मटा जाता है वह बहुत से मुल्कों की तुलना में यह एक डिबे ल

कंद्री है। यह सही बात है। कुछ मुल्को की तुलना में हम डिबेलपिंग कंद्री है लेकिन उन मुल्को की तुलना में चाहे वह अमरीका हो इंग्लैंड हों रूस हों कंद्री एक क्षेत्रों में हम डिबेलपिंग कंद्री कह जा सकते हैं, हम में कोई संन्देह की गुजाश नहीं है।

हमारी फौज का जो उपनब्धिया है उसको देखने हुए हम कह सकते हैं कि हमारी फौज किसी देश की फौज की तुलना में किसी तरह में कम नहीं है। यह किसी मुल्क की तुलना में बहुत श्रेय की बात होती है।

इसी तरह में टैको के मामले में भी हम बहुत आगे बढ़े हैं। एक गौरव की बात है। दूसरे देशों में जब पूछा जाता है कि क्या हम आप टैक द मकेंगे, हमारे मुल्का में पूछा जाता है कि क्या क्या हथियार आप द सकेंगे क्या एम्पनिशन द सकेंगे। उसमें यह मालूम होता है कि हमने भी प्रगति का है। पिछले 20-25 सालों में देश में आधुनिक आधार का निर्माण हुआ है। किसी देश की सुरक्षा के लिए आधुनिक आधार का निर्माण होना नितान्त आवश्यक होता है। एक इंडस्ट्रियल वेम की बहुत आवश्यकता होती है। हम सुरक्षा के उपादानों के सम्बन्ध में स्वावलम्बी नहीं हो सकते और सुरक्षा के उपादानों में स्वावलम्बी होने के लिए इंडस्ट्रियल वेम का होना आवश्यक होता है। प्राइवेट मैक्टर हों, पब्लिक मैक्टर हों, सरकारी मैक्टर में हों, सब मिल कर एक राष्ट्रीय मैक्टर बन जाता है। हमने प्रयत्न किया है कि सुरक्षा के उपादानों के काम में हम सभी मैक्टरों से चाहे पब्लिक हों या प्राइवेट जितना उसका उपयोग कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। यह तो गलतफहमी है और हमेशा स्थान रखना चाहिये कि चाहे किसी क्षेत्र या उद्योगपति या सरकार की शक्ति में उसकी शक्ति बड़ी ही मरती है। तब कैसे बड़ा जाया जा सके ? उद्योगपति आपके ऊपर सवार हो जाएगा ? जिस देश के अन्दर अपनी शक्ति का उसको भरोसा नहीं है वही वैसा कह सकता है नहीं

तो किसी उद्योगपति की शक्ति सरकार की शक्ति में बड़ी नहीं हो सकती है या उद्योगपतियों की सामूहिक शक्ति भी सरकार से बड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए हम तेजी में स्वावलम्बी बनना चाहते हैं।

एक बात और है। देश में किसी बात के निर्माण के लिए क्षमता होना बड़ी क्षमता फिर उद्योगपति करना देश के माधुनिकता का दुरुपयोग करना होता है। ये दोनों दृष्टिकोण हमारे सामने हैं।

नाम मनाया में बहुत लागू है। देश गरीब है। माधुनिकी शक्ति है। फौज के माधुनिकी की माधुनिकी कर्माग, काम करने का हानत का कुछ तुलनात्मक दृष्टि में देखना होगा। उनको विन्कुल समाज से अलग करने तो नहीं साध सकते हैं। हमारे मन में आता है कि इतने परिश्रम का काम करने हैं उनके लिये हम कुछ कर दे। लेकिन देखना पड़ता है कि देश का जितना साधन है उसके भीतर ही हमका प्रबन्ध करना पड़ेगा। फिर भी हमारे अफसर की जब बहाली करनी होती है तो जितने की आवश्यकता हो उससे कई गुना आवेदन-पत्र आते हैं। जहाँ तक जवानों की भर्ती करने का सबाल होता है वहाँ जितनी आवश्यकता होती है उस में न मालूम कितने गुना आ जाते हैं, कहीं नहीं पर ला एंड अफसर की समस्या खड़ी हो जाती है। अगर यह मान लीजिये कि हमारे फौज की बहाली वैकछा की बहाली है, हमारे देश की फौज वीटिन्दी फौज है। किसी अफसर से बात होती है तो मालूम होता है कि उनके ग्रान्ड फादर फौज में थे, उनके पिता थे, वह भी फौज में हैं और उनके लड़के भी फौज में हैं, और बड़े फरक में बढ़ते हैं कि हमारे तीन लड़के हैं और तीनों रिफिंग फार्मेशन में हैं। तो हमसे मालूम होता है कि हमारे लोगों में हमके प्रति देशभक्ति की भावना है और ए. ए. प्रसिद्धा की भावना है। आज भी फौज के साथ बढ़ते हैं कि हमारा बेटा नौवीं, एयर फोर्स या फौज

[श्री जगजीवन राम]

मे है। मैं नहीं समझता कि उसकी तरफ ध्यान से लागे वा कोई मकोच हो रहा है। यह जर्मन है कि उनके काम करने के हाता का हमें उक्त मुद्दा रहे।

आ हमें न कुछ बातें कहें जाना। खान में मध्य में अस्पताल में ध्यान में सम्बन्ध में। मध्य में नगना है। जर्मन उनका मारा गते बताया उसमें कुछ नये साथ नये नहीं लिया। मैं उनका दावा है कि मैं दिन प्रत्येक मध्य में वह कि आन चना तुम्हारे अस्पताल का खाना देखना चाहते हैं अनाना चन और वहां से खाने का खा कर देखना नये कर कि खाना खराब है या अच्छा है। आर दवा के सम्बन्ध में वह दवा कि दवा अफसर और जवान का नहीं दी जाती है उच्च बीमार का दी जाती है। और इमलिय जिम बीमार या जिम तरह की आवश्यकता है उसी तरह की दवा उमका दी जाती है। हमारे मिलिटरी अस्पताल से यह शिकायत नहीं आया है अभी तक। और अगर कहा में शिकायत उनके पास है तो मैं नजीर हमारे पास लिखे तो मैं देखगा। ऐसे रहने में कुछ नहीं हाता है। हमारे यहां कुछ सिमिग्रान्स्का राग है उनकी मारी बाना को उरठठा कर दिया जाय तो हमारे मार्ग आमा हा सम्बन्ध सम्बन्धन हा जाता है। मैं नहीं समझता था भी जिम्मेदार मदस्य चाहगा कि भारतीय मना का बन्धनशन कर दिया जाय। आर उमनि, जिसे नये नये कर न मां का दिया उसमें उनके साथ न्याय नहा लिया है।

नीमना के सम्बन्ध में मैं मानता हू कि उमका महत्त्व बढ़ा जा रहा है। और इमलिय हमारे रिफिस बजट के अनुपात में भी नौसैना के ऊपर बढ़ानगी हा रही है। पहले 7 प्रतिशत था, लेकिन इस साल 10 प्रतिशत हा गया है। अगल माय 11 प्रतिशत से ज्यादा हो जायगा। तो हम नौसैना के महत्त्व का समझ रहे हैं इमलिय नये नये उसमें युद्धपात भी लगा रहे

हैं। अपने यहां फिगेट भी बना रहे हैं, उमके नये तरह का बतन सिस्टम लगा रहे हैं, नये तरह के हथियार लगा रहे हैं मिसाइल का भी प्रबन्ध कर रहे हैं जिससे हमारी नौसैना एक मक्षम नौसैना बन सके और जो जिम्मे-दारी उमके ऊपर पड़े उम जिम्मेदारी का वह निमा मक। और जिम्मेदारी उमकी यह है कि हमारे जल की सुरक्षा करे हमारे मर वैंटाइन पाता का अर्थित जावाणिय करने बान जहाज है उनका सुरक्षा द मके। हमारा काम्ट सागर तट लम्बा है। काम्ट गाड के ता भी सगठन बन गया है। मैं न पिछली दफा बताया था वहा किसी प्रश्न के उत्तर में कि उमका निर्माण हा चुका है उसके लिए कुछ जहाज ल लिय गये हैं और एक सक्षम काम्ट गाड का निर्माण होगा जा हमारे समुद्र तट की निगरानी कर सकें।

बोचिन या प्रश्न माननीय गजून उठाया था। बोचिन मिबिल पाट है हमारी नौसैना ना नहीं है। विशाखापटनम का पूरा विकास हा रहा है यह आपका मालूम है। और मैं विस्तार के साथ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि श्री गजून उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। इनना ही कहूंगा कि विशाखापटनम का काफी विवाम किया जा रहा है। कंगडो रुपये उगम नग रहे है।

हमारा फाज से जा राग निकलते है, उनकी पर बडा समस्या है। यह समस्या विणेषकर वना उमनिय हा जाती है क्यकि दग में जा बेकारा की समस्य है उसके सदर्थ में दखन पर यह बहुत जटिल मालूम हाती है। 50 60 हजार राग माल में फीज से हटते है और ध्यान ले कि इसमे से आधा लोगो के लिये भी गोजगार का इन्तजाम करना है ता 25, 30 हजार लोगो का इन्तजाम करना हुआ। हमने केन्द्र के विभागी में राज्य सरकारों की

नौकरियों में, हमारी जो पब्लिक अडरटेकिंग है, उनकी नौकरियों में सेना से निकले हुए लोगों के लिये रिजर्बेशन किया हुआ है, सरक्षण किया हुआ है, लेकिन कठिनाई यह हो जाती है कि जिस तरह की योग्यता के आदमों उनको चाहिये, हमारा फीज में निकले हुए लोगों के पास वह योग्यता नहीं होती है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रशिक्षण देकर उनको उस योग्य बना सकें। अफसरों के लिये भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे इस तरह की योग्यता इनमें मके कि वे मिलिन में भी काम कर सकें इस तरह की योग्यता उनमें आ सके।

इमने पिछली दफा यह प्रयत्न किया था कि जब मानजर या भीमन फीज में निवन्तना है ना उमके 6 महीने पहले ही हम किमी टैक्नीकल या बॉकेशनल ट्रेड में उमे प्रशिक्षण दे जिससे वह नौकरी पा सके या सैन्फ एम्पलाय-मेंट में लग सके। स्वयं काई राजगार कर सके। उसकी एम्पलायबिलिटी बढ सके, गेटी कमाने की योग्यता बढ सके। इमलिय यह कर रहे हैं। यह स्कीम चल रही है, और कारगर मिड हुई तो इसको बडे पैमाने पर चलाना है। लेकिन इम चीज का नहीं भुलना चाहिय कि काई भी ट्रेड करे, उममें एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब सेचुरेशन प्वाइन्ट हो जायगा। इन्वैक्टिगियन को ट्रेनिंग करे ता एक नम्बर आने के बाद इन्वैक्टिगियन्स को माग नहीं रहेगी। ता यह समस्या टेडी हा जाता है। अगर इन्ही लोगों के लिये सरक्षण कर दे तो समस्या ज्यादा टेडी होगी क्योंकि इन लोगों को तो कुछ न कुछ पेशन मिल रही है, लेकिन जो नई लेबर फोर्स आ रही है, उसको तो कोई आमदनी नहीं है। यदि सम्पूर्ण रूप से देखे तो मालूम होता है कि जिसको 140 रुपये मिल रहा है, उसको प्राथमिकता दी जाये या जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसको प्राथमिकता दी जाये? इसीलिथे मैंने कहा कि यह एक टेडा सवाल हो

गया है। जब हम सोचते हैं तो एकागोरूप से तो नहीं सोचना पडता है, इसको सम्पूर्ण संदर्भ में सोचना पडता है, लेकिन फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इन्हे जमीन देकर, सैल्फ एम्पलायमेंट देकर, बैंको में वर्जो दिलाकर ट्राय्पार्ट में या किसी न किसी काम में यह लाग लग सके, इसका प्रबन्ध किया जा रहा है।

और भी बहुत में छोटे-छोटे प्रश्न उठाये गय है, लेकिन उन प्रश्नों के बारे में मैं मारतीय सदस्यों में यह निवेदन करूंगा कि जिन की जनरल इम्प्लीकेशन नहीं है, जा समस्या एक या दो व्यक्तियों में सम्बन्ध रखने वाली है, वह अगर हमें निख दे तो उमका ज्यादा समाधान हो सकेगा, बनिस्पत उमे सदन में उठान के और जिनका सम्बन्ध बम्बे में है, वह यहा उठाये। जिम का जबाब हम नहीं दे सकेंगे, उसके बारे में भी हम इतना आश्वासन देंगे कि विभाग में सब के ऊपर विचार करायेगे और उस पर जा कुछ उचित कार्यवाही करानी हागी वह करायेंगे।

जहा तक लेबर रिजेशन का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि आमतौर में सतोपजनक है। लेकिन हमारी भी कठिनाई बढ जाती है, आजकल हमारे देश में जा सम्पूर्ण श्रमिक आन्दालन की समस्या है, वह ट्रेड-यूनियनों की बहुतायतता है। एक-एक इडस्ट्री में कई-कई यूनियने हो गई है। (स्वबधाल) जितनी हमानी परेशानी है, उससे ज्यादा परेशानी श्री रबीन्द्र वर्मा भी है। लेकिन हम लोगों की परेशानी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि माग के मुद्दे पर उतना झगडा नहीं होता है, जितना इस बात पर झगडा होता है कि इस प्रतिष्ठान में मान्यता किस की रहेगी। अगर माग पूरी भी होन को होती है, तो यह झगडा होता है कि इस यूनियन के द्वारा क्यों हो, हमारी यूनियन के द्वारा हो। या मांग को इस तरह बडा दिया जाता है कि समस्या

[श्री जगजीवन राम]

सुलझने न पाय। हम इस सम्बन्ध में सदन के सदस्यों का सहयोग चाहेंगे। अगर यूनियनों को तादाद कम हों, तो सम्म्या कुछ सुलझ सकती है और श्रमिकों तथा मालिकों के सम्बन्ध अच्छे बन सकते हैं।

अध्यक्ष मतादय, मैं सदन का अधिकांश समय नहीं लाना चाहता हूँ। मैं फिर कहूँगा कि हमारी सुरक्षा सेनाप्रा के तीन। अर्थात्—स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना—के अफसर और जवान देशभक्ति से अनुप्राणित हैं। जब जब भ्रमण आया है, उन्होंने सिद्ध किया है कि मातृभूमि की मर्यादा का रक्षण के लिए वे किसी भी त्याग का बड़ा त्याग नहीं समझते हैं। जातिभेद, वर्णभेद और भाषाभेद, कोई भी इस में रुकावट नहीं पैदा कर सका है।

एक युग था, जब कुछ लडाकू जातियाँ समझी जाती थीं। वह युग बीत गया। चाहें कोई मद्रास का हा बंगाल का हा केरल का हा या पंजाब का हा मैंने पिछले पाकिस्तान युद्ध में उन सब में होड़ होते हुए देखी—उन में इस बात की प्रतियोगिता थी कि भारत माता के स्वाभिमान को बचाने के लिए कौन अगली कतार में रहेगा। और सब में बड़े पारितोषिक पाने वालों में मद्रास का एक युवक था बिहार का एक आदिवासी था। इस लिए यह कैसे मानें कि जो परम्परा में युद्ध लड़ने वाली जातियाँ समझी जाती थीं, वह कुछ न्यायसंगत बटवारा था? जब भ्रमण आया, तो मैंने सिद्ध किया कि बलिदान देने की शक्ति सब में है। मैं मानता हूँ कि माननीय सदस्यों द्वारा भारतीय सुरक्षा सैन्य की प्रशंसा और उन के द्वारा यह बात स्वीकार किया जाना उन का अनुप्राणित करेगा, उद्दीलित करेगा और मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर

करने के लिए उत्साहित करेगा। मैं उन की तरफ से सदन के प्रत्येक नैम्बर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि हमारी मांगे सर्वसम्मति से स्वीकार की जायगी।

MR. SPEAKER I shall now put all the Cut Motions moved to the Demands for Grants of the Ministry of Defence for 1978-79 to vote together unless any hon Member desires that any of his Cut Motions may be put separately I now put all the Cut Motions together to the vote of the House

All the Cut Motions were put up and negatived

MR SPEAKER I shall now put the Demands for Grants to the vote of the House The question is

"That the respective sums not exceeding the amount, on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1979, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demands Nos 19 to 24 relating to the Ministry of Defence"

The motion was adopted

MR SPEAKER We shall take up the next item tomorrow We can rise five minutes earlier, we deserve it We adjourn to meet again at 11 00 a m tomorrow

17.55 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 28, 1978/Chastra 7, 1960 (Saka).